राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या: 08

शुक्रवार,

25 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

बोराड़ा (किशनगढ़) में उप-तहसील का भवन निर्माण

106. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम पंचायत बोराड़ा में बजट 2021-22 में उप-तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त उप-तहसील में नायब तहसीलदार के साथ-साथ विभिन्न पदों का सृजन किया जाकर उप-तहसील ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घोषणा के अनुसार उक्त उप-तहसील हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी नहीं। ग्राम पंचायत बोराड़ा में उप-तहसील सृजित किये जाने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जिला अजमेर की तहसील सरवाड़ में राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(42)राज-1/2021 दिनांक 30.07.2021 जारी कर नवीन उप-तहसील बोराड़ा का सृजन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उप-तहसील बोराड़ा के नवसृजन पश्चात् राजस्व (ग्रुप-2) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(31)राज/2/2021 दिनांक 05.01.2022 द्वारा नवसृजित उप

(राजस्व मंत्री)

तहसील कार्यालय हेतु नायब तहसीलदार के पद सृजन के साथ अन्य विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। आज्ञा की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

वर्तमान में नवीन उप-तहसील बोराड़ा से संबंधित कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ एवं भू-अभिलेख निरीक्षक डबरेला तहसील सरवाड़ को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाकर नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। उप-तहसील बोराड़ा के नवीन भवन निर्माण हेतु 1.50 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया जा चुका है। भवन निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

वर्तमान में कार्यालय उप-तहसील बोराड़ा से संबंधित कार्यों का सम्पादन/निस्तारण ग्राम पंचायत बोराड़ा के पुराने भवन में किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। धन्यवाद नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): हां सर, धन्यवाद तो इसलिये दे रहा हूं कि क्वेश्चन लगने के बाद मेरी उप-तहसील चालू हो गयी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं यह जानना चाह रहा हूं कि स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने प्रमोशन किये हैं और एक वीक में इनके सारे पद भर देंगे, बाकी अभी कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देकर कार्य किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में नन्दीशालाओं हेतु भूमि का आबंटन

107. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्रदेश की समस्त पंचायत समितियों पर नन्दीशालाएं खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि

(श्री सुभाष पूनिया)
हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कौन-कौनसी पंचायत समितियों में नन्दीशालाएं खोली गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नन्दीशालाओं के लिए भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नन्दीशालाओं के लिये सरकार द्वारा बजट राशि का आबंटन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के मॉडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं। नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गोपालन समिति द्वारा किये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंघाना, बुहाना व सूरजगढ़ पंचायत समितियों में स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है।

(2) पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत जारी दिशा-निर्देश में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला हेतु बीस लाख रुपये संस्था के स्वयं के स्वामित्व के होना आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पंचायत समिति...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, क्या पढ़ रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो जवाब दिया है वो ही पढ़ें, जो रिटन जवाब है।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया):...पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत जारी दिशा-निर्देश में पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला हेतु 20 बीघा भूमि संस्था के स्वयं के स्वामित्व की होना आवश्यक है।

(गोपालन मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाओं के लिए अभी तक भूमि आबंटित नहीं की गई।

(3) इस वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तरीय समिति नन्दीशाला के लिए राशि रु. 111.91 करोड़ का प्रावधान है तथा जिलों को राशि रु. 3.85 करोड़ आबंटित की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक, 2019-20 के बजट में पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं खोले जाने की घोषणा की थी और आज 2022-23 का बजट पेश हो चुका है। अभी तक इसकी क्रियान्विति नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

दो, नन्दीशालाओं के चयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है, यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? क्या संस्थाओं को भूमि आबंटित की जायेगी? जिन पंचायत समितियों के पास बीस बीघा जमीन नहीं है वहां नन्दीशाला खोले जाने की क्या योजना है और अभी तक प्रदेश भर में इस तरह की कोई चयन सूची है क्या? कहां-कहां खोली गयी है? मंत्री जी, कृपया बतायें।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला की स्थापना के पीछे राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा आवारा पशुओं की समस्या के समाधान सहित नर गोवंश की जीवन रक्षा करने का लक्ष्य है। कार्य बहुत बड़ा है, अत: हमने यह आवश्यक समझा कि योजना व्यावहारिक होनी चाहिए और इसके लिए समुचित संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। संत समाज, राजस्थान में विभिन्न गोशालाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी। कई गोशालाओं का निरीक्षण किया गया, मेरे स्वयं के द्वारा भी और अधिकारियों के द्वारा भी, उसके पश्चात् राज्य में 1.57 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला योजना बनायी गयी, उसमें 90 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत अंशदान नन्दीशाला स्थापित करने वाली संस्था का होगा।

अध्यक्ष महोदय, संस्था को नन्दीशाला स्थापित कर उसे कम से कम बीस वर्ष तक चलाना भी होगा इसलिये हमने उसमें भी नवाचार किया। पहले जो कार्यकारी एजेंसी सरकारी एजेंसी हुआ करती थी, हमने इसमें नन्दीशाला का जो परिपत्र निकाला पंचायत समिति वाला, उसमें निर्माण वही संस्था करेगी

(श्री प्रमोद भाया)

जिसका चयन होगा जो उसको संचालित करेगी, ताकि वह निर्माण समय पर पूरा हो सके और समय पर शुरू हो सके। योजना हेतु पैसे की कोई कमी नहीं है। 650 करोड़ रुपये की यह योजना बनी। 2021-22 हेतु 111.91 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। योजना की विस्तृत गाइडलाइन 27.08.2021 को जारी की गयी। 33 में से 23 जिलों में संस्था चयन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इस कार्य हेतु विभिन्न जिलों को प्रारम्भिक रूप से 3.85 करोड़ रुपये का आबंटन भी किया जा चुका है। वर्तमान में पांच जिलों भरतपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, चूरू और झुंझुनूं में कुल आठ संस्थाओं का चयन हो चुका है, जिनमें से हनुमानगढ़ जिले की दो संस्थाओं के साथ अनुबन्ध भी हो चुका है। शेष जिलों में भी इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। जिला गोपालन समिति, झुंझुनूं द्वारा जिले की कुल, जहां से माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल 11 पंचायत समितियों के लिए नन्दीशाला हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। इसमें से दो पंचायतों यथा चिड़ावा में श्रीकृष्ण गोशाला और उदयपुरवाटी में श्रीकृष्ण गोशाला संस्थान चिरवा हिरवाना का चयन कर लिया गया है। इस देरी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अधिकारी दोषी नहीं है। कोरोना महामारी होने के कारण और योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए समय जरूर लगा लेकिन यह बहुत ही ऐतिहासिक योजना है और बहुत ही सफल योजना होगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबु लाल। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में प्रश्न विधान सभा के कई सत्रों में पूछे हैं और उत्तर बताये हैं। इस योजना की बजट घोषणा है 2019-20 और आपका यह आदेश जो अभी निकला है जिसमें आपने 3 करोड़ 65 लाख रुपये आबंटित किया है वह 16.2.2022 को किया है। यह अभी जो पांच दिन पहले निकला है, वह है तो यह जो आपने आबंटन किया है संयुक्त निदेशक को यह मात्र टोकन आबंटन किया है, 1-1 लाख रुपये, इसका मतलब केवल अकाउंट खोलने का हैड बना है तो नन्दीशाला खोलने की जो बजट घोषणा का अभिप्राय था, आवारा पशुओं की समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशाला बनायेंगे और आज अपन 2022 के बजट में आ गये और अभी तक आपका केवल बजट का एलोकेशन जो किया है जिलों को, वह संयुक्त निदेशक को केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और केवल टोकन अकाउंट खोलने के लिए 01 लाख रुपये उसमें डाला है। वह भी कब डाला है, यह विधान सभा शुरू हो जाने के बाद 16 तारीख को।

अध्यक्ष महोदय, अब आप ही विचार कर लें कि अगर डिपार्टमेंट 2019 की घोषणा की इस प्रकार से पालना कर रहा है तो क्या यह जनता के लिए दिया हुआ आश्वासन हम पूरा करने की स्थिति में हैं? उस जनता को संतुष्ट कर सकते हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से इसमें सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो जिला स्तरीय नंदी गोशाला योजना लागू की गई थी, उसमें जिला स्तर की नंदी गोशाला के लिये केवल मात्र 50 लाख रुपये की कोस्ट रखी गई थी। वह अव्यावहारिक थी और वह योजना पैदल नहीं चल पायी। अभी भी मात्र 13-14 जिलों में ही वह योजना आगे बढ़ पायी। उसको मद्देनजर रखते हुए जिस उद्देश्य से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने यह योजना लागू की कि आज की परिस्थिति में आवारा गोवंश की जो समस्या है, जो एक्सीडेंट होते हैं, अकाल मौतें होती हैं, किसान भी परेशान हैं, मुख्य मंत्री जी की यह भावना थी कि जो योजना बने वह बहुत ही व्यावहारिक बने और जो जमीन पर मूर्त रूप ले सके। इन भावनाओं को मद्देनजर रखने के लिये समय लगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अधिकारियों को मैंने निर्देश दिये, उन्होंने भी उसमें पूरी मेहनत की। मैं स्वयं भी कई गोशालाओं में गया। कई संत और जो प्रतिनिधि इससे वर्षों से जुड़े हुए हैं उनकी हमने कई बार बैठकें कीं, सबसे मार्गदर्शन लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यावहारिक योजना को बनाने में समय जरूर लगता है। यह पंचायत समिति स्तरीय नंदी गोशाला जो गोपालन विभाग के द्वारा जारी की गई है, राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जहां पर इस तरह की व्यापक और व्यावहारिक योजना लागू की गई है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए न तो बजट की कोई कमी है.....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस होता है...

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow it. I will not allow it. Minister is replying.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या उत्तर दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: He is not yielding. माननीय आप पार्लियामेंटेरियन हैं। मंत्री ने yield ही नहीं किया, आप कैसे खड़े होंगे? Let him speak. यह पूरी बात कहेंगे तभी तो आप खड़े होंगे। अगला प्रश्न, श्री बाबु लाल। ...(व्यवधान) No. I will not allow it. अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा।

अगला प्रश्न, श्री बाबु लाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

कोटड़ा (उदयपुर) में कृषि मंडी का कार्य

108. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल की तहसील कोटड़ा में कृषि मंडी का कार्य प्रारम्भ हुआ था? यदि हां, तो कब? उक्त की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की तहसील कोटड़ा में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) उदयपुर के अधीन गौणमंडी यार्ड कोटड़ा के निर्माण हेतु दिनांक 22.02.2017 को 2 कार्यों के लिए 205.86 लाख एवं दिनांक 04.06.2018 को 8 कार्यों के लिए 260.06 लाख रु. की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। गौणमंडी यार्ड कोटड़ा का निर्माण कार्य दिनांक 24.07.2017 से प्रारम्भ हुआ। निर्माण कार्यों की प्रगति की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा अच्छी थी कि दूरदराज के क्षेत्र में किसान को अपनी उपज का उचित दाम मिले। यह कृषि मंडी 2017 में स्वीकृत हुई थी और उसके बाद विभिन्न चरणों

(श्री बाबु लाल)

में यह काम पूरा होना था और एक बहुत बड़ा अमाउंट 286.57 लाख रुपये खर्च कर दिये। उसके बाद भी आज यह कृषि मंडी शुरू नहीं हुई है। आप उस कृषि मंडी को कब तक शुरू करेंगे? दूसरा मेरा आपसे यह सवाल है कि आपने इसमें एक कारण बताया कि कुछ जमीन विवाद के कारण हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस विवाद में आपने कोई संवाद किया और इतने समय तक विभाग ने संवाद नहीं किया तो इसके लिए दोषी कौन हैं? यह बताने की कृपा करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, इस मंडी यार्ड के लिए 50 बीघा भूमि में से मौके पर 36 बीघा भूमि पर विभाग द्वारा कब्जा ले लिया गया था। बाकी जो शेष भूमि है, उस पर वहां के कुछ लोकल आदिवासी लोग अतिक्रमी हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारे विभाग के सैक्रेटरी और कई अधिकारी, कर्मचारी जिला प्रशासन से इस संबंध में मिले थे और इस पर कार्यवाही जारी है। यदि अतिशीघ्र वहां के स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो हमारे स्तर पर, उच्च स्तर पर लेकर इसका समाधान कर देंगे और शीघ्र ही इस मंडी को चालू करेंगे।

श्री बाबु लाल (झाडोल): अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं रहता हूं और मेरे सामने ही कृषि मंडी है। केवल मात्र एक मकान वहां बना हुआ है और बात करके रास्ता निकाला जा सकता है। आप इसको जितना जल्दी कर सकेंगे तो उस क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्य, आप इसमें थोड़ा सहयोग करना, मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को भेज दूंगा। हम यह चाहते हैं कि सहमति से ही वह मंडी खाली हो जाये ताकि हमारे आगे का कार्य हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। वासुदेव देवनानी।

केन्द्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश को स्वीकृत राशि

109. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के किन-किन मंदिरों, किलों एवं पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) क्या केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को उक्त स्थलों के विकास के लिए कोई बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो किस-किस स्थल हेतु, कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई?

(3) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से स्वीकृत संपूर्ण राशि में से किस-किस स्थल पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि व्यय होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत सम्मिलित किए गए प्रदेश के मंदिरों किलों एवं पर्यटक स्थलों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत राशि का स्थलवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से स्थलवार व्यय की गई एवं शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लेकिन आपकी इजाजत लेकर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि केन्द्र की योजना है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप अपना जवाब दे दें, समझाने की जरूरत कहां है। Let him ask the question.

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आप पूछें उससे पहले ही बता दूं।

श्री अध्यक्ष: No. Let him ask the question.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हैरीटेज सर्किट में इन्होंने कई मंदिर, किले और पर्यटक स्थल जोड़े हैं, इसका क्या आधार रहा है? किस आधार पर आपने इनको जोड़ा है? साथ में, क्या इसमें अन्य स्थान भी जोड़े जा सकते हैं, जिनमें अजमेर का महाराणा प्रताप स्मारक, पृथ्वीराज चौहान स्मारक, महाराजा रायरसिंह स्मारक और अजयपाल मंदिर, जैन मंदिर की नसियां, क्या सरकार इनको जोड़ने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केन्द्र की जो स्कीम है, उसको लागू किया। यह अलग प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें, आप सीनियर आदमी हैं। केन्द्र ने जो योजना बनाई, उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। आप जो बात कर रहे हैं वह केन्द्र का पार्ट ही नहीं है, उसका जवाब क्या देंगे। प्लीज, आई एम सॉरी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप बात तो सुनिये, इसका आधार राजस्थान सरकार ने तय किया है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, राजस्थान सरकार नहीं, केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार ने भेजी है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। There is nothing new in it. अगला प्रश्न। No. Not at all.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चयन तो राज्य सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप तैयारी करके आएं। I am aware about this. मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, I am aware about Krishna Circuit. नाथद्वारा में भी है। जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर लेवल का आदमी ही वहां पर काम को देखता है। बाकी सब काम आउटसोर्स से हो रहे हैं, क्वालिटी मेनटेन नहीं हो रही है। Can you assure कि यह कृष्णा सर्किट या केन्द्र की जितनी योजनाएं आ रही हैं, उसकी क्वालिटी को मेनटेन करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): सर, आपके माध्यम से आपको भी एश्योर करना चाहूंगा और सबको एश्योर करना चाहूंगा कि जो आपने आदेश दिये हैं, उनकी पूरी पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, सुरेश रावत। ...(व्यवधान)... माननीय, प्लीज। अगला प्रश्न।

अजमेर में बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेंडर कार्य आबंटन

110. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेण्डर प्रक्रिया के भी कार्य आबंटित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला अजमेर में विगत पांच वर्षों में

(श्री सुरेश सिंह रावत)

बिना टेण्डर प्रक्रिया के कार्य कब-कब, कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? वर्षवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अजमेर जिले में पिछले पांच वर्षों में बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेण्डर प्रक्रिया के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): मंत्री महोदय, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेंडर प्रक्रिया के किस प्रक्रिया से कार्यादेश दिये जा सकते हैं, एक? दूसरा, कितनी राशि तक दिया जा सकता है? बेरोजगार स्नातक अभियंता किसी एक को कितनी बार इस प्रक्रिया से कार्यादेश दिया जा सकता है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सबसे पहली बात यह है कि जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, उसे 5 लाख रुपये तक के कार्य बिना टेंडर के दिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

शाहजहांपुर की राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड के श्रमिकों को वेतन भुगतान

111. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है औद्योगिक क्षेत्र शाहजहांपुर, जिला अलवर में स्थित राजस्थान ब्रेवरीज लि. द्वारा उक्त में कार्यरत श्रमिकों का वेतन व पी. एफ. एवं ग्रेच्युटी के गबन करने का प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में उक्त इकाई के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त इकाई में कार्यरत रहे श्रमिकों को उनका वेतन, पी.एफ. एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं। राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड शाहजहांपुर (अलवर) में कार्यरत श्रमिकों के प्रकरण अंतर्गत

(राज्य मंत्री, श्रम)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, तथा उपदान संदाय अधिनियम 1972, इस विभाग को प्राप्त हुए हैं।

पी.एफ. से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण विभाग के स्तर से नहीं होता है।

विभाग को प्राप्त प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में विभाग स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पीड़ित श्रमिकों द्वारा उनके वेतन, ग्रेच्युटी आदि से संबंधित वाद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

पी.एफ. से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण विभाग के स्तर से नहीं होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई भी लिमिटेड कम्पनी बन्द हो जाती है या बन्द कर देते हैं तो क्या सरकार से कोई अनुमति ली जाती है या वहां की लेबर को बताने का कोई सिस्टम है कि हम इस लिमिटेड कम्पनी को बन्द कर रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): यह फैक्ट्री 2001 में बन्द हो गयी। जितने भी पी.एफ. और वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण थे, उनमें समझौते के लिए मीटिंग बुलायी गयी, उस मीटिंग में ठेकेदार ने भाग नहीं लिया। जहां तक वेतन के भुगतान सम्बन्धी बात है, यह 1600 से ज्यादा होने की वजह से और सीमा से पार होने की वजह से उनको कोर्ट में जाने का निर्देश दिया गया है। जो श्रमिक कोर्ट में गये उनका भुगतान हो गया। कोई आज भी जाना चाहे तो आज भी जा सकते हैं, यह छूट है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मंत्री जी, क्या आपको पता है कि उसमें एकमात्र श्रमिक को मिला है? क्या आपके ध्यान में यह बात है कि वह कम्पनी बन्द हुई, बन्द होने के बाद दूसरी कम्पनी बनाकर उसमें डायरेक्टर

(श्री बलजीत यादव)

बनाया, उसके नाम ट्रांसफर हुई। फिर वापस वही जिसने बेचा, 65 लाख रुपये में बैंक से उस कम्पनी को खरीद लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सर, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उसको बैंक से खरीद लिया और फिर यू.बी. ग्रुप को, उसके दो पार्टिशन थे, एक तो डेढ़ सौ करोड़ में और एक 67 करोड़ में यू.बी. ग्रुप को बेच दिये गये। वे श्रमिक रोते फिर रहे हैं। उनको यह पता ही नहीं कि किसको बिक गयी, कहां बिक गयी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया कि श्रमिक को मिल गया है। किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है। न पीएफ मिला, न वेतन मिला, न कोई और भत्ते मिले। न उनको नौकरी मिली और न ही श्रमिक की एनओसी दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। मैं आपकी जगह प्रश्न पूछता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि एक श्रमिक को पैसा मिला है, क्या सरकार कोर्ट के आधार पर दूसरे श्रमिकों को पैसा देने की कार्यवाही करेगी?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): जब कोर्ट में खुद वाद पेश करेंगे, तब ही मिलेगा। खुद ही वाद-पत्र पेश करेंगे, सिविल सूट करेंगे तब ही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक है। क्या श्रम विभाग उनमें मदद करेगा, जिससे वे आदमी उसमें एप्लाई कर सकें? सबको लाभ मिल सके, जब कोर्ट का एक फैसला हो गया है तो बाकी सब की भी कोशिश करके मदद करें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): बाकायदा मदद की है, उन्होंने प्राधिकरण के सामने सूट पेश किये हैं और उनका डिस्पोजल भी हो गया है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो श्रमिक लिमिटेड कम्पनी में होता है, परमानेंट श्रमिक भी होता है। आप कम्पनी को दूसरे को बेच रहे हो तो क्या उस श्रमिक की कोई एनओसी ली जाती है? उसने कहा कि हमने सबका भुगतान कर दिया है। यह एग्रीमेंट में दिया गया है कि सब श्रमिकों का निपटारा कर दिया तो क्या ऐसा कोई कानून है कि जो असत्य बोल रहा है तो उसकी डील निरस्त हो? उसने लिख दिया कि सब कुछ कर दिया, लेकिन किया नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, डिपार्टमेंट लेबर वेलफेयर का है। जब लेबर वेलफेयर का है तो श्रमिकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यदि इस तरह की फिक्टिशियस चीजों को करके ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठायेगी? आप सीधी बात बतायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, जिनका वेतन बाकी है या ग्रेच्युटी बाकी है, उसके सम्बन्ध में बाकायदा यूनियन सरकार की तरफ से समझौता करने का प्रयास किया गया। वह पार्टी हाजिर नहीं हुई। उसके बाद उनके जितने भी क्लेम थे, उनके लिए प्राधिकरण के सामने दावे पेश किये गये। उनका निस्तारण 2001 और 2004 तक हो गया।

श्री अध्यक्ष: क्या यह सही है कि जब ट्रांसफर होते हैं तब जो एम्प्लाई काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है? क्या कोई तरीका है जिससे आदमी जो फैक्ट्री में काम कर रहा है और मालिक दूसरे को ट्रांसफर करता है तो जो पुराने लोग जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): सर, उसकी जांच करवा लेंगे कि क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

चित्तौड़गढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का वितरण

112. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री चन्द्रभान आक्या (चित्तौड़गढ़) के स्थान पर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अप्रैल, 2021 से 26 जनवरी, 2022 तक पोषाहार हेतु चावल, गेहूं, दाल व अन्य सामग्री का वितरण किस-किस संस्था, फर्म के माध्यम से कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त अवधि के फार्म 4 की प्रति तथा महिला बाल विकास परियोजना के 0 से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं किशोरी बालिका का संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा पोषाहार सामग्री हेतु विभाग में दिए गए पोषाहार के मांग पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत तिमाही अप्रैल 2021 से जून 2021, जुलाई 2021 से सितम्बर 2021, अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के दौरान गेहूं तथा चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम एवं चना दाल नैफेड के माध्यम से क्रय कर उक्त सामग्री का परिवहन राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों तक कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त पोषाहार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लाभार्थियों को वितरण किया जाता है।

(2) अप्रैल, 2020 से विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत साबुत खाद्य सामग्री गेहूं, चावल एवं चना दाल की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों पर की जा रही है। उक्त व्यवस्था के तहत वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फार्म 4 संधारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके स्थान पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित प्रारूप में संधारित रजिस्टर में सामग्री की प्राप्ति एवं वितरण का इन्द्राज करवाया जा रहा है। उक्त विधान सभा क्षेत्र की परियोजनाओं के 0 से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष तक बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं किशोरी बालिका का संख्यावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा अप्रैल, 2020 से आंगनबाड़ी केन्द्रों से मांग पत्र नहीं लिया जाता है। इसके स्थान पर विभाग द्वारा राजपोषण साफ्टवेयर पर दर्ज लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय मापदंडों के अनुसार लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न सामग्री का आबंटन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड3 में कहा कि राजपोषण साफ्टवेयर पर दर्ज लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय मापदण्डों के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जनवरी, 2021 को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि आप कच्चा राशन नहीं देकर फोर्टिफाइड और रेडी-टू-ईट राशन दें। आप लगातार भारत सरकार के 13 जनवरी, 2021 के लिखे पत्र की अवहेलना कर आज भी आप राजस्थान भर में कच्चा राशन दे रहे हैं। क्या यह भी सही है कि इसमें बजट का जो आबंटन होता है, उसमें राज्य सरकार और...., दोनों का आधा-आधा पैसा है, तो क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप भारत सरकार के निर्देशों की पालना करेंगे या फिर निर्देशों की अवहेलना करते हुए वैसे ही कच्चा राशन बांटेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार ने जनवरी, 2021 को निश्चित तौर पर पत्र लिखा और उसके बाद भी पत्र लिखा, लेकिन कोरोना महामारी इस प्रकार की आयी हुई थी कि हमारा विभाग सिस्टम को बदलने के लिए पूर्णतया कार्यरत नहीं था, लेकिन कई बार हमने प्रयास किया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम सिस्टम को बदलें और उसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कोशिश की, लेकिन बीच में फिर कोरोना की तीसरी लहर आयी और इस वजह से हमने इस राशन सिस्टम को थोड़ा-सा आगे बढ़ाया।

मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को और तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि भारत सरकार के जनवरी, 2021 के पत्र के आधार पर जिसमें रॉ-राशन को बन्द करके फोर्टिफाइड राशन के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे, हमने सब जगह पता किया, बहुत से राज्यों में भी इस समय प्रक्रिया चल रही है और हमारे राजस्थान में भी इस सिस्टम को बदलने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सुनिश्चित करना चाहूंगी कि बहुत शीघ्र ही यह प्रक्रिया बदलकर भारत सरकार के मापदण्डों और नियमों के आधार हम लोग इसकी सप्लाई चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में नवीन सड़कों का निर्माण

113. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में बजट वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा नवीन सड़कों के निर्माण हेतु दी गई पांच करोड़ की राशि में से कितनी राशि व्यय हुई व कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों के निर्माण हेतु निश्चित राशि की घोषणा की गई थी? यदि हां,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तो क्या सरकार शेष रही राशि हेतु नवीन प्रस्ताव लेकर उन्हें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र पाली में बजट वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा नवीन सड़कों के निर्माण हेतु दी गई पांच करोड़ राशि में से स्वीकृत सड़कों व अब तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रु. 5.0 करोड़ की राशि की घोषणा की गई थी।

जी नहीं। शेष बचत राशि का आकलन कार्य पूर्णता व समस्त दायित्वों के निपटारे के पश्चात् ही सम्भव है। ये सभी कार्य नाबार्ड बैंक से प्राप्त ऋण (आरआईडीएफ) अन्तर्गत स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में प्रगति पर हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड संख्या 2 में साफ पूछा है आपसे कि इनका निर्माण पूरा हो जाने के बाद में यदि 5 करोड़ रुपये में से कोई राशि शेष बचेगी तो क्या उस शेष राशि के लिए आप नवीन प्रस्ताव लेकर वापस स्वीकृति देंगे क्योंकि आपको नाबार्ड ने 5 करोड़ दिया है एक विधान सभा क्षेत्र के लिए। 5 करोड़ के अगेन्स्ट में जो आपने वर्क आर्डर जारी किया है, वह किया है 3 करोड़ 41 लाख 90 रुपये का। लगभग 1 करोड़ 58 लाख शेष राशि बचेगी, जब भी बचेगी। कार्य पूर्ण होने के बाद बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज मत कीजिए आप। जब बच जाएगी, सम्पूर्ण प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी तो क्या और भी विधान सभा क्षेत्रों में जहां-जहां जितनी-जितनी राशि बची है, उस राशि के लिए आप नवीन प्रस्ताव लेकर उनकी मंजूरी देंगे या नहीं देंगे? यह मुझे आपसे पूछना है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी एक तो कार्य अंडर प्रोसेस है, जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी बजट में सदस्यों की मांग और फीडबैक के आधार पर यह राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। माननीय सदस्य गत वर्ष की तुलना में दुगुने कार्य करवा सकते हैं। इस राशि से सभी सदस्य लगभग 700 किलोमीटर रोड की

(श्री भजनलाल जाटव)

मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण करवा सकते हैं तथा लगभग 2000 किलोमीटर मिसिंग लिंक बनवा सकते हैं। ये सिर्फ माननीय सदस्य और जन-प्रतिनिधियों के आधार पर ही दुगुनी राशि की गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ये समस्या केवल पाली से आने वाले माननीय सदस्य की नहीं है। हम सबकी है। जैसा आपने अभी 10 करोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिछली बार आपने 5 करोड़ दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन जो राशि हमारे को अलाट की है, एज ए विधायक, अगर आपके टेंडर प्रोसेस से हमारा पैसा बच जाता है, जब फाइनल उनका हिसाब करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाता है, क्या वह उसी विधायक को उसकी अनुशंसा पर खर्च करने के लिए सरकार विचार रखती है?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि जब कार्य अभी अंडर प्रोसेस है और उसकी निविदा लगी है, जब तक अगर कोई टेंडर प्रक्रिया मानकर चलें, अभी तो यह बी एस आर रेट से कम पर आ गया और बी एस आर रेट से अबव चला जाता, तब भी तो सरकार ही उस पैसे को वहन करती। यदि प्लस में चला जाता तब भी सरकार ही वहन करती। सुन तो लीजिए भाई। उसके बाद यह सारा पैसा, आप तो केन्द्र में मंत्री रहे हैं, सारा पैसा नाबार्ड स्वीकृत करता है। उसमें कुछ अपना हिस्सा होता है। नाबार्ड का एक्ट है, यदि कोई कार्य स्वीकृत होता है तो वह कार्य पृथक माना जाता है। दोनों कार्य पृथक हैं। स्वीकृत कार्य और शेष जो कार्य, जो राशि बची है, वह पृथक है। उस कार्य को अलग से ही गिनती मानी जाएगी, ऐसा नाबार्ड में एक्ट में नियम है।

प्रश्न संख्या 114

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

कोरोना काल में दिवंगतों के आश्रितों को सहायता

115. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोरोना महामारी में दिवंगत हुए नागरिकों के निराश्रित बच्चों एवं उनकी पत्नियों को सरकार द्वारा एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कोरोना काल में कितने लोग दिवंगत हुए एवं उनके आश्रितों को क्या-क्या लाभ दिए गये? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दिवंगत लोगों के आश्रितों को अनुग्रह राशि एवं अन्य सरकारी लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी के कारण राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ हुए प्रत्येक बच्चों तथा विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया है:-

1. प्रत्येक अनाथ बच्चे को तथा विधवा महिला को तात्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपये 1.00 लाख एकमुश्त सहायता दी जाती है।

2. प्रत्येक अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2500/- रुपए प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये देय है।

3. विधवा महिला को आजीवन 1500/- रुपये मासिक पेंशन देय है।

4. विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000/- रुपये प्रतिमाह देय है।

5. प्रत्येक अनाथ बच्चे तथा विधवा महिलाओं के बच्चों को विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु 2000/- रुपये प्रति बालक/बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यक्तियों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत विधवा महिलाओं को 1.00 लाख रुपये एकमुश्त व 1500 रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन तथा उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोविड 19 अनुग्रह सहायता योजनान्तर्गत दिवंगत हुए लोगों के आश्रित/परिजन को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि के लाभ दिये गये।

तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिवंगत लोगों के आश्रितों को कोविड-19 में हुई मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि के अन्तर्गत 50000/- रुपये मृतक के आश्रित/परिजन को प्रति मृतक अनुसार लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इसके अन्तर्गत 10461 आवेदकों को (केन्द्र सरकार 39,22,87,500 रुपये एवं राज्य सरकार 13,07,62,500 रुपये) कुल राशि 52,30,50,000 रुपये (अक्षरे राशि बावन करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। योजनान्तर्गत ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन करने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर्स के द्वारा जांच उपरान्त भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन मृतकों की आर टी पी सी आर रिपोर्ट नेगेटिव थी, परन्तु दूसरे लक्षण जैसे एच आर सी टी स्कोर 6 से ज्यादा था, आक्सीजन लेवल कम था और अन्य लक्षण के आधार पर कोरोना प्रोटोकाल के तहत जिन पेशेंटों का इलाज किया गया, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने उनको कोरोना पाजिटिव मृतक माना। ऐसे मृतकों के पूरे प्रदेश में कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्या राज्य सरकार ऐसे मृतकों के आश्रितों को सहायता देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं ऐसे नहीं, be confined. रानीवाड़ा का प्रश्न पूछिए, राजस्थान पर जा रहे हैं। ऐसे कैसे कर रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सर, राजस्थान का बता देता हूं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न ही राजस्थान का है, उत्तर में दिया है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ऐसे नहीं। आप पूरे प्रश्न को ही बिलकुल अलग ले जाओगे। मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अन्दर लगभग हमने अभी 111.74 करोड़ का भुगतान किया है, जो कि 15 हजार 564 बच्चों एवं विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया है। मैं साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि जो आपने मापदण्ड बताए हैं आर टी पी सी आर, कोरोना जांच आपने बताया या किसी भी प्रकार के सरकारी, प्राइवेट किसी भी हास्पिटल में, किसी भी प्रकार का कोई भी डाक्यूमेंट उपलब्ध है तो हम उसको कोरोना सहायता के अन्दर राशि मंजूर कर देंगे।

दूसरी बात, आपने भी देखा होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है केन्द्र सरकार को कि इन व्यक्तियों की मदद की जाय लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा तीन बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में 50 हजार रुपये मात्र की राशि स्वीकृत की गयी है और उसमें भी 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का है और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का है। मुख्य मंत्री कोरोना सहायता योजना पूर्ण रूप से प्रदेश के पैसों से चल रही है। मुख्य मंत्री जी के द्वारा की जा रही है और जब सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इसकी सुनवाई भी नहीं हुई थी, उससे पहले राजस्थान पहला प्रदेश बना था जो कोरोना सहायता योजना का आवेदन घर-घर जाकर हमने भरवाया और उन लोगों को भुगतान किया। ये दिन-रात का अन्तर है भारत सरकार और राज्य सरकार में। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हर स्तर पर आज भी प्रदेश के अन्दर कोई भी मृत्यु कोरोना से होती तो उसको हम भुगतान करने के लिए सौ प्रतिशत पाबन्द हैं। हम भुगतान कराएंगे। कोई भी एकमात्र कहीं से भी, हम सुओमोटो, अख़बार में अगर आया है कि इस व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनको भी हमने भुगतान कराया है। सी एम एच ओ की रिपोर्ट आयी है, उससे भी हमने भुगतान कराया है। एस डी एम की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने गांव-गांव जाकर सर्वे किया है, उससे भी हमने भुगतान किया है। सबसे बड़ी बात जिन लोगों का दाह संस्कार नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद् द्वारा किया गया, उन लोगों की सूची भी वहां से लेकर हमने उन लोगों को मृत्यु कोरोना सहायता का लाभ दिया।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह...

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा। माननीय सदस्य, I said, I will not allow. प्लीज आपको कह दिया कि अभी भी अलाउ है, आप लाइए न, मिल जाएगा। प्रश्न नहीं। You really don't want answer. अभी भी आपके पास कोई केस है, लाइए, पेमेंट हो जाएगा।

अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर में पटवारियों के रिक्त पद

116. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में कितने पटवार हलके हैं? उक्त में पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर व लूणकरणसर तहसील में कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसीलों में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवार भवन बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) बीकानेर जिले में 312 पटवार हलके हैं। इन हलकों में पटवारियों के 312 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध पटवारी के 187 पद भरे हुए हैं एवं 125 पद रिक्त हैं।

(2) बीकानेर व लूणकरणसर तहसील में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	तहसील	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	बीकानेर	93	77	16
2	लूणकरणसर	89	48	41

(3) बीकानेर तहसील में 33 ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं लूणकरणसर तहसील में 32 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार भवन बने हुए हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसमें 312 पटवारी बताए गये हैं, 9 तहसीलें हमारे बीकानेर में हैं। बीकानेर तहसील में पटवारी 93, लूणकरणसर में 89, यानी दो तहसील में 182 पटवारी हैं। मंत्री जी, यह आंकड़ा ही आप कहां से

(श्री सुमित गोदारा)

लाये हो जबकि सत्य में लूणकरणसर में 46 पद स्वीकृत हैं। आपने जवाब दिया, उसमें पद 89 बताये हैं। हम कहां से प्रश्न तैयार करे? मंत्री जी को आंकड़ा ही पता नहीं है, कितने पटवारी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आंकड़े मालूम नहीं हैं, आप प्रिविलेज लाइये। आप बैठिये। आपके पास सही जानकारी है, इनके पास गलत है, तो आपको अधिकार है प्रिविलेज लाने का। अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, जब जवाब ही गलत है, आपने कहा, आपके आदेश से...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, फिर आप इनके खिलाफ प्रिविलेज लेकर आइये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि क्या यह सही है कि पटवार भवन, जो रहने लायक नहीं है, जिसमें अधिकतर खाली हैं, क्षतिग्रस्त होने के कारण, क्या सरकार उन पटवार भवन को रहवास के लिए या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? जिससे आम जन को सुविधा मिल सके।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तहसील और विधान सभा में, कई बार तहसीलों के दूसरी विधान सभा के भी पार्ट होते हैं। दूसरी तहसील, एक विधान सभा में दो तहसील है, तीन तहसील हैं, इसलिये टोटल संख्या वह बताई गयी। इनके एरिया के, इसके अन्दर अलग-अलग है। आप चाहें तो, एक-एक के नाम हैं जिसमें आपने बीकानेर तहसील के टोटल 33 के ऊपर बने हुए बताये। रहित भवन, रहित जगह है 12, लूणकरणसर के अन्दर टोटल पटवार मण्डल 46 हैं। इसके अन्दर 32 में भवन बने हुए हैं, 14 भवन रहित हैं। टोटल मैंने बताया, जिला कलक्टर की, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैंने बताया है। रिकार्ड के अन्दर जो स्वीकृत है, उसके आधार पर बताया है। फिर भी, जो बाकी भवन बचे हुए हैं, वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है, आपको विधायक कोष भी हम देते हैं, मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ दिये, आप थोड़ा सहयोग करें तो उसमें अच्छे भवन बन जायेंगे। वहां के लोगों के लिये सुविधा होगी। अच्छा है सभी विधायक इसमें पहल करें, जहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है तो थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा काम हो जायेगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि पटवारी पंचायत मुख्यालय पर मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ग्रामवासियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है? इसी वजह

(श्री सुमित गोदारा)

से, जब सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान में, सबसे ज्यादा राजस्व के काम आये, आपने वाह-वाही तो लूटी, पर हकीकत यह है, पटवारी जब गांव में नहीं बैठते, तो सबसे ज्यादा वह काम आये। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार पटवारियों को पाबन्द करेगी कि वह अपने पंचायत मुख्यालय पर प्रत्येक सोमवार को मिले, अतिरिक्त चार्ज पर मंगलवार को भी मिले? अभी हमारे लूणकरणसर व बीकानेर में पटवारी सिर्फ क़स्बे व बीकानेर ज़िले में मिलते हैं। उन्होंने सहायक और रखे हुए हैं। खुद तो मिलते नहीं हैं फोन मिलते नहीं हैं, सहायक और रखे हुए हैं, एक असिस्टेंट जो काम करते हैं। ग्रामवासी चक्कर लगाते हैं, फोन मिलते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं?

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप पटवारियों को क्या पाबंद करेंगे कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को मिले ताकि कम से कम पटवारी एक दिन तो मिले?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी की, सदन के पूरे सदस्यों को, आपको पूरी जानकारी है, सब जगह कमी है। आज से ही नहीं है, वर्षों से कमी है। फिर भी, राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने अभी नई भर्ती की। हमारे पास टोटल जो 12 हजार 331 पटवारियों के पद हैं, जिसमें कार्यरत 6 हजार 970 हैं, 5 हजार 361 पद हमारे रिक्त हैं। अभी मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार 610 की भर्ती की। इनकी भर्ती हो गई, रिजल्ट आ गया। बोर्ड के स्तर पर, इनके रिकार्ड की जांच की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराऊंगा कि अगर कोरोना नहीं आया तो इनका जो 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड है, पहले 9 महीने था। राज्य सरकार ने प्रेक्टिकल, थ्योरी तो यह पढ़कर आते ही हैं, प्रेक्टिकल जानकारी इनको अपने ज़िलों में ही होगी। 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। इनके रिकार्ड की जांच करने में एक महीना-डेढ़ महीना, जो भी लगेगा, हम आने वाले टाइम में, एक भी पटवारी पद खाली नहीं रखेंगे। माननीय सदस्य, किसी पर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

दूसरा, आपने प्रश्न किया, सोमवार के लिये पाबन्द करने का। राज्य सरकार समय-समय पर निर्देशित जिला कलक्टर के माध्यम से करती है। फिर भी आपने अच्छा सुझाव दिया। हम उनको और पाबन्द करेंगे। जबकि प्रशासन गांवों के संग अभियान में, वह तमाम काम, कोरोना की वजह से जो पेण्डेंसी थी, वह हमने युद्ध स्तर पर निपटा दिया। फिर भी, हमने अभी इसके अन्दर

(श्री रामलाल जाट)

जो नया किया, आम जन के कार्य की सुगमता के लिए, 2019 में धारा एप के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की, लगभग हमारी 369 तहसीलों में 335 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसके अन्दर नकल, नक्शा ट्रेस, आप स्वयं आटोमेटिक सर्टिफाइड निकलवा सकते हो। इसके साथ ही बाकी जो नई तहसीलें बनी हैं, वह 30 तहसीलें इसी में से निकली हुई हैं। वह भी सर्वे का काम चल रहा है, कम्पनी को दे रखा है, जल्दी ही यह पूरा हो जाएंगा। काफी सुगमता इस नए आईटी के माध्यम से हो रही है। बहुत जल्दी ही, बाकी जो तहसीलें बची हैं, इनको भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बिना पटवारी के, राजस्थान का किसान, आराम से अपनी नकल, नक्शा ट्रेस, सुगमता से निकलवा पाएगा।

इसके साथ ही, पायलट प्रोजेक्ट में, हमने सर्वे-रीसर्वे का काम भी चालू कर रखा है। थोड़ा टाइम लगेगा। डीआईएलआरएम जो योजना है इसके माध्यम से हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पैसा है। बहुत जल्दी बिना पटवारी के नामान्तरण खोलना, बिना पटवारी के नक्शा, नकल ट्रेस, स्वयं किसान को अपने आप ई-मित्र के माध्यम से, किसान का लड़का पढ़ा हुआ है, खुद सुगमता से अपने घर पर भी निकाल सकता है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है, बहुत जल्दी यह काम पूरा हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगसी राम।

सिरोही में डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत कार्य

117. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के माइनिंग क्षेत्र से जिला सिरोही के डी.एम.एफ.टी. फण्ड में प्रतिवर्ष बड़ी हिस्सा राशि जमा होती रही है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष की अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र की किन-किन माइनिंग इकाइयों द्वारा कितनी-कितनी राशि उक्त फण्ड में जमा कराई गई? उक्त फण्ड की राशि सहित वर्ष वार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) जिला सिरोही में जनवरी, 2019 से अगस्त, 2021 की अवधि में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गईं तथा उक्त फण्ड कमेटी ने किन-किन कार्यों के प्रस्ताव पारित किये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के खनन क्षेत्रों से विगत पांच वर्षों में सिरोही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में प्राप्त वार्षिक अंशदान का हिस्सा 4.23 प्रतिशत से 7.18 प्रतिशत है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की खनन इकाइयों से उक्त फण्ड में वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) में प्राप्त अंशदान का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जिला सिरोही में जनवरी, 2019 से अगस्त, 2021 की अवधि में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से स्वीकृत कार्यों का राशि सहित कार्यवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि में ट्रस्ट की गवर्निंग काउन्सिल द्वारा पारित/अनुमोदित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने डी.एम.एफ.टी. का पैसा सिरोही ज़िले में वितरण किया है, वह समान्तर रूप से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, नम्बर 1. गवर्नेंस काउंसलिंग में गत वर्ष 2 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के कार्य, जो स्वीकृत किये हुए थे, वह चालू नहीं किये। नम्बर दो, जनवरी 2020 में स्टेट फण्ड से 50 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये गये हैं, अभी तक सिरोही जिले का फण्ड वापस नहीं लौटाया, जबकि दूसरे ज़िलों के अन्दर, मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वहां पर फण्ड जारी किया गया है। मंत्री महोदय, हमने यह दो सवाल किये हैं। पहला सवाल, समान्तर ज़िले को वितरण किया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री जगसी राम (रेवदर): यही प्रश्न कर रहा हूं कि इसमें जो अनियमितता हुई है, मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ज़िले के अन्दर डी.एम.एफ.टी. का पैसा है, रेवदर विधान सभा की कम से कम 150 माइंस हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न आ गया। प्रश्न पूछिये, यह रिकार्ड में आ चुका है।

श्री जगसी राम (रेवदर): यही कर रहा हूं, उसमें तुलनात्मक हमारे क्षेत्र का पैसा है, उसमें आप बराबर करेंगे या नहीं करेंगे डी.एम.एफ.टी. वाला?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं

(श्री प्रमोद भाया)

आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को जानकारी देना चाहता हूं, कि डी.एम.एफ.टी. की राशि का उपयोग डी.एम.एफ.टी. के नियमों के तहत, खनन प्रभावी क्षेत्र व व्यक्तियों के लिये किया जा सकता है। कार्य स्वीकृत किये जाने, किस विधान सभा क्षेत्र में किये जाने हैं, इसका निर्णय डी.एम.एफ.टी. की जिला स्तरीय गवर्निंग काउंसलिंग करती है।

वर्तमान नियमों में जिला गवर्निंग काउंसलिंग के अध्यक्ष कलक्टर जी हैं तथा सभी माननीय विधायक जी, सम्बन्धित सांसद जी, सम्बन्धित राज्यसभा सदस्य जी, जिस ज़िले को प्राथमिकता दें वह, उस ज़िले में, साथ ही कुछ राज्य सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत हैं। वर्तमान डी.एम.एफ.टी. नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिले के सभी विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी. की राशि का समान रूप से उपयोग किया जाये। साथ ही, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.07.2021 के आदेशों से डी.एम.एफ.टी. के नियमों में जो परिवर्तन किये गये हैं उसके पश्चात् राज्य सरकार या शासन के स्तर से डी.एम.एफ.टी. की जिला गवर्निंग काउंसिल को किसी भी कार्य को स्वीकृत करने या कोई निर्देश देने पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं।

साथ ही, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करूंगा कि आप स्वयं उसके सदस्य हैं। आप अपने काम के लिए पुरज़ोर तरीके से मजबूती से उसमें रखें और उसमें निर्णय करवायें।

जहां तक स्टेट मिनरल फंड की आपने जो जानकारी चाही है, यह प्रश्न आपने डी.एम.एफ.टी. जिला सिरोही का लगाया था। स्टेट मिनरल फंड की मैं डिटेल जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की पीड़ा है, वह हमारी सबकी है। एक तो आपकी इस कमेटी की तीन साल में मीटिंग नहीं के बराबर हुई है। इनके प्रश्न पूछने का यह है कि 2016 से लेकर 2021-22 तक सिरोही जिले में 178 करोड़ रुपया आपको प्राप्त हुआ और उसमें से रेवदर को जो मिला है वह केवल 5.69 प्रतिशत है तो यह आधार क्या बना?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तीन साल में आपकी मीटिंग हुई नहीं, फिर यह केवल इनको 5.69 प्रतिशत ही क्यों मिला? 178 करोड़ रुपये में से मात्र 10 करोड़ रुपये ही क्यों मिला? इसका क्या लॉजिक है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरक प्रश्न के जवाब में माननीय सदस्य को जो जानकारी दी कि इसके कामों को स्वीकृत करने का अधिकार गवर्निंग काउंसिल को है, उसके अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं, उसके सदस्य माननीय विधान सभा के सदस्य, सांसद महोदय, यह सभी उसके सदस्य हैं और वे ही निर्णय करते हैं। यह मैं पहले जानकारी दे चुका हूं।

जो आपने संग्रहण का कहा है, संग्रहण 178 करोड़ हुआ और कुल व्यय 102 करोड़ रुपये सिरोही में हुआ और 76 करोड़ रुपये शेष है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि बैठक कम हुई है, आपकी बात बिलकुल सही है और इसके लिए मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि भविष्य में समय पर बैठक करें ताकि समय पर निर्णय पारित हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप बैठें। अंकित नहीं होगा। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर कृषि उपज मण्डी में संविदाकर्मी

118. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी खानपुर में संविदा कर्मचारियों को लगाने का कार्य किस फर्म को दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में संवेदक द्वारा कितने संविदा कर्मियों को किस-किस पद पर कितने-कितने मानदेय पर लगाया गया है? संविदाकर्मी का नाम, पद व भुगतान की जाने वाली राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर द्वारा संविदा पर किसी भी कर्मचारी की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर द्वारा संविदा पर किसी भी

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कर्मचारी की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं, अपितु कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, जल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था एवं कम्प्यूटर आपरेटर मय मशीन के कार्य ठेके पर कराये जाने के लिए नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाता फर्म को ठेका स्वीकृत कर उक्त कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में संचालित ठेकों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो कर्मचारी लगाये जाते हैं क्या उनका पी.एफ. काटा जाता है?

दूसरा, क्या प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो कर्मचारी लगाये जाते हैं, उनकी सुनिश्चितता निश्चित हो कि वे कर्मचारी रोजाना आते हैं, इसके लिए कोई समय-समय पर जांच करने का क्या विचार रखते हैं? मेरा यह आरोप है कि ये कर्मचारी जितने भी होते हैं, वे मौके पर नहीं होते हैं।

तीसरा, खानपुर कृषि उपज मण्डी में सैक्रेटरी से लेकर सारे पद रिक्त हैं, क्या सरकार उनको भरने का विचार रखती है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारियों का पी.एफ. है वह विधिवत रूप से दिया जाता है और काटा भी जाता है। साथ में, आपने जो खाली पदों की बात कही है, काफी लम्बे समय से कृषि उपज मण्डी में बहुत से पद खाली चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमने कर्मचारी चयन आयोग को 400 पदों के लिए सिफारिश भेजी है और मैं यह समझता हूं कि उनकी भर्ती अतिशीघ्र होगी और जैसे ही उनकी भर्ती हो जायेगी तो आपके यहां पर कर्मचारी लगा दिये जाएंगे।

बाकी, संविदा पर जो कर्मचारी लग रहे हैं, उनकी विधिवत रूप से मानिटरिंग की जाती है, हमारे विभाग के कर्मचारी उनको चैक करते हैं और टाइम टू टाइम हर ईयर में उनके ठेके भी होते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं? ठीक है।

पर्यटन विकास कोष का गठन

119. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त का गठन कब किया गया एवं वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में उक्त कोष में कितनी धनराशि उपलब्ध करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पर्यटन सुविधाओं के विकास और उन्नयन के लिये वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में प्रत्येक सम्भाग में क्या-क्या योजनाएं कार्यान्वित की गईं व उक्त पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2020-21 में पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए राशि रुपये 100 करोड़ का पर्यटन विकास कोष गठित करने का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गयी थी, जिसे राज्य बजट वर्ष 2021-22 में बढाकर राशि रुपये 500 करोड़ किये जाने की घोषणा की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास कोष मद से चिह्नित विकास कार्यों के पेटे वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 26.00 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी गयी है।

(2) पर्यटन सुविधाओं के विकास और उन्नयन के लिये वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों एवं व्यय का सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जो 500 करोड़ रुपये की यह राशि बजट के अन्दर आबंटित हुई थी, उसमें से मात्र 26 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं, वह किन-किन योजनाओं में लगे हैं और वह योजनाएं कम्प्लीट हुई हैं या अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगी कि पर्यटन विकास कोष का क्या कोई अलग बैंक का खाता खुला है? 2020-21 और 2021-22 में इसमें कितनी

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

राशि आयी है और कितनी योजनाओं में इसका पेमेंट हुआ है और 31 जनवरी, 2022 तक अगर यह बैंक खाता है तो इसमें शेष कितनी रकम है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्भागवार राशि व्यय हुई थी, वह परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। साथ में, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पर्यटन निगम है, कोरोना काल की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट यदि कोई विभाग हुआ है तो पर्यटन विभाग हुआ है। यह बात सही है आपकी कि खर्चे कम हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले 100 करोड़ रुपये की राशि से गठन किया गया था और फिर उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया है और इस बजट में उसको एक हजार करोड़ रुपये किया गया है। यदि कोरोना काल सही रहा तो आने वाले टाइम में इसमें सुधार बहुत तेजी से किये जाएंगे और जो बचा हुआ पैसा है उसको खर्च किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान की उपलब्धियां

120. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत क्या उपलब्धियां रहीं? लम्बित कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृतियां शिवगंज पंचायत समिति की उथमण एवं पिंडवाड़ा समिति की दो ग्राम पंचायतों में वितरित नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त के लिए जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के निर्णय के तहत वर्ष 2022 में उक्त क्षेत्र में गोचर भूमि पर सौ वर्ग मीटर के पट्टे किस-किस ग्राम पंचायत में वितरित किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जिला सिरोही में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पी.एम.ए.वाई. में 5125 स्वीकृतियां, 11595 पट्टे जारी, 4437 जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी, व्यक्तिगत शौचालयों की 3085 स्वीकृतियां, 2338 जॉब कार्ड जारी एवं 168 कैटल शैड निर्माण की

(पंचायती राज मंत्री)

स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जिला सिरोही में कुल 430 पट्टों के आवेदन लम्बित रहे हैं।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से दिनांक 21.02.2022 के दौरान अभी तक पंचायत समिति शिवगंज एवं पंचायत समिति पिण्डवाड़ा की समस्त ग्राम पंचायतों की आवास की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'अद्ध व 'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2022 में उक्त क्षेत्र में गोचर भूमि पर सौ वर्ग मीटर के पट्टों का वितरण नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे मिल गया है, पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, ये पूरक प्रश्न पूछ लें?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जैसी आपकी इच्छा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उथमण में 116 परिवार और नया सनवाडा में 566 परिवार इस कारण से अपात्र हुए कि आपने बीघा की जगह पर हैक्टेयर जमीन फीड कर दी। जिसकी जमीन तीन बीघा थी, आपने तीन हैक्टेयर फीड कर दी और इस कारण से वे अपात्र हो गये तो इसके लिए जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही की है और इन परिवारों को आप आवास की सुविधा वापस कैसे प्रदान करेंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उथमण में जो आवास व्यवस्था थी, उसमें लक्ष्य 6 है, एक टार्गेट है और रजिस्टर 6 है, इनकी सेंक्शन है और फर्स्ट इंस्टालमेंट कर दी गयी है।

दूसरा प्रश्न इन्होंने जो रखा कि शेष रह गये तो सबसे पहले भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया था सामाजिक, सोशल और इकोनोमिक जातीय आधार पर तो उसमें करीब 15 लाख के आस-पास ये चिह्नित हुए थे। फिर हमने दुबारा रिक्वेस्ट की थी भारत सरकार को कि इसमें लोग रह गये हैं, सर्वे करवाया है उसमें 23 लाख, एग्जेक्ट फीगर आपको बता देता हूं, 57797 पात्र

(श्री रमेश चन्द मीना)

थे लेकिन दुबारा उन्होंने जो अपलोड किया तो उस समय मात्र उनकी संख्या 13 लाख, सॉरी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर दे रहे हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 13 के समथिंग हुई और उसमें भी 2 लाख 6 हजार 509 लोग रिजेक्टेड हो गये, उनके कारण थे। उसमें 13 पैरामीटर्स थे कि जो बीघा की जगह एकड़ लिखा गया और उसमें कहीं जॉब कार्ड सेम हो गये, कहीं पर इनकम टैक्स वाला है, मोबाइल की जगह पर लैण्डलाइन तो इस तरह के 13 पैरामीटर्स की वजह से वे रिजेक्टेड हो गये तो उनमें से हमने दुबारा उनको पात्र का सर्वे करवाया गया तो 1 लाख 55 हजार 609 लोग पात्र पाये गये। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया और उसके लिए हमने भारत सरकार के माननीय मिनिस्टर से चर्चा भी की, मैंने जाकर भी उनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने अभी आश्वासन ही दिया है और किये नहीं हैं जबकि कर्नाटक में उन्होंने इन नामों को जोड़ा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 की जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वह 2019 में एग्जास्ट हो गयी थी और उसके बाद यह नयी फीडिंग 2020 में हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें सिरोही जिले की सिर्फ दो पंचायतों में आपके कार्मिकों की गलती से ...(व्यवधान)

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कार्मिकों ने बीघा की जगह हैक्टेयर लिख दिया सिर्फ दो पंचायतों में। इसमें कहां भारत सरकार बीच में आ रही है। आपके इंचार्ज सैक्रेटरी जब सिरोही में आये तब उनकी जानकारी में आ चुका है। उसके बाद भी अब तक न कोई कार्यवाही हुई, न किसी कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वही पूछ रहा हूं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसकी समीक्षा की जा रही है कि क्या कारण रहे, किस वजह से यह प्रोब्लम रही और रिजेक्ट हुए। अगर वास्तव में मानिटरिंग सही नहीं की गई तो उन कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित तथा समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कृषकों की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से कोविड-19 स्वास्थ्य सहायकों का कैडर बनाकर नियमितीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत निगम कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध ट्रांसफार्मरों को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में ऋण न चुकाने वाले किसानों की जमीन बैंक द्वारा कुर्क किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर में आपराधिक मामलों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से अलवर शहर में 16 वर्षीय मूक बधिर बालिका के साथ गैंगरेप के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ईसीजी जांच के लिए प्रशिक्षित टेक्निशियन के पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित महामाया मन्दिर बन्दौल की जमीन को भूमाफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में कांकरी डूंगर प्रकरण पर जन प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में बाकली बांध में साकदड़ा माइन्स के दूषित पानी से कैचमेंट एवं सिंचित एरिया के किसानों की जमीन बंजर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा एवं बूंदी जिले में गांवों की चरागाह, सिवाय चक व खाते की जमीनों पर हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में सिवाय चक चरागाह एवं सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में जल जीवन मिशन के तहत नियम विरुद्ध किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।

(16) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों पर रेलवे अन्डरब्रिजों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(17) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पलोट गांव में अनुसूचित जाति की महिला से हुए बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से पीपाड़ शहर में शराब पीये हुए ड्राइवर की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के बांधों में डलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से भादरा एवं नोहर के हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री अविनाश, श्री कन्हैया लाल, श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में निचलागढ़ पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सक्षा क्षेत्र अलवर शहर के हृदयस्थली होपसर्कस की ऐतिहासिक इमारत की दुर्दशा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के मण्ड्रेला ब्लाक चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं में एक बालिका राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बीड़ फतेहपुर को शहरी वन क्षेत्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व मामलों के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पाल देवल एवं रामसागड़ा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में विभागीय अभियन्ताओं एवं ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से भरतपुर सम्भाग में निवास कर रहे बंजारा जाति की उप जाति गवरिया के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले के बृज क्षेत्र में पौराणिक पर्वत श्रृंखलाओं में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से बूंदी तथा सवाई माधोपुर जिले में 8 लेन सड़क निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा नियम विरुद्ध किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इंफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट, प्लीज बैठें आप। I am on legs. आप सीनियर मैम्बर हैं। I am on legs. आप बैठें। प्लीज आप बैठें। I am on legs. I said, please sit down. आप सीनियर आदमी हैं। क्या कर रहे हो?

यूक्रेन के सम्बन्ध में आपका प्रस्ताव मिला है। 02 तारीख को जब सदन मिलेगा तब सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आयेगा। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है।

श्री अध्यक्ष: I will not allow. श्री राजेन्द्र राठौड़। I will not allow. अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: पता है मुझे। आपका मुझे पता है। मैंने लीडर को कह दिया है। प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। Don't record. Don't compel me. श्री राजेन्द्र राठौड़, आपको बोलना है? कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। आपके पास क्या पावर है? आप बैठें प्लीज। You go and talk to the Government of India. आप बैठें। I said, I will name you. कटारियाजी, I will name him. आपकी पार्टी का डिसीप्लीन है यह? मैंने आपके लीडर से बात की। अब आप लीडर को नहीं मानना चाहते। चर्चा करने के बाद ही मैंने फैसला किया है कि सरकार स्टेटमेंट देगी। फिर भी आप स्कोर करना चाहते हो अपने नाम का। Please, I said, be seated. I said, आप बैठिए प्लीज। पूरे देश की चिन्ता आपको ही है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार की घटना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियम 50 के अन्दर आप जैसा विद्वान अध्यक्ष सदन में चर्चा करने की अनुमति तब देता है जब आपके मन मस्तिष्क में यह बात आती है कि सदन के संज्ञान में ये बातें आनी चाहिए और सदन की परिभाषा की बात करते हैं तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से परिपूर्ण होती है। सत्तापक्ष अगर कोई बात संवेदनशील होते हुए भी जवाब नहीं दे तो यह उनकी मर्जी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी अलवर की मूक बधिर बालिका के....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be on point. प्लीज अपने पाइन्ट पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...अनाचार की बात की स्याही सूखी भी नहीं थी, डीडवाना के पलोट गांव के अन्दर एक ऐसी लोमहर्षक घटना हो गयी जो न सुनी जा सकती है, न कही जा सकती है। मैं जो सदन में बोल रहा हूं, कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई घटनाओं में हमारे प्रशासन के सिस्टम का चरित्र उजागर होता है और इसीलिए उस पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पलोट गांव में एक दलित महिला 04 फरवरी को सायं 7 बजे गायब होती है। उसके परिवार के लोग, महिला का देवर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है। ऑनलाइन एफआईआर की बात करने वाले हुकमनारायण के हुकम नहीं चलते और ऑनलाइन एफआईआर की बात कहीं की कहीं रह जाती है, उस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उसके बाद 06 तारीख को एसपी को गुहार की जाती है। एसपी के कहने पर रोजनामचा नम्बर 14 के अन्दर तेजाराम पुत्र श्री सुण्डाराम रिपोर्ट दर्ज कराता है, साथ में टेलीफोन नम्बर देता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही वह संदिग्ध लोगों पर नामजद करता है कि इन लोगों से भी, जब उससे कहते हैं कि आधार क्या है, तो उन लोगों का नाम भी बताता है। 6 फरवरी को उस संदिग्ध व्यक्ति को, जिसका नाम सुरेश है, उसको पुलिस पूछताछ के लिये बुलाती है। पूछताछ अभी पूरी होती ही नहीं है कि कुछ ही देर में एक लग्जरी गाड़ी आती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उसके अन्दर एक आइदाना राम नाम का व्यक्ति, पुलिस की पूछताछ पूरी होती नहीं है, उससे पहले ही उसको छुड़ाकर ले जाता है। बिना पूछताछ के अपराधी सुरेश अपने घर चला जाता है। चहुंओर इस बात की आलोचना होनी चालू होती है। समाचार-पत्र लिखना चालू करते हैं और फिर पुलिस 4 तारीख को गायब महिला के सी.डी.आर., टेलीफोन नम्बर, जो 6 तारीख को उस रोजनामचे में लिखकर उसका देवर देता है, उसके आधार पर वापस उस सुरेश को बुलाती है और सुरेश 10 तारीख को यह कबूल करता है कि मैंने अबला के साथ अनाचार, बलात्कार किया और मैंने हत्या करने की नीयत से उस पर वार करके उसको पलोट गांव में नरेगा का जहां काम चल रहा है, वहां डाल दिया। 4 तारीख से गायब महिला 10 तारीख को वहां बरामद होती है सिसकती हुई जिन्दा महिला, मैं समझता हूं इस बात को जब याद करते हैं, एक जिन्दा महिला 6 दिन तक एक गांव के अन्दर सिर्फ इसलिए सिसकती रहती है, जीवन से लड़ती है, क्योंकि पुलिस ने 6 तारीख को जो संदिग्ध व्यक्ति था उसको उच्च पदस्थ लोगों के कहने पर छोड़ दिया, जो बाद में कबूल करता है कि हां, मैंने हत्या की है। इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती और उसके बाद 10 तारीख को एक एफ.आई.आर. दर्ज होती है, एफ.आई.आर. के अन्दर उसका देवर यह कहता है कि मुझे शंका है, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एफ.आई.आर. की बात पढ़ रहा हूं। उस अबला का नाम लिखता है। सुरेश पुत्र हरजीराम और अनीस पुत्र बिशनाराम, इन सहित अन्य लोगों ने मेरी भाभी का अपहरण किया है और उसकी हत्या की है। आज भी वह अन्य लोग कहीं नहीं, मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को महिला की मृत्यु होती है, आज अनुत्तरित सवाल खड़े हैं। आपने सिर्फ एक सी.आई. और एक हैड कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया। प्रथमदृष्टया में अगर उस सी.आई. का कसूर है और आपने एस.सी., एस.टी. एक्ट 1989 लगाया है, तो सैक्शन 4(7) कहता है 'इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, उस पर कार्यवाही नहीं की।' (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मेरा आरोप है, जिन लोगों के कहने पर उस अपराधी को छोड़ा जाता है पूछताछ किये बिना, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, रूह कांप उठती है, जब इन सारी चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, इसलिए इस पारदर्शी सरकार के समय कानून की जो धज्जियां उड़ रही हैं, गृह मंत्रीजी, आप जवाब दे दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आप आज नहीं कभी भी जवाब दे दें, पर निश्चित तौर पर उन किरदारों के चेहरे से नकाब उठाओ, जो इस प्रकार का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

पीपाड़ शहर में सड़क दुर्घटना में पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपाड़ कस्बे की एक ऐसी घटना के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह घटना 19 तारीख की है। शनिवार, 19 तारीख को एक नव-दम्पत्ति, जिसका 6-8 महीने पहले ब्याह हुआ था, गुडिया देवी और रामरतन माली दोनों एक कस्बे के शादी समारोह में उपस्थित होने के लिये पीपाड़ कस्बे में आते हैं। वहां साथिन चौराहे पर एक शराब पीया हुआ ड्राइवर तेज और लापरवाही से एक गाड़ी चलाता हुआ रोंग साइड से आता है और मोटर साइकिल को टक्कर मार देता है। उसी टक्कर में गुड़िया देवी की आन स्पाट डैथ हो जाती है और डैथ होने के बाद में वह बॉडी परिवारजनों को सुपुर्द कर दी जाती है। परिवारजनों ने यह मांग की कि जो आरोपी ड्राइवर है, शराब पीया हुआ है, उसको पुलिस पकड़ती नहीं है और

(श्री अविनाश)

उसके बाद में वह ड्राइवर वहां से एक शराब के ठेके पर जाता है। शराब के ठेके से शराब लेता है और वह शराब ठेका वाला जब उसको कहता है कि तूने एक्सीडेंट कर दिया तो यहां क्यों आया है, तो वह कहता है कि ऐसे तो साधारण केस होते हैं। वहां की वीडियो फुटेज अवेलेबल है। उसके बाद में जो घायल हो गया था, उसको मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया जाता है और विडम्बना इस बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि शराब पीये हुए व्यक्ति, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ देती है और लगभग छह से आठ घण्टे उसका राजनीतिक दबाव के अन्दर मेडिकल नहीं करवाया जाता। वह इसलिए नहीं करवाया ताकि वह मेडिकल करवाएंगे तो उसके ऊपर आरोप साबित हो जाएगा और जिस वाहन से टक्कर होती है, उस कार का नम्बर भी उस पुलिस थाने की रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता है। यह पुलिस की मिलीभगत से आरोपी को बचाने के लिये इस प्रकार का वाकया होता है और जब दूसरे दिन 20 तारीख को उसके पति रामरतन की भी डैथ हो जाती है और डैथ हो जाने के बाद में जब शव को मथुरादास माथुर अस्पताल से वापस पीपाड़ की तरफ लाया जाता है तो वहां पर समाजसेवियों के द्वारा इस बात की सरकार से मांग रखी जाती है और पुलिस थाने पीपाड़ के बाहर उस रामरतन की बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाता है और जब प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से तीन-चार मांगें रहती हैं सरकार से, एक तो आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही हो, एक पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने न तो एफ.आई.आर. दर्ज की, न आरोपी का मेडिकल करवाया, इसके साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी हो, जिसमें मुख्य रूप से चार पुलिसकर्मी हैं, पीड़ित परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। इस प्रकार की मांग को लेकर पीपाड़ थाने के बारह प्रदर्शन किया जाता है।

(समय: 12.14 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, दु:ख इस बात का है कि दो दिन तक संघर्ष चलने के बाद में अपनी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखने के बाद में वहां कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक समझौते की बात की जाती है। बन्द कमरे के अन्दर बात होती है और बात होने के बाद में जब सहमति नहीं बनती है तो पुलिस द्वारा जबरदस्ती लाठीचार्ज करके उस भीड़ को खदेड़ दिया जाता है और लाश को जबरदस्ती पीड़ित परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है

(श्री अविनाश)

और उसको सुपुर्द करने के बाद में अन्तिम संस्कार के लिये ले जाया जाता है। उसी दरम्यान, एक एफ.आई.आर. पुलिस के द्वारा दर्ज होती है। एफ.आई.आर. नम्बर 46/2022, उसमें 33 नामजद आरोपियों और अन्य 100-150 लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज होती है। वह धारा 147, 148, 149, 323, 427, 336, 332, 353 और सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान की धारा 3 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस पीपाड़ कस्बे को माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना दूसरा घर समझते हैं, वहां नगरपालिका पीपाड़ के पूर्व अध्यक्ष, दबंग समाजसेवी और एडवोकेट महेन्द्र सिंहजी कच्छावा, उनके बेटे, उनके पोते, उसके अलावा, जो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है और जिन 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनमें से अधिकांश लोग, करीब 27-28 लोग एक ही जाति विशेष के लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो पुलिस के द्वारा जो असत्य रिपोर्ट दर्ज की गयी है 46/2022, इसको रद्द करे और गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है और यह दबिश देने के बाद में आज यह जो निर्दोष लोग हैं, वह अपने घर पर नहीं बैठ पा रहे, उनके अन्दर डर बैठा हुआ है। इसलिए पुलिस की इस राजनीतिक दुर्भावना से की गयी कार्यवाही को रद्द करें और जो 33 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, उनको भी राहत दें। यह मैं सरकार से मांग करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी का मालपुरा के बांधों में प्रेषण

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे टोंक जिले के किसानों की महत्वपूर्ण मांग, जो पिछले 15 से 20 सालों से आन्दोलन चल रहा है टोरडी सागर के अन्दर बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी डालने के लिये, इस विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टोरडी सागर बीसलपुर के बिलकुल 30 किलोमीटर दूर पर बांध बना हुआ है और जब भी बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो का पानी होता है तो किसान चाहते हैं कि यह ओवरफ्लो पानी, जो एक्स्ट्रा बहकर समुद्र में जाता है, फ्लो से, क्योंकि उसका

(श्री कन्हैया लाल)

लेवल मिलता है फ्लो से टोरडी सागर मिले, जिससे हमारे किसान वहां पर कोई इण्डस्ट्री नहीं है, केवल सूखी जमीन है, कुछ पानी चला जाए तो किसानों को फायदा होगा। इसके लिये 15 साल पूर्व भी आन्दोलन हुआ था, उसमें गोलीकाण्ड के अन्दर हमारे कई किसानों की डैथ हुई थी। जब हमने इसका सर्वे करवाया तो इसकी कोस्टिंग भी ज्यादा नहीं आ रही थी, लगभग 200 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आ रहा था और अगर यह पानी एक साल भी मिल जाता है तो लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपये किसानों की एक्स्ट्रा आमदनी होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे।

पिछले 15 साल में लगभग सात बार बीसलपुर का यह बांध ओवरफ्लो हुआ है और यह पूरा पानी बहकर समुद्र में गया है। हम सब मिलकर सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस पर ध्यान दें और हमारे किसान अभी भी आन्दोलन कर रहे हैं, चार-पांच दिन पहले 19 तारीख को भी विधान सभा का घेराव करके गये थे और वह काफी ज्यादा दु:खी हैं तो उनकी मदद करें। यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

भादरा व नोहर को उनके हिस्से के पानी की आपूर्ति

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं भादरा-नोहर के किसानों के नहरों के हिस्से के पूरे पानी की मांग सदन में पुरजोर तरीके से उठाना चाहता हूं। हमारे भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का नियन्त्रण है, जिससे राजस्थान को पानी मिलता है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का पानी तय होता है। माननीय सभापति महोदय, जो हिस्सा तय होता है, वह सितम्बर के महीने में वह मई तक हिस्सा पहुंचता है लेकिन हमारे यहां CP5, जहां भादरा में पानी पहुंचता है और CP4 जहां नोहर में पानी पहुंचता है, हमारी नोहर-भादरा की नहरों में लगातार हरियाणा, पंजाब की तरफ से अनियमितता रहती है।

हमारा जो इण्डेण्ट हमारे अधिकारियों द्वारा जाता है, वह पानी लगातार 7 दिन तक या फिर 15 दिन तक रेगुलेशन के अनुसार नहीं मिलता है, जिससे पानी में उतार-चढ़ाव आता है। हमारी वितरिकाएं पिट जाती हैं। एनटीआरडीपीएन का विवाद खड़ा हो जाता है जिससे हमारे किसानों की पकी-पकाई फसलें बरबाद होने की स्थिति में आ जाती हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह पानी लगातार 7 दिन नहीं चलने से न सिर्फ वितरिकाएं टूटती हैं बल्कि जो भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं, जहां हिस्से का पानी तय होता है, वहां हरियाणा पहले अपनी नहर चला लेता है, पंजाब पहले अपनी नहर चला लेता है, उसके टेल के किसान को नुकसान होता है, इससे इस मैनेजमेंट बोर्ड का विश्वास भी खतम होता है। आज हमारे इलाके में किसानों की फसल बरबाद होने की स्थिति में है।

सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले बरसात हुई थी। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बची हुई फरवरी का और मार्च का हिस्सा बढ़वाएं और हमारी नहरों में पूरा पानी दिलवाने का प्रयास करें ताकि हमारी फसलें बरबाद ना हों।

मैं राजस्थान सरकार से यह भी चाहता हूं कि जिस तरह से काजले हैड पर हरियाणा ने डैम बना लिया, उससे पहले टुहाना पर डैम बना लिया, हमारे सीपी-5 जहां राजस्थान के भादरा में नहर एण्टर करती है, वहां सिद्धमुख नहर और अमरसिंह ब्रांच पर भी हैड का मिलान किया जाये, नहरों का मिलान किया जाये और वहां डैम बनाया जाये। हरियाणा कई बार अपना रेगुलेशन बदल लेता है। आज हरियाणा ने अपना रेगुलेशन बदल लिया, जिससे मेरे इलाके की नहरों में अनियमितता हो गयी।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी हजारों हैक्टेयर जमीन में जो फसल किसान ने बोयी, इतनी लम्बी लाइनें खाद की लगीं, खाद कहीं से लाकर के लोगों ने फसलें बोयीं, आज वह फसल बरबाद होने की स्थिति में है।

आज उदयपुर में भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसमें राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखे और उसमें यह कहे कि फरवरी में, मार्च में राजस्थान का वाया सीपी-4, सीपी-5 हिस्सा बढ़े और हमारी फसलों को पकाने का काम करे। भविष्य में जिस दिन राजस्थान का इण्डेण्ट एक्स.ईएन., ए.ईएन. भेज दे, उसमें हरियाणा की सरकार परिवर्तन न करे, अपने रेगुलेशन के अनुसार हमारी नहरों को चलाने का प्रयास न करे। यह राजस्थान की सरकार सुनिश्चित कराये। यह साफ-सुथरी सी बात है जिससे यह लगे कि भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का नियंत्रण है।

आज हमें कतई नहीं लग रहा है कि इन नहरों, डैम पर नियंत्रण

(श्री बलवान पूनियां)

भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है। यह लग रहा है कि पहले पंजाब अपनी नहरें पूरी चलाता है, उसके बाद हरियाणा अपनी नहरें पूरी चलाता है। हम टेल पर हैं। हमारी नहरें पिट जाती हैं। मैं इसलिए आज भादरा, नोहर के उन किसानों की तरफ से आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि हमारी नहरों के हिस्से का पूरा पानी दिलाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री समाराम गरासिया। (व्यवधान) आपस में वार्ता न करें ताकि आपको सुनाई दे जाये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पिण्डवाड़ा में निचलागढ़ पुलिस चौकी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आबू रोड तहसील के भाखर क्षेत्र के कुछ गांवों को पिण्डवाड़ा तहसील के रोहिड़ा थाने के हलके में जोड़ा गया है, जिसकी दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की पड़ती है। भाखर क्षेत्र में 100 प्रतिशत आदिवासी लोग ही रहते हैं। जब कभी दो गुटों में झगड़ा और सड़ोतरा जैसी स्थिति बनती है, तब तुरन्त प्रभाव से पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे पुलिस के पहुंचते-पहुंचते बहुत बड़ी घटना हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि निचलागढ़ जो पुलिस चौकी है, इसको पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाये। सम्पूर्ण भाखर क्षेत्र को निचलागढ़ थाने में जोड़ा जाये और भाखर क्षेत्र की आदिवासी गरीब जनता को राहत प्रदान की जाये।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर के होप सर्कस की ऐतिहासिक इमारत की दुर्दशा

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर का हृदयस्थल होप सर्कस प्रशासनिक उपेक्षा के कारण इन दिनों बदतर स्थिति में है। निर्माण के बाद सैकड़ों आन्दोलन का गवाह बने होप सर्कस की दुर्दशा की

(श्री संजय शर्मा)

सुध लेने वाला कोई नहीं है। साथ ही रविदास जयन्ती, भरत मिलाप जैसे धार्मिक आयोजन की साक्षी यह ऐतिहासिक विरासत सौन्दर्यता खोने को मजबूर है। ऐतिहासिकता के बावजूद इस विरासत को सहेजने की ओर जिम्मेदार लोगों का ध्यान नहीं है। इस कारण यह ऐतिहासिक विरासत आज समाजकंटकों का आश्रय स्थल बन गयी है। रंग-रोगन नहीं होने के कारण यह ऐतिहासिक इमारत आज बदसूरती में तब्दील हो गयी है। होप सर्कस के आसपास चारों ओर सीढ़ियां, बुर्ज एवं अन्य स्थानों पर गन्दगी के ढेर यहां की सौन्दर्यता को खराब कर रहे हैं।

अत: मेरा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के हृदयस्थल होप सर्कस की बदतर स्थिति को शीघ्र ठीक किया जाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

मण्ड्रेला (चिड़ावा) में बालिका राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार जहां छात्राओं की संख्या 500 या उससे अधिक है वहां एक राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्वीकृति की जानी है।

इस सन्दर्भ में मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अन्तर्गत मण्ड्रेला में श्रीमती बनारसी देवी लाठ राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं व अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 500 से भी अधिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस संबंध में प्रमाण के रूप में मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, चिड़ावा, जिसके अधीन मण्ड्रेला की सारी स्कूल्स आती हैं, द्वारा जारी अधिकृत सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग व माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय व माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र के मण्ड्रेला, ब्लाक चिड़ावा, जिला झुंझुनूं में एक बालिका राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराकर

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अनुग्रहीत करें। इसके संचालन हेतु भवन आदि की अस्थायी व्यवस्था स्थानीय निवासियों के माध्यम से नि:शुल्क करवा दी जायेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर बीड़ का शहरी वन क्षेत्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकास

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ऐतिहासिक बीड़ फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन प्राचीन समय में नवाबों के राज में बहुत बड़ा बीड़ गोवंश के लिये छोड़ा गया था, जो वर्तमान में वन विभाग के अधीन है तथा बीड़ फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। यह बीड़ लगभग 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बीड़ में विभिन्न प्रजातियों के पेड़-पौधे हैं जिनमें मुख्यत: केर के पेड़ हैं। भिन्न-भिन्न प्रजाति के वन्य जीव भी यहां निवास करते हैं, जिनमें जंगली बिल्ली, लोमड़ी, नील गाय, मोर एवं हजारों की संख्या में चिंकारा, हिरण पाये जाते हैं। हजारों की संख्या में बेसहारा गोवंश का भी यह आश्रय स्थल है। इसके अलावा इस बीड़ में कुएं, तालाब, जोहड़, वाच टावर व बावड़ी आदि प्राचीन काल से बने हुए हैं।

सभापति महोदय, इस बीड़ से होकर एनएच-52 निकलती है, जिस पर वाहनों का अत्यधिक आवागमन रहता है। बेसहारा गोवंश या वन्य जीवों के अचानक सड़क पर आने के कारण इस बीड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे काफी जन हानि भी होती है।

सभापति महोदय, सितम्बर, 2021 को पूर्व मुख्य सचिव, राजस्थान श्रीमान् निरंजन आर्य के दौरे के समय मुख्य सचिव ने भी इस क्षेत्र का अवलोकन कर स्थानीय अधिकारियों को इस बीड़ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये थे।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक नवाबी बीड़ फतेहपुर को शहरी वन और पर्यटन स्थल के रूप में

(श्री हाकम अली खां)

विकसित कर फतेहपुर बीड़ को कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाकर इसके चारों तरफ दीवार बनायी जाये तथा बीड़ क्षेत्र में एनएच-52 के दोनों तरफ दीवार अथवा तार फेंसिंग करवायी जाये जिससे वन एवं वन्य जीवों को बचाया जा सके तथा इस वन क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि बीड़ फतेहपुर में प्राचीन काल से बने हुए ऐतिहासिक कुओं, तालाबों, जोहड़, वाच टावर व बावड़ियों आदि का रिनोवेशन करवाया जाये। वन्य जीवों के चारे, पानी की व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोत एवं ग्रास लैण्ड विकसित किये जायें, ताकि वन्य जीवों को भूख-प्यास का सामना नहीं करना पड़े, जिससे वन्य जीवों के कुनबे में बढ़ोतरी हो। वन क्षेत्र बीड़ फतेहपुर में हर्बल गार्डन विकसित किया जाये। वनस्पति की अलग-अलग प्रजातियों के मोनोकल्चर प्लांट बनाकर बायोडायवर्सिटी को विकसित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)।

श्री धर्मेन्द्र कुमार।

हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल की मेडिकल कालेज से सम्बद्धता

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिला अस्पताल विगत 45 वर्षों से हनुमानगढ़ जिले के निवासियों को चिकित्सा सेवा मुहैया करवा रहा है। वक्त के साथ नागरिकों की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ने इसकी बैड क्षमता 230 कर दी। इसके कारण नियमानुसार हनुमानगढ़ के जिला चिकित्सालय को केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कालेज आबंटित हुआ है। 45 वर्षों के इस सफर में हनुमानगढ़ के नागरिकों ने करोड़ों रुपये दान एवं भेंट कर अस्पताल के विकास में अहम योगदान दिया है। अस्पताल बिल्डिंग, ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक, आईसीयू व अमरनाथ सेवा समिति द्वारा निर्मित धर्मशाला इसके उदाहरण हैं।

मेडिकल कालेज आबंटित होने के पश्चात् जिला अस्पताल को ही मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल रखकर उसमें सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा 26.08.2021 को कलेक्टर, हनुमानगढ़, पीएमओ,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हनुमानगढ़, जिला अस्पताल व प्रभारी चिकित्सक के हस्ताक्षर सीपीआर द्वारा जारी किया गया था। इसकी प्रतिलिपि मीडिया को भी प्रशासन के माध्यम से जारी की गयी थी किन्तु इसके पश्चात् कुछ निजी हितों के चलते इस अस्पताल की अधिकतर सेवाएं व बैड नवां बाइपास पर ले जाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जिसके खिलाफ हनुमानगढ़ के लोगों में रोष है।

इस रोष की अभिव्यक्ति के तौर पर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पिछले 75 दिनों से अधिक समय से अनिश्चितकालीन धरना जिला अस्पताल के सामने चल रहा है। धरने के साथ-साथ हनुमानगढ़ के नागरिक बाजार बन्द, चक्का जाम, आक्रोश रैली, मानव श्रृंखला, रोष मार्च व ज्ञापन के माध्यम से रोष व्यक्त कर चुके हैं।

हनुमानगढ़ का जिला अस्पताल पूरे जिले के लिए सुविधाजनक है। इसकी रेलवे स्टेशन से दूरी 500 मीटर, स्टेट हाईवे व प्रस्तावित भारत माला व बस स्टैण्ड से 1.5 किलोमीटर है। ये रास्ते किसी भी प्रकार के अवरोध रहित हैं। हनुमानगढ़ शहर 2.5 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है व लगभग 1 लाख लोगों की पैदल पहुंच में है। प्रस्तावित जगह पर अस्पताल के दोनों तरफ रेलवे के फाटक हैं व शहर की मुख्य आबादी से करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यह हर नागरिक के लिए असुविधाजनक व कष्टदायक है। जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कालेज निर्माण में जिला प्रशासन ने भूमि उपलब्ध न होना मुख्य कारण बताया है। इस पर हनुमानगढ़ के बाबा मस्तनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट के महन्त व वर्तमान अलवर सांसद बाबा बालक नाथजी ने जनहित में ट्रस्ट की 100 बीघा भूमि व कालेज निर्माण हेतु देने व इस पर व्यय हेतु आर्थिक सहयोग भी करने का समिति के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भिजवाया था। इसके बावजूद प्रशासन जनहित में निर्णय लेने में संकोच कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हनुमानगढ़ की जनता सरकार से निवेदन करती है कि हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल को मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल रखा जाये व अस्पताल का विकास राज्य प्रशासन द्वारा तय सीपीआर दिनांक 26.08.2021 के आदेश के अनुरूप करवाया जाये।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

पाल देवल व रामसागड़ा (डूंगरपुर) में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आते हैं। यहां से भुआली, शिशेद, बोखला, पालगामड़ी, पालवड़ा, साबली, घुघरा, टाडी, ओबरी, बटकाफला, पालदेवल आदि गांवों की दूरी 25-30 किलोमीटर है और आवागमन के साधन भी नहीं हैं। सरकारी बसों का संचालन भी न होने से निजी वाहन मनमाना किराया वसूल करते हैं। इससे वहां छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी घटित होती हैं जो कि बेहद शर्मनाक है।

यहां कुछ निजी विद्यालय भी हैं जो मोटी राशि वसूल करते हैं इससे गरीब तबके के छात्र-छात्राएं वहां अध्ययन नहीं कर पाते इसलिए शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है। अत: निवेदन है कि उक्त सभी गांवों के मध्य पालदेवल में राजकीय महाविद्यालय खोला जाये।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उप खण्ड बिछीवाड़ा, गुजरात बोर्डर समीप के गांव मेवाड़ा, वीरपुर, शरम, कानपुर, नारेली, भरतपुर, कोडियागुण, पादरड़ी, जालुकुआ, बेड, महिपालपुरा, गलन्दर, पांच महूडी, राम सागड़ा, रातापानी आदि गांवों के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु 35-40 किलोमीटर की दूरी तय कर डूंगरपुर आना पड़ता है। इतनी दूरी होने के कारण वहां की छात्राएं मजबूरन आवागमन नहीं कर पातीं, इससे उनको शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से कई विद्यार्थी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु पाल देवल व रामसागड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अनियमितताएं

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के माधोगढ़ कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हेतु पेयजल परियोजना के लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना पर कार्य शुरू होने से पूर्व कार्य में प्रयोग होने वाले पाइप एवं सिविल कार्य व मशीनरी की गुणवत्ता के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी। परियोजना के तथ्यों को छुपाकर ठेका फर्म खोखर एन्टरप्राइज एवं अधिशासी अभियन्ता ने सांठगांठ कर कार्यादेश जारी कर दिये जिसके लिए वह सक्षम नहीं है। कार्यादेश के लिए सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता होता है।

तकनीकी मानदण्डों की अवहवेलना कर पाइप लाइन बिछाने की गहराई 1.5 मीटर की जगह 50 सेंटीमीटर ही रख दी गयी है। उपयोग में लिए जा रहे पाइप की गुणवत्ता की न तो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच करवायी गयी है ओर न ही इन पाइपों का अनुमोदन करवाया गया है। घटिया स्तर के पाइप काम में लिये जा रहे हैं। पेयजल स्कीम माधोगढ़ कस्बे के लिए स्वीकृत है जबकि 75 प्रतिशत लाइन पास के दूसरे गांव गवालनी में डाल दी है। जल जीवन मिशन के तहत गठित विलेज वाटर, हैल्थ एण्ड सेनिटेशन कमेटी द्वारा घटिया स्तर के काम तथा माधोगढ़ की बजाय अन्य गांव गवालनी में पाइप लाइन डालने की शिकायत सरकार के हर उच्च स्तर पर करने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा 11 माह से कार्य बन्द है। इसी प्रकार ग्राम जटवाड़ा में घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है और न कोई सुपरविजन है और न कोई जांच की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जल जीवन मिशन के तहत 28 गांवों के लिए प्रथम योजना में कार्यादेश दिनांक 08.09.2021 को तथा दूसरा कार्यादेश 37 गांवों के लिए दिनांक 10.10.2021 को दिया गया था। दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों ने बिना कोई योजना बनाये एवं बिना किसी विधिवत कार्यादेश के फर्जी तरीके से हर घर नल की झूठी प्रगति दिखाने के लिए 9 ग्राम पंचायतों के गांव ढाणियों में 1338 कनेक्शन केवल उपभोक्ताओं से उनके आधार कार्ड लेकर आईएमआईएस साइट पर प्रदर्शित कर दिये गये हैं। इस प्रकार बिना कोई योजना

(श्री लक्ष्मण मीणा)

बनाकर कार्यादेश देकर दिखायी गयी है। अब इन 1338 कनेक्शन को किस प्रकार नियमित कर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा?

इस प्रकरण की पूर्व में कई शिकायतें सरकार के हर स्तर पर करने के बावजूद भी आज तक दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है।

मैं सरकार से वित्तीय अनियमितताओं और तकनीकी मानदण्डों की अवहेलना कर घटिया पाइप तथा सिविल कार्य करने में घोटाले के इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा माधोगढ़ का कार्य शीघ्र चालू कराने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

बृज क्षेत्र, भरतपुर में अवैध खनन

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर जिले के बृज क्षेत्र स्थित डीग और कामां जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। उक्त स्थानों के बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में स्थित कई पर्वतों को अवैध खनन कर नष्ट कर दिया गया है और कुछ पर्वत अपने विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां के पर्वतों पर हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई वर्षों से साधु-सन्तों और आमजन की संस्कृति व पौराणिक सम्पदा तथा भगवान कृष्ण के प्रतीक चिन्हों के रक्षण के लिए आन्दोलनरत हैं। इसके बाद भी कोई इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। इन पर्वतों में कनकाचल एवं आदिबद्री पर हो रहे विनाशकारी खनन से इन पर्वतों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।

बृज के पर्वतों में कोई छोटी-मोटी धरोहर नहीं बल्कि भारत के उस महानायक के भौतिक प्रमाण हैं जिसने इस देश को एक नई दिशा दिखाई थी। इनके महत्व को कम करके यदि कोई आंकता है तो निश्चित रूप से उसे भारत की समझ नहीं है। भगवान कृष्ण के आह्वान पर बृज क्षेत्र में स्थित केदारनाथ, आदिबद्री, कनकाचल, गंगोत्री, यमुनोत्री, नर-नारायण पर्वत एवं गुप्तकाशी के पौराणिक पर्वतों का अवैध खनन कर दोहन किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए भरतपुर जिले के बृज क्षेत्र में

(श्रीमती सफिया जुबेर)

स्थित पौराणिक पर्वत श्रृंखलाओं को अवैध खनन से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

भरतपुर निवासित बंजारा जाति की उप-जाति गवारिया का अनुसूचित जाति में सम्मिलन

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बंजारा जाति राजस्थान प्रदेश के अन्तर्गत बहुतायत में निवास करती है तथा बंजारा जाति को विभिन्न उप जातियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें बालदिया बंजारा, लवाना, गवारिया बंजारा, वामणिया भाट, मारू भाट, वागोरा भाट, कांगसिया आदि हैं। उक्त सभी जातियों में से बालदिया बंजारा, लवाना, वामणिया भाट, मारू भाट, वागोरा भाट आदि ओबीसी की श्रेणी में आते हैं व गवारिया बंजारा अनूसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं।

राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग ने बंजारा समाज की उप-जाति गवारिया को अनुसूचित जाति की श्रेणी ही में रखा हुआ है परन्तु कुछ जिलों में गवारिया को बंजारा नाम से ही पहचाना जाता है, जिस कारण से उन्हें मिलने वाले गवारिया बंजारा जाति के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। भरतपुर सम्भाग के अन्तर्गत उक्त जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं, जिनका जाति प्रमाण-पत्र बंजारा जाति के अन्तर्गत बनाया जाता है, जिस कारण से उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर इन्हें ओबीसी की श्रेणी में ही माना जाता है।

गवारिया उप-जाति के लोगों को ओबीसी श्रेणी में दर्शा कर, इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के अनुसार उक्त बंजारा जाति को उप-जाति गवारिया माना है, जो कि अनूसूचित जाति की श्रेणी में आती है।

अतः सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि सरकार अपने स्तर पर भरतपुर सम्भाग में

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

निवास कर रहे बंजारा जाति की उप-जाति गवारिया के लोगों का सर्वे करवाकर उन्हें अनूसूचित जाति में दर्शाकर उनको मिलने वाले लाभों से लाभान्वित किये जाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

बून्दी व सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बून्दी तथा सवाई माधोपुर जिले में 8 लेन सड़क निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों, चरागाह, वन विभाग, गै.मु. आबादी, तालाब, सिवाय चक आदि क्षेत्रों की बिना इजाजत अथवा इजाजत के नाम अन्य स्थान से खनन करके मिट्टी उपयोग में लेने एवं उनके द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों बाबत विभिन्न सरकारी विभागों खनिज, वन एवं पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन एवं सीएडी, पंचायती राज संस्थाओं, खातेदार, गैर खातेदार, कब्जाधारी किसान आदि के हितों को नुकसान पहुंचाने पर सुनवाई एवं कार्रवाई नहीं होना गम्भीर चिंतनीय स्थिति है।

चूंकि इस निर्माण कार्य में लगे करोड़पति-अरबपति व्यक्तियों (ठेकेदारों), जिनकी राज्य सरकार एवं भारत सरकार में ऊंची पहुंच होने से, उनके खिलाफ कोई मुंह खोलने व कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पुलिस-प्रशासन के जरिये हर किसी का धमकाना व कानूनी कार्रवाई में उलझा देना आम बात है। इस सड़क निर्माण के कार्यों में दौसा सहित विभिन्न स्थानों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर प्रकरण सामने आये एवं उनमें भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा एवं राज्य सेवा के अधिकारी भी लिप्त पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितता व भ्रष्टाचार तथा खनिज विभाग के परमिट के अतिरिक्त स्थानों पर सीमा से अधिक गहराई तक खनन करने के विभिन्न प्रकरण होते हुए भी कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर से प्रकरण दर्ज करवाने के लिए अति प्रभावी आदेश अविलम्ब ही जारी किये जाने आवश्यक हैं, ताकि सरकार के खिलाफ आमजन में बन रही दुर्भावना व भ्रष्टाचार के किस्सों की चर्चाओं पर कुछ हद तक विराम लगाया जा सके।

(श्री रामनारायण मीना)

उप-खण्ड अधिकारियों (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा भी मुआवजा राशि निर्धारण में जान-बूझकर किसानों के हितों की अनदेखी की गयी है। निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों द्वारा कई स्थानों पर ऐसे अधिकारियों से नापाक सम्बन्ध भी बनाये गये हैं। इसका प्रमाण इन गलत कार्यों पर अधिकारियों की मौन स्वीकृति है। ये कम्पनियां बहुत शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर नाजायज धनराशि की कमाई करके वापस चली जायेंगी और आमजन एवं किसान वर्षों तक इनके कारनामों से परेशान होता रहेगा। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि राज्य सरकार को आदेशित किया जाये कि बिना किसी देरी के अविलम्ब ही अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उच्चस्तरीय जांच दल का गठन किया जाकर प्रभावी ढंग से इसकी जांच की जाकर मौके पर ही कठोर कार्रवाई कराएं। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ समय एवं स्थान पर ही कठोर कार्रवाई की जाने का श्रम कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत (अनुपस्थित)।

अधिसूचनाएं, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(01) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 20.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET), 2021 से संबंधित समस्त सेवाओं को दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(02) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 23.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET), 2021 से संबंधित समस्त सेवाओं में दिनांक 30.09.2021 तक हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(03) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2021पार्ट1 दिनांक 20.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलार्पों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 20.10.2021 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(04) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्टI दिनांक 20.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में दिनांक 20.10.2021 से आगामी तीन माह तक हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।

(05) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 21.10.2021 जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 21.10.2021 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(06) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2021 दिनांक 21.10.2021 जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में दिनांक 21.10.2021 से आगामी तीन माह तक हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।

(07) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 06.12.2021 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को दिनांक 06.12.2021 से आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(08) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 21.01.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 19.01.2022 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(09) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 21.01.2022 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में दिनांक 19.01.2022 से आगामी तीन माह तक हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 05.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

(17) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 08.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020, 21.05.2020 एवं 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा।

गृह विभाग

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्न एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: प.4(10)गृह-7/2004 पार्ट दिनांक 28.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान गृह रक्षा नियम, 1962 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन, श्री बुलाकी दास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे मय अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे मय अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत निम्नांकित 2 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

01. राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18; एवं

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

02. राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19.

श्री सभापति: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 2 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

01. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; एवं

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

02. राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21.

श्री सभापति: श्री अंजना उदयलाल।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित 5 वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन व पूर्ति रिपोर्ट (वर्ष 2019-20 एवं 2020-21)

01. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन व पूर्ति रिपोर्ट वर्ष 2019-20 एवं 2020-21;

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

02. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

(श्री अंजना उदयलाल)

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

03. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19 एवं 2019-20)

04. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

05. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान। श्री अशोक लाहोटी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के जिस बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, यह केवल बजट ही नहीं है, यह दोनों पक्षों के लिए ही एक अर्थ संकल्प है और इस जनता-जनार्दन के लिए, इस संकल्प के लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध भी हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का यह चौदहवां बजट है। अब तक इन्होंने 1111 पेज पढ़े हैं और इसी पवित्र सदन में 3348 घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने की हैं। इतनी बड़ी घोषणाओं में जिस सदन को हम पवित्र मानते हैं, मैं केवल-केवल पहले बजट की उस घोषणा पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जिस बजट को हम एक पवित्र डाकूमेंट कहते हैं और उसे सालभर में पूरा करने की बात करते हैं, उस 1999 के पहले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि क्या राजस्थान फ्लोराइड मुक्त हो गया है? इसके साथ ही जयपुर को भिखारी मुक्त करने का, वर्ल्ड क्लास सिटी का संकल्प उन्होंने इसी सदन में लिया था, क्या वह पूरा हो गया है?

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी को जादूगर कहते हैं। जादूगर जी के आंकड़ों में कुछ समय के लिए तो लोगों को जादू नजर भी आता है और वे उस आंकड़ों के मायाजाल में रहते भी हैं। कल जब यहां सदन में घोषणाएं हो रही थीं तो मुझे तो पंक्तियां याद आ गयीं-

''कि वे बड़े सलीके से आंकड़ों की जोड़-तोड़ कर रहे थे,
मैं एतबार भी न करता तो और करता भी क्या।।''

सभापति महोदय, प्रतिवर्ष बजट को बढ़ाकर पेश करने का एक फैशन बन गया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज इस सदन में इस कार्यकाल का चौथा बजट है, उसमें दो ऐसे एक्चुअल्स हमारे सामने हैं जिन एक्चुअल्स के आधार पर 2019-20, 2020-21 की कि सरकार का ट्रैक रिकार्ड क्या है और अभी तक के ट्रैक रिकार्ड के अनुसार सरकार की घोषणाओं पर कितना अमल हो पायेगा।

सभापति महोदय, आपके सामने 2020-21 में जो जीएसडीपी में 11 प्रतिशत की काल्पनिक वृद्धि मानकर सरकार ने 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट पेश किया था उसका आज एक्चुअल आ गया है। वह काल्पनिक वृद्धि औंधे मुंह गिरी और करंट प्राइसेज पर माइनस फोर परसेंट की ग्रोथ है और वह माइनस में चली गयी और हमारी सारी जो घोषणाएं थीं, उनमें एक भी बड़ी घोषणा पूरी नहीं कर पाये, चाहे वह संविदाकर्मी की घोषणा हो या कोई भी घोषणा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की हो, चाहे नन्दीशाला के लिए आज जवाब देखने को मिल रहा था, चाहे और कोई विषय हो।

सभापति महोदय, जो 2019-20 के आंकड़े हैं वह आपके सामने एक बार रखना चाहूंगा। 2020-21 का एक्चुअल्स कल मुख्य मंत्री जी ने पेश किया। आपको राजस्व जुटाना था वह 77 हजार 29 करोड़ का लक्ष्य रखा था और आप केवल 60 हजार 284 करोड़ का राजस्व जुटा पाये यानी आपकी खुद की घोषणा से 22 प्रतिशत कम आप आन टैक्स कलेक्ट कर पाये। इसी प्रकार से जीएसटी में आप 28 हजार की जगह 20 हजार, 28 प्रतिशत कम, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में आपने 5600 की जगह 5200 माइनस 7 परसेंट, सेल्स टैक्स में 12 हजार की

(श्री अशोक लाहोटी)

जगह 9 हजार माइनस 17 परसेंट, एक्साइज में 21 हजार की जगह 17 हजार माइनस 16 परसेंट और जो अदर टैक्सेज थे उनमें 9161 की जगह 6619 माइनस 27 परसेंट कर पाये। सभापति महोदय, जब हमारा ट्रैक रिकार्ड कल आपने खुद ने सदन में यह पेश किया है कि आपके जितने भी रेवेन्यू सोर्सेज थे उन सब में 20 से लेकर 27 परसेंट की इन्कम कम प्राप्त की है तो फिर इस इन्कम में आप कैसे यह मानते हैं कि आपने कल जो इतनी घोषणाएं की हैं वे सारी आप पूरी कर पायेंगे?

सभापति महोदय, यही नहीं, इन घोषणाओं के बाद बजट में हम कुछ भी बोलें, यहां कौन काकाजी पूछ रहा है क्योंकि बोलने वाले आप हो और टेबल बजाने वालों की संख्या है। इस साल आप बी.ई. रखते हो, अगले साल आर.ई. लेकर आते हो और एक्चुअल तो तीसरे साल आयेगा तो तीसरे साल तक कोई पूछने वाला नहीं रहता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप 2020-21 में देखो तो 2020-21 का कोविड जहां दुनिया के लिए महामारी संकट था वह मैं आज इस सदन में आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि वह कोविड इस सरकार के लिए ब्लैसिंग-इन-डिस्गाइज बन गया। वह क्यों बन गया, क्योंकि उस कोविड के दौरान आपको केन्द्र सरकार ने एफआरबीएम एक्ट में तीन प्रतिशत की जगह पांच प्लस वन, छह प्रतिशत तक लोन लेने की आपको छूट दी। उस छूट के कारण जो आप तनख्वाह नहीं बांट पा रहे थे वह तनख्वाह बांटने के लिए आपने पैसा उस लोन की छूट से प्राप्त किया और सरकार ने यहां पर तनख्वाह बांटी। यह मैं आपको आंकड़े भी दे रहा हूं।

सभापति महोदय, 2020-21 में आपने टोटल रेवेन्यू थी वह 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ रुपये मानी थी और आप लाये कितनी? 23 प्रतिशत कम, 1 लाख 34 हजार करोड़ मात्र। यहां तक तो ठीक है। यहां के बाद में जब आपको तनख्वाह, ब्याज और पेंशन देना था....(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा किसी का भी। प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अब यह देखें कि तनख्वाह, ब्याज और पेंशन इस सरकार का 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये है। (व्यवधान) सभापति महोदय, जिस सरकार की इन्कम 1 लाख 34 हजार करोड़ हो और जिस सरकार का पेंशन और ब्याज, तनख्वाह पर खर्च 1 लाख 78 हजार करोड़ हो, यानी 44 हजार करोड़ रुपये आपको केवल तनख्वाह और ब्याज, पेंशन के लिए लोन लेना पड़ा और वह सरकार यहां घोषणाएं कर रही है। किस आधार पर

(श्री अशोक लाहोटी)

आप घोषणाएं पूरी कर रहे हो? आप यह बताते कि हमारी टोटल इन्कम से 44 हजार करोड़ रुपये ही हमारा लोस है और केन्द्र सरकार ने हमको छूट दी, हमने लोन लिया पर वह आपने यहां नहीं कहा। आप बजट में केन्द्र सरकार को पानी पी-पीकर कोसते हो पर आप यह भूल गये कि आपकी सरकार की स्थिति राजस्थान नगरपालिका की तरह है। आप केवल और केवल केन्द्र सरकार के अनुदान और अंश पर ही चल रहे हो, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। यह मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि एफआरबीएम की छूट के बाद भी आपको केन्द्र सरकार ने जीएसटी और सेंट्रल ग्रांट, अनुदान में 35 हजार और 24 हजार करोड़ यानी 60 हजार करोड़ रुपये आपको उस वर्ष और दिये हैं। यह सारा देने के बाद में, सभापति महोदय, आप 2021-22 का देखो जिसका आपने इस बार आर.ई. पेश किया है पर आप आर.ई. में यह तो बताते, तो आर.ई. के साथ-साथ दिसम्बर तक का तो एक्चुअल आ ही गया था, वह तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में भी है तो सदन को भी आप बता देते। आर.ई. में आपने क्या कहा? 2021-22 में तो कमाल कर दिया सरकार ने। कमाल इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में हमारी साइज के जितने स्टेट हैं, चाहे हम आन्ध्र प्रदेश देखें तो उसका बजट 2 लाख 29 हजार करोड़ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यहां तक आवाज आ रही है। प्लीज साइलेंस।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सदस्य, कृपया सहयोग करें। आप सभी अपने-अपने स्थानों पर जाएं और वार्ता चलने दें। सहयोग करें आप लोग।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप मध्य प्रदेश देखो तो 2 लाख 34 हजार करोड़, कर्नाटक 2 लाख 46 हजार करोड़, गुजरात 2 लाख 23 हजार करोड़, तेलंगाना 2 लाख 30 हजार करोड़, बिहार 2 लाख 18 हजार करोड़, इन सब स्टेट से हमारा आंकड़ा कहीं ज्यादा है। हमने क्या किया? हमने जीएसडीपी पर 25 प्रतिशत की काल्पनिक ग्रोथ, ओवर आप्टिमिस्ट बजट पेश किया और 2 लाख 50 हजार करोड़ का एक जम्बो बजट राजस्थान में पेश करके हम यह तो दिखा पाये कि राजस्थान दुनिया में सबसे बड़े बजट वाला, इस साइज के मिडकैप में हम सबसे बड़े स्टेट बन गये लेकिन हुआ क्या? आपकी सारी थोथी घोषणाएं औंधे मुंह पड़ीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो करंट प्राइसेज आपने

(श्री अशोक लाहोटी)

25 परसेंट काल्पनिक मानी थीं वे मात्र 11 परसेंट पर आ गईं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने खुद ने माना है कि वह केवल 11.6 परसेंट पर आ गई। उसका कारण क्या हुआ उसमें आप यह टेबल देखो कि 2020-21 में आपने माना था कि हम 90 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यु कलेक्ट करेंगे आन टैक्सेज से पर आपका दिसम्बर तक आया है मात्र 53 हजार करोड़ रुपये, मैं एक्चुअल बोल रहा हूं, आप तो आर.ई. बता रहे हो। मैं दिसम्बर तक का एक्चुअल बता रहा हूं, सभापति महोदय। 53 हजार करोड़ मात्र यानी केवल 58 प्रतिशत। आपने इस बार कितना माना है? 98 हजार करोड़। माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी बतायें कि इसको लाने का कौनसा तरीका है?

इस प्रकार आपने सब चीजों में, आपने जीएसटी में 37 हजार करोड़ माना, आपका अभी दिसम्बर तक आया है मात्र 19 हजार करोड़। स्टाम्प और रजिस्ट्री में आपने 6100 करोड़ माना है और आपका आया है 4500 करोड़, केवल 75 परसेंट। सेल्स टैक्स में आपने 13 हजार माना है, आया है 66 परसेंट 8,700 करोड़। एक्साइज में आपने 22,800 माना है और आपके 15,700 आया है, केवल 69 परसेंट और अदर शुल्क में टोटल यदि हम मिला लें तो आपके केवल 4,508 करोड़ आया है यानी केवल 46 परसेंट दिसम्बर तक आप लाये हो।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का तो आपने कभी आभार नहीं कहा। मैं सरकार के लोगों से कहूंगा कि आपने आभार तो कभी केन्द्र सरकार का नहीं कहा पर आपने खुद ने अपने आंकड़ों में कहा है कि सेंट्रल टैक्सेज में जो आपने 2021-22 की बी.ई. में 40 हजार करोड़ माना था कि केन्द्र हमको 40 हजार करोड़ देगा, उसमें आपको केन्द्र ने दिया कितना? 44 हजार करोड़ रुपये। फिर आपने 2022-23 में 49 हजार करोड़, पिछली बार 12 प्रतिशत ज्यादा और इस बार उससे भी 10 परसेंट ज्यादा, यानी आपको 22 परसेंट की ग्रोथ सेंटर दे रहा है। इसके साथ-साथ आपने सेंट्रल ग्रांट, जो सेंटर आपको एड दे रहा है, जो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दे रहा है वह आपने केवल 36 हजार करोड़ रुपये माने थे और आपको सेंटर ने कितना दिया? आपने एफआरबीएम की किताब में लिखा है कि आपको 43,290 करोड़ रुपये दिया है, 19 परसेंट ज्यादा ग्रांट दी है आपको। इसके अलावा आपने माना कि हमको 2022-23 में 45 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, उसमें भी हम आपको 9 परसेंट बढ़ाकर दे रहे हैं, यानी सब कुछ आप सेंटर के भरोसे। सभापति महोदय, मैं

(श्री अशोक लाहोटी)

सत्ता पक्ष को निवेदन करूंगा कि इतना तो सच बोलें, माननीय नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य महोदय सुनें।

"इतना तो सच बोलें कि होठों का तबस्सुम न बुझे,

इतनी रोशनी भी खत्म न करें, आगे भी अंधेरा होगा।"

आपको आगे भी एड लेनी पड़ेगी, आपको आगे भी सेंटर से मदद लेनी पड़ेगी, आपको आगे भी स्टेट चलाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आप स्वयं देखो कि इनकी बुक्स में क्या लिखा है और ये कर क्या रहे हैं। 2021-22 के आपके स्वयं का कर राजस्व आपने बी.ई. में जो मैंने कहा कि आपने 90 हजार माना, फिर आपने आर.ई. में उसको खुद ने घटा दिया कि हम 90 नहीं ला पायेंगे, हम 82 हजार ही ला पायेंगे। यानी अब मार्च में आप कह रहे हो कि हम 82 ला पायेंगे, 8 हजार करोड़ रुपये कम ला पायेंगे। फिर इस बार आपने आंकड़ों में लिख दिया कि हम 98 हजार ले आयेंगे। एक तरफ आप कम रहे हो और एक तरफ खुद बढ़ा रहे हो, तो एक स्टैंड तो रखो कि आप ला पाओगे या नहीं ला पाओगे। यह आंकड़ों का मायाजाल क्योंकि केवल एफआरबीएम सैट हो जाये और आप डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं आ पाओ। सभापति महोदय, जबकि दिसम्बर तक सरकार मात्र 53 हजार करोड़ रुपये ही ला पायी है।

(समय: 13.00 बजे)

अब आप 53 हजार करोड़ रुपये, इन ढाई महीनों में 98 हजार करोड़ कर देंगे। ये कौनसा जादू है। ये आपकी घोषणाएं औंधे मुंह गिरेंगी। आज आपको मैं सदन में कह रहा हूं। 2022-23 में आपने फिर ये घोषणाएं कीं और कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे ज्यादा छूट दी हैं स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में। अब स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में एक तरफ तो आपने छूट की अम्बार लगा दी। आपने दो-दो, तीन-तीन पेज तक लगातार छूट दी और आपने यहां क्या लिखा है? पिछले वर्ष आपने कहा, हम 6,100 करोड़ रुपये लायेंगे। आप अभी तक लाये कितने हो, मात्र 4 हजार 579 करोड़ रुपये और आप 2022-23 में कह रहे हो, सारी छूट देने के बाद हम 8 हजार 100 करोड़ रुपये लेकर आयेंगे। सभापति महोदय, या तो यह किताब असत्य बोल रही है या इनकी घोषणाएं असत्य हैं या फिर ये आंकड़े असत्य हैं। जब आप खुद कह रहे हो कि हम छूट ज्यादा दे रहे हैं और पिछली बार अभी तक केवल 46 परसेंट ला पाये हैं और अगली बार आप कह रहे हो, हम 8 हजार 100 करोड़ ले

(श्री अशोक लाहोटी)

आयेंगे। केवल इसलिए कि आंकड़े असत्य लिख दो, एक्चुअल आयेगा जब तक सरकार चली जायेगी और आप इधर आ जाओगे विपक्ष में।

सभापति महोदय, जब आपकी घोषणाएं हैं तो मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि इन घोषणाओं से छूट देने की इनकम कैसे बढ़ेगी, इसलिए राजस्थान का बच्चा यह कह रहा है। माननीय, ईमानदारी से जाकर पूछो कि यह बजट है कि नाथी का बाड़ा है। आप जाकर ईमानदारी से पूछो। यह राजस्थान का बच्चा-बच्चा कह रहा है। सभापति महोदय, सदन में ईमानदारी की बात करें।

श्री सभापति: शान्त रहें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, आपने सही कहा नाथी के बाड़ा में, जो मांगोगे वो मिलेगा। हमारा बजट ऐसा ही है। जिसने जो मांगा है, वह मिला है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो आप यह मान रहे हो। यह बजट नहीं है, नाथी का बाड़ा है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बिलकुल मानते हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। नाथी का बाड़ा है, बजट नहीं है। सभापति महोदय, हम सदन में ईमानदारी से बात करें कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है?

श्री सभापति: नाथी के बाड़े के लिए पांच दिन हवाले हो गये अब तो माफ करें सदन को। पांच दिन तो नाथी के बाड़े में चले गये, बाकी का तो सदन को दें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, आपने जो आदेश किया। सभापति महोदय, सरकार कह रही है 2021-22 की आरई में, प्रदेश पर आज कुल कितना ऋण है। आप नई घोषणाएं कर रहे हो, लोन लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं बची। आप यह नहीं बता रहे हो कि हमारी लोन लेने की छूट खतम हो गयी। आज सरकार पर 4 लाख 72 हजार 843 करोड़ रुपये आपने आरई में माना है, इतना लोन है। इसके बाद में आपने जो एक आंकड़ा छिपाया, डिस्काम का आडिट कहां जायेगा?

सभापति महोदय, डिस्काम और हमारे जो अन्य कारपोरेशन हैं, उनके आडिट में आप दिसम्बर में देखें। उसमें 82 हजार 661 करोड़ रुपये का लोन

(श्री अशोक लाहोटी)

है। यानी, कुल मिलाकर यदि आज प्रदेश पर देखें तो 5 लाख 55 हजार 504 करोड़ रुपये का आपका लोन है। यह आपका स्टेट फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट है।

आज मैं कह सकता हूं कि स्टेट फाइनेंशियल पैरालाइज हो चुका है। प्रदेश में प्रति वर्ष 22 प्रतिशत की दर से कर्जा बढ़ा रहे हो, 22 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष कर्ज बढ़ा है। यह आजादी के बाद पहली बार इन चार सालों में हुआ है कि प्रतिवर्ष 22 प्रतिशत की दर से कर्जा बढ़ा हो, वरना इतना कर्जा आपकी खुद की पिछली सरकारों में नहीं बढ़ा।

सभापति महोदय, इसमें भी यदि जनता का विकास, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो हम विपक्ष आपको सर्वसम्मति से यह कहेंगे कि आप कर्ज लेकर घी पीयो, लेकिन जनता का तो विकास करो। आज राजस्थान की आम जनता को इस बात से क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? उनको अपने एक्चुअल विकास से मतलब है। आप ब्याज, तनख्वाह, पेंशन में क्या बांट रहे हों, कोई लेना-देना नहीं है। राजस्थान की आम अवाम साढ़े सात करोड़ की जनता हमसे यह पूछ रही है कि हमारे सड़क, बिजली, पानी और नाली में कितना खर्चा हुआ है, उसका हिसाब सरकार दे।

सभापति महोदय, आज उसको यदि सरकार देखे तो आपको और हमको सबको शर्म आ जायेगी। मैं आपके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं जिससे जनता को लेना-देना है। आज 2020-21 में आपने खुद ने माना, 2 लाख 25 हजार करोड़ के बजट में मात्र 22 हजार करोड़ रुपये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे। उसमें भी यह आंकड़ा देखकर थोड़ी तो शर्म करें, सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा निवेदन है, मात्र 14 हजार 988 करोड़ रुपये, मात्र 14 हजार। यानी, आपके बजट का केवल 6.6 परसेंट।

सभापति महोदय, तीन सालों में एक बार भी 2020-21 को आप देख लें। दिसम्बर तक की एक्चुअल, आपने 2 लाख 50 हजार करोड़ के इतने भारी भरकम देश के सबसे बड़े बजट में आपने कहा, हम 26 हजार करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन आप कितना खर्च कर पाये दिसम्बर तक, मात्र 16 हजार करोड़ रुपये मात्र, मात्र 16 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता पर, ईमानदारी से अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में आप और हम सब चलें कि राजस्थान की जनता क्या कहती है। हमने अपने बजट का केवल साढ़े 6 परसेंट, हमने अपने बजट का 92 परसेंट, आपने तो

(श्री अशोक लाहोटी)

65 परसेंट लिखा है। मैंने आपको आंकड़ा दिया है, 92 परसेंट बजट का आपने केवल पेंशन और तनख्वाह में बांटा है और जनता के विकास पर केवल साढ़े 6 परसेंट।

सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर में आपको एक-एक सेक्टर का भी दूंगा कि आपने एक-एक सेक्टर में क्या किया, एक-एक सेक्टर में कितना खर्चा किया है। यानी, इतने बड़े बजट में भी हमने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया है?

सभापति महोदय, 2022-23 के बजट में आप देखें, जो कल इन्होंने पेश किया है। आप खुद कह रहे हो कि हम 2021-22 की आरई में 82 हजार करोड़ लायेंगे और 2022-23 में 98 हजार करोड़ लायेंगे। चलो, आपकी बात पूरी मान ली तो कितने लाये आप? 16 हजार करोड़ रुपये आप एक्स्ट्रा लेकर आये, बिलकुल अक्षरश: आपकी बात मान ली, सेन्ट्रल का भी हमने आपको बताया कि 49 हजार करोड़ रुपये और 45 हजार करोड़, यानी 7 हजार करोड़ रुपये आपकी अपेक्षा से ज्यादा केन्द्र सरकार आपको देगी। ये भी आप जोड़ लें, लेकिन यह तो देखो की आपकी सैलरी, पेंशन सब जोड़ने के बाद केवल सैलरी और पेंशन देने के लिए भी आपको 23 हजार करोड़ रुपये कम पड़ रहे हैं। ये आप खुद भी मान रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद मान रहे हैं कि 23 हजार करोड़ रुपये हमारे पास कम पड़ेंगे।

सभापति महोदय, लेकिन मूल बात यह है, जो मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में दें कि आपकी एफआरबीएम की पिछले साल तो 6 परसेंट छूट थी। इस बार उसको कम करके 5 परसेंट कर दी। यानी, आपने यह भी लिखा है कि हम 72 हजार करोड़ रुपये लोन चुकायेंगे, 23 हजार करोड़ रुपये आपके पास कम पड़ रहे हैं, 72 हजार करोड़ का लोन चुकाओगे तो मुख्य मंत्री जी यह बतायें कि एक लाख करोड़ रुपया आप लाओगे कहां से? लोन लेने की छूट आपको मिल नहीं रही है, वह तो आपको कम करना पड़ रहा है, एफआरबीएम 5 परसेंट पर आ जायेगा 6 की जगह तो फिर ये 1 लाख करोड़ रुपये आप कहां से लाओगे?

जो अभी हमारे हवामहल से आने वाले माननीय बड़े भाई कह रहे थे कि यह नाथी का बाड़ा है। हम सब ले आयेंगे तो मैं आपको यहां चैलेंज कर रहा हूं कि अगले साल इसी नाथी के बाड़े में, जिसको आप कह रहे हो, हम तो इसको पवित्र सदन मानते हैं, आप ये 1 लाख करोड़ रुपये लाओगे। ये चीज

(श्री अशोक लाहोटी)

आप इस सदन में साबित कर देना। हम सब विपक्ष के सदस्य आपको मान जायेंगे।

सभापति महोदय, ये असत्य के आंकड़े हैं, इसलिए चलने वाले नहीं हैं। जादुई आंकड़े भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जादू थोड़ी देर तो टिकता है, यह तो वो भी नहीं टिक रहा। सभापति महोदय, अब जो मूल बात मैं कहना चाह रहा था। राजस्थान में बड़े जोर-शोर से प्रचारित किया गया कि इस बार किसानों का बजट आएगा। राजस्थान के भोले-भाले किसान। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा अपने-अपने स्थान पर जायें। सदन में इस तरह से आप आवाजें करेंगे तो कैसे, प्लीज-प्लीज सहयोग करें, प्लीज अपने-अपने स्थान पर जायें। कोई गम्भीरता नहीं है। आपस में वार्ता नहीं करेंगे, प्लीज सहयोग करें। श्री लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था बड़े जोर-शोर से प्रचारित किया गया किसान का बजट आयेगा। राजस्थान का किसान गांव-गांव में इंतजार कर रहा था। हमारे मन में एक कल्पना थी कि रेलवे के बजट की तरह यहां एग्रीकल्चर का भी अलग से बजट आयेगा। इस कल्पना में मुझे तो जयपुर के टेलर ने बताया कि कृषि मंत्री जी ने अपनी जैकेट भी नई सिलवा ली है, पर हुआ क्या? वह जैकेट भी पड़ी रह गयी। खैर, यह आपका विषय है।

सभापति महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं केवल बजट में चार पन्ने किसानों के नाम पर जोड़ने से राजस्थान के किसानों का भला हो रहा है क्या? ये आप अपनी अन्तर आत्मा से पूछकर देख लो। जो किसानों की आपने घोषणाएं कीं, केन्द्र सरकार के उन सारे मदों को आपने राजस्थान की विधान सभा में पढ़ दिया। चलो, उनको भी आप अपने सक्षम स्तर पर पूरा कर लेंगे तो भी हम आपको मान जायेंगे।

सभापति महोदय, आज सत्ता पक्ष ईमानदारी से बता दे। ये घोषणाएं वैसी ही थीं जैसे एक से दस तक की गिनती थी। किसान का कर्ज माफ हुआ? 24 घण्टे बिजली किसानों को मिल रही है क्या? आज दिन में सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है क्या?

सभापति महोदय, ज्यादा घोषणाओं पर न जाकर मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यहां सारे सदस्य बैठे हैं। मेरी विधान सभा में तो ग्रामीण का थोड़ासा हिस्सा आता है, इनके ज्यादा आता है। आज पशुओं के लिए चारा कितने रुपये

(श्री अशोक लाहोटी)

किलो है? ईमानदारी से बता दें। जो हमारी सरकार के समय 3 रुपये किलो, 300 रुपये टन मिलता था, आज 1,500 रुपये टन मिल रहा है, 15 रुपये किलो। ये मैं असत्य बोल रहा हूं तो ईमानदारी से कह दें अपनी विधान सभा में जाकर पूछ लें। आज आपका बाटा क्या भाव मिल रहा है? कोई पशु पाल सकता है क्या? बाटा मिल रहा है, 18 से 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो तक बांटा चला गया, जो हमारे समय में 18-20 रुपये किलो से मिलता था। आज ईमानदारी से जाकर पूछ लो और आप दूध के कितने पैसे दे रहे हो? आप दे रहे हो दूध के 7 रुपये फैट, जो हमारी सरकार में, वसुन्धरा जी के समय 10 रुपये फैट मिलता था। और उन्हें बोनस अंक भी देते थे। आपने बोनस अंक बंद कर दिए और आज सात रुपये फैट में मिल रहा है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप पर मुझे विश्वास है कि आप अन्तरआत्मा से बोलोगे, ईमानदारी से बोलना आप इस बात को। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज शान्ति रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो जिस किसान की बजट की बात की, उन किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का राजस्थान की जो जीएसडीपी है, उसमें 30 प्रतिशत योगदान है। आपने पहले पन्ने पर लिखा है। आपने बजट एट ए ग्लांस और व्यापक बजट वाले में लिखा है 30 प्रतिशत किसानों का योगदान है पर आपने किसानों के लिए बजट कितना दिया है, 4.62 प्रतिशत यानी 78 लाख किसानों के लिए 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की घोषणाएं कीं। मैं सारे बारह सेक्टर बताऊंगा। केवल एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड ऐसा सेक्टर है जिसमें बजट दस रुपये कम हुआ है। मैं यहां पढ़कर बताऊंगा। यदि इस किसान बजट की ऐसी दुर्गति करनी थी तो या तो उस अधिकारी को पकड़ो जिन्होंने आज मुख्य मंत्री जी की इस सदन में ऐसी दुर्गति करवायी कि दस रुपये कम कर दिया। आप एक रुपया ही बढ़ा देते अगर आपके पास नहीं था तो, कम से कम किसानों का मान-सम्मान रहता। दस रुपये किसान के बजट में कम किये आपने, अभी मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से आप देखो सरकार के सबसे बड़े संकटमोचक शहरी मंत्री जी अभी हैं नहीं, उनका सेक्टर अलग से अपन बात कर लेंगे।

सभापति महोदय, पूरे बजट में देखो तो लोग केवल गांव और शहर दो ही जगह रहते हैं। आज किसानों के बजट में आपने दस रुपये कम कर दिए

(श्री अशोक लाहोटी)

और शहर के बजट में पूरी आप इंडेक्स देखो बारह सेक्टर में बजट जो बंटा हुआ है, उस इंडेक्स में (-)21% यानी शहरी मंत्री जी जो इस सदन के हम तो यह मानते थे कि सबसे भारी भरकम मंत्री हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रोंग मंत्री हैं। पूरी सरकार के संकटमोचक बने हुए हैं उनका तो बहुत भारी भरकम बजट होगा। आप यह देखो कि 2021-22 की आर.ई. में 11 हजार 44 करोड़ था और 2022-23 के बजट में आपको घटाकर 8 हजार 728 करोड़ रुपये कर दिया, यानी 21 प्रतिशत कम। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान के शहरी विधान सभा क्षेत्रों में न झाड़ू लग रही है, न कचरा उठ रहा है, न नाली बन रही है, न सड़क बन रही है, न पीने का पानी मिल रहा है, न सीवरेज डल रही है। लोग नरक में जीवन जी रहे हैं।

सभापति महोदय, ...(व्यवधान) आपके तो जिला बना नहीं, आप तो आराम करो अभी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया, कृपया सहयोग करें। बैठे-बैठे प्लीज, आपस में वार्ता नहीं। आप इन्वाइट करते हो उनको बार-बार में।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात इसलिये कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ मुखातिब हों।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से मैं तो निवदेन करूंगा कि हम राजस्थान के भोले-भाले लोग हैं। आप कभी कान इधर से पकड़ो कभी उधर पकड़ो, हम गांव के लोग हैं। हमको तो आप क्या घोषणा कर रहे हो सीधी-सीधी बता दो। मैं आज इस सदन में विपक्ष के नाते भी मुख्य मंत्री जी को एक सलाह दे रहा हूं। वैसे उनके पास नवरत्न सलाहकार हैं पर उनको कोई दर्जे-वर्जे का चक्कर पड़ गया कैबिनेट का तो हो सकता है इसलिए नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं आपने 50 यूनिट की छूट दी, आपने छूट में कई तरह की छूट देने के बाद में विद्युत सैस लगाया, यह किया, सीवरेज सैस, पेट्रोल सैस, टी एंड डी लोस, अडानी सैस आप इतना घुमा-फिराकर छूट क्यों दे रहे हो, सौ यूनिट पर इतने रुपये, तीन सौ यूनिट पर इतने रुपये, फिर गणित करो, फिर केलकुलेशन करो तो फिर ऊक-चूक होगी। आप तो केवल एक छूट दे दो। आप तो यह कह दो कि राजस्थान में दो साल के कोरोना की महामारी में राजस्थान की आम जनता के लिए हम दो साल का बिजली का बिल माफ करते हैं और आगे का

(श्री अशोक लाहोटी)

आप यह जो सैस और टैक्स जितना ले रहे हो, मूल जितनी यूनिट बिजली कंजम्पशन की उतना पर यूनिट पैसा ले लो। आप कभी बिल दो महीने का, कभी एक महीने का करते हो। आज सबसे सस्ती बिजली पूरी दुनिया में 2 रुपये 74 पैसे में पैदा हो रही है और सबसे महंगी बिजली ऊपर में 29 रुपये प्रति यूनिट तक की बिलिंग हुई है। मैं बिल की कापी टेबल कर दूंगा। यह हाल है राजस्थान की जनता का।

सभापति महोदय, मैं सबसे बड़ा एक फिगर आपके सामने रख रहा हूं। मुख्य मंत्री जी, आप यदि ईमानदारी से किसानों के संकटमोचक हो तो मैं बहुत छोटी सी मांग राजस्थान के किसानों की तरफ से कर रहा हूं क्योंकि जब अगला चुनाव आयेगा तो आपकी पार्टी भी और हमारी पार्टी भी दोनों ही उस समय दो यूनिट फ्री, तीन सौ यूनिट फ्री घोषणा करेंगे और जनता मानेगी नहीं। वह चुनाव की घोषणा होगी। यदि घोषणा ही करनी है तो आज करो जिसे जनता माने। दो साल बाद आप चुनाव में जाओगे तब घोषणा करोगे। आप पंजाब में कर रहे हो, दूसरी जगह कर रहे हो, आज राजस्थान में आपके पास मौका है और केवल आज राजस्थान में एग्रीकल्चर का यदि मैं फिगर आपको दूं तो राजस्थान में डिस्कोमवाइज 15 लाख 62 हजार 914 एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं कुल उन एग्रीकल्चर कनेक्शनों में टोटल 5 करोड़ 16 लाख यूनिट किसानों को सोल्ड हो रही है। उसकी आपकी बिलिंग बन रही है 3,243 करोड़ की। उसमें सभापति महोदय, आप पहले से ही बारह हजार रुपये प्रति साल की जो सब्सिडी दे रहे हो उसमें आप तीन हजार करोड़ की सब्सिडी पहले से ही दे रहे हो 2,953 करोड़ की यानी पर मंथ आपके ऊपर जो मंथली रियलाइजेशन आ रहा है, वह आ रहा है मात्र 212 करोड़ रुपये।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, बस पांच मिनट और लूंगा। वह 212 करोड़ रुपये आ रहा है यानी आप पूरे साल भर में इतनी बड़ी घोषणा में एक लाख करोड़ में केवल दो हजार करोड़ की व्यवस्था कर दें तो राजस्थान के किसानों की पूर्ण बिजली माफ हो जाएगी। यह मैं इस सदन में कह रहा हूं और हम विपक्ष की तरफ से आपको समर्थन देंगे।

सभापति महोदय, आज यह देखो कि इन सारी घोषणाओं में हमने कैपिटल पर क्या दिया। आज हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपने 3,116 करोड़ रुपये, यानी पूरे 2 लाख 94 हजार करोड़ रुपये के बजट में केवल आप

(श्री अशोक लाहोटी)

1.06% विकास के लिए खर्च कर रहे हो कैपिटल एक्सपंडीचर पूरे हैल्थ और इसमें। आप कितने ही आंकड़े दो।

इसके अलावा आप एजुकेशन में देखें। एजुकेशन में आपने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में आपने कहा कि 1 हजार कमरे बनायेंगे, ये बनायेंगे, कहां से बनाओगे? आपने केवल 1,881 करोड़ रुपये पूरे प्रोविजन में रखे हैं 0.63%। इस प्रकार आपने वेलफेयर एंड सेनिटेशन डवलपमेंट में रखे हैं केवल 1,831 करोड़ रुपये 0.62%। अरबन डवलपमेंट में इन्होंने रखे हैं केवल (-)21%।

सभापति महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की भी बात करूं मैं, अरबन डवलपमेंट में तो 600 से ज्यादा कालोनियां हैं जहां तीन साल से लोग सड़क, बिजली, नाली, पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। वेलफेयर आफ एससी/एसटी एंड ओबीसी में कैपिटल एक्सपंडीचर रखा है मात्र 0.11% 430 करोड़ रुपये। लेबर वेलफेयर में आप देखिये सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा, श्रमिकों के कल्याण के लिए कैपिटल एक्सपंडीचर जीरो रुपये रखा है। केवल आपकी तनख्वाह और उसमें आपने रखा है कैपिटल एक्सपंडीचर जीरो रुपये। यदि लेबर मंत्री जी बैठे हों तो इस पर संज्ञान भी लें। सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशंस में आपने कैपिटल एक्सपंडीचर रखा है 136 करोड़ मात्र 0.46%। इसी प्रकार आपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड में मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड में आपने बजट तो जीरो परसेंट बढ़ाया है लेकिन उसके साथ-साथ आपने कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केवल 0.28% 838 करोड़ रुपये ही आप लेकर आये हो।

सभापति महोदय, इस प्रकार इर्रिगेशन और फ्लड में आप देखें। आपने 2.2% अब तक सारे बजट में थोड़ा बहुत कहीं यदि है तो इर्रिगेशन मंत्री जी को कुछ 2.2% जनता की भलाई के लिए मिला केवल 2 प्रतिशत।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इस प्रकार से एनर्जी में आप लाये हो केवल 0.13% और इसी प्रकार आप देखो तो दुनिया भर के यदि हम नीति आयोग के आंकड़े देखें, सभापति महोदय, एक और चीज आप देखें। अभी सरकार ने एक अस्सी पेज की बुकलेट जारी की और उस बुकलेट का नाम क्या था, उसका नाम था सफलता की कहानियां। यह मैं लेकर आया हूं। इस सफलता की कहानियों में मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि क्या पता कैसी सफलताएं होंगी इस सरकार की। पहले पन्ने पर जो सफलताएं लिखी थीं,

(श्री अशोक लाहोटी)

मैं सदन में आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने लिखा सीकर जिले की मायादेवी को,..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमने दौसा जिले की मनीषा कुमारी का जन आधार कार्ड बनवा दिया।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): दौसा जिले की मनीषा कुमारी का जन आधार कार्ड बनवा दिया, यह आपने लिखा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें। प्लीज विराजिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है उसमें मुझे आपने अपने विचार रखने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने तीसरी बार के मुख्य मंत्री काल में इस बजट में भी जैसे कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद्, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी एवं समस्त प्रदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए यह मूर्त रूप देने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधन, दो वर्ष का कोरोना काल, पूर्व के तीन वर्षों में मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, इन तीनों वर्षों का जिस तरह से धरातल पर उतारने का काम हुआ, उन्होंने 85 परसेंट अपनी घोषणाओं को पूरा किया। यूपीए सरकार नरेगा योजना लाई। सभापति महोदय, यह नरेगा योजना गरीब के लिए वरदान बनी। जिस तरह से कोरोना में इस नरेगा योजना ने गरीब को सहारा दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ध्यान रखा, 100 दिन के इन्होंने 125 दिन किये। शहरी क्षेत्र में भी गरीब लोग रहते हैं, ठेले-रेहड़ी वाले, फल-सब्जी बेचने वाले, ढाबा-रेस्टोरेंट पर

(श्री बाबूलाल नागर)

काम करने वाले, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री जी को, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यूपीए सरकार जब यह नरेगा योजना लाई, शहर के लोगों की यह मांग रहा करती थी, शहर के गरीबों को रोजगार की आवश्यकता रहती है, मुख्य मंत्री जी ने उनका भी ध्यान रखा और शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की जो घोषणा की है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के खर्चे पर गांवों में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार नरेगा योजना में देना, राजस्थान के गरीब लोग कहा करते हैं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी राजस्थान के गरीबों के मसीहा हैं। सभापति महोदय, यह मुख्य मंत्री जी की उस गरीब के प्रति सोच को साबित करता है। कोरोना में स्कूलें, महाविद्यालय बंद रहे। उन्होंने तीन माह का ब्रिज कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की है। निश्चित रूप से कोरोना में बच्चों को शिक्षा में जो दिक्कत आई है, कमी आई है, वह इस ब्रिज कोर्स से निश्चित रूप से पूरी होगी।

मुख्य मंत्री जी ने बिजली के लिये, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास एक बल्ब रहता है, राजस्थान के 118 लाख घरेलू उपभोक्ता जो 100 यूनिट तक यूज करते हैं, सभापति महोदय, उनकी 50 यूनिट फ्री कर दी हैं। राजस्थान में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं, 50 यूनिट उनके बिजली आती है। उस गरीब को फ्री में बिजली देने का काम प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया है, सभापति महोदय, उस गरीब की दुआएं निकलेंगी। आज राजस्थान का गरीब जय-जयकार कर रहा है कि हम लोगों को मुख्य मंत्री जी ने घरेलू बिजली में भी सहायता दी है। इसी तरह 150 यूनिट तक तीन रुपये प्रति यूनिट का अनुदान दिया है। 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया है और 300 से अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट देने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है। 4,500 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक काम किया है।

मुख्य मंत्री जी पहली बार जब राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, पहले गरीब आदमी गम्भीर बीमारी में मकान, जमीन गिरवी रखता था। पहले कार्यकाल में ही बीपीएल नि:शुल्क योजना लेकर आये, राजस्थान के तमाम बीपीएल परिवारों का सारा इलाज सरकार कराती थी। जो लोग बीपीएल नहीं थे, गरीब लोग थे, उन लोगों की आवाज सुनी, मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन

(श्री बाबूलाल नागर)

लोगों का इलाज कराते थे। इस सदन में बार-बार कहा करते थे कि जो भी माननीय विधायक मुझे पत्र लिखता है, उन सबका मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि गरीबों के लिये, बीमार व्यक्तियों के लिये कौन विधायक कितने ज्यादा पत्र लिखता है। मुख्य मंत्री जी की वह सोच, नीरोगी राजस्थान का संकल्प था। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, 2011, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लेकर आये। निःशुल्क जांच योजना लेकर आये। अब मुख्य मंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के आम आदमी को यह एतबार हो गया है कि कितना ही गम्भीर से गम्भीर बीमार हो, कितनी ही असाध्य बीमारी से ग्रसित हो, आज प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने उसको गारंटी दे दी, पांच लाख तक का इलाज पहले चला आ रहा था, आज 10 लाख तक की उन्होंने इसमें घोषणा की है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी ने हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हैल्थ के मामले में राजस्थान को अग्रणी राज्य कर दिया। आज Cochlear Implant, Bone-marrow Transplant, Organ Transplant, Blood/Platelets/Plasma सभी तरह की असाध्य बीमारियों को मुख्य मंत्री जी ने इसमें शामिल किया है। सभापति महोदय, बहुत से लोगों के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है, कई बार परेशानी आ जाती है। मुख्य मंत्री जी ने सुनिश्चितता कर दी, राजस्थान के कलेक्टर्स को डाइरेक्शन दे दिये कि राजस्थान के किसी भी गरीब आदमी के पास अगर कार्ड भी नहीं है तो कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी है कि हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें उस गरीब आदमी का इलाज कराये, कार्ड बनाने की आवश्यकता है तो कार्ड बनाये।

सभापति महोदय, प्रदेश के जो असहाय, निराश्रित, वंचित लोग हैं, आज आसपास के राज्यों के लोग हमारे यहां इलाज कराने के लिये आते हैं। आज गुजरात जैसे राज्य के लोग राजस्थान में इलाज कराने के लिये आ जाते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया जहां सरकार की तरफ से उस गरीब का पूरा इलाज हो रहा है। पहले इनडोर, आउटडोर की बात चलती थी। मुख्य मंत्री जी ने इस बार फैसला करके चाहे आउटडोर पेशेंट हो, ओपीडी, इनडोर हो, सबको पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, गरीब की दुआओं में भगवान का आशीर्वाद रहता है। यही तो कारण है इस राजस्थान के जननायक को तीसरी बार राजस्थान की जनता ने मुख्य मंत्री बनाया है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, गरीब की दुआओं में भगवान का आशीर्वाद साथ रहता है। बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता है, कई लापरवाह होते हैं। मुख्य मंत्री जी ने उनकी भी सुध ली है। मुख्य मंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर सरकार की तरफ से फ्री हो रहा है। मैं समझता हूं कि कोई गरीब आदमी दुर्घटना में ग्रसित हो गया, अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होती है। कई बार लापरवाही की वजह से एफआईआर लिखवाने में गड़बड़ी हो जाती है, तथ्य सही नहीं लिख पाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने उसके परिवार की भी सुध ले ली। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो परिवार है, उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी ने आसरा दे दिया कि सरकार की तरफ से पांच लाख रुपये का बीमा कवर किया है।

सभापति महोदय, प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जो 15 मेडिकल कालेज खोलने का जो निर्णय किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिला मुख्यालयों पर पहले से ही 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय चल रहे हैं, सात में प्रगतिरत है। बाकी 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय नहीं थे। इस कोरोना ने नर्सिंग स्टाफ की याद दिला दी। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 18 जिले बच गये थे, उनमें भी नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया है।

सभापति महोदय, एसएमएस मेडिकल कालेज में जयपुर में नये पांच विभाग स्थापित किये जा रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कालेज पूरी दुनिया का बेहतरीन मेडिकल कालेज है। उसमें रोबोटिक सर्जरी एवं मोड्यूलर आपरेशन थिएटर्स की व्यवस्था की है। जयपुर में महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल और राज्य कैंसर संस्थान में विकास के कार्य करवाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में ढाई सौ करोड़ रुपयों की लागत से नये मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। सभापति महोदय, चिकित्सा सेवाओं में मुख्य मंत्री जी ने आजादी के बाद इतनी चिकित्सा संस्थायें खोली हैं, उप जिला अस्पताल बनाये हैं, सीएससी खोली हैं, केवल खोलने का काम ही नहीं, एक तरफ डाक्टरों की बड़ी संख्या में भर्ती हुई और हो रही है तो दूसरी तरफ, इनके विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है। जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी, भवन निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था मुख्य मंत्री जी ने की है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन तीन वर्षों में वह हुआ जो 70 सालों में नहीं हो पाया था। तीन वर्षों में दो-दो उप जिला अस्पताल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खोले हैं, फागी में उप जिला अस्पताल खोला है। आज 26-27 डाक्टर्स दूदू में हैं। 18-20 डाक्टर्स फागी अस्पताल में हैं और अब 600 करोड़ की इन्होंने व्यवस्था कर दी है। मैं मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि दोनों जगहों पर अभी भवन बनाने हैं, इसलिए दूदू और फागी दोनों उप जिला अस्पतालों में भवन निर्माण के लिए पैसा देंगे।

सभापति महोदय, सीएचसी भी खोली है, पीएचसी भी खोली है और बहुत बड़ी संख्या में खोले हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे यहां पर एक मण्डोर पीएचसी है, वह बहुत पुरानी पीएचसी है। उसके आसपास हास्पिटल नहीं है। वह सीएससी होनी चाहिए। मेरे यहां साखून में करीब चालीस साल से पीएचसी है, मुझे उम्मीद थी और मैंने निवेदन भी किया था कि इस साखून को सीएचसी करना है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह 40 साल पुरानी पीएचसी है, शायद मेरे पूरे क्षेत्र में सबसे पुरानी पीएचसी है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरे यहां से साखून को सीएचसी करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, कई बार कैंसर की जानकारी तब होती है जब वह थर्ड फेज में आ जाता है। 18-20 साल के जवान बच्चे, नौजवानों की कैंसर से डैथ होती है। जब उनको जानकारी होती है, उससे पहले तो थर्ड फेज में चले जाते हैं। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल कैंसर डाइग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि इससे राजस्थान के ऐसे हजारों नौजवान जो कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, अगर समय से पहले डाइग्नोस्टिक हो जाएगा, उसकी जांच हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि उनका समय पर इलाज हो जाएगा। समय पर इलाज हो जाएगा तो नौजवानों की कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि जब मैं बैठने जाता हूं, तब देखता हूं कि जवान-जवान बच्चे कैंसर ग्रसित हो जाते हैं।

सभापति महोदय, 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' मुख्य मंत्री जी का प्रदेश की जनता से एक कमिटमेंट है। जब-जब सरकार में आये, इन्होंने पूरा

(श्री बाबूलाल नागर)

प्रयास किया। सभापति महोदय, इसमें मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' में जन-जाग्रति का कार्य भी हाथ में लेना चाहिए। हम कितनी ही जांच कर लें, अगर जनता में जाग्रति होगी तो मैं समझता हूं कि इस अभियान में हम ज्यादा कामयाब होंगे। पहले जब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे, उस समय में एक चल प्रयोगशाला लाये थे। उस चल प्रयोगशाला का राजस्थान की जनता में एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ था। हालांकि कानूनी दृष्टि से उस चल प्रयोगशाला का ज्यादा अस्तित्व नहीं था, लेकिन जहां कहीं भी वह जाती थी तो दो मिनट में ही बता देती थी कि इसमें गुणवत्ता है या नहीं है, कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। इससे आम आदमी में जाग्रति आती थी। उस जमाने में जो दुकानदार थे, जो परचूनी का सामान देते थे, खाने का सामान देते थे, उन तक में इतना भय हो जाता था कि वे मार्का वाला सामान लाते थे कि पता नहीं, कब चल प्रयोगशाला आ जाये तो एक वातावरण बनता है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी का कमिटमेंट है, इसमें जाग्रति पैदा करने के लिए कोई न कोई अभियान चलाकर इस 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' को कारगर बनाना चाहिए। अभी भी यह सफलता से चल रहा है, लेकिन और कारगर बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय, राज्य के समस्त सैकण्डरी विद्यालय, हमारे प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं। राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजस्थान में जितनी भी सैकण्डरी स्कूल हैं, आज आपको इस जन नायक को साधुवाद देना चाहिये कि उन्होंने इस सदन में घोषणा की। हमारी जो 3,820 सैकण्डरी स्कूल हैं, एक घोषणा में सीनियर सैकण्डरी किया है। आप तो जानते हैं और कई बार मुझे भी विधान सभा में आने का मौका मिला है, एक साल में एक-दो स्कूल मिलती थी। आज प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 3,820 जो हमारी सैकण्डरी स्कूल हैं, वे एक साथ हायर सैकण्डरी स्कूल बनेंगी। यह एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। इसी तरह से 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों में 1,200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की घोषणा की है। सभापति महोदय, यह इतना कामयाब प्रयोग हुआ है कि आज गरीब सपना देखने लग गया है कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकता है। बिना खर्च और पैसे के भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकता है। मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत ही कारगर कदम उठाया है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 1,200 स्कूल खोलने की बात की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसी तरह से हमारी जो बालिकाएं हैं, उनको घर के समीप शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो जाये, इसलिए माध्यमिक स्तर के 389 स्कूल, उच्च प्राथमिक स्तर के 1,846, प्राथमिक स्तर 115 विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा का संकल्प लेकर इस राजस्थान के तमाम बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा रहता है। शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। मुख्य मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, तीन वर्षों में 123 सरकारी महाविद्यालय खोले हैं। इस बार भी उन्होंने 19 बालिका महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 पंचायतें हैं, 4 ग्राम पंचायतें हैं। हमारे पास ही फुलेरा विधान सभा क्षेत्र है, उधर मेरा फागी उपखण्ड है। वहां पर एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र दूदू में एक कन्या महाविद्यालय खोलें। हमारे यहां अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ज्यादा हैं, गरीब लोग हैं। आज भी वहां के लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। को-एजुकेशन में बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। अगर हमारे यहां पर कन्या महाविद्यालय खुल जायेगा तो हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, उनको कम से कम कालेज स्तर की शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें।

अल्प आय वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग के लिए ठहरने के लिए दिल्ली में सुविधा दी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली में हमारे बच्चे कोचिंग करने के लिए जाते हैं। वहां पर रहने की बहुत परेशानी होती है। बहुत ही महंगा मामला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है। आज जिस तरह से पूरे हिन्दुस्तान में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका जो मुख्य मंत्री जी ने मौका दिया है। उन्होंने 500 बच्चों के लिए उदयपुर हाउस में Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre खोलने की घोषणा की है, वह बहुत ही काबिलए-तारीफ है। हमारे 500 बच्चों को वहां पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से सरकारी नौकरियां, मुख्य मंत्री जी बता

(श्री बाबूलाल नागर)

रहे थे तीन सालों में जितनी हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, उनमें करीब सवा दो लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। पिछली सरकार पांच साल में भी दो लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दे पायी थी। एक लाख सरकारी नौकरी देने की और घोषणा की है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक काम किया है, हमारे नौजवानों के लिए। नौजवानों में बहुत बड़ा आत्मबल पैदा करने का काम किया है हमारे मुख्य मंत्री जी ने। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारी उद्योग मंत्री जी बैठी हैं, 2019-20 में 11 औद्योगिक स्थान शुरू करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। 10 स्थानों पर काम चालू हो गया है, रीको का। एक मेरा बिचून भी था उसमें। जमीन के आबंटन के चक्कर में 2019-20 का, मेरे तो जितनी भी तीन साल में मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की, करीब 30-35 काम मेरे इन तीन सालों में हुए। टोटल काम हो गये। केवल एक काम बच गया जो बिचून में औद्योगिक क्षेत्र रीको का शुरू करना था। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसकी जमीन के आबंटन के चक्कर में यह बच रहा है। इसको भी प्राथमिकता से लें। फागी में भी, कुंजबिहारीपुरा, फागी जब दूसरी बार मुख्य मंत्री जी थे, उस समय बजट में घोषणा की थी। बजट में घोषणा होने के बाद किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया लेकिन पर्यावरण की स्वीकृति की वजह से यह कुंजबिहारीपुरा रुका हुआ है। मैं चाहूंगा उद्योग मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि हमारे यहां रोजगार के लिए केवल खेती है। इसके अलावा कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। अगर ये उद्योग-धंधे खुल जाएंगे, खेती का काम तो 5-6 महीने रहता है। ये तो नरेगा है जिससे लोग अपना जीवन-यापन करते हैं। रीको के अगर ये इंडस्ट्रीयल एरिये खुल जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

सभापति महोदय, 2020-21 में एससी/एसटी समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने 100-100 करोड़ रुपये दिये थे। बजट में घोषणा की थी। इसको बढ़ाकर 500-500 करोड़ की घोषणा की है, मुख्य मंत्री जी ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के तमाम एससी/एसटी की तरफ से, मुख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देकर 100 करोड़ के स्थान पर 500-500 करोड़ रुपये की घोषणा की।

सभापति महोदय, इंदिरा रसोई योजना इस कोरोना के समय जो

(श्री बाबूलाल नागर)

कामयाब हुई है, मैं आग्रह करूंगा कि अभी ये शहरों में चल रही है। नगरपालिका क्षेत्रों में चल रही है। पूरे राजस्थान में जो उपखण्ड मुख्यालय हैं, जहां उपखण्ड मुख्यालय पर कस्बे हैं, कहीं पंचायत समिति मुख्यालय है, कहीं तहसील मुख्यालय है, मुख्य मंत्री जी को इसको शहरों से आगे निकालकर ग्रामीणों में भी इंदिरा रसोई योजना शुरू करनी चाहिए। विशेष तौर से जो कस्बे हैं, उपखण्ड मुख्यालय हैं, पंचायत समिति मुख्यालय हैं, वहां भी इंदिरा रसोई योजना क्योंकि वहां भी बहुत गरीब लोग रहते हैं। इस इंदिरा रसोई योजना से आज गरीब आदमी को निश्चिंत कर दिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो भूखे सोने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, दूसरी सन्तान के समय 6 हजार रुपये पूर्व में ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां में थी, अब प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज ये पालनहार योजना, पेंशन योजना, आप सभापति महोदय, बहुत वरिष्ठ विधायक रहे हैं। आपको स्वयं को पता है कि पेंशन योजना किसको मिलती थी, जिसके नाबालिग बच्चे हों, 58 साल से ज्यादा पुरुष की उम्र हो, 55 साल से ज्यादा महिला की उम्र हो, अगर नाबालिग बच्चे होते हैं तो ही पेंशन मिलती है। यह कैसे सम्भव है? जब 58 साल मांग रहे हैं और बच्चा 18 साल से छोटा हो, इसका मतलब तो 40-45 साल बाद में आदमी का ब्याह होना चाहिए, फिर उसके बच्चे-बच्ची हो। मुख्य मंत्री जी ने इस राइडर को खतम किया। आज राजस्थान का आम जो गरीब है, वह दुआएं देता है। वह वृद्ध आदमी दुआ देता है, जिसकी औलादें कई बार उसका ध्यान नहीं रखतीं, वह दुआ देता है। मुख्य मंत्री जी ने पेंशन में राइडर खतम किया। पालनहार के बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको 500 रुपये मिलते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अनाथ बच्चे जिनको महीने के 500 रुपये मिलते थे, इस राजस्थान के जननायक ने बढ़ाकर उनके लिए 1500 रुपये कर दिया महीने के। 1500 रुपये उन बच्चों को, उनके पालन पोषण के लिए कर दिया।

सभापति महोदय, 06 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये दिया करते थे, पालनहार योजना में। आज उनको 1,000 के स्थान पर 2,500, एक साथ 1,500 रुपये बढ़ाए। उस बच्चे को जो अनाथ बच्चा है, अब उसको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आराम से उसको रोजी-रोटी के लिए इधर-

(श्री बाबूलाल नागर)

उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर वह अनाथ बच्चा है, उसको पालन-पोषण के लिए 2,500 रुपये महीने का मिलेगा। आराम से गुजारा हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में भी पैसे बढ़ाए। विधवा पेंशन में मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई जवान विधवा होती है तो 500 रुपये देते हैं। मुख्य मंत्री जी तो हमेशा सब लोगों का ध्यान रखते हैं। ये 500 रुपये कम हैं। मैं कहना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधवा को स्टार्टिंग में अगर कोई 55 साल से कम उम्र की कोई महिला है और वह विधवा होती है तो उसको 500 रुपया मिलता है। मैं समझता हूं ये बहुत कम है। कम से कम उस विधवा को 1,000 से 1,500 रुपये महीना उसको 500 के स्थान पर मिलना चाहिए। सभापति महोदय, 55 से 75 साल की जो उम्र है, उनको 1,000 रुपये मिलता है और 60 से 75 साल में 1,500 रुपये किया है। मैं कहना चाहता हूं कि 75 साल बाद फिर 1,500 मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कितने लोग जीते हैं 75 साल, बेचारे 75 साल लोग जी ही नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा ये जो 75 साल का राइडर है इसको कम से कम 70 साल कर दिया जाए। 70 साल बाद में उसको 1,500 रुपया मिलना चाहिए। 75 साल बाद में मिलते हैं। अधिकतर आप देख रहे हैं कि 70 साल के बाद में बहुत-से लोग मर जाते हैं। उसको फायदा नहीं होता है। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को देखता हूं। मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति गरीब आदमी था बेचारा। एक पेड़ के नीचे था, सौ-सवा सौ बीघा उसके जमीन थी। एक दिन मैं उसके गांव में चले गया, मुझे दूर से आवाज देकर बुलाया। वह उठता नहीं था, उसने अपने खाट के नीचे एक पीपा रखा हुआ था और पीपे में उसने गुड़ भर रखा था। उसने मुझे बुलाया।

श्री सभापति: कन्क्लूड कीजिए माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उसने कहा तूने मेरा बुढ़ापा सही कर दिया, यह जो पेंशन बांध दी। मैं गुड़ रखता हूं और जैसे ही एक बच्चे को आवाज देता हूं कि बेटा मेरे को इसकी जरूरत है, उसके लकवा आया हुआ है। एक बच्चे को बुलाता है और दो बच्चे भागकर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन बच्चों को गुड़ की कांकरी दे देता है। ये बड़ा सहारा है बुजुर्गों के लिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने सड़कों के लिए आपके जिलों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। तीन-तीन सड़कें, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र की भी सड़क है। यह जो 10 करोड़ रुपये का किया है, 7 करोड़ रुपये आपकी नोन-पेचेबल सड़कों के लिए किया है और 3 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक के लिए किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए अब आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये 10 करोड़ रुपये विधायक पर छोड़ देना चाहिए। वह नोन-पेचेबल सड़कों का काम करवा रहा है या नई सड़कों का काम करवा रहा है। मैं समझता हूं नोन-पेचेबल सड़कें तो सरकार की कई योजनाओं में हैं। आपके केन्द्र की भी योजना है, पी.एम.जी.एस.वाई. भी है, आपका सी.आर.एफ. भी है, जब नई सड़कें बनाते हैं तो लोग याद करते हैं। उसको कभी नहीं भूलते। राजस्थान के विधायक आपकी जय-जयकार करेंगे। 10 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये 10 के 10 करोड़ रुपये चाहे मिसिंग लिंक में करें या नोन पेचेबल सड़कों में काम लें, मुख्य मंत्री जी को ये करना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी राजधानी बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज जयपुर दूदू से मिल गया है, जयपुर बस्सी से मिल गया है, फागी से मिल गया है, चौमूं से मिल गया है। मुख्य मंत्री जी ने सैटेलाइट टाउन बनाने की जो कल्पना की है, अभी तो डी.पी.आर. की घोषणा की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

श्री सभापति: कम बोलने की बात नहीं है। समय की सीमा है माई डियर। एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, दूदू को भी इसमें शामिल किया जाए।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा था। मंत्री जी अभी बैठे थे। कई गरीब लोग 2,500 रुपये नहीं दे पाते हैं। डी.डी.बी. ब्लाक में आधे पैसे कर रखा है लेकिन अभी भी जल जीवन मिशन में डी.डी.बी. ब्लाक में फिफ्टी परसेंट पैसा लेना चाहिए। 2,500 रुपये, गरीब आदमी पानी तो पीना चाहता है लेकिन डी.डी.बी. ब्लाक वालों को कम से कम इसमें छूट देनी चाहिए।

इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कानून व्यवस्था के लिए मुख्य मंत्री जी ने काम किया है। चौकी पुलिस की कई चौकियां बनाई हैं। मेरे यहां महला हाईवे पर पूरे पर कोई चौकी नहीं है, दूदू के बाद, बगरू के बाद कोई चौकी नहीं है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि महला में एक चौकी बन जाये। इसी तरह, मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय किये। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, आधे मिनट में, मैं अपनी कांस्टीटूएंसी की बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे मौजमाबाद में तहसील मुख्यालय है, मौजमाबाद में पंचायत समिति मुख्यालय है, मैं चाहता हूं कि वहां एसडीएम आफिस भी खोलना चाहिये। इसी तरह, एक उप तहसील साखून है, उस उप तहसील के लिये मैंने आग्रह किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, कृषि बजट...

श्री सभापति: धन्यवाद स्वीकार किया आपका, विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता ने चौथी बार बजट पेश किया। सदन के अन्दर जो बजट पेश किया जाता है, वह एक तरीके से सरकार का दर्पण होता है, जनता के अन्दर एक विश्वास होता है। जनता यह मानकर चलती है कि सदन के अन्दर जो बात कही गई है, उसके ऊपर सरकार काम करेगी और धरातल के ऊपर क्रियान्वित करने का काम करेगी।

सभापति महोदय, विगत तीन बजटों को हम देखें, सरकार के कामों को देखें, तो मुझे लगता है कि सरकार का सिर्फ एक ही काम बचा है। सरकार का एक ही काम है, सुबह उठना, एक पानी का गिलास पीना, एक चाय का कप पीना, उसके बाद अपनी सरकार की तारीफ करना, मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार जवाबदेह है। उसके बाद, भारत सरकार को कोसना, संघ पर प्रहार करना और फिर यह कहना लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अपने प्रदेश की प्रगति की बात वह कभी नहीं करते। राजस्थान के अन्दर, पिछले तीन सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी बात कभी नहीं करते। सिर्फ मुद्दे को विमुख करने का काम करते हैं। जो समस्याएं हैं, उनसे दूर भागने का काम करते हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर, जो कांग्रेस के माननीय विधायक हैं, या जो कांग्रेस के नहीं होते हुए भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कई माननीय नवरत्न भी हैं। वे सलाहकार भी हैं। वे सरकार की आंख व कान हैं। वे सरकार को सही दिशा दिखाने का काम भी करते हैं। सही बातें सुनाने का काम भी करते हैं। सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर, उन्हीं माननीय विधायकों की पीड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं।

एक माननीय विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनको एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठना पड़े। एक विधायक इसी सदन के अन्दर मौजूद हैं, उनको एक कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए धरने पर बैठना पड़े। एक विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के अन्दर यह कहा कि तीन साल के अन्दर फूटी कौड़ी का काम नहीं हुआ। एक विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिये, जिस तरह से वी.आर.एस. की सुविधा है, अगर वी.आर.एस. की सुविधा होती तो मैं कभी का राजनीति से सन्यास ले लेता। एक विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि सरकार ने मेरी मांग नहीं मानी, जब तक वह मांग नहीं मांगेगे, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। मुझे लगता है कि सरकार की इस मांग के आधार पर...

श्री सभापति: 130 विधायक इधर हैं, एक-एक की गिनती कराने लगोगे तो आपका चौमूं का टाइम निकल जायेगा। चौमूं पर बोल नहीं पाओगे फिर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने अभी तो जूतों का त्याग किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको कपड़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। एक विधायक तो सरकार के ऐसे हैं...

श्री सभापति: मेरी बात सुनो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस, आ गया, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं फूफाजी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 130 हैं इधर। एक-एक के बारे में बताओगे तो फिर चौमूं के बारे में नहीं बोल पाओगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक विधायक तो ऐसे हैं, जिनको सरकार की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, यह फर्जी एनकाउण्टर है, इस एनकाउण्टर की जांच सीबीआई से कराओ। अब जब सरकार के विधायक ही सरकार से सन्तुष्ट नहीं हैं तो दूसरे विधायक कैसे सन्तुष्ट होंगे?

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं उन योजनाओं का जिक्र करूंगा जो योजनाएं हमारे शासनकाल के दौरान चल रही थीं। उन योजनाओं को, इस सरकार ने आने के बाद, बन्द करने का काम किया। मुख्य मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां, पिछले तीन सालों के अन्दर 10 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी अपील राजस्थान के उपखण्ड अधिकारी के यहां पेण्डिंग, उनको भी हम नाम जोड़ने का काम करेंगे। तीन साल तक, उनके अधिकारों का जो हनन हुआ, उसकी भरपाई आप कैसे करोगे?

इसी सरकार ने, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, जो हमारी सरकार की वेलफेयर स्कीम थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। दो साल तक उस योजना को बन्द किया। एक भी गरीब आदमी को उस योजना के तहत लाभ नहीं मिला। जो भारत सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत योजना, उस योजना को परिवर्तित करके, चिरंजीवी योजना नाम देकर, दो साल बाद उस योजना को स्वीकृति दी गयी। दो साल तक, इलाज के अभाव में गरीब आदमी, जो मौत के ग्रास में चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा?

सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना चल रही थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। हमारे समय मुख्यमंत्री दुग्ध योजना चल रही थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। हमारे समय मुख्यमंत्री बिजली सब्सिडी योजना चल रही थी, दो साल तक उस योजना को बन्द करके, अब उसको परिवर्तित करके, फिर योजना शुरू करने का काम किया है। हमारे समय निर्माण श्रमिक योजना के तहत, जो कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 55 हजार रुपये गरीब की बेटी की शादी के अन्दर दिये जाते थे, इस सरकार ने उस योजना को भी बन्द करने का काम किया। यही नहीं, कई जगह तो अधिकारियों की छोटी सी त्रुटि की वजह से, अगर पैसा उसके खाते में चला गया तो उसको वापस मंगाने का काम भी किया है।

सभापति महोदय, हमारे शासन काल में, अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उस योजना को भी कई सालों तक बन्द किया, फिर उसको शुरू किया तो इंदिरा रसोई योजना के नाम से शुरू किया। हमारे समय में चार गुणा अधिक लोगों को लाभ मिल रहा था। इस इंदिरा रसोई के अन्दर एक प्रतिशत लोगों को भी लाभ नहीं मिल रहा।

सभापति महोदय, हमने सुना यह था कि हाकिम बदलता है, हुकुम नहीं बदलता। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हाकिम तो क्या बदला, हुकुम भी बदल

(श्री रामलाल शर्मा)

गया। इस सदन के अन्दर घोषणा करके गये थे कि राजस्थान की 10 हजार ग्राम पंचायतों के अन्दर हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे। हाकिम बदलते ही वह हुकुम भी बदल गया। ग्राम पंचायतों के अन्दर, जो विकास पथ बनने थे, वह भी बन्द हो गये।

सभापति महोदय, अगर आंकड़े उठाकर देखोंगे, तो हमारी सरकार के नहीं आने का प्रमुख कारण यही था पूर्वी राजस्थान। 28 सीटों में से हमारी एक सीट धौलपुर की है। जिस व्यक्ति के अन्दर लोगों ने यह विश्वास किया था कि आने वाले समय में, हमारे प्रदेश का मुखिया बनने की उम्मीद है, उस व्यक्ति की इतनी बड़ी दुर्गति यह सरकार करे, मेरे ख्याल से इनको आत्ममन्थन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पिछले तीन बजटों के अन्दर दो घोषणाएं की गयीं। एक घोषणा तो यह की गयी कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र, आमेर और जमवारामगढ़ को ईसरदा बांध से पानी पिलाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, ईसरदा बांध का पानी चौमूं कब पहुंचेगा यह तो पता नहीं, अभी तक तो उसकी डीपीआर ही नहीं बनी। डीपीआर कब बनेगी, बजट कब अलाट होगा, धरातल पर टेंडर कब होंगे, काम कब शुरू होगा, यह तो पता ही नहीं।

सभापति महोदय, इन्होंने एक घोषणा यह की, चौमूं के पास सामोद वीर हनुमान जी का मन्दिर है, पिछले बजट की घोषणा है। वीर हनुमान जी को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिये, हम एक लग्जरी बस चलाने का काम करेंगे। अब भगवान को भी आप धोखा दे रहे हो। वह भी कलियुग के हनुमान को आप धोखा दे रहे हो। एक साल बीत चुका, चौथा बजट आ गया, अभी तक बस नहीं चली। मेरी बालाजी से प्रार्थना है कि बालाजी, जो आपको धोखा दे रहे हैं, अगली बार आप भी, 2023 के चुनावों के अन्दर, बस जितनी सवारी भी मत देना। चालक की सीट भी खाली रहे, कण्डक्टर की सीट भी खाली रहे और बस के पीछे वाली जो सीट आती है, वह भी खाली रहेगी। आपने बालाजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, कई घोषणाओं का जिक्र मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया, जो पिछले तीन बजटों के अन्दर घोषणा की गयी। नंदीशालाओं की भी घोषणा की गयी थी, वह भी धरातल पर नहीं आई। इन्होंने यह भी घोषणा थी कि हमारी सरकार आने के

(श्री रामलाल शर्मा)

दो साल के अन्दर-अन्दर, ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, जिनको आपने सपना दिखाया था, कि हम कर्ज माफी भी करेंगे।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर यह कह देते, चौथे बजट के अन्दर कि हम एक भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे तो हमें खुशी होती, हम भी आपको धन्यवाद देते। आज हज़ारों किसानों की जमीन नीलाम होने के कगार पर पहुंच गयी। वह सिर्फ आपके एक सपने के आधार पर, आपने यह कहा था कि हम सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे।

सभापति महोदय, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान के भण्डार का, जयपुर की धरती, गुलाबी नगर में जो भाषण देकर गये थे, यहां कहा था कि हिन्दू अलग है और हिन्दुत्व अलग है। मेरे ख्याल से, कल शिव से आने वाले विधायक के, इस सदन में दिये गये उद्बोधन के बाद, उनके ज्ञान के चक्षु खुल जायेंगे कि हिन्दू और हिन्दुत्व में कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने जो कहा कि इस सरकार के अन्दर हम 95 परसेंट से अधिक वोट देते हैं। जब उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही तो जो वोट नहीं देते, उनकी सुनवाई तो यह सरकार करने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि सरकार जो घोषणाएं करती है, जयपुर शहर को हम भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का काम करेंगे, अभी तक तो यह शहर भिक्षामुक्त शहर नहीं बना।

(समय: 14.00 बजे)

मुख्य मंत्रीजी ने एक कन्यादान योजना शुरू की थी। क्या सरकार यह बतायेगी कि कितनी कन्याओं का कन्यादान देने का काम आपने किया? सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एक लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया?

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि हम प्रत्येक जिले के अन्दर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आयेंगे और अभियान चलायेंगे और लैबोरेटरी स्थापित करने का काम करेंगे। मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कोई हत्या करता है तो हत्या करने वाला दिखता है, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति को रोज जहरीला दूध पिलाकर, जहरीला मावा खिलाकर, जहरीले मिष्ठान्न खिलाकर जो लोगों को मौत के ग्रास के अन्दर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यह सरकार उनके खिलाफ कब कार्यवाही करेगी?

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आज किसी दूध का व्यापार करने वाले व्यक्ति को रात को भी कहो कि सुबह मुझे 50 क्विंटल दूध चाहिए तो वह यह कहेगा कि कहां पर पहुंचाना है। यह मेरी मांग है कि सरकार इस चौथे बजट के अन्दर यह कहती कि हम उस कठोर कानून को भी लेकर आयेंगे और जो मिलावट करेगा उसको फांसी की सज़ा देने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से भय के बिना प्रीति नहीं होती है। सरकार यह कानून लेकर आये कि हम आमजन को सुरक्षा देने का काम करेंगे और जो मिलावट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का काम करेंगे। आपने लैबोरेटरी की घोषणा प्रत्येक जिले में की थी, वह लैबोरेटरी की घोषणा भी धरातल पर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा जो आम व्यक्ति उससे पीड़ित, दु:खी और परेशान है, वह यह है कि सरकार अगर चौथे बजट में यह कहती कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए हम कानून भी लेकर आयेंगे और पुलिस को संसाधन मुहैया करवाने का काम भी करेंगे। अपराधी की गाड़ी तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन पुलिस की गाड़ी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी नहीं चल रही है। जब तक आधुनिक यंत्र आप पुलिस को नहीं देंगे, जब तक पुलिस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक पुलिस के 24 घंटे काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में आप चिन्ता नहीं करेंगे, उनको अतिरिक्त मानदेय देने का काम नहीं करेंगे तब तक मुझे यह नहीं लगता कि अपराध पर नियंत्रण होगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रकृति का यह नियम है कि हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सज़ा मिले, लेकिन इस सरकार के अन्दर तो जो हकदार है वह तो खांचे की पोस्टिंग में उधर बैठा हुआ है और जो गुनहगार है, जिसके ऊपर कई कलंक लगे हुए हैं, जो आरोपी हैं वे मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। इसलिए सरकार को यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि हम पदस्थापन करते समय व्यक्तियों का चरित्र भी देख लें कि वह जनता का भला करेगा या जनता का अहित करने का काम करेगा।

(समय: 14.02 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सरकार कैसा काम कर रही है, इसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लूट मची है। जिस तरीके से हर व्यक्ति, सरकार की प्राथमिकता साढ़े सात करोड़ जनता की नहीं है कि हम

(श्री रामलाल शर्मा)

साढ़े सात करोड़ जनता की हिफाजत करने का काम करें या उनका विकास करने का काम करें। सरकार की मंशा और सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ 101 विधायकों का समर्थन करके सरकार को हम कैसे बचा कर रखें, सत्ता पक्ष का विधायक यह कहे रात को बारह बजे कि मुझे एस.डी.एम. चाहिए अभी के अभी नया तो सरकार उसकी बात मानने के लिए तैयार है। सरकार का कोई नुमाइंदा यह कहे कि मुझे माइन्स चाहिए तो सरकार उसकी बात मानने के लिए तैयार है। सरकार का कोई नुमाइंदा यह कहे कि बजरी में मैं किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो सरकार उसकी बात भी मानने के लिए तैयार है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार अगर यह कहती कि राजस्थान के अन्दर मानव तस्करी हो रही है, राजस्थान के अन्दर मानव तस्करी के ऊपर रोक लगाने के लिए हम कठोर कानून लेकर आ रहे हैं तो हमें खुशी इस बात की होती कि वास्तव में यह सरकार कुछ करना चाहती है। राजस्थान के ही एक बड़े अख़बार ने मानव तस्करी की लाइव स्टोरी छापने का काम किया कि किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर मानव तस्करी होती है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर भी कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बजट पर भी तो बोलो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बजट पर तो आप बोलिये न। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार की प्राथमिकता एक भी नहीं है। सरकार ने यह घोषणा की थी 2021 में निरोगी राजस्थान, सरकार ने घोषणा यह भी की थी कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। सब विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, इनसे यह पूछ लो कि कितनी जनता क्लिनिक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में खुलवाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और जो गांवों में चर्चा है, लोगों में चर्चा है कि बिना सेवा शुल्क के कोई काम होता ही नहीं इस सरकार के अन्दर। अब चिकित्सा महकमे में एक आदेश ऐसा निकला है, या तो पहले वाले चिकित्सा मंत्रीजी गलत थे या अब आये हैं वे सही हैं। अब यह तो सरकार स्पष्ट करे कि आखिरकार यह है क्या? एक आदेश यह निकाल दिया कि जो कहीं से भी पदस्थापन हो, सरकार के आंकड़े में स्थायी नहीं है, उसको वापस अपने मुख्यालय के ऊपर आना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति जहां पर पदस्थापित है, वहां पर पोस्ट खाली है, वहां से ही उसका

(श्री रामलाल शर्मा)

वेतन उठ रहा है तो उसको भी कहते हैं कि नहीं, चलो मुख्यालय के अन्दर। उसके बाद में नये तरीके से आपका पदस्थापन करने का काम करेंगे इसलिए मेरी यह मांग है कि जो डाक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ, जहां पर पोस्ट वेकेंट है, जहां पर उसका पदस्थापन है और जहां से उसका वेतन उठ रहा है तो कृपा करके ऐसे व्यक्तियों को तो वहीं पर सेवा देने का काम करें। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने बेहतरीन काम करने का, अच्छा काम करने का प्रयास किया था।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दस ट्यूबवैल देने का काम करेंगे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में चालीस हैण्डपम्प लगाने का काम करेंगे। आप पूछ लें कि कितने विधायकों के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चालीस हैण्डपम्प और दस ट्यूबवैल लगे हैं? हो सकता है कि लगे होंगे किसी एक दो विधायकों के क्षेत्र में। हमारे विधान सभा क्षेत्र में न तो चालीस हैण्डपम्प लगे हैं और न ही दस ट्यूबवैल लगाने का काम किया है। मैंने मंत्री महोदय से भी यह निवेदन किया है कि किस तरीके से पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गलत तरीके से जल जीवन मिशन के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए तखमीना बनाने का काम किया। जहां पर सोर्स डवलप कर रहे हैं, जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, मौके पर यह गये नहीं हैं, एक एन.जी.ओ. हायर किया तकनीकी रूप से और उसको कमरे में बैठाया और उसी गांव की जो स्कीम बनानी है, वह भी कमरे में बैठकर बना दी कि एक ट्यूबवैल ले लो, दो ट्यूबवैल ले लो, पाइप लाइन पांच किलोमीटर ले लो, एक एस.आर. की टंकी ले लो, स्कीम तैयार। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिन्होंने भी इस तरीके से गलती की है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सरकार ने काफी घोषणाएं की हैं, लेकिन वह धरातल के ऊपर नहीं है। अभी मैंने विधान सभा के अन्दर यह पूछा कि प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष की सरकार ने घोषणा की थी, इस कोष का गठन हुआ क्या? अभी मुझे यह जवाब मिला है कि अभी इस कोष का कोई गठन नहीं हुआ है। मैंने यह पूछा कि पैसा खर्च हुआ क्या? कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है तो घोषणा करने की आखिरकार आवश्यकता ही क्या पड़ रही है जब धरातल के ऊपर आ ही नहीं सकता?

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय के अन्दर सरकार वे ही घोषणा करे जिन घोषणाओं को धरातल के ऊपर वह क्रियान्वित कर सके।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर फिल्म सिटी को प्रोत्साहित करने के लिए एक पर्यटन नीति लाने का काम करेंगे। अब यह कोई बतायेगा कि फिल्म सिटी को प्रोत्साहित करने की जो पर्यटन नीति आयी थी, वह धरातल के ऊपर कितनी आयी है?

सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। मुझे यह नहीं लगता कि किसी विधायक ने अपने कोष से अगर पैसे दे दिये होंगे तो जरूर उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण हुआ होगा और अगर जिन्होंने पैसे नहीं दिये होंगे या जिन्होंने सी.एस.आर. का पैसा नहीं लगाया होगा उन ब्लाक्स के अन्दर तो कोई मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया।

सरकार ने यह घोषणा की कि प्रत्येक थाने के अन्दर एक स्वागत कक्ष बनाने का काम करेंगे। सरकार क्या यह बतायेगी कि स्वागत कक्ष के लिए सरकार के खजाने में से कितना पैसा रिलीज करने का काम किया? वह सारा का सारा भी विधायकों और सांसदों के कोष के अन्दर थोप दिया गया कि विधायक और सांसद ही वह पैसा देने का काम करे इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आने वाले समय के अन्दर जो सरकार कर सके उसी की घोषणा करे।

माननीय सभापति महोदय, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे, वास्तविकता के अन्दर यह किसान की पीड़ा है और दर्द भी इस बात का है कि पंजाब से चारा राजस्थान के अन्दर हजारों किसान लेकर आते हैं, खरीदकर लाते हैं। आज वास्तव में चारा 1,400-1,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। 1,400-1,500 रुपये प्रति क्विंटल का चारा खिलवा कर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 1,400-1,500 रुपये प्रति क्विंटल का चारा खिलवाकर पशुपालक आखिरकार क्या बचायेगा?

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह घोषणा की कि पचास

(श्री रामलाल शर्मा)

यूनिट तक हम फ्री बिजली देने का काम करेंगे। सरकार यह भी घोषणा कर दे कि हम एक भी वी.सी.आर. भरने का काम नहीं करेंगे। आप लाखों रुपये की वी.सी.आर. भरकर और हजारों रुपये की रिलीफ देने का काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से सरकार की यह नीति ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी लाखों रुपये की वी.सी.आर. भरने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यह वादा किया था, जब चुनाव 2018 के अन्दर चल रहे थे कि हम सम्पूर्ण संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। कल्लाजी की अध्यक्षता के अन्दर एक कमेटी भी बनी। आज भी संविदा कर्मी सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार हमें कब रेगुलाइज्ड करने का काम करेगी? जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकारी महकमे के अन्दर संविदा के रूप में दे चुके हैं, आज भी उनकी तनख्वाह छह हजार रुपये, आठ हजार रुपये है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि सरकार और मुख्य मंत्रीजी बजट की रिप्लाई दें उस समय कम से कम संविदा कर्मियों के बारे में भी दो शब्द जरूर कहें कि हम इनको रेगुलाइज्ड इतने समय में कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा इस बात की भी की थी कि साढ़े तीन लाख राजस्व न्यायालय के अन्दर मामले विचाराधीन हैं। जिस तरीके के राजस्व न्यायालयों के अन्दर जो फैसले हो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही उल्लेख करना चाहूंगा कि सामोद के अन्दर महामाया का मन्दिर है। उस मन्दिर की 19 बीघा जमीन 1963 से पहले बारानी, 1963 के सैटलमेंट के टाइम गलती से एक पर्चा बन गया भूरा माली के नाम से। 1963 के बाद में पर्चा संशोधित होता है, सार्वजनिक प्याऊ बंदौल के नाम से यह 19 बीघा जमीन, उस जमीन को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय में बैठकर व्यक्ति विशेष को लाभ देने का काम किया है। इस सरकार ने महामाया के मन्दिर की जमीन को नहीं छोड़ा तो इस सरकार से क्या आशा और उम्मीद की जा सकती है।

सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। जब तक महामाया के मन्दिर की जमीन वापस मन्दिर के नाम नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का काम करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त

(श्री रामलाल शर्मा)

कर रहा हूं, मेरा निवेदन है। सरकार कह रही है कि हम इन सारी स्कीम्स को धरातल पर लाने का काम करेंगे, लेकिन लाएंगे कैसे? पटवारी के पद रिक्त, ग्राम सेवकों के पद रिक्त। सरकार ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीएसएस खोलेंगे। व्यवस्थापकों के पद रिक्त पड़े हैं। एलडीसी के पद रिक्त पड़े हैं। आखिरकार सरकार इनकी भर्ती कब करेगी? थोड़ा सा समय बचा है। समय बीत जायेगा, लेकिन आपकी योजना धरातल पर नहीं आयेगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। रीटा चौधरीजी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में पेश बजट आम जनता का बजट है। यह बजट किसी के मन की बात नहीं है। सभापति महोदय, काबिल मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के किसानों के दर्द को समझा, युवाओं के जज्बे को समझा और कर्मचारियों के मर्म को समझा। यह बजट वर्क और हैल्थ पर आधारित बजट है। यह जुमलों के व्यापार का बजट नहीं है। यह डबल इंजिन की सरकार का भी बजट नहीं है। यह बजट किसान पुत्र द्वारा किसान हृदय सम्राट के लिए, युवा के पिता के रूप में प्रस्तुत किया हुआ बजट है। अच्छे दिनों का बजट भी इसे नहीं कह सकते, यह जादूगर का जमीनी बजट कहा जायेगा।

सभापति महोदय, मेरा इस बात में पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से हर वर्ग का हैप्पी इन्डेक्स बढ़ा है। जब हम राज्य सरकार के बजट की बात करते हैं तो हमें केन्द्र बजट को भी ध्यान में रखना होता है। मैं इस सदन में कहना चाहूंगी कि 01 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट के समय आम जनता, इस देश की जनता, उस केन्द्र बजट से कुछ शब्दों की आशा कर रही थी। वह बड़ी उत्साहित थी यह शब्द सुनने के लिए और वह शब्द थे बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, किसान, महिला और युवा। 90 मिनट के भाषण के अन्दर केन्द्र सरकार के अन्दर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ और शब्दों का प्रयोग हुआ स्मार्ट सिटी डिजिटल, ग्रीन, क्लाइमेट, आत्मनिर्भर, make in India, ease of doing business, tax revenue and green fuel, लेकिन राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट के अन्दर किसान को केन्द्र बनाया, किसान हितैषी बजट लेकर आये, बेरोजगारों की बात की, युवाओं की बात की, चिकित्सा की बात की, शिक्षा की बात की और महिला शब्द का इस्तेमाल किया।

(सुश्री रीटा चौधरी)

सभापति महोदय, 2015 के अन्दर तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटलीजी ने कहा था कि देश 2022 के अन्दर आजादी का 75वां वर्ष पूर्ण रूप से अमृत महोत्सव के रूप में मनायेगा। उन्होंने यह भी वादा किया था देश की जनता और किसानों से, कि 2022 के अन्दर उनकी आय दुगुनी हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी 2022 का केन्द्र का बजट हमने देखा और कहीं पर भी दुगुनी नहीं हुई। सीधा 25 साल के ऊपर बजट चला गया। अमृत महोत्सव का जो जश्न मनाना था 75वें वर्ष के अन्दर, वह चला गया अगले 25 सालों के अन्दर। किसान की आय तो दुगुनी नहीं हुई सभापति महोदय, किसान की लागत दुगुनी हो गयी। यूरिया के ऊपर सब्सिडी कम करने का काम केन्द्र की सरकार ने किया। मैं आज इस सदन में बताना चाहूंगी कि अमृतकाल की बात करते हैं देश के प्रधान मंत्री, यह कैसा अमृतकाल है। लोग बेहाल है और मित्र मालामाल हैं। देश के गरीब 20 परसेंट परिवारों की आय में 53 परसेंट की कमी आयी है और देश के 20 परसेंट अमीर लोगों की वार्षिक आय के अन्दर 49 परसेंट की वृद्धि हुई है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप केन्द्र के लिए नहीं बोले, आप उनके अंश और अनुदान पर निर्भर हैं। मैं कहना चाहूंगी केन्द्र सरकार अगर राज्यों को बजट देती है, अंश और अनुदान देती है तो वह राज्य सरकारों का हक है, कोई भीख नहीं दे रही है। उसके अन्दर भी जो उनका हक है, जो उनका परसेंटेज है, उसमें भी डाका डालने का काम केन्द्र सरकार कर रही है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का बजट इतना प्रगतिशील और इतना स्वदेशी था कि मध्यम वर्ग के लोगों को मोटरसाइकिल पर भी पैडल मारना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया। यह बजट युग बनाने वाला बजट के रूप में याद किया जायेगा। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे राजनैतिक मूल्यों में बहुत गिरावट आ रही है। इतनी गिरावट कि गलत काम करने के लिए किसी साहस की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए बहुत साहस की जरूरत पड़ती है और इस रूप के अन्दर राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट हमेशा याद किया जायेगा अपनी सकारात्मक सोच के लिए और साहसिक कदम के लिए।

सभापति महोदय, जब राजस्थान के बजट की बात होती है तो कुछ

(सुश्री रीटा चौधरी)

बिन्दुओं पर मैं बात करना चाहूंगी जो मुख्य रूप से इस बजट को और अहम बनाते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब मुख्य मंत्रीजी यहां पर बजट पढ़ रहे थे और जब उनका बजट खतम हुआ तो राजस्थान के अन्दर एक खुशी का माहौल था। हर दफ्तर के अन्दर पटाखे चल रहे थे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरानी पेंशन योजना को अपनाकर उन्होंने लाखों कर्मचारियों के उनके बुढ़ापे की लाठी देने का काम किया है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जिसने यह काम किया, जिसने यह योजना लागू करने का साहसिक कदम उठाया। 2003 के अन्दर एनडीए की सरकार थी और उन्होंने यह फैसला अपनी सरकार में किया कि उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन को बन्द कर दिया जाए और उन्होंने राज्यों पर छोड़ा कि यह आप पर है कि आप इस पेंशन की योजना को लागू करते हैं या नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। राजस्थान के अन्दर उस समय बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने भी पेंशन योजना को बन्द करने का काम किया। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का यह निर्णय अभूतपूर्व रहेगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की धरती से देश को एक नई राह दिखायी है। मैं समझती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी देश के अलग-अलग राज्यों के अन्दर राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं, आप भी झुन्झुनूं से आते हैं। जिस जिले से आते हैं हम वह एक सैनिक जिला है। जिले के हर गांव और ढाणी के अन्दर देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहूतियां दी गईं। हर गांव और ढाणी के अन्दर शहादत देने वाले वीरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इन प्रतिमाओं में हमारे अर्द्ध सैनिक भी शामिल हैं चाहे वह बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ओटीबीपी हो, इनकी भी पेंशन रोकने का काम तत्कालीन एनडीए की, बीजेपी की सरकार ने किया था।

दूसरा, बजट का जो सबसे बड़ा पहलू है सभापति महोदय, वह स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार की योजनाओं को बन्द किया। मैं बताना चाहूंगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार 5 लाख रुपये तक के बीमा की घोषणा की, उसको बढ़ाकर 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किये जाने की उन्होंने इस बार घोषणा की। अब

(सुश्री रीटा चौधरी)

दस लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा और यह सबसे बड़ा कमजोर वर्ग जो समाज का है, उसको राहत देने का काम किया है।

इसी के साथ मुख्य मंत्री महोदय ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की और पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा हमारे जो गरीब लोग हैं, समाज के पिछड़े व्यक्ति हैं, जो अन्तिम छोर पर बैठा है, उनको इसका लाभ मिलेगा।

मैं इस मंच से कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि स्वस्थ राजस्थान और खुशहाल राजस्थान का जो सपना 2011 में हमने देखा था, नि:शुल्क दवा वितरण हो, चाहे नि:शुल्क जांच योजना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा के रूप में हो, वह प्रदेशवासियों तक पहुंचा। आज सभी जानते हैं, यहां सभी बैठे हैं, चाहे वह पक्ष हो, चाहे वह प्रतिपक्ष हो कि केन्द्र की आयुष्मान योजना, जिसका जिक्र बार-बार चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उसके अन्दर कितने लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा है। कृपा करके वह यह बताते तो ज्यादा अच्छा लगता।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा और रोजगार की बात कही गयी। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत-सी घोषणाएं की हैं और जब मैं चेहरा देख रही थी और जब बजट पर बहस हो रही थी तो प्रतिपक्ष के विचार भी मैंने सुने। बजट पर बोलने के लिये इनके पास कुछ नहीं है। कल जो माननीय सदस्य बोले, वह पिछले पांच साल का हिसाब लेकर आ रहे हैं। वैसे इनकी पार्टी 70 साल का हिसाब मांगने में बहुत माहिर है और वह पन्ने पलट-पलटकर यह घोषणा हुई थी, यह घोषणा हुई थी, वह धरातल पर नहीं उतरी। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी 90 प्रतिशत से ज्यादा पिछले बजट की घोषणाएं धरातल पर उतर गयी हैं और मूर्त रूप भी ले लिया है। यह कमी इन लोगों की है जब यह बात करते हैं कि 10 ट्यूबवैल और 40 हैण्डपम्प लगे या नहीं लगे। यह जन-प्रतिनिधि पर डिपेण्ड करता है कि वह जो बजट के अन्दर घोषणा हुई है, उनको वह अपने क्षेत्र के अन्दर कितना लागू करवा पाता है। आप यह सोचो कि बजट की घोषणा हो गयी और घर बैठे आपके पास थाली आ जाएगी, यह तो हो नहीं सकता, यह सम्भव नहीं है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मण्डावा की बात करूंगी। पिछले बजट के अन्दर जो भी घोषणाएं हुईं, चाहे वह तहसील की घोषणा हो, चाहे वह कृषि

(सुश्री रीटा चौधरी)

महाविद्यालय की घोषणा हो, चाहे वह ट्यूबवैल की घोषणा हो, चाहे वह मिसिंग लिंक की घोषणा हो, वह सारी की सारी धरातल पर हैं। कृषि महाविद्यालय चालू हो गया और उसमें लड़कों और लड़कियों का एडमिशन हो गया, कन्या महाविद्यालय चल रहा है, मिसिंग लिंक्स का काम चल रहा है, तहसील बन गयी है, सारे काम हो रहे हैं लेकिन हमें तो बुराई करने की आदत है, कहीं न कहीं कोई मीन-मेख निकालने की बात आती है, इसलिए हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। एक जो सबसे बड़ी घोषणा (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें प्लीज।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): पांच मिनट लूंगी माननीय सभापति महोदय, मुझे समय दें। संविदाकर्मियों के मानदेय को 20 प्रतिशत बढ़ाने की जो घोषणा है, वह बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इस सदन में हमारे मुख्य मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगी कि उनका नियमितीकरण भी करने के ऊपर विचार करें, क्योंकि बहुत संख्या के अन्दर यह संविदाकर्मी हैं और हम लोगों को समय-समय पर इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। इसके अन्दर स्थायीकरण की इनकी जो मांग है, वह वाजिब मांग है, इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में, मैं अपने बजट भाषण को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी-

"संज्ञा भी नहीं देनी आयी तुझको, तेरा दिमाग था खाली,
वो किसी के दिल की मलिका बन गयी और तू कहता रहा दुल्हन काली।
जब जनता ने खुशी मनायी है, भाजपा तेरी आंख क्यूं पथराई है,
सुनकर पुरानी पेंशन की बहाली, उड़ गयी तेरे होठों की लाली,
वो किसी दिल की मलिका बन गयी और तू कहता रहा दुल्हन काली।
बहाली क्या कर दी पुरानी पेंशन, गहलोत जी ने दे दी भाजपा को टेंशन,
बुढ़ापे की थी जो रात काली, उसको भी कर दी गहलोत जी ने दीवाली,
वो किसी के दिल की मलिका बन गयी और तू कहता रहा दुल्हन काली।"

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव जी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया। सत्ता पक्ष ने खूब

(श्री वासुदेव देवनानी)

मेजें थपथपायीं। मैंने भी पूरा बजट पढ़ा तो मुझे बचपन के उस जादूगर की याद आयी, जिसने स्कूल में आकर एक कागज से 100 रुपये का नोट बनाया और बनाकर हमको हाथ में थमा दिया। जब मार्केट में गये तो असलियत का पता चला तो होश उड़ गये। यही हाल इस बजट से राज्य की जनता का होने वाला है। छह माह बीतने पर यही जनता आपको ढूंढती रहेगी कि आप कहां हो। अभी भले ही आप मेजें थपथपा दो, लेकिन उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। पर मैं सोचता हूं कि आखिर मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा बजट प्रस्तुत क्यों किया? एक ओर केन्द्र के मोदीजी का बजट है, जो चुनावी न होकर आगामी 25 वर्षों के बाद भारत की विश्व में तस्वीर बनाने में जो जुटे हैं, क्या होगी और यहां खजाने में पैसा न होते हुए भी ढेर सारी कागजी घोषणाएं कर दीं। मेरी समझ में आया कि मुख्य मंत्रीजी पूरा समय अपनी पार्टी के सचिन पायलट से लड़ने में इतने व्यस्त हो गये कि उन्होंने अपने बजट को भी हवाई बातों से, हवाई घोषणाओं से परिपूर्ण बनाकर हवाई सपने पूरा करने की एक असफल उड़ान भरी है। यह मुख्य मंत्रीजी का आज का नहीं, बहुत पुराना स्वभाव रहा है कि घोषणाएं करो और भूल जाओ। चाहे वह 1999-2000 की कुछ घोषणाएं हों, चाहे 2009 की घोषणाएं हों, चाहे 2011-12 की घोषणाएं हों, तो उसमें आज तक कभी हिसाब-किताब नहीं कि कितनी मैंने घोषणाएं कीं और उनमें कितनी पूरी हुईं। हर साल बस घोषणाओं का ही अम्बार लगा दो ताकि जनता, चूंकि भोली है, छह महीने पुरानी बात भूल जाती है और नई बातें कहकर घोषणाओं में जनता को भ्रमित करने का प्रयास करो।

मैं बहुत अधिक गहराई में न जाकर, केवल अजमेर के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने उस समय खूब तालियां बजायीं। सौगातों की बौछारों के बड़े-बड़े विज्ञापन भी छपवाये, पर हुआ क्या? यह जरा सुनिए। अजमेर सम्भाग केन्द्र में पब्लिक हैल्थ कालेज बनाने की घोषणा की थी। कहां हैं वह पब्लिक हैल्थ कालेज? कहीं दूर तक पता नहीं कि कोई कालेज नाम की चीज भी बननी है, न कोई प्रस्ताव है, न कोई बजट ही उसके लिये रखा है।

आपने बड़ी घोषणा की राजस्थान राज्य आयुष अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करेंगे। मैंने आयुर्वेद के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई खबर नहीं, हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। यानी साल भर बाद भी अधिकारी यदि यह कहे कि हम प्रस्ताव भेज रहे हैं तो उस बजट की क्या पवित्रता रहेगी। बजट तो एक साल के लिये होता है। आगे आ जाओ रोज

(श्री वासुदेव देवनानी)

एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रोमा सेण्टर बनेगा। ट्रोमा सेण्टर 25 करोड़ से बनाएंगे, यह घोषणा है, लेकिन आज तक ट्रोमा सेण्टर का कोई पता-ठिकाना नहीं है। फिर आयुर्वेद-योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय बनेगा, उसका कहीं पता-ठिकाना नहीं। फिर कहा कि मल्टीपरपज इण्डोर हाल बनाएंगे। अजमेर की जनता मोमबत्ती लेकर ढूंढ रही है कि वह इण्डोर हाल कहां है, कहीं पता नहीं लग रहा है। हास्पिटल की आवास व्यवस्था सुधारने के लिये कहा था कि हम हास्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे, वह कैडर कहां पर बनाया? मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, अपने बजट का जब जवाब दें तो इन बातों का उत्तर दें कि यह चीजें कहां हुईं? विशेष योग्यजनों को भी नहीं बख्शा। उनके लिये कहा था कि आवासीय स्कूल खड़ा करेंगे, आज तक नहीं। केवल विधान सभा के अन्दर, जो यह पवित्र सदन है, उसके अन्दर आपने घोषणा की और साल भर उसमें पत्ता भी नहीं हिला और इस साल थोड़ा पत्ता हिला भी है तो मुख्य मंत्रीजी कहते आये हैं कि मैं राजनीतिक भेदभाव के बिना घोषणाएं करता हूं। लेकिन पूरे अजमेर जिले में उनको केवल केकड़ी ही दिखायी देता है। अब थोड़ा बहुत मजबूर हुए तो किशनगढ़ और मसूदा भी थोड़ा दिखने लगा है लेकिन अजमेर जिले में और भी कई विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां पर कुछ तो ध्यान रखते। वहां पर भी जनता रहती है। आप सारे सदन के नेता हो, आप केवल एक पार्टी के या कुछ विधान सभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि नहीं हो, लेकिन इसकी कहीं कोई खबर नहीं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यह सोचते हैं कि केवल घोषणाएं ही तो करनी हैं, पूरी तो करनी नहीं। तालियों पर तालियां बजवाते जाओ। विज्ञापन छपवाते जाओ। पूरी तो करनी नहीं हैं। पूरी तो तब होंगी जब जेब में पैसा होगा। पैसा तो जेब में है नहीं। खर्च तो एक रुपया और कमाई अठन्नी, तो हश्र बुरा होना ही है। फिर बार-बार कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।

आपको ध्यान हो, गत चुनाव से पहले आप नम्बर वन मुख्य मंत्री हर मुद्दे पर कहलाते थे। बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाते थे। होर्डिंग छपते थे। हुआ क्या कि आप 21 तक सिमट गये। अब मुझे लगता है कि यदि यही हाल रहा तो आप एक वैन में 11 तक सिमट जाओगे। उससे आगे नहीं बढ़ोगे। जरा हवाई घोषणाएं करनी बन्द करो। आप धरातल पर आओ। जनता ढूंढ रही है। मैंने आपकी घोषणाएं देखीं। उसको पूरा पढ़ा। उसमें लगभग सवा लाख रुपये की घोषणाएं की गयी हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सवा लाख करोड़।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सवा लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं। आपके पास पैसा कहां है? आप कहते हो कि रेवेन्यू कलेक्शन, दिसम्बर तक केवल 63 परसेंट हुआ है। उसके बाद भी आगे बढ़ो तो आपका जो स्टेट टैक्स कलेक्शन है, वह आपने बीई में लिखा था कि 90,049.62 करोड़ होगा और आप आरई में कहने लगे कि अब 82,803 होगा। आपने ही मान लिया कि टैक्स का कलेक्शन कम होगा। जब टैक्स का कलेक्शन कम होगा तो रेवेन्यू आयेगा कहां से?

आपने इस बजट के अन्दर जो आधार बनाया है, वह बीई से 16 परसेंट बढ़ाकर के 116 परसेंट का सपना देखा है। हमारा रेवेन्यू 116 परसेंट बढ़कर आयेगा। पिछला ही रेवेन्यू कलेक्शन पूरा नहीं हुआ। आगे उसको कैसे बढ़ाकर कर रहे हो? लेकिन हमें तो केवल घोषणाएं करनी हैं। उस आधार पर आपने गत बार बीई में 1 लाख 84 हजार करोड़ का प्रोविजन रखा था। वह आज बढ़ाकर आपने 2,14,977.24 करोड़ रखा। इतने से 1 लाख 25 हजार करोड़ की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? आपका 92 परसेंट तो सिर्फ वेतन पर जा रहा है। आपके पास केवल साढ़े 6 परसेंट ही विकास के लिये बच रहा है फिर भी क्योंकि तालियां बजवानी हैं। तालियां बजवाते-बजवाते आपने तीसरा सोर्स ढूंढा कि हम कर्जा लेंगे। इस वर्ष 58 हजार करोड़ का भार कर्ज के कारण बढ़ेगा। टोटल मिलाकर के साढ़े 5 लाख करोड़ का कर्जा हो जायेगा। अर्थात् एक परिवार पर साढ़े 3 लाख का कर्जा होगा। उस गरीब ने एक पैसा लिया नहीं लेकिन उस परिवार पर साढ़े 3 लाख का कर्जा स्टेट ने थोप दिया। यह कहां का बजट है? जरा इसको तो कोई बताये। इस प्रकार का तो बजट है।

आपने आधार बनाया कि केन्द्र से हमें जीएसटी का कम्पनसेशन मिलता आया है। वह कम्पनसेशन सिर्फ 5 साल के लिये था। वह 5 साल जून, 2022 में समाप्त होंगे। उसके बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। उस आधार पर यदि बजट की कैलकुलेशन करोगे तो बजट औंधे मुंह गिरेगा। यह स्थिति बनी है। इससे केवल महंगाई बढ़ेगी। आप महंगाई बढ़ाने के लिये प्रदर्शन करते रहो। मोदी जी को गालियां देते रहो। रात-दिन सपने में भी मोदी जी आते हैं। आप केवल वातावरण बनाकर के डायवर्ट करने की कोशिश करते हो।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): आपका आर्थिक प्रबन्धन बहुत अच्छा था पिछले राज में?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां, वह बताता हूं। आप बैठो। सभापति जी, मुझे इनके जवाब देने पड़ेंगे, फिर मेरे मिनट्स बढ़ेंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह समय बढ़ायेंगे तो बताऊंगा। वह भी बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): वह टीचर्स के अन्दर जो आपने किया, आपका आर्थिक प्रबन्धन बहुत बढ़िया था?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह क्या है?

श्री सभापति: प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): आपका आर्थिक प्रबन्धन बहुत बढ़िया था। उसके चर्चे आज हर मास्टर करता है। जितने शानदार तरीके से आपने काम किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इस तरीके से अगर बात करेंगे तो, विषय पर जब आपको मौका मिले, नहीं तो आप मौका ले लेना। कोई बात नहीं अगर कुछ कहना चाहो तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है।

श्री सभापति: बोलिये, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, यदि वास्तव में सरकार के मन में महंगाई घटाने का एक प्रतिशत भी भाव होता तो पेट्रोल, डीजल का वैट आप घटाते। जो आज सारे भारत में सर्वाधिक है। चाहे एमपी ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे पंजाब ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे गुजरात ले लो, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल यहां है। जब डीजल के भाव ज्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ेगी लेकिन उस पर एक परसेंट बात नहीं करेंगे। उस पर भी केन्द्र को कहेंगे कि डीजल के भाव ज्यादा हैं।

कल हमारे उप नेता ने कहा था कि गंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये प्रति लीटर है। इससे ज्यादा शेमफुल बात और क्या हो सकती है? यदि घटाना ही था तो आपको भी ध्यान होगा कि उद्योगों और बाकी चीजों में बिजली का बड़ा रोल होता है। आप बिजली की दरें घटाते। कोई सैस समाप्त करते। कोई अन्य शुल्क हटाते। लेकिन नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक बिजली की दर ज्यादा होगी। पेट्रोल, डीजल जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2014-15 में 8 हजार करोड़ आय करते थे और आज सरकार क्या आय कर रही है? सरकार को 15 हजार

(श्री वासुदेव देवनानी)

करोड़ की पेट्रोल, डीजल से आय इस वैट के कारण है। आप उस पर तो कुछ करोगे नहीं।

यही हाल आपके बिजली का है। सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिक आज राजस्थान के अन्दर रेट्स हैं। दर तो एक कर दी। शहरी सैस, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क, जल संरक्षण शुल्क और यदि विश्वास नहीं हो तो 2018 का बिल आप अपना उठाकर के देख लेना। दिसम्बर, 2021 का बिल उठाकर के देख लेना तो ध्यान आयेगा कि कितना भाव बढ़ा है। कितना अन्तर आया है। जब बिजली की रेट बढ़ेगी, वैट बढ़ेगा, फिर महंगाई तो बढ़ेगी ही। उस महंगाई की असली दोषी तो यह सरकार है, न कि केन्द्र है। इस पर कहीं न कहीं मन को टटोलो तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है? आपका जो 48 हजार परिवारों को लूटने का सपना है, वह केवल इस आधार पर है कि प्री पेड बिजली मीटर भी आप लगाने जा रहे हो। उस पर 3,565 करोड़ का व्यय है। यह जनता से वसूला जायेगा। जनता पर तो आपने एक रुपये का टैक्स लगाया और केवल 10 पैसे की छूट दे दी और वाहवाही लूटने लगे। यह कहां का न्याय है? कहीं तो बात हो। इस प्रकार का दृश्य आज सारा खड़ा किया है।

सभापति महोदय, यह कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। महंगाई तो आपने बढ़ा दी। आज राजस्थान में 27 परसेंट बेरोजगारी है, जो सारे देश में दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक है। कहते हैं कि केन्द्र के कारण बेरोजगारी है। केन्द्र की बेरोजगारी 6.7 परसेंट है। राजस्थान में उससे तिगुनी बेरोजगारी है। फिर भी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। आपका बेरोजगारी रजिस्टर देख लो। साढ़े 16 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। यहां राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। गुजरात में 13 ग्रेजुएट में एक 1, एमपी और महाराष्ट्र में 9 में से 1 और राजस्थान में 2 में से 1 बेरोजगार है। कुल मिलाकर के 20.67 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। राजस्थान के अन्दर कुल 65 लाख बेरोजगार हैं।

आप कहते हो कि बेरोजगारी दूर करेंगे। हम नौकरियां देंगे। पिछले 3 बजट में आपने 1 लाख 78 हजार नौकरियों की घोषणा की। 2019-20 में 75 हजार, 2020-21 में 53 हजार, 2021-22 में 50 हजार की घोषणा की। अब तक आपने नौकरियां कितनी दीं? आपने घोषणा की कि एक लाख दीं। हालांकि वह गलत है। उस एक लाख में से 61 हजार वह नौकरियां हैं जो हमारे समय की हैं। जो कोर्ट में अटकी हुई भर्तियां थीं। उनको आपने नियुक्तियां दी हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसका मतलब आपने तो एक लाख 78 हजार में से केवल 39 हजार नौकरियां ही दी हैं। उसको ही आप 3 बजटों में पूरा नहीं कर पाये।

आप कह रहे हैं कि एक लाख नौकरियां देंगे। किस विभाग में कितनी दोगे? कब करोगे? इसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है। केवल घोषणा पर घोषणा किये जाओ। युवकों को चकमा देते जाओ। उनको आश्वासन देते जाओ। भर्तियां जितनी हो रही हैं वह विवादों में हैं। मैं रीट पर अभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि शिक्षा की मांग पर इस पर विस्तार से बोलूंगा। रीट विवाद जिसमें मंत्री तक इनवाल्व हों, उसके बाद बचा क्या है? 2-2 मंत्रियों का जिसके अन्दर रोल आये। उसके बाद रीट और अन्य परीक्षाओं का आगे भी हश्र क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

सभापति महोदय, संविदा कर्मियों की बात करें। संविदा कर्मियों को कहा था कि हम इनको परमानेन्ट करेंगे। अब कहते हैं कि उसके लिये अलग कॉडर बनायेंगे। अलग वेतन श्रृंखला बनायेंगे। क्या करेंगे? कुछ पता नहीं है। सवा तीन साल हो गये हैं। वह ठगे से रह गये हैं।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के यदि आप दृश्य खड़ा करोगे तो आखिर यह कैसे आगे बढ़ेंगे? सदन में कई कांग्रेसी मित्र कल और आज बोल रहे थे कि केन्द्र की सहायता नहीं होती। लगता है कि मुख्य मंत्री जी से उन्होंने यह वाक्य रट सा लिया है। मुख्य मंत्री जी, यदि मन के अन्दर ईमानदारी है तो केन्द्र ने साथ में अनुदान कितना किया, अनुदान कितना किया, वह मैं बताता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, सुनिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बीजेपी के शासन से आपको दुगुनी सहायता मिल रही है। आपके 2018-19 में 20,037 करोड़ मिली ...(व्यवधान) और आज 2022-23 में 45,317 करोड़ रुपये मिल रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): माननीय सदस्य के मुंह से ईमानदारी शब्द अच्छा नहीं लगता है। यह सैकण्ड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): इनकी जो रेट थी ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): व्यवधान हो रहा है। यह क्या है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जब इधर का टर्न आये, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक्सपंज कराओ सभापति महोदय। एक्सपंज कराओ ...(व्यवधान) नोटिस देकर आयें ना फिर। मंत्री महोदय के पास तथ्य हैं तो 273 को नोटिस दो।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम जवाब देंगे। एक्सपंज कराओ।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज सुनिये। आप बोलिये, वह तो बैठे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, अब आपने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन रिवाइव करने की बात की लेकिन वह देनी तो 2035 में है। अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इन कर्मचारियों का विगत 18 वर्ष में 2400 से लेकर के 14 हजार प्रति वर्ष तक जो लाखों रुपया जमा कराया, उस पर बजट चुप है। मुख्य मंत्रीजी उस पर कुछ बोले नहीं हैं कि वो पैसा लौटायेंगे, ब्याज सहित लौटायेंगे, उस राशि का क्या होगा, आज कर्मचारी देख रहा है, घोषणा पर तो खुश हो गया, लेकिन घोषणा के बाद उसका लाखों रुपया इस सरकार के पास जमा है, उसके बारे में सरकार ने चुप्पी डाल रखी है। मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जब डिमांड का उत्तर दें तो इस मुद्दे पर भी जरूर बोलें।

दूसरा, आपने वाहवाही लूटी, एग्रीकल्चर का बजट हम अलग से प्रस्तुत करेंगे, खूब ढिंढोरा पीटा, जैसे किसानों पर आपने नोटों की बरसात कर दी हो, पर खोदा पहाड़ और चुहिया भी नहीं निकली। 2021-22 का बजट 13,491 करोड़ रुपये था और 2022-23 का बजट है 13,470 करोड़, यानी पिछले बजट से भी आपने 21 करोड़ रुपये कम कर दिया और कहते हैं कि हम तो किसानों की बहबूदी करेंगे, हम तो किसानों को यह कर देंगे, यानी किसानों का आपने कर्जा तो माफ नहीं किया, वो एक-दो-तीन-चार-पांच-दस तो किसान अभी याद रख रहे हैं। उनका गिनती के बाद कर्जा भी माफ नहीं किया, बजट भी नहीं बढ़ाया, केवल अलग किसान का अलग बजट प्रस्तुत करेंगे, अलग प्रस्तुत करना होता तो अलग मंत्री प्रस्तुत करता है। रेल बजट हमारा पहले अलग से प्रस्तुत होता था, उसको रेल मंत्री अलग से प्रस्तुत करता था। आपके यहां मंत्री महोदय ने न करके और उसको प्रस्तुत किया है।

श्री सभापति: कृपया कन्क्ल्यूड कीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां, कर रहा हूं। इन्होंने दो-तीन मिनट डिस्टर्ब किया, उसका मैं समय चाहूंगा आपसे।

माननीय सभापति महोदय, फिर आ जाओ अरबन डवलपमेंट पर। स्मार्ट सिटी, केन्द्र ने प्रत्येक शहर को एक हजार करोड़ रुपये दिया है। आपने 6 शहरों के लिए केवल 1,500 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है, यानी प्रत्येक शहर को केवल 250 करोड़ रुपये मिलेंगे। जब एक हजार करोड़ रुपये में ही पूरा नहीं हो रहा है तो 250 करोड़ रुपये का तो आपने केवल एक झुनझुना-सा पकड़ा दिया कि हम आपको स्मार्ट कर रहे हैं। बजट आपने 21 परसेंट इस सिटी अरबन डवलपमेंट में घटाया है। 2021-22 का बजट था 11,044 करोड़, पर 2022-23 का बजट है 8,728 करोड़, यानी आप बजट तो घटा रहे हो और कहते हो कि स्मार्ट सिटी बनायेंगे। स्मार्ट सिटी में भी केवल आप दाना फेंक रहे हो। इस तरह की स्थिति वास्तव में दयनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को पहला प्रयास करना चाहिए था गुड गवर्नेंस देने का, इसमें सारे पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना था, आज सबसे ज्यादा सरकारी अफसर और पुलिस अफसर असुरक्षित हैं। 2 वर्षों में 3324 हमले हुए हैं अर्थात् 1 दिन में 4 लोग पिट रहे हैं, फिर भी आंखें सरकार की नहीं खुल रही हैं और चुपचाप बैठी है, क्या यही सुशासन का नाम है? महिला दुष्कर्म बढ़ रहे हों, बजरी माफिया खनन बढ़ रहा हो, खनन माफिया बेलगाम हो रहा हो, अपराधों में राजस्थान नम्बर वन, भ्रष्टाचार में राजस्थान नम्बर वन, आज अपराधियों में किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा में हैल्थ इंडेक्स में आप 16वें नम्बर पर हो, आपके पास डाक्टर्स नहीं, आपके पास नर्सें नहीं, पर आप कह रहे हो कि आप आगे बढ़ेंगे। आपने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, पर अब तक केवल 7 शुरू हो पाये हैं। आपने फूड सेफ्टी लैब्स के लिए कहा था, लेकिन 7 खोलीं, वो भी अधूरी हैं। जनता क्लिनिक, कहां गया, जिसकी ढेरों तालियां पीटी थीं हम जनता क्लिनिक सारे शहरों में खोल देंगे, आज कहीं जनता क्लिनिक नजर नहीं आती हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि हमने 3,230 स्कूलों को क्रमोन्नत किया। 7 हजार स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्रमोन्नत करके इतिहास बनाया था और आज आप 3

(श्री वासुदेव देवनानी)

हजार देकर वाहवाही लूट रहे हो। आज स्थिति यह है कि 292 कालेजों में से 270 में प्रिंसिपल नहीं हैं। डीपीसी सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग सीनियरिटी में नहीं आ रहे हैं इसलिए उनकी डीपीसी नहीं करा रहे हो। आपने कहा था 22 हजार जो प्राइमरी स्कूल इन्होंने बन्द किये थे, उनको खोलेंगे। अब 200 पर आ गये। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आप खोल रहे हो, यह आप 1,000 हिन्दी मीडियम के स्कूल आप बन्द करके खोल रहे हो, आप नये अंग्रेजी मीडियम के स्कूल नहीं खोल रहे हो। न तो वहां नई बिल्डिंग, न वहां और कुछ, न कोई क्वालिटी, यह आपकी बजट की घोषणा है।

आपने विकास पुरुष के रूप में घोषणा की, एससी, एसटी के लिए 100-100 करोड़ रखे और उनको अब 500-500 करोड़ कर दिये। उन 100-100 करोड़ में से कितना खर्च किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के अन्दर आपने 500 करोड़ रुपये पहले रखे, पैसा एक खर्च नहीं किया और इस बार एक हजार करोड़ रुपये आपने उस पर रखा।

आपने जिला गठन की बात सोची थी, आश्वासन दिया था और कहा था लोगों को, आज आपका ही एमएलए जूते विधान सभा के भवन के बाहर खोलकर नंगे पांव घूम रहा है लेकिन आप अपनी पार्टी के विधायकों को भी नहीं सम्भाल पा रहे हो। ये हाल हैं आपके।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में आप खर्चा कुछ कर नहीं रहे हो, केन्द्र सरकार को केवल आरोपित कर रहे हो, आपको इस बार 13,500 करोड़ मिला है, पर आपने खर्चा एक हजार करोड रुपये भी नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की दयनीय स्थिति होगी तो इस बजट का भी वही हाल होगा जिस प्रकार के पिछले वर्षों के बजट के होते आये हैं। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, छह महीने बाद आपको ढूंढ़ती रहेगी, और आप वैन जितने 11 विधायक अगली विधान सभा के अन्दर आओगे, इससे ज्यादा आप आओगे नहीं, इसलिए अभी भी सम्भल जाओ, जरा जनता की आशाओं को पूरा करो। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के आम बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

(श्री पुखराज)

माननीय सभापति महोदय, बजट से पूरे राजस्थान को अपेक्षा होती है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है और किस दिशा में प्रदेश को ले जा रही है लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट घोषणाएं की थीं उनमें से अधिकतर का धरातल पर क्रियान्वयन कैसे होगा, यह प्रश्ननीय बिन्दु है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कन्या महाविद्यालय तथा आसोप में उप तहसील खोलने की स्वीकृति मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रदान की, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियों की तरफ मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि भोपालगढ़ मुख्यालय पर स्थित राजकीय कालेज में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं तथा एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र की बीएड कालेज बन्द हो गयी है। नये संकाय खोलने की मांग लगातार की जा रही है इसके बावजूद सरकार का इस मसले को नजर अन्दाज करना चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरी मांग है कि इस पर भी सरकार ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बावड़ी कस्बे में जहां सरकारी कालेज स्वीकृत है, परन्तु अभी तक जगह के अभाव में नया भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। इस वस्तुस्थिति की तरफ की मुख्य मंत्रीजी संज्ञान लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि विधान सभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी और अलग से कृषि बजट पेश करके श्रेय लेने की होड़ मची हुई है लेकिन आज 3 साल से अधिक समय चुनाव के हो जाने के बावजूद सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पायी है इसलिए राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी भी लगातार सरकार से यह मांग कर रही है कि राजस्थान के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की जाये क्योंकि एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये कृषि का कर्ज राजस्थान के किसानों पर बकाया है। कांग्रेस पार्टी दलितों के हितों के संरक्षण की बात करती है, लेकिन आंकड़े उठाकर देखेंगे तो यह सामने आयेगा कि हर रोज राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिस

(श्री पुखराज)

प्रकार से बालिकाओं और बच्चों के साथ में दुष्कर्म और कुकर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे राजस्थान रोज शर्मसार हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई प्रकार की घोषणाएं की हैं, बजट में की हैं, लेकिन वित्तीय प्रावधान इनके क्या होंगे, इस चीज को उन्होंने नहीं बताया है और न ही किसी को समझ में आ रहा है। सरकार पूर्व की घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए कटिबद्ध नजर नहीं आ रही है। सरकार के मंत्री तथा विधायक क्षेत्र में सरकार के भरोसे जिन घोषणाओं को करके आते हैं उनमें से अधिकतर लम्बित ही पड़ी नजर आती हैं।

पूर्व सरकार ने राज्य राजमार्गों पर टोल फ्री किया था, आपकी सरकार ने आते ही उसको बन्द कर दिया इसलिए राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी यह मांग करती है कि प्रदेश के अन्दर स्टेट टोल से प्रदेश की जनता को फ्री किया जाये। आज बेरोजगार संगठन हर रोज अपने हक और अधिकार के लिए आन्दोलन करते नजर आते हैं और सरकार की हठधर्मिता के कारण मजबूरन उनको आन्दोलन करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने बजट में रोजगार का स्थायी समाधान देने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है। राजस्थान सरकार के जिम्मेदारों की कमी और खामी के कारण हर भर्ती न्यायालय में जाकर अटक जाती है जिसके कारण भी बेरोजगारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रदेश में जनसंख्या के क्रम में पुलिस की नौकरी बहुत कम है। साथ ही, जिस प्रकार राजस्थान में लगातार गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति के मामले बढ़ रहे हैं, उनमें कमी लाने के लिए भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। ऐसे में राजस्थान के जो हालात बने हैं, वे बहुत चिन्ता का विषय हैं। आज न केवल प्रत्येक विधायक की यह पीड़ा है कि इस विधान सभा में लगाये गये सवालों के जवाब समय पर सम्बन्धित विभाग नहीं देता है, सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती है और अधिकतर मामलों में गलत तथा गुमराह करने वाले जवाब प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में विधान सभा में प्रश्न लगाने का क्या औचित्य रह जायेगा? इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और जलदाय विभाग के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब गर्मी के दिन आने शुरू हो गये हैं। ऐसे में जोधपुर जिले और पश्चिमी राजस्थान सहित राजस्थान के कई

(श्री पुखराज)
जिलों में गर्मी के दौर में भारी जल संकट का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में नये नलकूप सृजित करने तथा पुराने नलकूप रिपेयर करने और खराब पाइप लाइनों को सही करने के जो कार्य हैं, उन्हें जल्द से जल्द किया जाये। सरकार को नहरी पानी से वंचित ढाणियों को भी जोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि संविदाकर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। राजस्थान सरकार के विभिन्न महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाये जाएं। यह मेरी मांग है। आज राजस्थान में सशक्त और मजबूत लोकायुक्त की जरूरत है, क्योंकि सत्ताधारी दल और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही सरकारों के समय में इनके नेताओं के विरुद्ध लोकायुक्त के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने की सिफारिश की गयी थी, मगर एफ.आई.आर. नहीं की गयी, इसलिए मेरी मांग है कि लोकायुक्त पर विशेष बल दिया जाये, उसे न्यायिक शक्ति दी जाये और उसके निर्णय को न्यायालय के निर्णय के समान समझा जाये।

माननीय, बजट के बिन्दु संख्या 19 में पंचायत समिति मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डायलिसिस प्रारम्भ करने की घोषणा भी की गयी है, परन्तु बहुत सारी सी.एच.सीज. में पर्याप्त डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ नहीं हैं। स्टाफ की व्यवस्था कैसे होगी, इसमें किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की सी.एच.सी. में 100 बैड्स स्वीकृत हैं, लेकिन आज भी वहां पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ नहीं लगाया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ सीएच.सी. में पर्याप्त स्टाफ लगाने की व्यवस्था करें। साथ ही, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सी.एच.सी. बावड़ी, जो एन.एच.-62 पर आयी हुई है, जहां हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, वहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधा समय पर प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वहां विशेषज्ञ डाक्टर लगाने के साथ ही ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा करें।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): बजट के बिन्दु संख्या 121 में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कर भूतपूर्व सैनिकों सहित सैनिकों की विधवाओं एवं परिवार को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है, लेकिन दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जिले के जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद स्मारक हेतु भूमि आबंटन नहीं किया जा रहा है। इससे शहीदों का अपमान हो रहा है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर प्राधिकरण को निर्देश दें कि शहीदों के स्मारक के लिए भूमि आबंटित करे। साथ ही, शहीदों के नाम से स्कूलों का नामकरण कराएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी सौगातें दी हैं। मैं और मेरे क्षेत्र की जनता सबसे पहले तो मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बजट में जो हमने सोचा था, उससे ज्यादा मिला है। अगले साल नहीं, अबकी बार ही मिल गया है।

सभापति महोदय, सामने जो अभी ईमानदारी की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, इन लोगों से यह पूछें कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप लोगों की केन्द्र की सरकार और आपके राज्य के नेता जो हमारी चुनी हुई सरकारों को पटक रहे हैं, जो एमएलएज को लालच दे रहे हैं पैसे से खरीदने के लिए, वे ईमानदारी की दुहाई कर रहे हैं। हां, गुलाब चन्द कटारिया जी तो बात कर सकते हैं। वे तो जरूर मुझे ईमानदार लगते हैं इस दल में, बाकी तो मुझे पूरा दल ही एक-सा लगता है। वे ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, जो चुनी हुई सरकारों को पटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने पैसे के दम पर सरकार गिरायी। कहां से आया इनके पास पैसा? कर्नाटक में इन्होंने सरकार गिरायी। कहां से आया पैसा इनके पास? गोवा में इन्होंने सरकार नहीं बनने दी। उत्तराखण्ड में इन्होंने सरकार पटकी। हर जगह इनका यही ड्रामा है और यहां आकर ईमानदारी की दुहाई देते हैं कि हम ईमानदारी का काम कर रहे हैं। किस मुंह से ईमानदारी की बात कर रहे हैं? इनकी तो मैं क्या बात करूं, पूरा देश जानता है कि इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। न खाऊंगा, न खाने दूंगा और सबको खिलाऊंगा। यह इनका नारा है।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, मैं इनकी केन्द्र की सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो 2022 में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा, मैं भी एक किसान हूं, मेरी तो आय दुगुनी नहीं हुई। अगर बीजेपी वालों की आय कहीं दुगुनी हो गयी हो तो ये लोग बता सकते हैं। मुझे बताएं ऐसी कौन-सी फसल है, जो आपने दुगुनी कर दी? कौन-सी आपने किसान की आय दुगुनी कर दी? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): दुगुनी आय हो गयी। ग्वार बिक रहा था 1,500, आज 6,000 बिक रहा है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ग्वार आपके कारण नहीं बिक रहा, वह तो सट्टे वालों के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है।

श्री सभापति: आप इधर बात करिये। उनसे बात नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, इन्होंने आय तो दुगुनी नहीं की, इन्होंने 750 किसानों को शहीद जरूर कर दिया। वह इन्होंने जरूर किया। संसद में गरीब लोगों के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। न तो माननीय प्रधान मंत्री जी बोले, न इनके कृषि मंत्री जी बोले और न ही इनका कोई नेता बोला। सभापति महोदय, भाजपा की सरकार में नरेगा की स्कीम पर इन्होंने अंगुली उठायी, जो हमारी कांग्रेस सरकार के पीरियड में चालू हुई तब इन्होंने अंगुली उठायी।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने अंगुली उठायी थी कि मनरेगा इतनी खराब योजना है। अगर योजना इतनी खराब थी तो इस योजना को इन्होंने साढ़े सात वर्षों तक क्यों झेला? इन्हें बन्द कर देनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, यह नरेगा योजना इतनी अच्छी योजना है कि गरीब लोगों के रोजगार के लिए यही एक साधन बचा है। सभापति महोदय, उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी। अब ये कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं।

सभापति महोदय, जैसे ही मैं बोलना चालू करूंगा न, अन्दर से ये सब निकलकर आ जायेंगे और मुझे ही देखते रहेंगे कि यह क्या बोलेगा। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार में ही मनरेगा चालू हुई और हमारी सरकार ने ही अभी सवा सौ दिन का रोजगार दिया है। पहले सौ दिन का दिया था। सभापति महोदय, राजस्थान में पूर्व में भाजपा की सरकार थी, जिन्होंने हजारों की संख्या में स्कूलों को बन्द किया।

(श्री गिर्राज सिंह)

(समय: 15.00 बजे)

और हमारी सरकार आते ही मुख्य मंत्री जी ने हमारे विद्‌यालयों को चालू कराया, जिनकी जरूरत थी, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी और भी लोगों से मांगे गये हैं कि अगर कहीं भी नये स्कूल खुलवाने हैं या चालू कराने हैं तो मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिन-जिन को जरूरत है उनको मैं सबको स्कूल दूंगा। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी हाल ही में बजट में सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने विद्‌यालयों को क्रमोन्नत किया है।

सभापति महोदय, जो सरकारी कर्मचारी है, मैं जानता हूं कि करीब 20-25 वर्ष तो पढ़ाई-लिखाई, पूरी शिक्षा लेने में लग जाते हैं तब वह जाकर नौकरी पर लगता है तो उसके 25 वर्ष तो वहां खराब हो गये, 30-35 वर्ष उसके फिर सरकारी सेवा देने में खराब हो जाते हैं। सभापति महोदय, इन्होंने तो, इनकी केन्द्रीय सरकार ने उनके बारे में यह भी नहीं सोचा कि उनके लिए बुढ़ापे के लिए कोई सुविधा करें पर इन्होंने तो उनके हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया। किसी की औलाद खराब निकल जाती तो उनको घर में खाने की भी दिक्कत आ जाती है पर, सभापति महोदय, इन्होंने तो एक काम किया है कि उनकी पेंशन बन्द कर दी। अब हमारी सरकार ने उनकी पेंशन चालू कर दी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से दर्द हो रहा है कि जो आने वाले समय में विधान सभा के चुनाव आयेंगे उसमें इनको मालूम है कि इनका एक भी खाता नहीं खुलने वाला है, एक भी जीतकर नहीं आयेंगे और यह इनको मालूम है। एक कटारिया जी आ जायेंगे, राठौड़ साहब आ जायेंगे, एक-दो आ जायेंगे बाकी कोई नहीं आयेंगे। जो ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं।

सभापति महोदय, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केन्द्र सरकार ने प्रावधानों में अभी तक कोई छूट नहीं दी है पर हमारी सरकार ने सभी छूटों को लागू कर दिया, सिर्फ 8 लाख रुपये की रखी है। सभापति महोदय, इनकी केन्द्र में सरकार होने के बाद में और ये यहां पर बड़े जोर-शोर से हल्ला मचाते हैं पर केन्द्र सरकार से जाकर ये इतना नहीं कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों का जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो केन्द्र सरकार ने इतनी अड़चन लगा रखी है कि इतना प्लाट नहीं होगा, इतनी इन्कम होनी चाहिए, यह होना चाहिए और तमाम तरह की अड़चन लगा रखी है। क्या आप लोग यह भी नहीं कह सकते हैं क्या? आप लोगों ने कभी कहा? आपके 25 के 25 सांसद यहां से चुनकर

(श्री गिर्राज सिंह)

गये हैं पर उन्होंने कभी इसके लिए एक शब्द बोला? बताओ किसी ने बोला हो तो। आप तो सपने देखना कि कब आयेगी, बतायेंगे आपको कि कब आयेगी।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी 100 करोड़ रुपये का कोष बनाया है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा में ऐसे करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनके नाम सूची में से कटवा दिये। सभापति महोदय, यह केन्द्र सरकार तो कुछ देने वाली नहीं है, यह तो सिर्फ लेने ही वाली है, गरीब लोगों का खून चूसने वाली है, यह बीजेपी की सरकार तो कुछ करेगी नहीं इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे गरीब परिवारों का आप सर्वे कराकर जिनको राशन की जरूरत है, ऐसे परिवारों को चिह्नित कर उनको राशन देने का कार्य कराया जाये।

सभापति महोदय, हमारी सरकार में भेदभाव नहीं है। मुझे याद है कि जब हम उधर बैठते थे, जब हम 21 लोग थे और ये 163 लोग थे तब भी इन्होंने, बीजेपी सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैण्डपम्प देने की घोषणा की थी पर, माननीय सभापति महोदय, हमको एक भी इन्होंने हैण्डपम्प नहीं दिया जबकि हम 21 लोग थे। ये भेदभाव नहीं करते तो क्या करते हैं? अभी हम कुछ कहेंगे तो ये लोग और आगे जाकर हल्ला मचायेंगे।

सभापति महोदय, मिसिंग लिंक की इन्होंने 10-10 किलोमीटर की घोषणा कर दी कि प्रत्येक विधायक को हम 10-10 किलोमीटर मिसिंग लिंक देंगे पर इन्होंने हमको नहीं दी। जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी लोग थे उन लोगों से इन्होंने प्रस्ताव लेकर रोड दी तो यह तो इनके अन्दर भेदभाव है पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक बार भी भेदभाव नहीं किया है और सबको एक समान रखा है।

सभापति महोदय, ये हमेशा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं और गरीब लोगों के लिए इन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया है। अभी बिजली में 50 यूनिट फ्री किये हैं। 100 यूनिट भी हम कर दें तो भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सभापति महोदय, मैं तो मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं और यह मेरी मांग है कि गरीब लोगों के लिए 50 के बजाय इसको 100 करें और जो छूट दी है उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें क्योंकि इसमें सब गरीब लोग ही हैं। जो पैसे वाले लोग हैं इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये तो पैसे वालों की वकालत करते हैं जबकि हमारे मुख्य मंत्री गरीबों की वकालत करते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से इसके लिए मांग करता हूं क्योंकि

(श्री गिर्राज सिंह)

इनकी सरकार तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है और हमारे मुख्य मंत्री गरीबों को फायदा पहुंचाते हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की नीति थी और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक भाषण दिया कि हम हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दो करोड़ लोगों को इन्होंने कहीं पर रोजगार नहीं दिया है, पर दो करोड़ लोगों के रोजगार इन्होंने एक साल में छीने जरूर हैं। हर साल दो करोड़ बेरोजगार कर देते हैं। सभापति महोदय, कहने और करने में बहुत अन्तर है।

सभापति महोदय, इन्होंने जो भी कोई घोषणाएं की हैं, केन्द्र सरकार ने कीं या इनकी पूर्ववर्ती राज्य सरकार थी, इन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं उसमें मुझे तो लगता नहीं कि इन्होंने एक भी वादा पूरा किया हो। जब भी चुनाव आते हैं तब हिन्दू-मुसलमान पर आ जाते हैं और जो घोषणा की और विकास का मुद्दा आता है उन पर देश में कोई चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हिन्दू और मुसलमान, पाकिस्तान और ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ा-बहुत चीन को दिखा देंगे। सभापति महोदय, यह इनकी नीति है और इसके अलावा इनके पास कोई एजेण्डा नहीं है, काम इनको कोई करना नहीं है, सिर्फ हिन्दू-मुसलमान के नाम पर वोट लेने हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी चिरंजीवी योजना चालू की थी और पहले भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही दवा फ्री की थी। अब इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिये, इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार के कार्यकाल में जो डीजल-पेट्रोल के भाव थे उनमें डीजल का भाव 31 रुपये, पेट्रोल का भाव 53 रुपये तथा गैस का भाव 400 रुपये प्रति सिलेंडर था। सभापति महोदय, इनकी सरकार आते ही इन्होंने जस्ट इसको डबल कर दिया। अब इसको मानने के लिए भी ये तैयार नहीं होंगे, तैयार हो या नहीं? डीजल-पेट्रोल के भाव दुगुने हुए या नहीं हुए? यह भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। गैस का सिलेंडर कहां पर पहुंच गया, यह भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको तो तब मालूम होगा, तब पता पड़ेगा जब थोड़े दिन बाद जनता आपके पीछे पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अन्दर कान पकड़कर वह ऊपर-नीचे हो रहे हैं न वैसे होगा आपका, आपके एमपी और आपके केन्द्र वाले मंत्रियों का तथा

(श्री गिर्राज सिंह)

आपका भी उनके साथ में होगा। आप कल के अख़बार में देखना, फोटो दिया है और मोबाइल पर भी आया है कि कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। ऐसे ही आप सब लोग माफी मांगेंगे। इसलिए समय रहते हुए आप लोग सुधर जाओ।

श्री सभापति: इधर एड्रेस करें, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप अपने ऊपर वाले आकाओं को बतायें। मजा इधर ही आता है, इनसे ही करने में आता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपना उद्‌बोधन समाप्त करें, प्लीज।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आय दुगुनी तो इन्होंने नहीं की पर कम कर दी। सभापति महोदय, इन्होंने दुनिया को बेरोजगार कर दिया।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से कुछ मांगें हैं। मेरी बसई नवाब उप तहसील है वहां पर रिंग रोड की मैं मांग करता हूं। एक नगला भिदौरा, एक पुलिया जो कहीं भूल में रह गया है। माननीय मुख्य मंत्री 18 नवम्बर को स्वयं घोषणा करके आये थे। सभापति महोदय, यह थोड़ी सी कहीं चूक हो गई होगी। सभापति महोदय, बसई नवाब के अन्दर एक सीसी खरंजा की, नाले निर्माण की मांग है। सभापति महोदय, एक रोड है जिसकी प्रशासन गांव के संग कैम्प में मुख्य मंत्री जी स्वयं घोषणा करके आये हैं पर यह कहीं भूल से रह गई है जो 20 किलोमीटर की रोड है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चिकित्सालय, ट्रोमा सेंटर की मैं मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पेयजल आपूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जायें क्योंकि हमारा डांग का एरिया है और डांग एरिया में हर जगह पानी की पाइप लाइन नहीं जा सकती है तो पूर्वी राजस्थान को एक ही दृष्टि से नहीं देखें। कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर जंगल है तो सभापति महोदय, सभी के लिए हम एक जैसी स्कीम नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि हर जिले की परिस्थिति अलग-अलग हो सकती है। सभापति महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इसी पर बोलें और सभी लोग इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, ईडब्ल्यूएस वालों का जो पिछड़ा वर्ग है, जो सामान्य जाति को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है, सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि हर तहसील लेवल पर इनके लिए एक छात्रावास बनाया जाये। गरीब हर समाज के अन्दर हैं, ये गरीब लोग हैं, तभी सामान्य जाति में से इन लोगों को 10 प्रतिशत रिज़र्वेशन दिया गया है।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, इन लोगों के लिए मैं मांग करता हूं कि हर तहसील लेवल पर इनको वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो अन्य रिज़र्वेशन वालों को दी गई हैं। इनके लिए बिल्डिंग बनायी जाये, इनको रहने व खाने के लिए सभी व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, अब आप बोलने नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। चलो, ठीक है कोई बात नहीं है, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक्यू। श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आय-व्यय वर्ष 2022-23 का यह जो बजट है। इसको मैं क्या संज्ञा दूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये हाथी वाले दांत हैं, देखने में तो बहुत सुन्दर हैं। सभापति महोदय, बजट जब पढ़ रहे थे तो बहुत सुन्दर लग रहा था पर इसके अन्दर घुसकर के देखा तो वह हाथी के दांत, जैसे खाने के काम में नहीं आते हैं, वैसे ही यह बजट काम का नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे पहले जब इस सरकार ने पहला बजट पेश किया तो राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर बेसहारा पशुओं, आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा की गयी थी। यह बात मैं बार-बार इस सदन में क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने शपथ ली थी, उस टाइम मैंने एक और शपथ ली थी कि जब तक आवारा पशुओं का सरकार प्रबन्ध नहीं करेगी, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं।

सभापति महोदय, उसके बाद में क्या हुआ, अगले बजट के अन्दर फिर वही जिक्र कि हम नन्दीशाला बनायेंगे और किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलायेंगे। सभापति महोदय, मैंने छोटा मुंह बड़ी बात कही। मैंने सरकार को सुझाव दिया कि आप स्टाम्प ड्यूटी और बढ़ा दो, शराब पर टैक्स लगा दो। सभापति महोदय, मेरे बाद में मैंने हमारे विपक्ष के नेता महोदय से कहा कि आप भी, साहब, सहमति दे दो। साहब ने खड़े होकर इस सदन के अन्दर कहा पूरा विपक्ष आपके साथ है। आप इन पशुओं का प्रबन्ध करो, किसानों को इससे निजात दिलाओ और पशु भी परेशान हैं।

सभापति महोदय, ये तीसरा बजट है। बार-बार वही बात रिपीट, पंचायत समिति के स्तर पर एक नन्दीशाला बनाओगे। भई, आप कितनी बड़ी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बनाओगे, 10 फीट की बनाओगे, 1000 पशुओं की बनाओगे, 200 की बनाओगे, कोई खुलासा तो करो। यही नहीं इस बजट में एक झुनझुना और पकड़ा दिया। वह यह है कि आगामी वर्ष में जिस पंचायत के अन्दर कोई एनजीओ होगा, सार सम्भाल करने वाला, वहां हम एक करोड़ रुपये देंगे। सभापति महोदय, आप जानते हो गांवों के अन्दर कौन-सा एनजीओ है। गांवों के अन्दर गांव के आदमी हैं। अगर सरकार गौशाला बनाकर के गांव के लोगों को सम्भला दे तो गांव के लोग बिलकुल सम्भाल लेंगे।

सभापति महोदय, यहां मैं एक सुझाव सरकार को और देना चाहता हूं, अभी समय है चेत जाओ, नहीं तो बजट में आप यह तीसरी बार रिपीट कर रहे हो और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आपने विकास पथ के नाम पर विधायकों को बेवकूफ बनाकर के कहलवा दिया, हमने घोषणा कर दी कि ये-ये विकास पथ बनेंगे। आज तक एक भी विकास पथ नहीं बना।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आपने पेज संख्या-80, पैरा संख्या-141 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर के अन्दर, जो पहले बने हुए खाले थे, वे टूट गये, उनका पुनर्निर्माण करोगे, आ गई बात समझ में, वे भी किसान हैं। सभापति महोदय, मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि पक्के खाले बनाने हैं तो प्रथम चरण के अन्दर बनाओ। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा, गंग-कैनाल वहां एक बीघा में जितना अनाज होता है, वहां एक कैनाल में प्रथम चरण में होता है। यानी, प्रथम चरण में 10 गुना आमदनी ज्यादा है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे हमारी थी, चाहे आपकी, यह जनता जल योजना है। इस जनता जल योजना ने गांवों को बर्बाद करके रख दिया है। इस जनता जल योजना के कारण लोग प्यासे मर रहे हैं। पंचायतें हाथ खड़े कर रही हैं, आये दिन बिजली के बिल कट रहे हैं, गांव के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। इस योजना को भी सरकार समाप्त करे।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की थी। सभापति महोदय, मैंने यह भी सुना था कि जिस तरह से गीता के अन्दर जो शब्द लिखे हुए हैं, सही होते हैं, इसी तरह से राजस्थान विधान सभा का जो बजट है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है, वह सही होता है तो आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सर्वप्रथम किसानों का कर्जा माफ करें, बेरोजगारी भत्ता दें, फिर मोदी जी वाली दुगुनी आय का हिसाब लें। सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस सरकार ने संविदाकर्मियों को परमानेन्ट करने की बात कही थी। कहां गई आपकी वह घोषणा? कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। मोटे रूप में, मैं एक-एक बात पर नहीं जाना चाहूंगा और मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम40 परसेंट घोषणाएं आपकी बिलकुल ही अधूरी हैं, चाहे कोई-सा भी बजट उठाकर देख लो।

सभापति महोदय, बिजली के बारे में इस सरकार ने कहा था कि राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। मैं आत्मनिर्भरता का हाल बता रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सूरतगढ़ थर्मल पावर है और आठवीं-सातवीं इकाई में बिजली भी सस्ती बनती है। आप वाहवाही लूट रहे हो कि हमने इतने किसानों को कनेक्शन दे दिये और पिछली सरकार ने पांच वर्ष में बहुत कम कनेक्शन दिये और आगामी दो वर्षों में आप सारे कनेक्शन कर दोगे।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, समय निर्धारित है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, क्या कर रहे हो।

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं। आप प्लीज बोलिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): तो फिर मैं सीधा-सीधा अपनी बात पर ही आ जाऊं। क्या पड़ा है इन आलोचनाओं में, मैं मेरी बात पर आ जाता हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सूरतगढ़ को जिला बनाओ। आप बनाओ, अन्यथा आने वाली सरकार बनायेगी। क्यों बनायेगी कि वहां जिले के सब नार्म्स हैं। सूरतगढ़ के अन्दर छावनी है, केन्द्रीय फार्म है, हवाई अड्डा है, थर्मल है, बीएसएफ की यूनिट है, बहुत सारे यंत्र और भूमि उपलब्ध है। हर तरह की सुविधा सूरतगढ़ में है इसलिए मैं बार-बार सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग करता हूं। सूरतगढ़ सीएचसी है वहां कम से कम डेढ़ लाख की जनसंख्या है वहां सुविधा होनी चाहिए जिला स्तर की तो आप जिला स्तर का नहीं तो कम से कम उसको उप जिला स्तर का हास्पिटल क्रमोन्नत करो।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं 1977 के अन्दर सूरतगढ़ में कालेज बना था और उस कालेज का नाम स्वर्गीय गुरुशरण

(श्री रामप्रताप कासनियां)

छाबड़ा महाविद्यालय है। उसके अन्दर सिर्फ एमए इतिहास है, कोई दूसरा सब्जेक्ट आज तक नहीं खोला और वहां 2 हजार छात्र रेगुलर और 9 हजार छात्र घर पर तैयारी करके उसके अन्दर परीक्षा देते हैं। इतना बड़ा कालेज है और उस कालेज की हालत यह है कि उसके चारदीवारी नहीं है, चारों तरफ टूटी पड़ी है और कच्ची बस्तियों का पानी उसके अन्दर भरा हुआ है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र उस कालेज के अन्दर हर विषय राजस्थानी, पंजाबी, विज्ञान, गणित सब खोलो।

सभापति महोदय, नगरपालिका सूरतगढ़ के अन्दर पेरीफेरी क्षेत्र में टीसी की भूमि बहुत ज्यादा पड़ी है उस भूमि को भूमाफिया कोड़ियों के भाव खरीदते हैं। मैं उदाहरण दूं तो एक मुरब्बा 5 लाख, 2 लाख में खरीद लिया और एक कमेटी ऐसी बनायी है सरकार ने, इस पर ध्यान दें, उस कमेटी के अन्दर कोई जन प्रतिनिधि नहीं है। आपके भी जन प्रतिनिधि हैं, प्रधान है, नगरपालिका के चेयरमेन है, विधायक तो मैं बीजेपी का हूं, कोई गुनाह नहीं किया। पूरे राजस्थान में अलाटमेंट कमेटी में सब जगह जन प्रतिनिधि हैं पर उस पेरीफेरी क्षेत्र में करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे करते हैं पर कोई जन प्रतिनिधि उसमें सदस्य नहीं है। उस भूमि को खरीद कर भूमाफिया खातेदारी प्राप्त कर लेते हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग बहुत है।

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं यह कह रहा हूं कि पेरीफेरी क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी इसलिये नहीं दी जा रही है कि तरह-तरह के राइडर लगा रखे हैं, जैसे पेरीफेरी यह बहुत बड़ा कलंक है, हेराफेरी है यह। पेरीफेरी नहीं है यह हेराफेरी है और भूमाफियाओं की जेब भरने की कहानी है।

सभापति महोदय, मैं सदन में चार्ज लगाऊं तो अच्छा नहीं है। राज्य सरकार के नुमाइंदे दो-दो, तीन-तीन घूम रहे थे वहां पहले और जमीन खरीदी है कम से कम सैकड़ों मुरब्बे। यह हकीकत है और आगे भी वह खरीदी हुई भूमि है उन व्यक्तियों का सरकार पूछे तो नाम तक बताने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, जेतसर के अन्दर पी.एच.सी. है उसको सी.एच.सी. का दर्जा दिया जाये।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो कनेक्शन हैं, ...

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सारे के सारे जो जी.एस.एस. निर्माण हुए हैं उनमें घटिया मैटेरियल लगा हुआ है।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अब क्या बोलना। मैं सोचता था पारीक साहब ही करते हैं, पर मेरे लिए तो सब एक समान हो गये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने बजट भाषण पर शामिल होने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी विधान सभा क्षेत्र के गांव सूडसर में उप तहसील खोले जाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सूडसर क्षेत्र की वर्षो से लम्बित मांग को मेरे और जनता के आग्रह पर पूरा किया। इसके साथ ही दुलचासर पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से लम्बे संघर्ष के बाद देश में नरेगा जैसा महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ, इस बजट में राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। यह एक बेहतर कदम है। इस बजट में मनरेगा में 100 के बजाय 125 दिन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से काम दिये जाने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि आज बढ़ती महंगाई में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी साठ रुपये प्रति दिन लागू करने का प्रावधान करें। सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का प्रावधान किया है जो कि अच्छी बात है मगर साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर एग्रीकल्चर बेस्ड है जहां हमारे मुख्य मंत्री ने घोषणा भी की है कि ज्यादा कनेक्शन देंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी जवाब दें तो बतायें कि बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शन जब भी किसी सरकार ने किये हैं, सबसे महंगी

(श्री गिरधारीलाल)

श्रेणी है। जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने सभी कृषि कनेक्शन की रेट्स वापस ले ली मगर बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शन की उन्होंने यथास्थिति रखी। हमने पूछा ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह जी से कि यह श्रेणी किसमें आती है मंत्री जी, तो कहा कि पता नहीं तो हम इसकी आस लगाये बैठे हैं जो बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन हैं उनकी रेट बीजेपी के राज में जो बढ़ा दी गई थी वह माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय वापस लेने का जरूर विचार करेंगे।

सभापति महोदय, इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना में बीमा की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया है। इस वर्ष में इस योजना पर 930 करोड़ रुपये खर्च होना बताया है। यह जनता का धन बीमा कम्पनियों को गया है। अगर सरकार इसी धनराशि से अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाती तो हम एक बेहतरीन स्वास्थ्य तंत्र विकसित कर पाते इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि हम प्रदेश में अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करने में अपना धन लगायें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। प्लीज। एक मिनट और ले लें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, अभी राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम दुबारा शुरू करने की घोषणा की, वह बहुत क्रान्तिकारी कदम पूरे देश के लिए है। उनके लिए हमारा सदन हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता है। इस तर्ज पर पूरे देश में यह प्रचलन चल चुका है तुरन्त ही यूपी के मुख्य सचिव ने हमारे मुख्य सचिव से राय मांगी तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, बजट साल में एक बार आता है। हमारा यह तीसरा साल है। यह जनता की अदालत है। हमारे क्षेत्र में मायड़ भाषा है, राजस्थान में मायड़ भाषा होती है। हम मांग करते हैं कि मायड़ भाषा को दो नम्बर का दर्जा दिया जाये जिससे उन छात्रों को जो आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षा देते हैं, लाभ मिल सके।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड और कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान के बीकानेर जिले में नहरी क्षेत्रों में दी गई बैल्टों पर ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है। सभापति महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि राजस्थान में समान रूप से हर किसान को

(श्री गिरधारीलाल)

बीकानेर जिले की तर्ज पर, चाहे ट्यूबवैल का क्षेत्र हो, चाहे बारानी हो, तमाम किसानों को नहरी तर्ज पर अनुदान दिया जाय।

श्री सभापति: थैंक्यू। श्री रामनिवास जी गावड़िया।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, अन्त में यही कहूंगा कि जो हमारे सहकर्मी हैं, जन सहयोगी हैं, रोजगार सहायक हैं, तमाम कर्मचारियों को स्थाई करें। यह कहते हुए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनिवास जी।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है इसमें आम नागरिक के खुशहाल जीवन और तमाम वर्गों के कल्याण के संकल्प को लेकर विभिन्न लोकप्रिय योजनाओं के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। सभापति महोदय, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बजट के माध्यम से मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं और छात्र वर्ग के तमाम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बजट में उन तमाम बिन्दुओं पर चर्चा की गई जिससे पूरे राजस्थान में एक गुड गवर्नेंस का और जो हमारी सरकार का मैसेज जाना चाहिये, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का मौका मिले।

माननीय सभापति महोदय, अभी देश में इस तरह की स्थिति है कि जहां देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जब केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया तो सब लोगों की निगाह थी कि किस तरह से केन्द्र सरकार बजट के माध्यम से तमाम देशवासियों को सौगात देगी और उन तमाम किसानों और मजदूरों को फायदा पहुंचायेगी। लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया तो देखने को मिला कि जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उन्होंने इस देश के किसान और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों के लिये जो तीन काले कानून लागू किये, उस समय जब इन्होंने लागू किया तब भी इन्होंने यह नहीं पूछा कि यह लागू क्यों किये जा रहे हैं और जब देश से माफी मांग कर इन्होंने उनको वापस लिया तब भी इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर इस बात के फायदे गिना रहे थे कि जब लागू किया तब क्या फायदे थे और जब इनको हटाया गया तब ये फायदे गिना रहे थे। देश की जनता इस बात को टकटकी नजर से देख रही थी और

(श्री रामनिवास गावड़िया)

उसका परिणाम, माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में यूपी चुनाव हो रहे हैं, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि इनके विधायकों के, इनके प्रत्याशियों के रोजाना जूते पड़ रहे हैं और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह जनता इस बात का सबूत है कि इन्होंने जिस तरह से देशवासियों से वादे किये, जिस तरह से इन्होंने देश के नौजवानों से वादे किये, किसानों से वादे किये लेकिन उससे कोसों दूर इन्होंने बजट में कुछ भी नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया। आज हम लोगों ने सरकार के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया, इससे आज प्रदेश में खुशी का माहौल है। आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विभिन्न सरकारें जो सत्ता में बैठी हैं, वे लोग भी इस बात की सराहना कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू की।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दोहरी नीति पर काम करती है। ये जो विपक्ष में बैठे हैं, इनकी गलती नहीं है। यह बार-बार नरेन्द्र मोदी जी का नाम लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। ये जो सदन में लोग बैठे हैं, यही नहीं, इनसे नीचे के भी चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो, इन्होंने हमेशा वोट नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर मांगे हैं लेकिन अब जनता समझ चुकी है और उसी का परिणाम आप लोगों को आने वाले समय में यूपी की जनता ने जो इनके प्रत्याशियों को दिया है, इनके विधायकों को दिया है, वह सबके सामने आ जायेगा।

साथियों, मैं आप सब लोगों को सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से आज यूक्रेन में हमारे कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उनको सकुशल यहां लौटाया जाय। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि वह किन विषम परिस्थितियों में वहां रह रहे हैं। उनको वापस यहां देश में लाने के लिये केन्द्र सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी

(श्री रामनिवास गावड़िया)

सरकार ने, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की इस बजट में घोषणा की है। इसमें चिकित्सा में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, जिसमें 5 लाख रुपये सालाना प्रति परिवार दिये गये थे, उसमें वृद्धि करते हुए आज 10 लाख रुपये किये गये हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू कर प्रदेश वासियों को एक सौगात दी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर आम जन जीवन को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जो घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समानीकरण के नाम पर प्रदेश में कई स्कूलें बंद कर दीं। इसके अलावा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज को बंद करने का इन्होंने काम किया। वहीं हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लेकर जा रही है। इन्होंने पूरे प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे स्कूल को क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे प्रत्येक कस्बे में महाविद्यालय खोलने की बात हो, हर तरीके से नौजवानों का भविष्य हम कैसे सुनहरा कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया।

(समय: 15.36 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा हमारी सरकार ने पांच हजार की आबादी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से इस बार जो कृषि बजट पृथक से लागू किया गया, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि हमारी सरकार ने इन विषम परिस्थितियों में जो बजट पेश किया, आज हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं, डीजे बजाकर लोग नाच रहे हैं, तो इन लोगों को इस बात की तकलीफ है कि जब हम लोग क्षेत्र में जायेंगे तो जनता हमसे जवाब मांगेगी। आज मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से जब हमारे देश में स्थितियां बद से बदतर से हो गई थीं तो

(श्री रामनिवास गावड़िया)

हमारी सरकार ने, हमारे नुमाइंदों ने जब केन्द्र सरकार के सामने इस बात को रखा तो देश के प्रधान मंत्री ने हमारी बात को न मानकर इन्होंने अपने चुनावी प्रचारों पर ध्यान दिया। लेकिन स्थिति क्या हुई, देश में प्रवासी भारतीय लोग सड़कों पर रहे, कितने किसान लोग मारे गये? लेकिन हमारी यूपीए की सरकार ने जो मनरेगा योजना लागू की थी, आप सब लोगों से कोई छिपा नहीं है, कोरोना काल में जो आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, उसको वापस पटरी पर लाने का काम नरेगा के माध्यम से किया गया। उसमें हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किये हैं और शहरों में पहले नरेगा नहीं चलती थी, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से घोषणा की है। जबकि केन्द्र सरकार ने वर्तमान बजट में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये नरेगा के कम किये हैं जो इस देश का दुर्भाग्य होना चाहिये। जो लोग आधार कार्ड का विरोध करते थे, जो लोग नरेगा का विरोध करते थे, जो लोग जीएसटी का विरोध करते थे, आज इनकी सरकार में बैठे नुमाइंदों के मत और सुझाव इस बात पर अलग हो गये हैं कि किस तरह से देश में नरेगा में आधार कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। इसके अलावा किसानों के लिये 50 यूनिट बिजली फ्री और अन्य उपभोक्ताओं के लिये सब्सिडी की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की, उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में मेरे परबतसर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नवीन खेल स्टेडियम, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बडु, परबतसर में उप तहसील, जावला में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिये जो घोषणा की है, उसके लिए मैं परबतसर वासियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मेरे परबतसर में रीको औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें 1976 में उस समय के भार के अनुसार वहां पर 33 केवी जीएसएस की स्थापना की गयी, लेकिन वर्तमान में वहां भार बढ़ गया है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि जब आप रिप्लाई दें तो वहां अन्य जीएसएस की स्थापना करें और जो पुरानी विद्युत लाइनें हैं, उनको वापस आज की परिस्थितियों के हिसाब से

(श्री रामनिवास गावड़िया)

बिछाने का कार्य करें। इसके अलावा, मेरे परबतसर क्षेत्र में पोस्को कोर्ट या एससी एसटी कोर्ट हो। इसके अलावा, वर्तमान में जावला और बागोट में पीएचसी है, वहां की परिस्थतियों को देखते हुए सीएचसी बनाये जायें। वे तमाम मापदण्ड पूरे करती हैं जो कि सीएचसी के लिए होने चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी बजट पर रिप्लाई दें तो परबतसर वासियों के लिए आपने जिस तरह से पहले बजट में घोषणायें की हैं, उसके अनुरूप आने वाले समय में भी इसकी घोषणा करें। इन्हीं तमाम बिन्दुओं के साथ मैं पुन: हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यह लोक कल्याणकारी बजट पेश किया और इसका मैसेज और संदेश पूरे राजस्थान के हर घर में है कि किस तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 2022-23 की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी बात बजट के विरोध में रखूंगा। जो बजट राजस्थान की जनता के लिए पेश किया गया है, उसे मैं दिशाहीन बजट की संज्ञा दूंगा। इस बजट में युवा, गांव, गरीब, पिछड़े, उपेक्षित, वंचित, युवा बेरोजगारों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई प्रबन्ध जैसी बात नहीं है। बजट को मात्र केन्द्र की जन हितैषी सरकार को यह बताकर अंकित किया गया कि बजट कटौती के कारण प्रदेश में स्वयं का प्रबन्ध करके कार्य करेंगे, जबकि प्रदेश को लगातार केन्द्र से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वह मिल रही है। सड़क निर्माण का कार्य पूरे प्रदेश में केन्द्र की योजनाओं से चल रहा है। पेयजल को लेकर प्रदेश को पूरे देश में सबसे अधिक बजट अलाट कर आम जन को राहत देने का कार्य केन्द्र की सरकार कर रही है।

मेडिकल लाइन को लीजिये तो प्रदेश में सभी जिलों में मेडिकल कालेजें बन रही हैं, वे केन्द्र के बजट से बन रही हैं। दूसरी ओर, कोविड टीकाकरण जैसा कार्य दुनिया के सभी देशों के बनिस्पत भारत में अधिकतम हुआ है, राजस्थान में युवा टीकाकरण नि:शुल्क हुआ है जो कि कोविड प्रबन्धन को लेकर राज्य सरकार असत्य प्रशंसा कर रही है। माननीय मोदी जी

(श्री हमीर सिंह भायल)

ने ठीक प्रबन्ध को सराहा, अच्छी बात है, लेकिन हर मामले को केन्द्र की सरकार पर डाला जाना ठीक बात नहीं है।

पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बेरोजगारों के लिए, भर्ती को उलझन में डालना, ग्रामीण विकास को गर्त में डाल दिया। पंचायती राज में पंचायत पुनर्गठन को लें तो दो वर्षों तक नियमों को ताक पर रखकर नयी पंचायत के गठन तथा समिति के गठन जैसे कार्य किये, जिससे आमजन भी परेशान है और पंचायती राज के चुनावों को देखा जाये तो दो साल का समय चुनावों में ही निकाल दिया। पिछले किसी भी कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने 2019-20, 2020-21, 2021-22 बजट में जो घोषणाएं की थीं, उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। अभी कई माननीय सदस्यों ने भेदभाव के लिए बोला। भेदभाव इससे बढ़कर नहीं हो सकता है कि बाड़मेर में सात विधान सभा क्षेत्र हैं। सात विधान सभा क्षेत्र के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि गत बजट और इस बजट में मुख्य मंत्री जी द्वारा तीन-तीन रोड्स रिपेयरिंग के नाम पर दी गयी हैं, वे एक ही विधान सभा क्षेत्र में दी गयी हैं, जहां से वर्तमान में आज मंत्री विराज रहे हैं। शिव से माननीय विधायक कल अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे।

डीएमएफटी के लिए मैं आपको निवेदन करूं तो 80 करोड़ की लागत से कमेटी ने जो निर्णय किया, उसमें भी पांच विधान सभा क्षेत्र में 9 करोड़ की और दो विधान सभा क्षेत्र में 60 करोड़ की, माननीय सभापतिजी, इससे ज्यादा भेदभाव नहीं हो सकता है। विकास हर विधान सभा क्षेत्र के लिए चाहिये। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण के लिए चाहिये। शिक्षा हर एक को चाहिये। चिकित्सा हर एक को चाहिए, पानी हर एक को चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पोकरण-फलसूण्ड जोधपुर डिवीजन में बाड़मेर और जैसलमेर के लिए जो महती योजना है, आज सिवाना एक टहल में है। गत बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इस बार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, परन्तु मैं आपको धरातल की बात कह रहा हूं कि मेरे यहां 186 गांव हैं, वे आज भी पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं। वहां पर चपरासी से लेकर एक्स.ईएन. तक 13 पोस्ट हैं, एक अधिकारी तीन साल से डेपुटेशन पर लगा हुआ है। इससे ज्यादा बढ़कर क्या भेदभाव हो सकता है?

(श्री हमीर सिंह भायल)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पेयजल की इस योजना को अगर गम्भीरता से नहीं लिया गया, एक समय था कि बाड़मेर में सिवाना कश्मीर था, पर पिछले 15 साल से बारिश कम होने की वजह से आज की तारीख में पीने के लिए और गरीब के लिए और पशुधन के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है और उस योजना में आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एक अधिकारी भी नहीं है। मेरे वहां पर तहसीलदार अभी लगाया गया है। तीन तहसीलें होते हुए भी तीन साल में एक तहसीलदार नहीं रहा। पटवारियों की तो गई, ग्राम सेवक भी नहीं। सारे अधिकारी, डाक्टर, चिकित्सा विभाग में डाक्टर नहीं। शिक्षा विभाग में टीचर नहीं। आप कालेज खोल रहे हैं, एक खोलने से कुछ नहीं होगा, लेक्चरर नहीं है, प्रिंसीपल नहीं है। एडमिशन के लिए जिला हैडक्वार्टर से बुलाया जाता है और बच्चों का एडमिशन हो जाता है, उससे पार पड़ने वाली है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की महती आवश्यकता है, उसमें आप नर्मदा प्रोजेक्ट सिन्दरी में जो 13 गांव हैं, होडू से लगाकर और उसके बाद बाड़मेर प्रोजेक्ट का पानी सिर्फ तीन किलोमीटर पर आया हुआ है। उस पानी को अगर नहीं देंगे तो होडू का हथियारा विलेज, जो कि रेवेन्यू विलेज है, उसके लिए पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। सिन्दरी में धनवा, भाटा, खारा, मीठा, छोडो की ढाणी, उनियाली, गालानाड़ी, दाका, गमठायू, होडू, दंडाणी, करणा, लोयड़ी, गोणिय, सिवाना में मुकुन्दसर, मायलावास मेड़ी, देवड़ा, फूलड़, धीरा, बागवा, काटाणी, कूण्डल, गुढ़ा, सिनेर, इन्द्राणा, धारणा, पादरू, बिठोड़ा, थापड़, मूठली, कुसीब, थानमाता हिंगलाज, ये जितने भी गांव हैं, वे आज की तारीख में बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। इनके लिए अगर समय रहते प्रबन्ध नहीं हुआ तो गर्मी में यह हालत हो जायेगी कि पीने के लिए पानी कहां से लायेंगे? अभी टैंकरों की सप्लाई भी नहीं हो रही है, इस वजह से मेरा निवेदन रहेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिवाना को नगरपालिका दी। पूरे सात विधान सभा क्षेत्र में दोनों बार में जो रोड दी हैं, 92 करोड़ की, वे एक ही विधान सभा क्षेत्र में दी हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर विराजे हैं। उनके विधान सभा क्षेत्र में भी यही का यही हाल है। शिव के माननीय विधायक कल अपना दर्द बयां कर रहे थे। ये सरकार में हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं, पर मेरे से ज्यादा दर्द उनको भी है, यह पीड़ा उनको भी

(श्री हमीर सिंह भायल)

खटकती है। हमारे चौहटन के विधायक विराजे हैं, इनके भी नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यान दें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को निवेदन करें कि जवाब दें उस समय दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में रोड भी दें और पेयजल का काम भी करें।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कला और संस्कृति को सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। जैसलमेर, बीकानेर, पाली में जो थार महोत्सव चलता था, यह बाड़मेर में 2013 से बन्द कर दिया है। इसलिए कलेक्टर को कहकर इस होली के पर्व पर मेरे यहां कनाना से लेकर शीतला के मेले का अयोजन किया जाता है। उसमें थार महोत्सव को शुरू किया जाये और यह संस्कृति भी जीवित रहे। यह अपना रीति-रिवाज है, कला है, वे भी सुरक्षित रहें, इसको भी जल्दी से जल्दी चालू कराने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पड़ोस के विधायक नंगे पांव तो हो गये हैं और बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो बालोतरा जिला बनना भी अति आवश्यक है। मेरे सिवाना से बाड़मेर जाने के लिए 210 किलोमीटर पड़ता है, सामूंजा से। अगर बालोतरा जिला बनेगा, विकास होगा, मेरे साथी के जो नंगे पांव हैं, उनमें जूते भी आयेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बालोतरा को जिला बनाकर यह सौगात दें। सभापति महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी सिफारिशें करें, क्योंकि हम बोर्डर साइड पर रहते हैं। इसलिए हमको बोलने का मौका भी कम मिलता है और दूरी की वजह से जयपुर भी कम आते हैं। आप बालोतरा को जिला बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। एक निवेदन कर रहा था, जो बिजली के बारे में कह रहे थे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): दो मिनट में कर दूंगा, सभापति महोदय।

बिजली के अंदर इस बार की जो बूंद-बूंद में लोगों ने दस-दस लाख रुपये ट्यूबवैल खोदकर डिमांड भर दिया। आज दिन तक उनको पूरा सीजन चला गया है, सामान नहीं मिला। खम्भे मिल गये, तार नहीं मिले, तार मिल गया, ट्रांसफार्मर नहीं मिला। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय, 2014 के बाद में दीनदयाल ज्योति योजना जो चालू हुई थी उससे हमारे बाड़मेर में 1 लाख 85 हजार कनेक्शन हुए हैं। मैं

(श्री हमीर सिंह भायल)

धन्यवाद दूंगा भारत सरकार ने जो शुरू की थी। अभी भी 1200 करोड़ रुपये आए हुए पड़े हैं। आज दिन तक तीनों डिस्काम में टेंडर नहीं कर पाई सरकार। आज लोग फाइलें लेकर घूम रहे हैं। कई ढ़ाणियां वंचित रह गयी हैं। उनके लिए दीनदयाल ज्योति योजना के जो ये 1200 करोड़ आए हुए हैं, इनके शीघ्र टेंडर करवाए और टेंडर करवाकर किसानों को राहत दें। जल्दी से जल्दी सहायता प्रदान करें।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन रहेगा, स्थायी नवीनीकरण, मेजर रिपेयरिंग सड़कों में जो दूसरी विधान सभा में भी देने के लिए आपसे मैंने निवेदन कर दिया। संविदाकर्मियों को स्थायी करके उनको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): धन्यवाद, सभापति महोदय, मुझे आय-व्यय 2022-23 पर बोलने का आपने मौका दिया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। आज पूरा राजस्थान इस तरह से झूम रहा है जैसे कोई दीवाली या होली मना रहा हो। कौनसा वर्ग है जिसको फायदा नहीं मिल रहा? ये हमारे सामने जो साथी बैठे हैं, अपनी पार्टी की वजह से चाहे उस बात को गलत कहें, लेकिन इनका हर कार्यकर्ता और हर विधायक भी यह कह रहा है कि मुख्य मंत्री जी का बजट एक ऐतिहासिक बजट है, जो आज तक नहीं आया। आप किसी को भी ले लीजिए। चाहे आप रोजगार गारंटी ले लें, सौ के सवा सौ दिन कर दिए और शहर में तो थी ही नहीं रोजगार गारंटी योजना, उसके भी 100 दिन कर दिये।

आप बिजली को लीजिए जो गरीब का एक साधन है, उसमें जिस तरह की छूट दी गयी है 50 यूनिट तक और 150 यूनिट तक 3 रुपये की जो छूट दी गयी है, यह भी गरीब के लिए बहुत हितकारी है। अगर हम सोचें और देखें कि एक सबसे बड़ी मुख्य मंत्री जी की देन, पहले के राज में भी रही और आज भी, स्वास्थ्य के ऊपर उनका इतना फोकस है और ये निरोगी काया, सबको इलाज के हिसाब से जिस तरह से इन्होंने जो काम किया है, चिरंजीवी योजना लाए, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिये। चिरंजीवी योजना में एक चीज और जो स्पेशल है कि अगर किसी भी आदमी के पास चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं है तो भी जिला कलक्टर को अधिकृत किया कि अगर वे

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

चाहें तो उस गरीब का फ्री कैशलेस इलाज करा सकते हैं। समस्त अस्पतालों में फ्री कैशलेस इलाज हो गया, ये ऐसी योजना है जिसके लिए पूरा राजस्थान और हर आदमी खुशी से झूम रहा है। 8 जिलों में नवीन महाविद्यालय, जिनमें धौलपुर को भी मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को कि हमारे जिले का उन्होंने ख्याल रखा।

सभापति महोदय, 1000 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1000 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना किसको कहते हैं। मैं सोचता हूं कि कोई भी ऐसा पंचायत और गांव नहीं बचेगा जिसमें कि उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हो। 100 स्वास्थ्य केन्द्र आपको दिए हैं। सबको मिलेंगे हमको भी मालूम है, लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा तीन तारीख को जब जवाब हो, हमको कहीं चिह्नित कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि पी एच सी, हम जो मांग रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं साहब हमारा नंबर नहीं आया। हम बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खुलेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे जारगा एक बड़ा कस्बा है, उसमें पी एच सी तीन तारीख के जवाब में घोषित करें। मेरा निवेदन है कि वहां पर एक कालेज खुलने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।

डायलेसिस की जो सुविधा है, वह 352 पंचायत समिति मुख्यालयों में, हर सी एच सी में मिलेगी, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फायदेमंद और हितकारी योजना है। सैकण्डरी से सबको हायर सैकण्डरी करना, यह कितना महत्वपूर्ण और अच्छा कदम है क्योंकि कई बार होता है कि पार्टी के हिसाब से, पार्टी के एम एल एज को दे दिए, लेकिन शायद ये एम एल ए और कार्यकर्ता इसीलिए खुश हैं कि एक लाइन में जितने भी सैकण्डरी थे उन सबको हायर सैकण्डरी कर दिया। ये ऐतिहासिक कार्य हमारे मुख्य मंत्री ने किया है। 5000 से अधिक जो आबादी के हैं, उनको भी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय मिलना कितनी बड़ी बात है। 50-50 लाख के सावित्री बाई फूले वाचनालय खोलना, ये सब वह पाइंट मैं गिना रहा हूं जो महत्वपूर्ण-महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो किताब भरी पड़ी है जिसमें एक-एक चीज आपको देखने को मिलेगी।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो हमारे विद्यार्थी हैं, आई ए एस की तैयारी करते हैं और आर ए एस की तैयारी करते हैं, दिल्ली में कोचिंग करते हैं, वे लोग भटकते रहते हैं। उनके लिए मकान नहीं मिलता, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कितना बारीकी से शिक्षा के ऊपर हमारे मुख्य मंत्री

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

जी ने मनन करके उदयपुर हाउस को 250 कमरे बनाकर नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलिटेशन सेंटर बनाने की जो घोषणा की है, मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं और यूथ लोगों के लिए ये कितना हितकारी है कि आज पूरे मार्केट में इस बात की चर्चा है। इंदिरा रसोई जो एक आम गरीब की थाली बनती है। सब जगह चर्चा है कि जहां भी कहीं ऐसी स्थिति है और कोरोना काल में भी जिस तरह से इंदिरा रसोई ने अपना काम किया, आज संख्या बढ़ाकर 1000 की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच है, दिव्यांगों के लिए भी स्कूटी योजना में बढ़ाए हैं और दूसरी देव नारायण योजना, काली बाई योजना में स्कूटियों की संख्या बढ़ाई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इसमें 133 करोड़ और हर जिले में 3 सड़कें की हैं। प्रत्येक विधान सभा में 10 करोड़ का जो दिया है, एक बहुत बड़ी बात है। हम काफी समय से इस बात को लेकर चल रहे थे कि कोरोना की वजह से हम काफी पिछड़ गये हैं। उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पूरी 200 विधान सभाओं को जिस तरह 10 करोड़ की सड़कें दी हैं। मैं उसके लिए भी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, पेयजल योजना की जहां तक हम बात करें तो मेरे यहां सरमथुरा में और बसेड़ी में 87 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत की है। पूरा का पूरा विधान सभा क्षेत्र और हमारे लोग मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। धौलपुर में भी 400 केवी जी एस एस बना दिया। बाड़ी में 132 की जगह 220 के वी जी एस एस दे दिया और सबसे बड़ी बात जो आज देखने को मिलती है, त्रिनेत्र गणेश जी, रणथम्भौर में है। सबकी आस्था का केन्द्र है। सब आदमी चाहे शादी हो या चुनाव लड़ना हो, हर आदमी गणेश जी के जाता है। उस स्थान पर जो रोप-वे की स्वीकृति दी है, वह इतनी सराहनीय है कि हर आदमी और पूरा इलाका साधुवाद और धन्यवाद करता है। जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई पर बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में दिक्कत आती थी लेकिन आज रोप -वे से हर आदमी को भगवान गणेश के दर्शन होंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सोने का गुर्जा में जो चौकी थी, उसको थाने में कन्वर्ट किया, लेकिन मेरा एक निवेदन और है इस मौके पर कि मेरे एक डांग क्षेत्र का एक मदनपुर इलाका है, जहां

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

से एम पी लगा हुआ है, वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। अगर वहां पुलिस चौकी खोल दी जाए तो मैं बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी3 तारीख को इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे। किसानों के लिए जहां तक बात की जाए तो 2 रुपये से 5 रुपये की सब्सिडी, हर किसान इतना खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है।

सबसे बड़ी खुशी की जो बात है, कर्मचारियों की पेंशन। उसने तो चार-चांद लगा दिए सरकार के बजट में। लोग कह रहे हैं कि ऐसा बजट हमने कभी नहीं देखा। मेरे पास सी डी भी है और देखने को मिलेगा कि हर आदमी, चाहे वह कर्मचारी महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, सब इस तरह से झूम रहे हैं जैसे कोई बरसात हो गयी है। इस खुशी का कोई इजहार नहीं कर सकते। महोदय, ऐसे मौके पर जो पेंशन चालू की है, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे सरमथुरा में एक मुंसिफ कोर्ट की आवश्यकता है, अगर तीन तारीख को ये थोड़ा-सा हमको मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे इतना दिया है कि अगर हम हिसाब लगाएंगे तो हमने हर बार जो भी कहा है कि हमें क्रमोन्नत चाहिए, क्रमोन्नत के लिए लिखा कि सैकण्डरी होना चाहिए, हायर सैकण्डरी होना चाहिए लेकिन एक ही लाइन में ऐसी स्थिति कर दी कि अगर हिसाब लगाओ तो 15 स्कूल मेरे क्रमोन्नत हुए हैं जो कि ऐतिहासिक है। ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं मुख्य मंत्री जी का, तीन तारीख में बचे हुए काम हमारे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

(समय: 16.00 बजे)

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, हमारे गांव में ऐसी कहावत है कि जब कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल बोलना पडता है तो देशी भाषा में एक कहावत बनायी गयी है, कि लाल्या को होली में कांई बलग्यो। यही हालत इस बजट की है। अगर हम पिछले तीन बजटों पर नजर डालें तो ऐसे हालात हैं, राजस्थान में पटवारियों की स्थिति है, चार-चार पंचायतों पर एक पटवारी।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पटवारियों के कारण काश्तकार, जनता इतनी परेशान है, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपने कहा कि हमने इतनी भर्तियां कर दीं, उतनी भर्तियां कर दीं, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं।

बजट का वास्तविक स्वरूप तब आता है, जब वह धरातल पर उतर कर आता है। इस बजट को बहुत बढ़िया बजट बताया जा रहा है। उसको बढ़िया तब ही कह सकते थे जब पिछले तीन बजटों की धरातल पर क्रियान्विति सही तरीके से हो जाती, तो जनता को यह विश्वास होता कि इस बजट की घोषणाओं की भी निश्चित रूप से क्रियान्विति होगी। मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है, जिस तरह से तीन बजटों का हश्र हुआ है उसी तरह का हश्र इस बजट का होने वाला है। इस जादूगर ने जो जादू दिखाया है, वह जादू ऐसा जादू है, जिस जादू में न कोई सच्चाई होती है। जादूगर आता है, फूल को चांदी का सिक्का बना देता है, सौ के नोट को दो हजार का नोट बना देता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। यही हालात इस बजट के हैं कि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, यह सब थोथी घोषणाएं हैं। इनकी क्रियान्विति करना सम्भव कार्य नहीं है। जो हालात इस राजस्थान के इस सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बनाये हैं, बेरोज़गारों को भत्ते की घोषणा की थी, वह घोषणा थोथी घोषणा। आज भी बेरोजगार आसमान की तरफ मुंह देख खड़ा है कि आज हमारे बेरोजगारी भत्ता आयेगा।

किसानों के ऋण माफी की घोषणा थी, वह घोषणा। आज सत्ता पक्ष में बैठे कई लोग यह कहते हैं, मोदी जी नहीं कर रहे। वोट तो आपने लिये थे, आपके राष्ट्रीय नेता ने घोषणा की थी कि हम दस दिन में ऋण माफ करेंगे। आज आप मोदी जी का नाम लेकर बचकर निकलना चाहते हो। जब आपने घोषणा की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इन बैंकों का ऋण माफ किया जाये। यह आप चिन्ता कीजिये। आप मोदी जी, मोदी जी चिल्ला कर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते जा रहे हैं। यह आपकी बजट की घोषणाएं हैं और चुनावी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं पर अगर जनता को आपने जवाब नहीं दिया, अगर उन पर क्रियान्विति नहीं की तो निश्चित रूप से जनता आपको धोखेबाज कहेगी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): पता लग जायेगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हां लग रहा है न। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विधायक जी, आप अपने स्थान पर जाइये। स्थान पर जाइये। माननीय सदस्य, स्थान पर जाइये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): संविदाकर्मियों को आपने नियमित करने की बात कही थी।

श्री सभापति: नये-नये आये हो, कुछ सीखोगे तो अच्छा रहेगा। जरूरत नहीं है आपको इस तरह बीच में, इस तरह बैठे-बैठे बोलने की। ... (व्यवधान) अभी तो पुराने ही नहीं सीख रहे, वह क्या सीखेगा?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जहां तक संविदाकर्मियों को नियमित करने का सवाल है, आपके चुनावी घोषणा पत्र में और बजट की घोषणाओं में भी कहा गया था कि संविदाकर्मियों को हम स्थायी करेंगे, आज तक वह संविदाकर्मी भगवान भरोसे बैठा है। पांच-पांच हजार रुपये तनख्वाह लेकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत कर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर। इनको कोई जरूरत नहीं। आप इधर बताओ। मेरा ज्ञानवर्धन करो आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा में 30 किलोमीटर रोड प्रत्येक विधान सभा में दिया गया था। पिछले बजट की घोषणा है, आज भीलवाड़ा में एक किलोमीटर रोड, नोन पेचेबल सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यह बजट की घोषणाओं के हालात बता रहा हूं। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर, सांगानेर पुलिया पर 30 करोड़ रुपये की लागत से एक ओवरब्रिज का निर्माण करने की इस बजट में घोषणा हुई थी। उस बजट में एक इन्च का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है। किस तरह से हम विश्वास करें? इस बजट का छलावा जो आपने पेश किया है, यह बजट साकार आकार ग्रहण करेगा, इसका विश्वास न तो जनता को है। तीन बजटों की हालत देखते हुए इस बजट का विश्वास तो जनता कतई नहीं करेगी।

आज आपने पेंशन की घोषणा की। 2004 में जो कर्मचारी लगे, वह पेंशन पर जायेंगे 2030-32 में। आपको क्या लगेगा? घोषणा कर दी। मैं घोषणा कर दूं, 2024 में पैदा होने वाले हर बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, तो 18-20 साल की उम्र होगी तब जाकर देंगे, हमारा उसमें क्या लगेगा? पेंशन की घोषणा करके, असत्य वाह-वाही लेने का मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

रहा, जब आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसीलिये मैंने कहा लाल्या को होली में कांई बलग्यो।

आपने कृषि का अलग से बजट पेश किया है। उस कृषि बजट में, राजस्थान की जीएसडीपी पर 30 परसेंट हिस्सा एग्रीकल्चर का होता है और आपने केवल 5.82 परसेंट का बजट राजस्थान की कृषि को दिया है। यह कृषि के साथ, काश्तकारों के साथ भारी अन्याय है।

महिलाओं को इस पूरे बजट में अछूता रखा गया है। राजस्थान का 50 प्रतिशत हिस्सा महिला है। उन 50 परसेंट महिलाओं को इस पूरे बजट में किसी योजना के साथ नहीं जोड़ा गया।

मेरे भीलवाड़ा में नर्सिंग कालेज की घोषणा पिछले बजट में हुई थी, उस नर्सिंग कालेज का आज तक कहीं दूर-दूर तक पता नहीं है। शुरुआत होना तो दूर है, कहीं बिल्डिंग की घोषणा, कि भई यह कालेज है, इसमें एडमिशन हो रहे हैं, उस बजट का क्या होगा, नंदीशालाओं का हाल हुआ, वैसा होगा। आपने पहले बजट में नंदीशालाओं की घोषणा की थी। इस बजट में भी आप नंदीशाला की घोषणा कर रहे हैं। किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? आप हर बजट में हर योजना को जोड़कर वह की वह घोषणा रिपीट करते हैं। एक बार विचार करिये, आपको मोदी का जो फोबिया हो रखा है, उस मोदी ने तो देश को आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया दुनिया में। इस राजस्थान को हमने कहां पहुंचा दिया, इस पर चिन्ता करिये।

यूपी जैसा प्रदेश, जो देश में कानून-व्यवस्था व अन्य क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, आज योगी के राज में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर आ गया। हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, आज उत्तर प्रदेश का स्थान पांच सालों में दूसरे नम्बर पर आ गया। राजस्थान कौनसे नम्बर पर पहुंच गया, हमको यह सोचना चाहिये। अपराध के क्षेत्र में ईज आफ डूइंग बिजनस के मामले में, कानून व्यवस्था से पूरी तरह प्रभावित यूपी जैसा क्षेत्र आज देश में दूसरे नम्बर पर है। राजस्थान में उद्योगों की दुर्दशा जितनी इस शासन काल में हुई है, आज मेरे भीलवाड़ा के उद्योग, जो मैनचेस्टर कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जहां 10 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है, उस भीलवाड़ा की यह हालत है कि वहां के उद्योगपति एमपी व गुजरात जाने को मजबूर हो रहे हैं। आज ऐसी हालत है। उद्योग मंत्री यहां विराजी हुई थीं, कहीं पधार गई हैं। मेरा निवेदन रहेगा, भारत सरकार ने एक टैक्सटाइल पार्क राजस्थान को देने की घोषणा की है। उस टैक्सटाइल पार्क का हक केवल और केवल भीलवाड़ा का बनता है। यह पूरा भारत जानता है कि भीलवाड़ा भारत का मैनचेस्टर है। उस मैनचेस्टर के कारण, वहां इतना कपड़ा बनता है, कम से कम डेढ़-दो लाख मजदूर, वहां कार्यरत हैं। ऐसे क्षेत्र को उपेक्षित करके, वह टैक्सटाइल पार्क, वह जोधपुर ले जाना चाहते हैं। इस तरह का अन्याय और उपेक्षा अगर उद्योगों की होती है, जोधपुर में टैक्सटाइल का इतना कोई कारोबार नहीं है। वह टैक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा का हक बनता है। मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा का हक भीलवाड़ा को मिलना चाहिये। टैक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा होना चाहिए, राजस्थान सरकार से मैं यह मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): धन्यवाद सर।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, एक मिनट। सर प्लीज। एक मिनट।

श्री सभापति: धन्यवाद का आदान-प्रदान हो गया, अब और क्या बाकी रह गया?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैंने तो उनका दिया है, सर। उन्होंने समर्थन किया।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि मेरे भीलवाड़ा में पुर उप नगर है, उस उप नगर पुर में जब मैं धरने पर बैठा था, वहां मकानों में दरारें आ रही थीं और पचास दिन का धरना दिया था। उस धरने के वक्त में मुख्य मंत्रीजी स्वयं पुर पधारे थे और उन्होंने मौका देखा था, वहां के पुर क्षेत्र की पचास हजार की आबादी है, तो उस आबादी ने मुख्य मंत्रीजी का स्वागत भी किया और बहुत अभिनंदन भी किया कि आप

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हमें देखने के लिए पधारे हैं। उस वक्त जनता ने यह मांग की थी पुर की पी.एच.सी. 35-40 वर्ष पुरानी पी.एच.सी. है, वह पी.एच.सी. आज पचास हजार की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है और उस पुर की क्षेत्र की जनता की बहुत भारी मांग है कि उस पी.एच.सी. को शहरी सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराया जाये। मैं लगातार तीन वर्षों से यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जे.पी. चन्देलिया। थैंक यू।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सरकार को यह निर्देशित करें कि पुर में शहरी सी.एच.सी. का क्रमोन्नयन जरूर हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनकी सही मांग है।

श्री सभापति: आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात करें। आप तो मिनिस्टर हैं। आप उनसे बात करें। पास में मंत्रीजी बैठे हुए हैं। मंत्रीजी आपके मित्र हैं, आप इनसे बात करो।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान ने 23 फरवरी, 2022 को जो बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आम नागरिकों के खुशहाल जीवन के लिए दिया है। आम नागरिक में कृषक आ गया, पशुपालक आ गया, मजदूर आ गया, युवा आ गया, वृद्ध आ गया, विद्यार्थी आ गया, महिलाएं आ गयीं, प्रोफेशनल लोग भी आ गये, शिक्षाविद् आ गये, चिकित्सा विशेषज्ञ आ गये, जन-प्रतिनिधि आ गये, सिविल सोसाइटीज आ गयीं, समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बजट राज्य की जनता को दिया है। उन्होंने यह बजट देते समय इस बात का ध्यान रखा है कि राज्य के सतत विकास की गति बनी रहनी चाहिए, उसमें गिरावट नहीं हो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज के सभी वर्गों को और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बजट जनता को प्रस्तुत किया है, राजस्थान की जनता को प्रस्तुत किया है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत मैसेज की राजनीति करते हैं, मैसेज सकारात्मक मैसेज देते हैं और मिशन मोड पर काम करते हैं ताकि जनता को अधिक से अधिक फायदा मिल सके।

मैसेज दिया उन्होंने वर्ष 2012-13 में जब उन्होंने राज्य को प्रथम जेण्डर बजट पेश किया था। प्रथम जेण्डर बजट राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने 2012-13 में पेश किया। इसी प्रकार पेपरलेस बजट भी माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिया, वह दिया 2021-22 में और यह बजट जो 2022-23 का उन्होंने दिया है, यह भी राज्य का पृथक से जो एग्रीकल्चर बजट है, वह दिया गया है माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा और अगर परफोरमेंस की बात करें, राजस्थान के बजट परफोरमेंस की बात करें तो 70 परसेंट से भी ज्यादा वादे राज्य सरकार के द्वारा निभाये जा चुके हैं और 85 परसेंट से भी ज्यादा जो घोषणाएं हैं, जो राज्य सरकार ने की थीं, वह पूरी हो चुकी हैं। यह कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, जैसा कि मेरे विपक्ष के साथीगण बता रहे थे, यह आंकड़े नहीं हैं, यह यथार्थ है, धरातल पर जो चीज है, जो राज्य सरकार ने दिया है, जो हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है, यह उसका नक्शा है।

माननीय सभापति महोदय, जिस दिन 23 तारीख को यह बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया उस दिन का नजारा राजस्थान के हर गांव में, हर ढाणी में, हर नगर में, हर शहर में न केवल राजधानी में बल्कि राज्य के अन्तिम छोर तक वह नजारा देखने लायक था। राजस्थान के कर्मचारी जो 01 जनवरी, 2004 और उसके बाद राजकीय सेवा में आये हैं उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा जश्न मनाया है और इतना ही नहीं मैंने तो यह भी देखा है कि जो लोग अपनी डी.पी. पर, माननीय सभापति महोदय, जो लोग अपने मोबाइल की डी.पी. पर कमल के फूल की फोटो रखते थे, उन्होंने हाथ का निशान लगा दिया, यह बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं कि वहां पर 23 तारीख को ऐसा हुआ है कि जैसे कि

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

कोई दीपावली मन रही हो तो यह एक बहुत बड़ा बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है।

अभी मेरे सामने वाले माननीय सदस्य यह बोल रहे थे कि 33-34 साल बाद आयेगा तो इनका क्या लगा। यह घोषणा कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही था तो यह घोषणा आप कर देते, कहां पर दिक्कत थी, किसने रोका था जब आपका राज था? 01 जनवरी, 2004 से जो पेंशन बंद की गयी तो वह इन लोगों के हितों पर कुठाराघात था। अगर आदमी को पेंशन ही नहीं मिले, 34-35 साल नौकरी करके जाये और जो लम्पसम पैसा मिलता है, माननीय सभापति महोदय, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप बहुत अनुभवी हैं और यहां पर जो बैठे हैं, वे सब यह जानते हैं कि रिटायरमेंट का जो पैसा मिलेगा, चंद महीनों में, चंद सालों में कुछ सोशल रेस्पांसिबिलिटीज में खतम हो जायेगा तो पूरी जिंदगी वह कर्मचारी क्या करेगा? इसलिए यह एक बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है और जिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है, उनके परिवारों को मिला है, लाखों कर्मचारी हैं, एक परिवार में एवरेज पांच लोग तो आप मानेंगे, बहुत बड़ा है। यह जो घोषणा है, मैं आज कहता हूं इस सदन में और यह रिकार्ड पर रहेगा कि यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्री की यह जो पुरानी पेंशन योजना को चालू करने की घोषणा है, यह अगली बार कांग्रेस को वापस राज में लाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फेक्टर होगा, यह तय है।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि अब हैल्थ की कोई टेंशन किसी भी व्यक्ति को नहीं रही है। राज्य में जो भी व्यक्ति है, वह अपना इलाज पहले पांच लाख रुपये तक का करा सकता था, अब उसको दस लाख रुपये तक का करा दिया। इतना ही पांच लाख रुपये तक का जो इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है, वह भी एक बहुत बड़ी बात है। कैशलेस दस लाख रुपये का इलाज मिलना एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का काम है। देखिये, हर व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है। डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी जो हमारे माननीय सदस्य हैं और बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, वे यह कहते रहते हैं कि एक डाक्टर के रूप में उन्होंने गरीब को तड़पते हुए देखा है। लोगों को अपने बच्चे को पैसे के अभाव में मरते हुए देखा है। यह सत्य है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए बजट में यह जो प्रावधान किया है दस लाख रुपये तक का, यह दस लाख रुपये बहुत बड़ी राशि होती है, कम नहीं होती है, यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेकिन इसी हैल्थ सैक्टर की

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बात करते हुए मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं रिकार्ड पर देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी में मैंने यह निवेदन किया है राज्य सरकार से, माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लाम्बा में, लाम्बा गोठड़ा में और डुलानिया में पी.एच.सी. की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आस-पास कोई भी मेडिकल फैसेलिटीज नहीं है। छोटे-छोटे कोई सब-सेंटर्स भी होंगे तो वह एक्स्ट्रीम कोने पर हैं तो इसलिए यह तीन जो मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, सी.एम.एच.ओ. से भी रिकमण्ड हो चुका है और वहां पर आवश्यकता भी है तो वहां लाम्बा में पी.एच.सी. खोली जाये। लाम्बा गोठड़ा में पी.एच.सी. खोली जाये और डुलानिया में भी पी.एच.सी. खोली जाये। यहां इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अब मैं यह निवेदन करता हूं कि मनरेगा एक बहुत बड़ा एम्प्लायमेंट जनरेटिंग फैक्टर है। एक बहुत बड़ा जनरेशन का काम है जो 100 दिन की बंदिश लगी हुई थी इसके गाइड लाइन्स के अन्तर्गत उसको अपने खर्चे पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य सरकार के खर्चे पर 100 से 125 दिन किया है, यह बहुत बड़ी बात है। यह उन लोगों को जो मनरेगा में काम करते हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा है। यह भी एक सकारात्मक सोच है और बहुत बड़ी बात है। गरीब के प्रति माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दृष्टिकोण को यह प्रकट करता है।

बहुत लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, बहुत सारे लोग थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स की डेफिनेशन में आते हैं, ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, पटरी पर काम करने वाले लोग, उन सबके लिए और अन्य लोग जो शहर में रहते हैं, जिनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई और विशेषकर यह जो दो साल कोरोना काल हमको मारकर गया है, उसमें उनका सारा रोजगार तहस-नहस हो गया। शहर में भी गरीबी है और बहुत गरीबी है। गांव में तो है ही, शहर में भी है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो प्रदान की है, वह हमारे इस प्रदेश के लिए और उस जनता के लिए जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, एक बहुत बड़ा सहारा होगा। 1 लाख 25 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। मैं विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि प्रक्रियाधीन है, कोई किस स्टेज पर है, कोई किस स्टेज पर है। कोई इनीशियल स्टेज पर है, कोई फाइनल स्टेज पर है, कोई

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

आरपीएससी को देने की स्टेज पर है, कोई सर्विस सलेक्शन बोर्ड को देने की स्टेज पर है, 1 लाख 25 हजार नौकरियां देना अभी प्रक्रियाधीन है। अगर पिछले तीन साल का देखें तो लगभग तीन लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। यह तो रिकार्ड पर है। कोई जांच करना चाहे तो जांच ले। जब आपको बोलने का मौका मिले, माननीय सदस्य महोदय, तब आप जबाव दे देना। आंकड़े असत्य नहीं बोलते। शीशा असत्य नहीं बोलता। शीशे के सामने खड़े होकर आप देखेंगे तो वही दिखेगा जो सामने है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अलग से कृषि बजट देने का माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया है, यह बहुत बड़ी बात है। पहले दो हजार करोड़ की मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना होती थी, उसको पांच हजार किया है। डबल से भी ज्यादा करना एक बहुत बड़ी योजना है। जैसा कि मैंने निवेदन किया माननीय मुख्य मंत्री महोदय सकारात्मक मैसेज देना चाहते हैं और उनकी धारणा है कि देश का कृषक वर्ग, राज्य का कृषक वर्ग सबसे पहला हक रखता है, देश इकोनॉमी पर, राज्य की इकोनॉमी पर। इसलिए उन्होंने किसान के विकास के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, किसान के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मिशन मोड पर काम करने के लिए, 11 मिशन से इस कृषि बजट पर काम करने का एक मैसेज दिया है।

इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा कानून आ रहा है जिसका नाम है, एससी, एसटी के लिए डवलपमेंट फण्ड कानून। इसी हाउस में आयेगा। जिस दिन आयेगा, उस पर हम अलग से बोलेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा कानून आयेगा। कई राज्यों में यह है। दूसरे राज्यों की कापी भी मैंने मंगवायी है। अपने हिसाब से राज्य सरकार ने जो ड्राफ्ट दिया है, उस ड्राफ्ट की बहुत अच्छी सराहना हम कर सकेंगे।

ईडब्ल्यूएस वर्ग समाज का बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है। देखिए हम कहते हैं कि एससी में गरीबी है, एसटी में गरीबी है, ओबीसी में थोड़ी दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, माइनोरिटी में भी है लेकिन समाज का टोटल हम देखें तो सामान्य वर्ग है, जो किसी भी रिजर्वेशन में कवर नहीं होता, उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे विचार से एससी से भी गरीब होंगे, एसटी से भी गरीब होंगे, माइनोरिटी से भी गरीब होंगे, कोई संसाधन उनके पास नहीं होगा। ऐसे लोगों को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यान में रखा है और जो 10

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

परसेंट रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए किया है, वह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। पिछली बार कर दिया था और इस बार उन्होंने 100 करोड़ का अलग से फण्ड उनके वेलफेयर के लिए रखा है। देखिए, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब देश को प्रारम्भ किया था तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी पर इस देश की आधारशिला रखी थी और उसी राह पर हमारे मुख्य मंत्री महोदय चल रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका विकास हो। इस राह पर चल रहे हैं।

सभापति महोदय, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना के अन्तर्गत स्मार्ट फोन मिलेगा। अभी मेरे साथी सदस्य कह रहे थे विपक्ष वाले, कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। कृपया बजट भाषण 23 तारीख का जो है, उसको पढ़कर देखें। महिलाओं के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं स्मार्ट फोन तो है ही, और कई छूट दी हैं। कई जगह वेलफेयर एक्टिविटीज दी हैं। महिला एवं बाल विकास का बजट आप पढ़कर देखिए, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का बजट पढ़कर देखिए आपको अपने आप पता लग जाएगा।

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए भी अलग से बोर्ड बनाया है और उसको फोकस किया है। इससे हमारे राज्य की बहुत बड़ी जनता का हित होगा। ट्यूरिज्म और हास्पिटिलिटी को उद्योग का दर्जा दिया है। कई ड्यूटीज में छूट दी है। राज्य की राजधानी जयपुर है। इसके फ्यूचर डवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अजमेर रोड से ट्रांसपोर्ट नगर तक और अम्बाबाड़ी से सीतापुरा तक जयपुर मैट्रो के विस्तार की योजना जो दी है, वह एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, 17 जिलों में 32 उद्योग केन्द्र स्थापित करने की बात जो उन्होंने कही है, वह भी सराहनीय कदम है। मैं यहां रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिलानी भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां उद्योग अच्छी स्थिति में नहीं है और वहां औद्योगिक क्षेत्र की कमी भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सम्बन्धित अधिकारियों को माननीय उद्योग मंत्री महोदया डायरेक्शन दें कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करवाकर, जहां भी वह सूटेबल समझें, रीको जहां भी सूटेबल समझे, वहां रीको की तरफ से एक इण्डस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट होना चाहिए।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

सभापति महोदय, चूंकि समय को आपने बांध रखा है, मैं पहले अपने विधान सभा क्षेत्र पर आना चाहूंगा। हर विधान सभा क्षेत्र का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय हर विधान सभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं और बजट में भी यही समावेश है। पिलानी विधान सभा क्षेत्र के सन्दर्भ में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी कृपा से, राज्य सरकार की कृपा से, यहां राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, उनको एड्रेस करके भी मैं बोल रहा हूं कि उनकी कृपा से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत प्रयास के बाद पिलानी में एक अलग से पंचायत समिति मैंने बनवा ली। पंचायत समिति बन गई पिलानी। पिलानी में दो नगरपालिकाएं हैं, पिलानी नगरपालिका और विद्या विहार नगरपालिका। पंचायत समिति पिलानी की 24 पंचायतें हैं। इसके अलावा 7 पंचायतें सूरजगढ़ की हैं। वह 7 पंचायतें विधान सभा क्षेत्र पिलानी की हैं। सब मिलाकर उनका काम सूरजगढ़ एसडीएम के यहां हो रहा है। उनका काम हो रहा है तहसीलदार सूरजगढ़ के यहां। Why? जब एसडीम बैठा है चिड़ावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, तहसीलदार बैठा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चिड़ावा में, तो जो प्रशासनिक काम है, रेवेन्यू का काम है, वह वहां के एसडीएम और तहसीलदार से क्यों नहीं करवाया जा रहा है? नागरिकों को वहां भटकना पड़ता है। एक विधान सभा क्षेत्र से दूसरे विधान सभा क्षेत्र में जाना पड़ता है। एसडीएम वहां नहीं है तो वापस आना पड़ता है। तहसीलदार वहां नहीं तो वापस आना पड़ता है। पिलानी और चिड़ावा दोनों ट्विन टाउन हैं। दोनों बिलकुल नजदीक हैं। चिड़ावा एसडीएम का प्रशासनिक नियंत्रण हो जाये। मैं निवेदन करता हूं कि पंचायत समिति पिलानी की 24 पंचायतें और 7 पंचायतें जो एडजेसेंट हैं, पंचायत समिति सूरजगढ़ की और 2 नगरपालिकाएं, पिलानी नगरपालिका और विद्या विहार नगरपालिका, ये सारा कार्य क्षेत्र एक इण्डिपेंडेंट तहसीलदार का होना चाहिए। आपने इस बजट में छोटी-छोटी घोषणा कर दी। मेरा विनम्र निवेदन है राजस्व मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि पिलानी में एक तहसील घोषित की जानी चाहिए। यह आम जनता के हित में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के हित में है।

दूसरा और निवेदन कर रहा हूं, इसको रिकार्ड पर ले लीजिए, कि जिला कलेक्टर ने तहसील बनाने की रिकमंडेशन राजस्व मण्डल को भी कर दी है और आज जैसी मेरी बात हुई है, उन्होंने राज्य सरकार को भी कर दी है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

पूरा खाका दे दिया है, पूरा नक्शा दे दिया है। पिलानी तहसील में कौन-कौन से पटवार सर्किल आयेंगे, कौन-कौन से गिरदावर सर्किल आयेंगे, बिलकुल काम्पेक्ट नक्शा बनाकर दे दिया है। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इसको बहुत गम्भीरता से देखें। बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनता में उत्सुकता भी है और व्यग्रता है कि हम दूसरी विधान सभा क्षेत्र में क्यों जाएं। सर, जब पिलानी इन्टरनेशनल लेवल का शहर है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर का शहर है, उसमें कोई तहसील नहीं, उसमें कुछ नहीं। वहां से सूरजगढ़ जाओ। सूरजगढ़ एक छोटा सा कस्बा है। पिलानी बहुत बड़ी चीज है तो आप पिलानी में कृपया जरूर यह घोषणा करवायें माननीय मुख्य मंत्री महोदय से। माननीय राजस्व मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप जरूर रिकमंड करिये, अनकंडीशनल रिकमंड करिये, जिला कलेक्टर की सिफारिश को मानिये। जिला कलेक्टर आपका एक चैनल है जिसके माध्यम से सरकार काम करती है। आप करिये। हम तो जिला कलेक्टर को वहां की गवर्नमेंट मानते हैं। जिस दिन यहां पर जिला कलेक्टर का प्रस्ताव आया, हमने सोचा कि हमारी तहसील बन गयी, वहां लड्डू बंट गये पिलानी के अन्दर। अब उनको क्या जबाव दूं मैं? सरकार हमारी है, मैं वहां का विधायक हूं, आप हमारे मंत्री हैं, हमारा मुख्य मंत्री है तो यह मेरी सबसे बड़ी डिमांड है कि पिलानी में तहसील होनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र का जो रोड नेटवर्क है वह बिलकुल तहस-नहस स्थिति में है। मैं किसी को दोषारोपण नहीं करता। मैं थोड़ा-सा समय चाहूंगा, मुझे मालूम है मेरा समय निर्धारित कर रखा है लेकिन मेरे क्षेत्र के विकास की बात है। आपसे थोड़ा फेवर चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय। बिलकुल तहस-नहस स्थिति में है। तीन साल तो मुझे हो गये, जो कुछ मुझसे बन पा रहा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 40 रोड्स का एक मास्टर प्लान बनाकर दिया था। चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर को बुलाकर, तसल्ली से बात करके, हमारे जितने सरपंच थे, हमारे जितने बीडीसी मैम्बर थे, जिला परिषद् सदस्य हैं, उनको बैठा करके मैंने नेटवर्क तैयार किया कि हमारी ये 40 रोड बन जाएं तो अपने क्षेत्र का समुचित विकास हो जायेगा क्योंकि 3 साल में हमने जो कुछ किया, पिछले दस साल वहां बीजेपी थी, उसको तोड़ कर, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहां से कांग्रेस के विधायक के रूप में जीता हूं, अच्छे वोटों से

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जीता हूं। सात बार जो विधायक रहा, उसको हरा कर आया हूं, चार बार जो मंत्री रहा, उसको हरा कर आया हूं तो जनता इतना तो अपेक्षा करती है जिन्होंने मुझे वोट दिये कि इसका रोड नेटवर्क आप ठीक करायें। 40 रोड्स का मैंने एक मास्टर प्लान दिया था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि गत वर्ष उन्होंने 6 रोड्स की स्वीकृति मुझे दे दी।

चीफ इंजीनियर से मेरे पास चिट्ठी आयी कि आपकी 34 रोड और बच गयी हैं। मैं इस सदन के मार्फत पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, कि वह 34 रोड जो मेरी बच गयी हैं उनको भी स्वीकृति देवें। अभी जो तीन रोड जिले की बनी है, उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। नाम आया पिलानी से सूरजगढ़ होते हुए, पचेरी होते हुए हरियाणा सीमा तक, मुझे क्या करना है, साहब, हरियाणा सीमा का, मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र को देखना है। मुझे तो पांच-सात किलोमीटर मिला है तीन रोड्स में। आप कृपया पिलानी से बेरी रोड को स्वीकृत करिए, वह है हरियाणा की सीमा तक। वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पांच पंचायतें पड़ती हैं, जो मुझे हराने की और जीतने का सबसे बड़ा कारण होगा। इसलिए, हम यह वादा करके आये थे कि पिलानी से बेरी तक की हम रोड बना देंगे। साथ ही, मण्ड्रेला पर हमारी सात-आठ पंचायतें पड़ती हैं इस रोड पर, चिड़ावा से मण्ड्रेला रोड पर, वह स्वीकृत करिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह जरूर करवाइए। दूसरा, मण्ड्रेला में लगभग 500 का क्राइटेरिया माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दे रखा है कि जहां 500 बच्चियां होंगी, वहां कन्या महाविद्यालय खुलेगा। मेरे मण्ड्रेला में 500 नहीं 500 से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बालिकाएं हैं, उनकी एजुकेशन बारहवीं के बाद बन्द हो जाती है। 10+2 करने के बाद वह कहीं नहीं जा सकतीं, दस-दस किलोमीटर तक कोई कालेज नहीं हैं और हमारी सोसायटी का सिस्टम आप समझते हैं बच्चियों को भेजते नहीं हैं, इसलिए मण्ड्रेला में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए।

इसके अलावा, चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल पर जरूर बोलना चाहूंगा। हमारा इलाका पानी के मामले में बिलकुल संकटग्रस्त हो चुका है। वहां पर पीने को पानी नहीं है। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की 7,700 करोड़ की योजना राज्य सरकार ने मंजूर की, उसके लिये तो धन्यवाद। लेकिन उस खाली मंजूरी को हम क्या चाटें, उसका हमें पानी मिलना चाहिए। उस पर काम

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

करना चाहिए। उससे मैं भी ग्रसित हूं, सूरजगढ़ के विधायक महोदय बैठे हैं, वह भी ग्रसित हैं। आगे वाले बैठे हैं, वह भी ग्रसित हैं, उस पर काम होना चाहिए। काम शुरू होगा तब जनता को आशा की किरण नजर आएगी।

पिलानी का पानी बिलकुल सूख चुका है। पिलानी एक इंटरनेशनल सिटी है, उसका पूरा पानी सूख चुका है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब 21 घंटे की वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी, तब उनको मैंने अपने भाषण में कहा था He was very kind to approve. 6 एम.एल.डी. पानी साहवा लिफ्ट कैनाल से एडिशनल, जो आगे सूरजगढ़ वगैरह लाइन जाएगी, उसमें मेरे को एलोकेट कर दिया गया था। उसमें मलसीसर से चिड़ावा तक लाइन आये, वह काम हो। 15 लाख का इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जोड़ा है चिड़ावा में, उसमें वह स्वीकृत करें ताकि पिलानी की जनता को पानी मिले। मीनव्हाइल, मैं कह रहा हूं मीनव्हाइल, गर्मी का मौसम आ रहा है, एक बहुत मजबूत कंटींजेंसी प्लान बनाने के लिये माननीय कलेक्टर साहब को यह निर्देश दिये जाने चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाने चाहिए, वहां के एस.ई. को, एक्स.ईएन. को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। राजकीय महाविद्यालय, जो चिड़ावा में है, वह माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आशीर्वाद से खुल चुका है। माननीय सभापति महोदय, 25 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय की कृपा से दान में प्राप्त की है। कॉलेज के लिए 25 करोड़ की प्रोपर्टी मैन रोड पर प्राप्त की है और उस पर कम से कम 20 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगते हैं। आज वह कालेज चल पड़ी और बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 500 बच्चियां उसमें पढ़ाई कर रही हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर अगले सत्र से कामर्स विषय और खोल दिया जाए। आर्ट्स तो है, हमारी बच्चियां भी, बच्चे भी कामर्स के प्रति काफी रूझान दिखा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): एक मिनट लूंगा, सर। अन्त में, यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 21 फरवरी को लिखी है और निवेदन किया है कि राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भुगतान किया जाये, क्योंकि सारी नगरीय इकाइयां आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय सभापति महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्यू वैरी मच। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के 2 घंटे और 56 मिनट का जो बजट भाषण था, अगर वह बजट धरातल पर उतर जाये तो मैं समझूंगा कि इस राजस्थान का काया-कल्प हो जाएगा लेकिन पूर्व की भांति तीन बजट हम देख चुके हैं और चौथा बजट, जो यहां पेश किया गया है, मुझे लगा और मुझे ही नहीं करीब-करीब अन्य वक्ताओं ने भी कहा है कि इसमें सिवाय घोषणाओं के कुछ भी मिलने वाला नहीं है।

मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आंकड़ों के मायाजाल में फंसूंगा तो समय की सीमा है। मेरे विद्वान साथी बता चुके हैं, लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो झुन्झुनूं जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और हरियाणा प्रदेश से लगता हुआ है, चार विधान सभा क्षेत्र हरियाणा के टच करती हैं। वहां एक उपखण्ड स्तर पर कालेज नहीं है बुहाना में और हमने मुख्य मंत्रीजी से आग्रह भी किया था। पिछले बजट सत्र में भी प्रश्न लगाया था और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा भी थी कि जहां 500 से ऊपर सरकारी स्कूल में बच्चियां होंगी, वहां हम लड़कियों के लिये सरकारी कालेज देंगे, लेकिन मुझे बजट में नहीं दिया गया। हो सकता है, मेरे से कोई नाराजगी हो मुख्य मंत्रीजी की, मेरे से सरकार की नाराजगी हो, लेकिन उन बच्चियों के साथ क्या नाराजगी है, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 36 महाविद्यालयों की घोषणा की गयी है, लेकिन क्या सूरजगढ़ इसके काबिल नहीं था? लेकिन खैर, कोई बात नहीं। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछली बार पिलानी में कृषि उपज मण्डी समिति की घोषणा करवायी थी। 12 महीने बीत चुके, आज तक कहीं कृषि उपज मण्डी समिति नहीं आयी है। मैं झुन्झुनूं जिले की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट पोलीटैक्निक भी कहीं नहीं है। मैंने सुना कि वह भी झुन्झुनूं में चल रही है। यह हाल जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका है। मैं कहूंगा कि इस बजट में क्या है, यह सब आपके सामने हैं।

मैं सूरजगढ़ में दो-तीन सत्र से औद्योगिक क्षेत्र के लिये बात कर रहा

(श्री सुभाष पूनिया)

हूं। मैं यह नहीं कहता कि सूरजगढ़ में बनाओ। बुहाना, सिंघाना तीन-तीन पंचायत समितियां हैं, कहीं भी बनाएं। जमीन की उपलब्धता भी है और हरियाणा प्रदेश से लगता हुआ इलाका है और दिल्ली के पास भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्रीजी संज्ञान में लेकर हमें औद्योगिक क्षेत्र में अच्छे उद्योग लगाने का काम करें।

अभी महंगाई की बात हो रही थी। महंगाई के मामले में पेट्रोल और डीजल, क्योंकि सूरजगढ़ से चार किलोमीटर की दूरी पर ही आठ रुपये के अन्तर से पेट्रोल-डीजल मिल रहा है। आज महंगाई के मामले में राजस्थान प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल आज भी है। बिजली के दाम सबसे अधिक कहीं हैं तो राजस्थान प्रदेश में हैं। फिर भी कहते हैं कि इस प्रदेश का काया-कल्प करेंगे। बहुत ही शर्म की बात है।

मैं जहां तक सड़कों की बात करूं, तो सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। मैंने निवेदन किया था तीन सड़कें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जो हरियाणा की सीमा को जोड़ती हैं, जो चलने लायक नहीं हैं। असाज से बालोत बोर्डर है, गडराणा गोड से ठिठाना बोर्डर तक है, लेकिन PMGSY में सुना गया है कि एक सड़क गडराणा वाली तो आने वाली है, लेकिन मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से आग्रह करना चाहूंगा कि असाज से चूड़ेला की जो रोड है वह इस बजट में ली जाये, यह भी मेरा आग्रह रहेगा।

अभी मुख्य मंत्रीजी ने हर विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़कों की घोषणा की है। तीन करोड़ रुपये तो मिसिंग लिंक के दिये हैं और सात करोड़ रुपये नोन-पेचेबल के लिये दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि 10 करोड़ रुपये हमें मिसिंग लिंक के दिये जायें, यह भी मैं आग्रह करना चाहूंगा।

नगरपालिका सूरजगढ़ की सीवरेज के लिये मैं पिछले सभी सत्रों में प्रश्न के माध्यम से भी, 295 के माध्यम से भी आग्रह कर चुका हूं लेकिन आज तक सूरजगढ़ नगरपालिका में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी मैं यूडीएच मिनिस्टर से आग्रह करना चाहूंगा।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य भी अभी कह रहे थे कि 3 साल से कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का झुनझुना हमें पकड़ा रखा है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना में 50 परसेंट

(श्री सुभाष पूनिया)

पैसा इन्होंने जल जीवन मिशन से उठा लिया है। जायका कम्पनी जो जापान की है, 50 परसेंट उसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। पहले हमें अधिकारियों ने बताया था कि फरवरी में हम शिलान्यास कर देंगे लेकिन अभी तक उसका टेण्डर नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि यह गर्मी आये इससे पहलेपहले टेण्डर करवाकर काम शुरू हो, नहीं तो सूरजगढ़ विधान सभा में जहां 1-1 हजार फीट पर भी पानी नहीं है, सरफेस वाटर तो कहीं है ही नहीं, जब तक यह काम नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की प्यास बुझेगी।

हमारे पीएचईडी मिनिस्टर सामने ही विराजे हुए हैं। पहले भी मैंने बहुत निवेदन किया था कल्ला जी से। कहावत थी कि 'ऊपर अल्लाह और नीचे कल्ला'। मैं 3 साल तक खूब चिल्ला-चिल्लाकर उनको कह चुका लेकिन पानी के मामले में मेरे साथ भेदभाव बरता गया है। मैं झुंझुनूं और सीकर दोनों जिलों में एकमात्र बीजेपी एमएलए हूं। मेरे साथ इतना भेदभाव तो नहीं बरतें। यह भी मैं जलदाय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मुख्य बात तो मेरी रह गयी। मैं चाहूंगा कि मुकदमों के हिसाब से बुहाना में भी एडीजे कोर्ट खोलने की कृपा करें।

बिजली के मामले में, बून्द-बून्द सिंचाई परियोजना में जो फाइलें जमा हुई, उनके डिमाण्ड नोटिस भी जमा हो चुके। हजारों कनेक्शंस आज भी किसानों के बकाया हैं। किसान जाता है तो कभी कहते हैं कि खम्भा नहीं है। पोल उपलब्ध कराने के बाद, तार नहीं हैं। तार मिल जाता है तो ट्रांसफार्मर नहीं हैं। किसानों के साथ यह लूट हुई है। मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 2 साल में ही हम सारे कनेक्शंस दे देंगे। बून्द-बून्द सिंचाई में तो यह था कि पैसा जमा होते ही कनेक्शन मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। किसानों को अतिशीघ्र कनेक्शन दिये जायें।

सभापति महोदय, नन्दीशाला, आज वह प्रश्न भी लगा था। पिछले 3 साल से हर पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला खोलने की जो घोषणा हुई थी, उसका आज तक कहीं अता-पता नहीं है। एक भी नन्दी शाला पूरे प्रदेश में नहीं खोली गयी है। किसान आवारा पशुओं से परेशान है। किसान पलायन की

(श्री सुभाष पूनिया)

स्थिति में है। किसान ने खेती छोड़ने का काम किया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पंचायत समिति स्तर पर अतिशीघ्र नन्दी शाला खोली जाये।

मेडिकल के क्षेत्र में, सभी जिलों में मेडिकल कालेज खुल गयी। हमें एक आशा बंधी थी कि झुंझुनूं में मेडिकल कालेज अतिशीघ्र खुलेगा लेकिन आज तक मेडिकल कालेज का कोई नाम नहीं है। हमने सोचा था कि 2 मंत्री और 2 मुख्य मंत्री जी के विद्वान सलाहकार वहां से बनाये हैं तो यह काम भी जल्दी होगा लेकिन आज तक वह नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि यह मेडिकल कालेज का काम भी जल्दी से जल्दी हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। किसानों के लिये 12 महीनों से एक ढिंढोरा पीट रहे थे कि किसान का बजट हम अलग से जारी करेंगे। वह कैसा बजट आया है, वह भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। मेरे पूर्व साथी वक्ता बता चुके हैं। किसान को झुनझुना पकड़ाया है। निश्चित रूप से किसान 2023 में इस बजट को देखकर ही बदला लेगा। इस सरकार की विदाई तय है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब जिन चीजों से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र वंचित रहा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन चीजों की व्यवस्था करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती मीना कंवर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती मीना कंवर।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): सभापति महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया। मैं राजस्थान के जननायक मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि उन्होंने किसान वर्ग, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों व 36 कौमों का ध्यान रखते हुए इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया, इसके लिये पूरा प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, इससे भी राजस्थान की आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिये मैं आपको बहुतबहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिये जितनी सराहना की जाये उतनी ही कम है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन योजना लागू की गयी है। इससे कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोगों में खुशी की लहर छा गयी है।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि पूर्व मंत्री जी दाता हुकुम स्वर्गीय खेतसिंह जी राठौड़ की आत्मा भी आपको आशीष दे रही होगी कि मेरे शेरगढ़ के विकास में जो कमियां रह गयी थीं, वह माननीय गहलोत जी ने पूरी की हैं।

मैं सदन को बताना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की जनता को ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। नवगठित पंचायत समिति चामू में पुलिस थाना खोलने से मेरे क्षेत्र की जनता को 40 किलोमीटर दूर देचू नहीं जाना पड़ेगा। इससे आम जन में खुशी की लहर छा गयी है। साथ ही चामू पंचायत समिति को उप तहसील एवं कृषि क्षेत्र में गौण कृषि मण्डी खोलने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का सदन के माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी।

(श्रीमती मीना कंवर)

मेरी पंचायत समिति सेखाला में कन्या महाविद्यालय एवं स्थायी पुलिस चौकी खोलने, पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत आगोलाई में आईटीआई कालेज खोलने, खुडियाला में औद्योगिक क्षेत्र व प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने पर मैं मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालेसर खनन क्षेत्र है। उसमें क्वारी लाइसेंस की अवधि गत भाजपा सरकार ने कम करके 2025 कर दी थी, जिसको माननीय गहलोत जी ने बढ़ाकर 2040 कर दिया है। इसके लिये शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 40 हजार खनन श्रमिक आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। उसको देखते हुए देवानिया-नाथाडाऊ परियोजना में 330 करोड़ 52 लाख रुपये स्वीकृत करने पर शेरगढ़ के 372 राजस्व गांव के नागरिक आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इतनी बड़ी सौगात देने के लिये आज स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्व मंत्री दाता हुकुम खेतसिंह जी राठौड़ भी आपको धन्यवाद देते होंगे कि आपने मेरे जाने के बाद मेरे क्षेत्र की जनता का सुख-दुख में ख्याल रखा है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की जनता को खूब सौगातें दी हैं। इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में तहसील स्तर पर सबसे ज्यादा सैनिक हैं। करीब 5 हजार पूर्व सैनिक हैं, वर्तमान में 7 हजार शेरगढ़ के बेटे भारत मां की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। विभिन्न युद्धों में शेरगढ़ के सैकड़ों बेटे शहीद हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से उनकी स्मृतियों को अमर करने के लिए फलौदी रोड, फाटा पर एक शहीद स्मारक निर्माण करवाये जाने की मैं मांग करती हूं। यह अति आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शहीद स्मारक का नायाब तोहफा हमें देंगे और वीर प्रसूता भूमि शेरगढ़ को गौरवान्वित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत आभार।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में हमें सम्बोधित किया और उन्होंने 2022-23 का चौथा बजट सदन में रखा। बड़ा मनमोहक, बड़ा आकर्षक, सुनने और देखने में ऐसा लग रहा था कि इन अपार घोषणाओं के साथ जैसा कि आपका स्वभाव है, पूर्व में आपने इसी भांति बजट में बेहतरीन घोषणाएं की थीं, लेकिन मैं इससे पूर्व कि बजट की बात करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संवैधानिक प्रमुख महामहिम ने बजट सत्र का शुभारम्भ किया। उनके उद्बोधन के बाद हमारे प्रतिपक्ष के विधायकगण वेल में आये और उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि रीट के मामले में जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिले और सीबीआई के द्वारा इस नकल घोटाले की तमाम जांच हो। परन्तु सरकार ने बहाने बनाये और कहा कि ये नकल तो पहले भी होती रही है, सीबीआई को कठघरे में खड़ा किया। मेरा मानना है कि साढ़े बीस लाख परीक्षार्थियों ने रीट की परीक्षा दी थी और उनके एक करोड़ परिजन इस रीट की परीक्षा से प्रभावित थे और न्याय चाहते थे, सरकार उनको न्याय नहीं दे पायी है। सदन प्रारम्भ हो चुका है लेकिन हमारी आज भी यही मांग है कि रीट परीक्षा नकल के जो प्लानर थे, जो सूत्रधार थे, उनको जेल के सीखचों में पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट को सुना, बड़ा खूबसूरत बजट था, एक फुटबाल खूबसूरत जिसमें हवा भरी हो, फुटबाल बड़ी आकर्षक, बड़ी सुन्दर दिखायी देती है, बड़ी मनमोहक फुटबाल नजर आती है। माननीय सभापति महोदय, इसमें यदि कांटा या कील घुस जाये तो उसकी हवा निकल जाती है।

माननीय सभापति महोदय, जब अर्थवेत्ताओं ने, अर्थ विज्ञानियों ने, अर्थशास्त्रियों ने इस बजट को देखा तो बड़ा मनमोहक और बड़ा सुन्दर बजट दिखने लगा लेकिन जब उन्होंने इसका आपरेशन किया तो उस फुटबाल की तरह यह बजट बिलकुल पिचका हुआ नजर आने लगा। जिस तरीके से सरकार की अपनी आदत है वैसे ही इस बजट में भी खूब सारी घोषणाएं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। आज समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से आपने अपनी आय से ज्यादा खर्चा दिखाया, बिना संसाधनों के, बिना वित्तीय उपलब्धता के, आपके इस बजट की अनुपालना, सवाल ही नहीं उठता, सम्भव ही नहीं है कि आप बजट की अनुपालना करवा पाओगे।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, अभी पांच लाख सैंतीस हजार करोड़ रुपये राजस्थान वासियों पर, प्रदेश की जनता पर कर्जा है। अगर एक राजस्थानी का हिसाब लगायें तो 75 हजार रुपये एक राजस्थानी पर कर्जा है। न जाने यह सरकार विदा होते-होते राजस्थान की जनता को कितने और कर्जों में डुबोकर जायेगी। ऐसे चुनावी वादों को लेकर तीन बजट घोषणाओं में आपने जनता को ठगा। आपने बेरोजगार युवकों, संविदा कर्मियों, किसानों, मजदूरों को सिर्फ आकर्षक वादों और घोषणाओं से छला। आपने सरकारी भर्तियों को लेकर राजस्थान के युवाओं को लगातार गुमराह किया। सरकारी भर्तियां निकालकर उन्हें विवादों में उलझाकर आपने वो भर्तियां डम्प करवा दीं और उनको ठेंगा दिखा दिया।

आज 27 प्रतिशत लोग राजस्थान में बेरोजगार हैं। राजस्थान आज देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार रहते हैं, 20.67 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, हमारे राज्य में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। 65 लाख कुल बेरोजगारों के साथ राजस्थान को देश में अव्वल नम्बर पर लाकर आपने खड़ा कर दिया है। पिछले एक वर्ष में आपने युवाओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर, तीन परीक्षाओं में 200 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र कर लिया और परीक्षाओं को अटका दिया और उनको ठेंगा दिखा दिया।

संविदा कर्मियों का भी आपने किस तरीके से शोषण किया, उनके लिए चुनावी घोषणा पत्र में आपका वादा था कि इनको स्थायी कर देंगे, तीन लाख आंगनबाड़ी, एनआरएचएम, एनयूएलएम, शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, पंचायत सहायक के लिए कमेटी बनाकर उनको उलझा रखा है। इसी प्रकार से आपने दस दिन के अन्दर किसानों के कर्जा माफी की बात की जो आज तक नहीं हो पायी। आपका कृषि बजट भी वैसा ही निकला जैसी पिचकी हुई फुटबाल। बेरोजगारी भत्ता, आपने जटिल प्रक्रियाओं में छह लाख युवा बेरोजगारों को चयनित तो कर लिया, लेकिन उसमें से भी आप चार लाख युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हो और वो भी कभी मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है।

महंगाई के लिए आप केन्द्र सरकार को कोसते हो। सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में है। यदि हम पास के प्रदेशों में जायें, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो वहां दस रुपये कम पेट्रोल और डीजल की कीमत है। यही कारण है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आप वैट घटा दो तो महंगाई वैसे ही कम हो जायेगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी।

(श्री संदीप शर्मा)

शिक्षा को लेकर आपके वादे, 122 कालेज आपने पहले खोल दिये, 36 कालेजों की घोषणा आपने इस बजट में कर दी और 4 वो कालेज जो आपने विधायकों के नाम पर खोले थे और वाहवाही लूटी थी, उनमें से एक भी कालेज में मैं समझता हूं, आपके शिक्षा मंत्रीजी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उन कालेजों को भू-आबंटन नहीं हुआ, 80 प्रतिशत कालेजों के लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षक और स्टाफ तो बहुत दूर की बात है। ये शिक्षा का स्तर है। न वहां शिक्षक है, न वहां स्टाफ है, न वहां पर और कुछ सुविधाएं हैं। हॉस्टल्स में कालेज चल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, और प्राइवेट मकानों में कमरे लेकर कालेज चला रहे है।

केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसमें आपको 23 करोड़ 60 लाख रुपये मिले, उसमें से आप आधे भी खर्च नहीं कर पाये। 11 जिलों में ऐसी स्थिति है कि बच्चों के आप नामांकन तक नहीं करवा पाये। आपने 180 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक आवासीय भवनों के लिए दिये, 500 मदरसों के लिए आपने स्मार्ट क्लासेज खोल दी। उन संस्कृत के बच्चों का भी ध्यान रख लेते जिनके सिर पर छत नहीं है, जहां पर बैठकर वह पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा विभाग के स्कूल जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं वहां पर पानी टपकता रहता है, बिना छत के, बिना शौचालयों के वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कई महाविद्यालयों में स्टाफ नहीं है, कोटा शहर की मैं बात करूं तो पिछली बजट घोषणा में 5 करोड़ रुपये से सड़क बनाने की घोषणा की थी, अभी वहां पर एक धेले का काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री शकुन्तलाजी बैठी हैं, माननीय रामलालजी बैठे हुए हैं, टीकारामजी कह रहे थे तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैं कह रहा हूं कि कोटा शहर में इतनी बड़ी रोड खराब होने से दुर्घटना हुई कि वाल्मीकि समाज के नौ लोग उस रोड के जरिये चम्बल नदी में डूब कर मर गये। ये हाल है टूटी रोडों का कोटा शहर में, कह रहे थे कि वहां बहुत ज्यादा काम हो रहा है लेकिन अभी स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां हैं नहीं, मैं उनके मुंह से स्वीकार करवाता, पीडब्ल्यूडी के जो काम आपने सैंक्शन किये थे उनमें से एक काम नहीं हुआ।

(समय: 17.00 बजे)

कोटा बैराज, कोटा जवाहर सागर डैम, गांधी सागर डैम, इनके लिए वहां के विभाग ने लिखकर भेज दिया कि ये कभी भी भर भराकर टूट सकते हैं। इनकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कोटा बाढ़ के सैलाब में कभी भी डूब

(श्री संदीप शर्मा)

सकता है। एक पैसा उन बांधों के रख-रखाव हेतु, उन्हें सही करने के लिए नहीं दिया। बहुत बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, सुपर स्पेशियलिटी विंग को खोले हुए चार साल हो गये हैं 150 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी विंग खड़ी हुई है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वहां परम विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं लग पाये, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ नहीं लग पाया। वह धूल खा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें जिस तरीके से आपने वादा किया था कि हम पूरे राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करा देंगे, कोटा शहर में चम्बल के किनारे भी लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। पाइपलाइनें 40-40 प्रतिशत तक जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं, उनका अभी तक बदलाव नहीं किया गया। उनके लिए कुछ बजट देना चाहिए था सरकार को।

किसानों का कर्ज आप माफ नहीं कर पाये। कृषि बजट में किसानों के साथ मजाक किया है। नहरी तंत्र, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। जितना पैसा आपने कोटा के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया, मेरा मानना है कि उसका थोड़ा-सा अंश मथुराधीश मन्दिर के जीर्णोद्धार में लगा देते, जो वल्लभ सम्प्रदाय की प्रथम पीठ है और जिसमें गुजरात और आस-पास के बहुत सारे धार्मिक पर्यटक आना चाहते हैं, लेकिन वहां परिक्रमा का मार्ग नहीं होने के कारण वे आ नहीं पाते हैं। यदि वह हो जाये तो कोटा धार्मिक पर्यटन नगरी बन जाये और लोगों को व्यवसाय मिल जाये, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है।

आपने केन्द्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को अपना बना लिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना केन्द्र सरकार की योजना थी, जिसे आप बड़ी अदा से असत्य बोलकर चिरंजीवी योजना कह देते हैं। उसमें भी मात्र 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा पाये हैं, बाकी 6 करोड़ लोगों का इलाज नहीं हो सकता। जो लोग चिरंजीवी योजना का कार्ड लेकर जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो पाता।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, प्रदेश के समन्वित विकास के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से और समाज के सभी वर्गों- किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, व्यापारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए भरपूर लाभ और खुशियां बांटने वाला है। यह एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि पूरे देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, जिसमें पहली बार कृषि बजट दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह हर वर्ग के लिए मददगार है। इससे पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। इसी सन्दर्भ में मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूं-

"साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं,
सम्मान में आपके सिर झुकाते हैं।।
आप आये तो माहौल में खुशियां छा गयीं,
आपके खिदमत में सदा के दीप जलाते हैं।।"

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भीलवाड़ा जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लिए इस बजट में जो घोषणाएं की गयी हैं, उनके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार कि उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में चिकित्सा राशि 5 लाख रुपये सालाना को बढ़ाकर 10 लाख रुपये की। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की और उसमें 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध कराया। मुख्य मंत्री जी, आपने एक हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

हमारे भीलवाड़ा मेडिकल कालेज में यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सुविधाएं शुरू करने से भीलवाड़ा के मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरे साहब दिवंगत विधायक स्वर्गीय

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

कैलाश जी त्रिवेदी का सपना था, जो अब पूरा हुआ। इसके लिए सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य के समस्त सैकंडरी विद्यालयों को सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने, एक हजार और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करने, 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती करने, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणाएं की है। विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। नये कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करने से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान को ''फिट राजस्थान, हिट राजस्थान'' बनाने के लिए राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। मेरे साहब दिवंगत विधायक श्री कैलाश चन्द्र जी त्रिवेदी भी स्वयं खिलाड़ी थे। गहलोत साहब खिलाड़ियों के लिए हमेशा हरसम्भव मदद के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्टेडियमों की घोषणाएं की हैं। आप गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए आपके सम्मान में दो लाइनें पढ़ना चाहती हूं-

''आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहां बेकरार था,
अब आयी है वह घड़ी, जिसका मुद्दतों से इन्तजार था।।''

विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग के लिए कमजोर तबकों के युवाओं का ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली के उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपये की लागत से 500 युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनाने की घोषणा की। महिलाओं को ''वर्क फ्रोम होम जाब'' की योजना लागू कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने की बात कही है। मुख्य मंत्री जी ने भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन करने की घोषणा की है।

अब तक 1 लाख 25 हजार पदों पर विभिन्न भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा आगामी वर्ष में 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्तियां करने की घोषणा हुई है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर के ग्राम खेमाणा और गंगापुर के ग्राम खाखला में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा पर मुख्य

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। मुख्य मंत्री जी ने हमारे मध्यमवर्गीय परिवार, जो 50 लाख रुपये तक के फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उन्हें 2 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी। इसी तरह से 1 परसेंट ड्यूटी की छूट हमारे सीनियर सिटीजंस को मिली है, जो कि एक अभूतपूर्व निर्णय है।

गहलोत साहब ने 50 यूनिट बिजली फ्री की, 150 यूनिट तक 3 रुपये की सब्सिडी और 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये की सब्सिडी दी, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक है। पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों, पर्यटन से सम्बन्धित आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए प्रत्येक जिले के दो पर्यटक स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अभय कमांड सेंटर को मजबूत कर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर पुलिस स्टेशन सेंटर फोर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की है।

वहीं भीलवाड़ा में पारिवारिक न्यायालय खोलने से कई परिवार उजड़ने से बच जायेंगे। मुख्य मंत्री जी द्वारा पेंशन योजना लागू करना एक अभूतपूर्व काम है। जब से बजट में यह घोषणा हुई है तब से कर्मचारियों के घर में दीपावली मन रही है। नये कर्मचारियों के बुढ़ापे का सरकार सहारा बन गयी है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में एक नया उत्साह पैदा हो गया। उनका जो जोश है, उनमें जो खुशी देखने को मिल रही है उसे देखकर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा काम मुख्य मंत्री जी ने किया है। सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य की चिन्ता से मुक्त होकर सुशासन में अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी समस्या का निदान किया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों की ओर से मुख्य मंत्री जी को एक बार पुन: धन्यवाद देती हूं।

मुख्य मंत्री जी ने डिजिटल सेवा के लिए 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष के इंटरनेट से कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन देने से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी सशक्त होंगी और महिला शक्ति को सरकार की योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए मैं सभी महिलाओं की ओर से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

जो बच्चे देश-विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके एजुकेशन लोन पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज 100 परसेंट माफ कर दिया है।

हमारे दिव्यांगजनों की बात है, उसमें पिछली बार 2 हजार स्कूटी थीं, इस बार 5 हजार स्कूटी की घोषणा की गयी है।

मुख्य मंत्री जी ने हर विधान सभा क्षेत्र को सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये दिये हैं ताकि वे अपने हिसाब से पुन: डामरीकरण और मिसिंग लिंक में जहां चाहे वहां पैसे दे सकता है।

जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए अभूतपूर्व योजना है। इसके द्वारा प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी कार्यशैली से आज हर वर्ग खुश है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि-

"हर फूल बाग़ में लगाये नहीं जाते हैं,
हर लोग महफिल में बुलाये नहीं जाते हैं।
कोई तो पास आकर भी याद नहीं आते,
आप कुछ दूर होकर भी भुलाये नहीं जाते।।"

मेरे हिसाब से यह बजट शानदार है, यह बजट जानदार है, यह बजट वजनदार है और यह बजट राजस्थान की जनता के लिये विकास में असरदार है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साहब ने कोरोना काल में, यानी जनता की सेवा करते-करते अपने जीवन को त्याग दिया है तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूं उनकी यादगार में जहां जलाया उसको श्मशान न किया जाये और स्मृति संस्थान का रूप देकर पर्यटन स्थल बनाने की अनुमति दिलाने की कृपा करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सुवाणा पंचायत में एक भामाशाह बिल्डिंग बनाकर देने को तैयार है तथा सीएचसी बनाना चाहता है तो आप वहां पर सीएचसी बनाने की कृपा करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे कारोल में पीएचसी है उसको सीएचसी बनाया जाये। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

यह बजट राजस्थान की जनता के लिए विकास में असरदार है। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनी उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 23 फरवरी को 2022-23 का जो बजट पेश किया गया उससे पूरे राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीद थी, विशेष रूप से झालावाड़ और मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर को बहुत बड़ी उम्मीद थी। बहुत बड़ा विश्वास था कि पिछले तीन साल तक जो विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं उनमें निश्चित रूप से बजट मिलेगा और सभी विभागों की तरह कहीं न कहीं घोषणा निश्चित रूप से होगी। पर मैं मानता हूं कि राजस्थान का 33वां जिला झालावाड़ है और लगता है कि झालावाड़ राजस्थान का जिला नहीं है और उसी हिसाब से खानपुर विधान सभा क्षेत्र का इस बजट में कहीं नाम नहीं है। इससे बड़ी निराशा मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को हुई। एक पुल के निर्माण की जरूर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, एक पुल की समस्या थी। सीनियर सैकण्डरी स्कूल तो मुख्य मंत्री जी ने पहले ही झालावाड़ में ज्यादा खोल दिये थे पर फिर भी जो घोषणा हुई, अच्छी घोषणा हुई, उसका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में तो उलझना नहीं चाहता, पर मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। विशेष रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो खानपुर विधान सभा क्षेत्र में खानपुर मुख्यालय पर डाक्टर्स की बहुत बड़ी समस्या है। जब से सरकार बनी है तब से एक-एक डाक्टर करके वहां से सबने ट्रांसफर करा लिये हैं। सरकार से निवेदन करता हूं कि वापस उन पदों को भरा जाये ताकि वहां के लोगों को इलाज के लिए झालावाड़ न जाना पड़े। इसके लिए विशेष रूप से सरकार को प्रयास करना चाहिए।

साथ ही मेरे वहां बकानी तहसील में 30 बैडेड हास्पिटल है उसको क्रमोन्नत करके 50 बैडेड अस्पताल बनाया जाये ताकि उस क्षेत्र के निवासियों को उसका लाभ मिल सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी उसमें साढ़े तीन लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में किया जाता था। इस बार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की और उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक भी किया। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि साढ़े तीन लाख रुपये तक की जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी तब अस्पताल वाले निश्चित रूप से इलाज करते थे

(श्री नरेन्द्र नागर)

और प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी पेशेंट जाने के बाद वापस नहीं आता था, किसी पेशेंट का फोन नहीं आता था कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, पर वर्तमान में स्थिति यह है कि चिरंजीवी बीमा योजना में पता नहीं इसका पैकेज या तो आप लोगों ने कम कर दिया या कहीं न कहीं विशेष बात है इसलिए इसके लिए दुबारा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी पेशेंट प्राइवेट योजना में जाये, उसको उस योजना में लाभ मिले, उसको वहां से वापस नहीं लौटाया जाये, इस प्रकार का प्रयास सरकार का होना चाहिए। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा गरीबों को मिले, इस प्रकार का इसमें प्रयास होना चाहिए।

साथ ही, मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर, 2012 के बाद जो एग्रीकल्चर कनेक्शंस का बैकलाग था उसके लिए घोषणा की है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। अभी स्थिति यह है कि पिछली बार सरकार ने बजट में कनेक्शनों के लिए घोषणा की थी परन्तु सीजन में ऐसी स्थिति रही कि पुराने कंज्यूमर का ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसको एक-एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला। यह मैं हकीकत कह रहा हूं और आप चाहें तो उसकी जानकारी करा लो। किसान का ट्रांसफार्मर जलने के बाद वह एक महीने तक इन्तजार करता रहा पर उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिला। इससे उसकी कहीं लहसुन की खेती थी वह सूख गयी, कहीं अफीम की खेती थी उसमें उसको पड़ोस से पानी लेना पड़ा। सौभाग्य है कि इस बार बीच-बीच में वर्षा का पानी गिरता रहा जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत कम आयी परन्तु यदि बरसात नहीं होती और यह समस्या होती तो वास्तव में किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती।

इसी प्रकार से जो डोमेस्टिक कनेक्शन हैं उनमें जब शहर के लोगों का एक बार ट्रांसफर जल जाता है, दिन में जल जाता है तो शाम को ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है पर गांव के लोगों का जब ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको 15-15, 20-20 दिन, एक-एक, डेढ़-डेढ़ महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिला और गांव अंधेरे के अंधेरे में रहे। साथ ही वीसीआर के नाम पर जो लूट हो रही है उसमें किसी घर में एक बल्ब जलता है, दो बल्ब जलते हैं तो भी उसके 50-50 हजार की वीसीआर भरी जा रही है। फिर उसको सैटलमेंट के नाम पर उसको 50 परसेंट कर रहे हैं और 25 हजार उससे ले रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार गांवों में यह जो विजिलेंस कमेटी है उसके द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार सरकार अपने खजाने को भरने का काम कर रही है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को रोका जाये और विशेष रूप से निवेदन करना

(श्री नरेन्द्र नागर)

चाहता हूं कि यह ऊर्जा विभाग की ही बात नहीं है, सहकारी क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, अपना जो वित्तीय वर्ष है, यह मार्च में खतम हो जाता है तो फरवरी में सरकारी विभाग द्वारा चाहे को-आपरेटिव हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, सभी के द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जाता है कि आप पैसे जमा करो, 31 मार्च आने वाला है।

सभापति महोदय, स्थिति यह है कि पिछले लगभग 10 साल से जो अपना वित्तीय वर्ष है वह तो मार्च ही है पर जो सीजन है, जो बरसात की फसल है, वह जुलाई में बोई जाती है और जो रबी की फसल है वह नवम्बर-दिसम्बर में बोई जाती है। जब नवम्बर-दिसम्बर में बुआई होगी, सर्दी लेट शुरू होती है, जब सर्दी लेट शुरू होती है तो मार्च और अप्रैल तक फसलें आती हैं, जब अप्रैल तक फसलें आती हैं तो मार्च में किसान के पास पैसा कहां से आयेगा? जब उसके पास पैसा नहीं आया तो उसको पानी पिलाने के लिए उसको अन्तिम बिजली चाहिए और उसका पैसा जमा नहीं हो रहा है तो उसका ट्रांसफार्मर उतारा जा रहा है। वह पैसा कहां से देगा? इसको मई-जून किया जाये ताकि लोग अपना साल भर में पैसा जमा करा सकें, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

साथ ही, पिछली सरकार ने 833 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी थी। सरकार ने 12 हजार रुपये उसकी सब्सिडी बढ़ा दी, पर मैं यह कह रहा हूं कि जो बिजली का बिल आ रहा है, उसमें आप एक हजार रुपये, जब सब्सिडी दे रहे हो तो वह कम कर दो। स्थिति यह है कि किसानों के पास 12 महीने में दो बार पैसे आते हैं, किसान हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कराता है। जब वह बिजली का बिल जमा नहीं करा सकता तो उसको सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं तो उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब उसको लाभ मिले, तो सरकार की योजना है। मैं यह मानता हूं कि यदि योजना का लाभ आप सभी किसानों को देना चाहते हैं तो आप उसके बिजली के बिल में 1 हजार रुपये कम कर दो, चाहे वह दे या नहीं दे। वह साल भर में 6 महीने में देगा तो इस ओर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए।

साथ ही, मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, सरकार के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गये। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल तो खोले गये, पर आपने कहीं न कहीं उस क्षेत्र का, उस कस्बे का एक स्कूल बन्द कर दिया।

(श्री नरेन्द्र नागर)
पिछली बार आपने मेरे खानपुर में बालिका सीनियर स्कूल बन्द करके, अंग्रेजी स्कूल की घोषणा कर दी। जब वहां हो-हुल्लड़ हुआ, हड़ताल हुई तो उसके बाद आपने चेंज करके दूसरा स्कूल खोला। फिर मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल रटलाई में खोला। आपने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। वहां भी सीनियर बालिका विद्यालय को बन्द करके आप अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो, अभी भी वहां हड़तालें हो रही हैं, वहां के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बार-बार मुझे फोन कर रहे हैं, आप स्कूल तो खोलना चाह रहे हो, लाभ देना चाहते हो, उस सीनियर स्कूल की छात्रायें कहां पढ़ने जायेंगी?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे स्कूल बन्द मत करे। जिनमें बालिकाओं की अच्छी संख्या है। आप यदि स्कूल खोलना चाहते हैं, अलग स्कूल खोलो, बहुत से मिडिल स्कूल मर्ज हुए हैं सैकण्डरी स्कूल में चले गये, उन बिल्डिंग में आप शुरू करें, दो-तीन साल में आपके पास संसाधन हो उसके बाद में भवन बना देना।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): ठीक है साहब, दो मिनट में कर देता हूं। विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही सड़क की बात करें, पिछली सरकार के द्वारा जो काम सैंक्शन हो गये थे, जो काम चल रहे थे। अभी भी बजट नहीं मिलने के कारण वे काम पूरे नहीं हो पाये। पहले तो लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं होती थी। अब वे गिट्टी पर से निकल रहे हैं, बार-बार उनके टायर पंक्चर होते हैं साइकिल मोटर साइकिल के, अभी भी तीन साल पूरे होने के बाद भी सरकार को, जो पिछली सरकार वसुन्धरा जी की सरकार में जो काम सैंक्शन थे और काम चल रहे थे। वे काम तीन-साढ़े तीन साल में भी पूरे नहीं हुए हैं। सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि काम तो कम से कम पूरा कराये। साथ ही, गौरव पथ की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, हमने गौरव पथ बनाये थे। मुख्य मंत्री जी ने फिर घोषणा की, विकास पथ की, विकास पथ के नाम से अभी एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास पथ बना है।

सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घोषणा है तो निश्चित रूप से बजट एक साल के लिए होता है तो घोषणा करे तो कम से कम कुछ तो आप बनाओ, ताकि आपने जो घोषणा की है, वह घोषणा तो निश्चित रूप

(श्री नरेन्द्र नागर)

से पूरी हो सके। विशेष रूप से पेयजल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पिछले काफी लम्बे समय से हमारी जो परवन वृहद सिंचाई परियोजना है, उसमें आपने घोषणा की थी। जबकि पिछली सरकार वसुन्धरा सरकार ने भी घोषणा कर दी थी। उसने वित्तीय प्रबन्धन दे दिया, मुख्य मंत्री जी ने उसकी घोषणा करके स्वीकृति जारी कर दी थी, केवल टेण्डर प्रोसेस में थे। अब वापस 3 हजार 523 करोड़ रुपये का जल जीवन मिशन में बजट दिया है, कोटा, बारां, झालावाड़ को इस योजना के अन्तर्गत पानी दिया जायेगा तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि काम अभी तक हुआ नहीं, केवल घोषणा ही घोषणा है।

इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि का बजट अलग से पेश किया है। इस बजट में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, किसानों की फसलों का बीमा होता है। उसमें 2 परसेंट किसानों से लिया जाता है, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का उसमें पैसा होता है। बीमा कम्पनी वास्तव में किसानों को कुछ देना नहीं चाहती है। खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, जब फसल खराबा होता है तो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं, तब जाकर वे कहीं तैयार होती हैं और उनकी स्थिति यह है कि जब क्लेम का पैसा देते हैं।

(समय: 17.24 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जितना प्रीमियम जमा है, उसके बराबर वे पैसा देते हैं। इससे तो बढ़िया है कि जितना प्रीमियम सरकार दे रही है, उतना किसानों के खाते में डाल दो, तो वे भी खुश हो जायेंगे। प्रीमियम से ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते, कभी ज्यादा ही दबाव हो तो उससे दुगुना दे देगी, पर यह बहुत बड़ी लूट है। ये जो बीमा कम्पनियां हैं, वे वास्तव में लूट रही हैं, केन्द्र सरकार का पैसा ले रही हैं, राजस्थान सरकार का पैसा ले रही हैं और कुछ देना नहीं चाहते। इस प्रकार की व्यवस्था है।

सभापति महोदय, ऊंट को हमारी पिछली सरकार ने राज्य पशु घोषित किया था। कृषि मंत्री जी यहां से चले गये हैं। वास्तव में, जो रेबारी समाज के लोग हैं, उनका आग्रह है कि राज्य पशु से इसको निकाला जाये। वे ऊंटों को

(श्री नरेन्द्र नागर)

छोड़ रहे हैं, उनका मोह भंग हो गया है तो कहीं न कहीं उसके लिये योजना बनाये। राज्य पशु से दिक्कत है तो राज्य पशु क्या, किसी सरकार ने घोषणा कर दी, हमने बना दिया राज्य पशु हट भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इस पर दुबारा अपने को सोचना चाहिए, भले इसकी डिबेट हो। सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको ह्दय से आभार-धन्यवाद करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार का चौथा बजट पेश किया गया है जो कि ऐतिहासिक है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने राजस्थान के किसानों का, बेटियों और मांओं की ऊंची उड़ान का और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, प्रदेश के आम अवाम की अच्छी सेहत के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, गांव के हाल व शहरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए, बेहतर बजट पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष सवाल करता है कि बजट घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाती है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन साल के अन्दर जो घोषणाएं हुई हैं, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जो कि धरातल पर नहीं उतरी हो।

माननीय सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, उस समय विपक्ष के चेहरे देखने लायक थे। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष चुपचाप उस बजट भाषण को सुनकर मुझे लगता है अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा हो कि ये कब बन्द करें बजट भाषण, क्योंकि ये क्षेत्र में जायेंगे, क्षेत्र में ये जवाब नहीं दे पायेंगे कि आपने पिछली सरकार में क्या किया?

सभापति महोदय, मैं पहली बार विधायक बनी हूं, लेकिन मैंने पहले कभी इस तरह का बजट भाषण सुना नहीं। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना लागू की, उससे तो पूरे राजस्थान के अन्दर खुशियां इतनी छाई हैं कि पूरी रात भर हमारे क्षेत्र के कर्मचारी या कहीं पर भी पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने इतना उत्साह और जोश के साथ जश्न मनाया कि पूरे देश के अन्दर इसका मैसेज गया है। माननीय सभापति

(श्रीमती इन्द्रा)

महोदय, भाजपा ने उन कर्मचारियों का अधिकार छीना और कांग्रेस ने उनको अपना अधिकार वापस लौटाकर उनका मान-सम्मान बढ़ाया है।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष बेरोजगारी पर बात करता है। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा पिछली साल हमने एक लाख से ऊपर नियुक्तियां दे चुके हैं। और सवा लाख की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं और एक लाख नियुक्तियां अब इस बजट भाषण में देने की घोषणा की है जबकि पिछली सरकार में पूरे पांच सालों में दो लाख नियुक्ति दे पाये हैं, फिर किस मुंह से इस सदन में बेरोजगारी बढ़ाने की और विपक्षी हमले करने की बात ये लोग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग की कि बीस-बीस विद्यालय हमारे क्षेत्र के क्रमोन्नत कर दीजिये लेकिन जो हमने मांगा वह तो कहीं आस-पास भी नहीं रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने कोई भी स्कूल, मैं सोच रही थी कि कौन सा विद्यालय क्रमोन्नत कराऊंगी और कौन सा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि दो-तीन हो सकते हैं इस सत्र में लेकिन सम्पूर्ण विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं दसवीं से बारहवीं तक के, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी को और विशेषकर बालिकाओं के जो विद्यालय हैं वे सारे जो क्रमोन्नत किये हैं, उनकी संख्या भी 389 माध्यमिक स्तर के और 115 प्राथमिक स्तर के क्रमोन्नत किये।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में मुख्य मंत्री एक महिला थीं लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो माननीय मुख्य मंत्री जी गहलोत साहब ने इस बजट में करके दिखाया है। पीएचसी भवन बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिपलाई नारोली चोड, जाहिरा बपुई के भवन बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं और भेड़ोली में उप स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि यह बजट स्वीकृत किया जाये। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने पांच लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी बीमा राशि को दस लाख कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 125 दिन

(श्रीमती इन्द्रा)

का और शहरी क्षेत्रों के लिए 100 दिन का जो रोजगार गारंटी की घोषणा की है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि पिछली बार मेरे बामनवास की नगरपालिका बनी तो कुछ लोगों ने विरोध किया इस बात को लेकर कि अब नरेगा कार्य बंद हो जाएगा और गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ा काम था।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, हम धन्यवाद देना चाहेंगे नयी सड़कों के लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दस करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। हम मांग करना चाहेंगे कि दस करोड़, 7:3 का जो रेशो दिया है वह सारा नयी सड़कें या किसी भी प्रकार की सड़कें बनाने के लिए खुला किया जाए क्योंकि मेरे क्षेत्र में पुरानी सड़कें बहुत कम संख्या में हैं। सारी नयी बन चुकी हैं तीन साल के अन्दर। अब हमें नई रोड्स बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं का भी पूरा ध्यान इस बजट में रखा है। एक करोड़ तैंतीस लाख स्मार्ट फोन देने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है। उसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां जी ने बात कही है काली दुल्हन की। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं का जो अपमान किया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): महिलाओं का जो अपमान किया है जब ये राजस्थान में क्षेत्र में जायेंगे, विधान सभा क्षेत्र में जायेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उन्होंने जिस तरीके से काली दुल्हन बताया है, महिलाएं काले झण्डे दिखाकर इनका विरोध करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग दो सौ करोड़ की राशि तीन साल में स्वीकृत हो चुकी है पानी के लिए। अधिकतर गांवों में पानी की स्कीम स्वीकृत हो चुकी है लेकिन कुछ गांव, कुछ पंचायतें ऐसी बची हैं जिनके अन्दर सिर्फ चम्बल ही सोल्युशन है तो मैं मांग करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में चम्बल परियोजना के लिए स्कीम बनायी जाये। इस बजट के अन्दर मेरे क्षेत्र में नगरपालिका बौंली को दी है। वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमोन्नत किया है। मित्रपुरा को पहले तहसील बनाया और अब थाना बना दिया गया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और एक भाडोती से दतवास को हाईवे बनाया है उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किसानों के लिए बहुत बेहतर

(श्रीमती इन्द्रा)

स्कीम माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट में लेकर आये हैं क्योंकि पहले तारबंदी होती थी वह ग्रुप में की जाती थी, अब तारबंदी छोटे-छोटे कृषकों को भी मिल पायेगी और अपनी फसलों की वे सुरक्षा कर पायेंगे। कई सारी स्कीम्स किसानों के लिए फायदेमंद हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कुछ मांगें हमारी रह गयी हैं। उप तहसील बरनाला को तहसील बनाने की मांग थी वह घोषणा नहीं हो पायी है। मित्रपुरा में जनरल कालेज की घोषणा नहीं हो पायी है तो मैं मांग करना चाहूंगी कि वहां दूर पड़ता है, दो जिलों की सीमाएं पड़ती हैं और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। आंती क्षेत्र में एक संस्कृत विद्यालय है उसको कालेज में क्रमोन्नत करने या जनरल कालेज खोलने के लिए मैं मांग करना चाहूंगी। बाटोदा में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करती हूं और बामनवास में डिपो स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना निगम की घोषणा की है वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे उधर किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। 16 जिलों में दिन में लाइट का पहले कर चुके हैं और 17 जिलों में इस साल में करने की जो घोषणा की है वह बहुत बड़ा मैटर होगा क्योंकि किसानों को रात में पानी पिलाने में बहुत तकलीफ होती है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा सरकार का चौथा बजट सदन के पटल पर रखा गया। बजट लोक लुभावना तो है लेकिन वित्तीय प्रबन्ध का अभाव है। जब तक वित्तीय प्रबन्धन नहीं होगा तब तक उस बजट का कोई सार नहीं है। 2022-23 के बजट के अन्दर जो भी घोषणाएं की गयी हैं वो सिर्फ घोषणाएं ही लगती हैं, धरातल पर कैसे उतारी जायेंगी यह भविष्य में देखने पर पता चलेगा। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बढ़-चढ़ करके इस बजट के बारे में सराहना भी की, बजट को अच्छा भी बताया। मेरी नजर में यह बजट नीतिगत

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

नहीं है। यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले 5-6 महीने में कोई चुनाव है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा बेरोजगार का इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं है। यह बजट घोषणाओं का एक पुलिन्दा है। घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबन्धन इस बजट में दिखायी नहीं देता है। इस प्रदेश में अभी बेरोजगार युवाओं के साथ जो रीट में चीट हुई है वह जगजाहिर है और पेपर लीक करने वाले सीबीआई के चंगुल में आने चाहिए, उनके सरगना को पकड़ने की आवश्यकता है लेकिन सरकार उन सरगनाओं तक पहुंचना नहीं चाहती है, सीबीआई से जांच कराना नहीं चाहती है। पेपर लीक के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है इसकी जांच जरूरी है। यह बजट हवाहवाई है। आने वाले चुनाव में सरकार की भी हवा निकलने वाली है। मैं पिछला बजट 2021-22 पढ़ रहा था। इस बजट में मैंने माननीय गहलोत साहब का एक शेर पढ़ा उसमें यह लिखा था-

''"मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है।

यह तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है।

मेरी सादगी से मेरे बारे में अन्दाज मत लगाना।

यह तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है।''

इस बजट को देखने के बाद और पिछले कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, पिछले वर्ष काम नहीं हुआ तो मैंने इस शेर को इस तरह से समझा, इस शेर को मैं वापस पढ़ता हूं-

''मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है,

यह तो बिना दाम का बजट है।

अभी तो मेरी कलाकारी बाकी है,

मेरी सादगी पर मत जाना ऐ मेरे दोस्त,

मेरी जादूगरी देखना, यह तो शुरुआत भर थी,

असली जादू तो अभी बाकी है।''

तो यह जादूगरी वाला बजट है। होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार के अन्दर जो-जो काम स्वीकृत थे उन सब कामों को, उन सब सड़कों को आपने बंद करने का काम किया।

गत वर्ष के बजट में जो सड़कों की घोषणाएं थीं, उनका धरातल पर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

काम नहीं हो रहा है। किसानों की ऋण माफी की घोषणा आपने की थी, 10 दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ उस कर्ज माफी का, कहां कर्ज माफी हुई है? लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं, जमीनें नीलाम हो रही हैं, नोटिस मिल रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहा है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की आपने बात कही। प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, आप मात्र 40 हजार बेरोजगार युवाओं को भत्ता दे पा रहे हैं। पिछले बजट में कहा गया था बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी। आपने पीछे के दरवाजे से बिजली की दरें बढ़ा दीं। लाखों रुपये के वीसीआर बनाये जा रहे हैं। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और वह घोषणा लागू होनी चाहिये थी, लागू नहीं की। मुख्य मंत्री जी ने कहा था किसानों को अच्छी बिजली देने के लिये, बिजली खरीद में पारदर्शिता रखने के लिये, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिये नई कृषि विद्युत वितरण कम्पनी बनाने की घोषणा करता हूं। कहां गई वह विद्युत कम्पनी? तहसील मुख्यालय पर नंदी शालाएं खोलने की बात कही। तीन साल हो गये हैं, नंदी शालाओं का अता पता नहीं है। पिछले कार्यकाल में एक घोषणा और की थी, गोशालाओं और पशुपालकों के घर पर ही आपात कालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटरिनरी सेवा लागू की जायेगी। कहां है वह वेटरिनरी सेवा, कहां गई वह 102 एम्बुलेंस? धार्मिक पर्यटक सर्किट बनाया जायेगा। यह धार्मिक सर्किट कहां चला गया? पिछले बजट में इस प्रकार से कई थोथी घोषणाएं हुई हैं जिनकी क्रियान्विति आज तक नहीं की गई।

हमारी सरकार की जो योजनाएं थीं, उन योजनाओं को आपने बन्द करने का काम किया। भामाशाह योजना को बन्द किया। स्टेट रोड टोल जो हमने माफ किया था, उसको आपने चालू किया। अन्नपूर्णा योजना को बन्द किया, उस योजना का नाम बदल दिया। हमारी पिछली सरकार में किसानों के बिजली के बिल माफ थे, आपने तीन साल तक बिजली के बिल लिये और अब उसको माफ करने का काम किया। ग्रामीण गौरव पथ योजना को बन्द कर दिया। प्रदेश में अम्बेडकर भवनों के काम चल रहे थे, उनको बन्द कर दिया। डीएमएफटी की तीन साल तक मीटिंगें नहीं हुईं। पंचायतों को राज्य मद का पैसा नहीं दिया गया। विद्यालय में बालकों को जो दूध दिया जाता था, वह दूध आपने बन्द कर दिया। सरकार की घोषणाओं पर भी कार्य नहीं हो रहा है। हमारी योजनाएं बन्द कर दीं, कोई बात नहीं लेकिन सरकार की योजनाओं पर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

तो काम करो। चुनाव में संविदा कर्मचारियों को कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको स्थायी किया जायेगा। एक भी संविदा कर्मचारी को नियुक्ति नहीं दी गई। जो पहले पीएचईडी मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था 40-40 हैंडपम्प देंगे, 10-10 सोलर डीएफयू देंगे, किसी के भी एक भी स्वीकृत नहीं हुआ। जेजेएम योजना में जो पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी, उनके काम और उनके टेंडर भी नहीं हो रहे हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी कि प्रत्येक गांव में ग्रामीण विकास पथ बनेंगे। कहां चले गये विकास पथ? प्रदेश में कहीं विकास पथ नजर नहीं आ रहे हैं और न विकास नजर आ रहा है। सरकार तीन साल तक बिजली के बिल बढ़ाती रही। वीसीआर बनाकर किसानों के साथ लूट करती रही। 15-15 दिन तक जले हुए ट्रांसफार्मर, चोरी गये ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। किसान ट्रांसफार्मर बदलाता है लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने का ...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ट्रांसफार्मर बदलने का काम किसान करता है लेकिन सरकार के चहेते ठेकेदारों को बिल पास करके करोड़ों रुपये का घोटाला करने का काम किया जा रहा है। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल-पेट्रोल राजस्थान में। आदर्श सीएचसी बनाने की घोषणा की गई थी, कहां गई आदर्श सीएचसी बनाने की घोषणा? प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी चौपट है और मुझे लगता है कि पूरी सरकार को माफिया चला रहा है। कौन-कौन से माफिया हो गये, और माफिया पनप गये। पेपर लीक माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया। बजरी माफिया के तो कहने ही क्या हैं। कोटा में और जहां-जहां भी बनास नदी बहती है, वहां तो करोड़ों रुपये के घोटाले, घपले और पुलिस भी सुरक्षा देती है। खान विभाग का कोई उड़न दस्ता जा रहा है तो भू माफिया और बजरी माफिया उस पर ट्रक चढ़ा देता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अवैध वसूली माफिया, नकली दवा माफिया। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आये दिन बलात्कार, गैंग रेप, चोरी, लूट, डकैती, सरेआम हत्याएं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट। खुलेआम मारपीट, गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती है क्योंकि बदमाशों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक और निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने कृषि का अलग से बजट पढ़ा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपने कृषि का बजट अलग से पढ़ा, लेकिन हुआ क्या, प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग किसान हैं लेकिन आपने उनके लिये ऊंट के मुंह में जीरा दिया। आपने सिर्फ यह कहा कि आठ लाख किसानों को संकर मक्का दिया जायेगा, दो लाख किसानों को मूंग मोठ, तीन लाख किसानों को चारे का बीज। एक-एक ग्राम पंचायत में....

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राकेश पारीक।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): राजस्थान में 10 हजार ग्राम पंचायतों में यदि (व्यवधान) किसानों को दिया जायेगा, मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो यह बजट रखा है, उसमें वित्तीय प्रबंधन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा साबित होगा। धन्यवाद।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है और ऐसा बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग को इसमें सहायता दी है। सबसे पहले तो आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को, वह यह सोचता था कि नौकरी लग कर क्या करूंगा, पेंशन तो नहीं मिलेगी। इनकी सरकार ने उनकी पेंशन को बन्द किया, लेकिन एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम आम आदमी के लिये, जो सरकारी कर्मचारी था, पटवारी था, मास्टर था, उन सब लोगों को तोहफा दिया। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार का और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

जहां तक सवाल है कृषि का अलग से बजट पेश किया और एक मिसाल पेश की। मैं खुद भी किसान हूं, हम सुना करते थे कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आज हालात ऐसे हैं कि यह किसान को भिखारी बनाकर रख देंगे। जब आप नीरव मोदी और तमाम उन व्यापारियों का पैसा माफ कर सकते हो तो यह किसान के डीजल-पेट्रोल और गैस का पैसा, हम क्या घोषणा करें, आपके 25 के 25 सांसद बैठे हैं। सभापति महोदय, अभी केन्द्र सरकार का भी बजट पेश हुआ था। आज हम बड़ाई कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। लेकिन थोड़ी इन लोगों को भी सुध आनी चाहिये कि इस बजट में किसान को सब्सिडी दे दो। जब नीरव मोदी पैसे लेकर भाग सकता है, वह दूसरा मोदी भाग सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से रोज देखते हैं आज

(श्री राकेश पारीक)

पांच राज्यों के चुनाव में इनकी क्या हालत हो रही है। वो कि वो हालत इस बजट के आने के बाद राजस्थान में इन लोगों की होने वाली है। बात करना बहुत आसान है लेकिन कांग्रेस पार्टी एक गरीब, मजदूर, किसान की पार्टी है और किसान के लिये जो भला किया है, इसके लिये हम आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

कृषि का बजट अलग से पेश करना और उस बजट में जो रियायतें दी गई हैं, किसान उससे बहुत खुश है। यह वह लोग हैं जिनको पचता ही नहीं है कि किसी गरीब को रोजगार मिले। हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जो नरेगा योजना चालू की, क्या हाल किया इन्होंने, नरेगा में बहुत पैसा कम कर दिया। कोरोना काल में नरेगा योजना नहीं होती तो हमारा आम आदमी भुखमरी का शिकार हो जाता। आज नरेगा ने किसानों को, मजदूरों और गरीबों को इतनी राहत दी है और इन लोगों ने बजट में कटौती की है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि अपने यहां से बजट बढ़ाया जाये। हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि सौ दिन से सवा सौ दिन किये हैं, यह बहुत ही सराहनीय बात है, इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस बजट में मेरे इलाके के नागोड़ा में ज्योतिबा फूले बालिका आवासीय छात्रावास दिया है। एक प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय दिया है। एक ब्यावर-विजयनगर होते हुए गुलाबपुरा तक की नयी रोड दी है। हमारे यहां 425 करोड़ की स्कीम सरकार ने दी है, इसके लिए मैं सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। मेरे इलाके में तीन डीवाई.एस.पी. लगते थे, ब्यावर का मसूदा में, विजयनगर का नसीराबाद में और भिनाय का केकड़ी में तो मैं सरकार का और सीएम साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बजट में हमें डीवाई.एस.पी. का कार्यालय दिया। किसी भी तरह से विकास के कार्यों में कांग्रेस के शासन ने कमी नहीं रखी है, मगर मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक गांव काणियां का नाम मैंने पिछली बार भी बजट में उठाया था। उसमें एमएलए मसूदा का है और एमपी भिनाय का है और बाकी सारी भीलवाड़ा जिले में आती है। हमारे रामलाल जी बैठे थे, कहीं चले गये होंगे, सुन रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि उस काणियां गांव को चम्बल योजना से जोड़ा जाये। मैंने एक मांग पिछले सत्र में भी की। बीसलपुर के अन्दर पानी की दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि विजयनगर तहसील को, क्योंकि पहले कभी बीसलपुर का पानी हमारे पड़ोस में

(श्री राकेश पारीक)

गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जाता था। हम चाहेंगे कि चम्बल का पानी पूरी विजयनगर तहसील को मिले, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

मेरा इस सदन के माध्यम से आदरणीय सीएम से आग्रह है कि मेरे विजयनगर क्षेत्र के अन्दर सरकारी कालेज नहीं है। प्राइवेट कालेज है, जिसकी फीस 20-25 हजार लगती है, इससे वहां के गरीब बच्चे पढ़ने में परेशान होते हैं। मेरी मांग है कि विजयनगर के अन्दर एक सरकारी कालेज खोला जाये। इसी 3 तारीख को घोषणा की जाये, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और बच्चों को राहत मिलेगी। मेरा आग्रह है कि हमारी विजयनगर तहसील में उपखण्ड नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा और मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि रिप्लाई में हमारे विजयनगर में उपखण्ड कार्यालय खोला जाये। भिनाय एसडीएम आफिस से केकड़ी करीब 70 किलोमीटर है तो भिनाय थाने के लिए एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोला जाये, जिससे आम जनता को लम्बा सफर नहीं करना पड़े। मैं मांग करूंगा कि रामगढ़ जो कि जो मसूदा तहसील में आता है, उसमें एक उप तहसील का निर्माण कराया जाये और एक पुलिस चौकी खोली जाये, जिससे रामगढ़ के लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी दसवीं की स्कूलें थीं उनको सीनियर कर दिया, लेकिन पांचवीं से आठवीं और आठवीं से बारहवीं कर देना, दसवीं का तो रखा ही नहीं, जिससे कि शिक्षा की प्रगति होगी, क्योंकि हमारा किसानों का इलाका है।

हमारे मगरे का इलाका है, वहां बहुत बहादुर लोग रहते हैं। मेरे मसूदा विधान सभा क्षेत्र के मगरे में देश भक्ति और राष्ट्र भक्ति के लिए अब तक 23 लोग शहीद हो चुके हैं। जितनी भी विकास की योजनायें हैं, वे मेरे इलाके में जारी करें। मैं एक बार पुन: सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जो 10 करोड़ रुपये की सड़कें दी हैं, पिछली बार भी 5 करोड़ की सड़कें दीं, उससे गांवों का सुधार हुआ। सड़कों का जो पेचवर्क है, पेचवर्क की बजाय इस पेचवर्क का पैसा भी सड़कों में दे दें, नहीं तो वे पेच करेंगे कि नहीं करेंगे या लेकर भाग जायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पेचवर्क को बन्द किया जाये और पेचवर्क के स्थान पर हमें और पैसा दे दिया जाये, जिससे कि वह फायदा मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग और करूंगा। अभी महेश जी

(श्री राकेश पारीक)

भाई साहब नहीं हैं। मेरे विजयनगर की पीने के पानी की 25 करोड़ रुपये की स्कीम यहां पर आयी हुई है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से और मुख्य मंत्री जी से एवं पीएचईडी मंत्री महेश जोशी जी से यह मांग करूंगा कि विजयनगर की स्कीम को सेंक्शन करें, जिससे कि हमारे वहां की जनता पानी पी सके। धन्यवाद। जय हिन्द। राम राम-सा।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बलवीर सिंह जी लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, 2022-23 के बजट के आय-व्ययक पर आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ने अपने इस कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया है। 15वीं विधान सभा के किसी भी बजट सत्र में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं लिया गया। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की घोषणा की, जबकि सम्पूर्ण राजस्थान के मुखिया सीएम साहब हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डेन्सिटी और पोपुलेशन के हिसाब से विकास करवाये जाने चाहिये। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तवज्जो देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि जनता सब जानती है। अगले विधान सभा चुनावों में जनता द्वारा आपको आईना दिखा दिया जायेगा। हां, इस बार भी सीएम साहब ने घोषणायें तो खूब की हैं, मगर धरातल पर ये लागू होंगी, इसका मुझे पूरा-पूरा संशय है।

बजट घोषणा के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ छात्र-छात्राओं का मुझे फोन भी आया और उन्होंने कहा कि जिन मेधावी छात्रों को वर्ष 2019-20 में लैपटाप दिये जाने थे, वे लैपटाप आज तक हमें नहीं मिले। बड़ा अफसोस है कि जो मेधावी छात्र लैपटाप के हकदार थे, उन्हें लैपटाप तक नहीं मिला। बजट भाषण के दौरान सीएम साहब विपक्ष की तरफ हाथ करके बार-बार इशारा कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसे वे कह रहे हों कि तुम विपक्ष वालों को कुछ नहीं मिलने वाला।

अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में श्रीगंगानगर के पूरे जिले समेत मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर को भी नजरअंदाज किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र और विजयनगर के लिए मैं लगातार पिछले सालों से ट्रोमा सेन्टर खोलने की मांग करता आ रहा हूं, मगर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में तीन सीएचसी हैं। वहां न तो कोई स्वास्थ्य उपकरण हैं, न ही डाक्टरों के पूरे पद भरे हैं। डाक्टरों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। किसी भी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए डाक्टरों द्वारा पेशेन्ट को अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है। विजयनगर और रायसिंहनगर से जिला मुख्यालय बीकानेर सौ-दो सौ किलोमीटर दूर है। कई बार तो इलाज के अभाव में पेशेन्ट की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंनगर और विजयनगर में ट्रोमा सेन्टर खोला जाये एवं तीनों सीएचसी में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड इत्यादि शीघ्र उपलब्ध करवाये जायें। मेरे द्वारा विधायक कोष से चिकित्सीय उपकरण खरीदने हेतु जो राशि उपलब्ध करवायी गयी थी, आज तक वे उपकरण भी सीएचसी में नहीं पहुंचे हैं।

सभापति महोदय, 2019-20 के बजट में रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह कालेज को सरकारी करने की घोषणा की गयी थी, मगर आज तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिए मैंने तीन साल में माननीय मुख्य मंत्री जी को कई बार आग्रह किया, जिसकी घोषणा भी नहीं की गयी। बहुत से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने वाले हैं, वे भी नहीं किये गये हैं। कई विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीविजयनगर का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

(समय: 18.00 बजे)

उल्लेखनीय है कि शहीद भगत सिंह कालेज के सरकारीकरण हेतु न तो कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की जमीन की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी समस्त लेनदारियां व देनदारियों को समाहित करके इसको शीघ्र ही शुरू किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, श्रीविजयनगर कस्बे में रीको क्षेत्र घोषित किया जाकर नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां पर औद्योगिक

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

इकाइयां लगाई जा सकें एवं क्षेत्र में एक वृहत प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। मेरी विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अधिकांश गांव पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा से बिलकुल सटे हुए हैं। इस क्षेत्र में कई गांवों में अभी भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से गांव अभी भी डामर रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। बहुतसी सड़कों में खडवंजे लगे हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं और नीचे बैठ चुके हैं। मेरी विधान सभा में 100 किलोमीटर डामर रोड स्वीकृत की जावे एवं निम्न सड़कों का तुरंत डामरीकरण किया जाए जिसकी महती आवश्यकता है।

गांव 16 बीएलडी से रामसिंहपुर तक 3 किलोमीटर; गांव 6 बीएलएम से गांव 5 बीएलडी लिंक रोड तक वाया 6 बीएलडी, 3 बीएलडी, 8 बीएलडी, 5 किलोमीटर; गांव 47 जीबी से गांव 52 जीबी तक 3 किलोमीटर; गांव 73 आरबी से गांव 19 आरबी तक 1 किलोमीटर; 74 आरबी से आरबी नहर पुल डामर रोड तक 1.5 किलोमीटर; डामर रोड गांव 20 जीबी से 23 जीबी डामर रोड तक 1.5 किलोमीटर; गांव 22 पीटीडी से गांव 25 पीटीडी 3 किलोमीटर; गांव 4 जेकेएम डामर रोड से गांव 4 जेकेएम'ए' तक 3 किलोमीटर; रायसिंहनगर-अनूपगढ़ भारतमाला रोड 74 एनपी बस स्टैण्ड से गांव दुलरासर तक 3 किलोमीटर; 45 जीबी डामर रोड से मोटासर डामर रोड तक; 17 जीबी डामर रोड से 21 जीबी डामर रोड तक; गांव 79 एनपी डामर रोड से गांव बरूवाला तक; रायसिंहनगर-अनूपगढ़ भारतमाला रोड 41 एनपी बस स्टैण्ड से गांव रामजीवाला तक; जैतसर-पदमपुर रोड 2 एलसी से गांव 3 एमएसडी की तरफ 2 किलोमीटर; मोकमवाला से गांव 7 एसजेएम वाया 8 केएसडी बी, 7 एसजेएम बी 3 किलोमीटर।

अनूपगढ़-सूरतगढ़ रोड के साथ-साथ घग्घर नदी बहती है। इस पर बसे गांव 11 जोईयांवाली में घोड़ा पुलिया बनी हुई है। उक्त घोड़ा पुलिया पर बड़ा पुल बनाया जाए ताकि बड़े साधनों का आवागमन हो सके। इस पुलिया से 25-30 गांव जुड़े हुए हैं। ग्रामवासियों को शहर तक फसल ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन गांववासियों को पुल के अभाव में 20 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी विधायकों से 2-2, 3-3 विकास पथ के प्रस्ताव मांगे थे। विधान सभा रायसिंहनगर में मैंने ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलोचिया एवं शिवपुरी में विकास पथ के प्रस्ताव भेजे थे

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

जिसका सर्वे भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया था मगर आज तक विकास पथ नहीं बने। यही हकीकत है राजस्थान सरकार की। रायसिंहनगर तहसील के जिन गांवों में विधायक कोष से 5 करोड़ रुपये से जो सड़कें स्वीकृत हुई थीं, उनका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं किया गया। अधिकारी लापरवाही बरतते हैं।

सभापति महोदय, इस बार पहली बार कृषि के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान के किसानों को, मगर निराशा ही हाथ लगी। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी मगर सरकार द्वारा बजट में यह घोषणा पूरी नहीं करके, किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी नहीं करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसके उलट ऋण वसूली के लिए किसानों की जमीनें नीलाम करके ऋण वसूली की जा रही है। दुःखी होकर किसान आत्महत्या करने पर विवश है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र तो लगभग सिंचित है। किसानों को अपनी फसल पकाने के लिए पूरा पानी नहीं मिलता। समय पर रेगुलेशन कमेटी का गठन नहीं करके सिंचाई विभाग के आला-अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरें चलाकर किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। रेगुलेशन कमेटी के अभाव में किसानों को यह पता नहीं चलता कि मेरे खेत में कब पानी लगेगा?

सभापति महोदय, वर्ष 1981 से 0.6 एम.ए.एफ. मिलियन एकड़ फीट जो कि लगभग तीन लाख क्यूसेक पानी बनता है, ये राजस्थान के हिस्से का पानी पिछले कई वर्षों से पंजाब उपयोग कर रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी मिले। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई क्षेत्र के जितने भी खाले कच्चे हैं उन्हें सी.ए.डी. विभाग द्वारा पक्का किया जाए। आई.जी.एन.पी. एवं गंग कैनाल की जितनी भी वितरिकाएं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत की जाए। फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके लिए मैं सी.एम. साहब का धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कृषि हेतु अलग बजट घोषित किया। श्रीगंगानगर जिले में कोई बड़ा कृषि उद्योग लगाने

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

की घोषणा नहीं की। राजस्थान में डी.ए.पी. व यूरिया खाद की हमेशा से किल्लत रहती है। किसानों को लाइन में लगकर यूरिया लेनी पड़ती है और पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले में यूरिया व डी.ए.पी. की औद्योगिक इकाई लगाई जावे ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके एवं साथ ही क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों द्वारा कृषि डिग्गियों के जो आवेदन किये गये हैं, उनका पंजीयन तो कर लिया गया है, मगर लक्ष्य कम होने की वजह से किसानों को डिग्गियों पर अनुदान नहीं मिला। आवेदन जमा होने पर सरकार द्वारा लाटरी सिस्टम के द्वारा आवेदनकर्ताओं का चयन किया गया। इसमें जिन किसानों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें इसका लाभ न मिलकर लाटरी द्वारा निकले लाभार्थियों को इसका लाभ मिला जो कि सरासर किसानों के साथ अन्याय है। पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर वरीयतानुसार सभी आवेदनकर्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। डिग्गियों पर मिलने वाली अनुदान राशि भी बहुत कम है। महंगाई को देखते हुए कृषि डिग्गियों पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 5 लाख तक की जावे।

किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए किसानों को सहायक कृषि धन्धों पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि वह मछलीपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन आदि व्यवसाय कर सके। किसानों को ऐसे व्यवसाय करने के लिए बैंक भी ऋण नहीं देते। इस वजह से गरीब किसान यह व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। अत: सरकार को ऐसे धन्धे शुरू करने के लिए किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान देना चाहिए।

श्री सभापति: थैंक यू माननीय सदस्य। धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर, प्लीज दो मिनट। आवारा पशुओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कीजिए आप।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): पिछले बजट में सरकार द्वारा नन्दीशालाएं खोलने की घोषणा की थी। आज तक गंगानगर जिले में एक भी नन्दीशाला खोली नहीं गयी। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गोशाला खोली जावे। इसके रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बजट दिया जावे ताकि आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सके। बीकानेर सम्भाग में पिछले 2 वर्षों से टिड्डियों के आक्रमण होते आये हैं। इससे किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। सरकार द्वारा टिड्डियों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबन्धन किया जावे।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, प्लीज एक मिनट में अपना पूरा कर लूंगा।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, जिन कच्ची बस्तियों में गरीब लोग निवास करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जावे। चूंकि जब इन बस्तियों में पानी, बिजली, स्कूल अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं तो फिर वहां के गरीब लोगों को...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों वंचित रखा गया है? आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। पिछले तीन वर्षों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद पड़ा है जिसकी वजह से पात्र लोगों के नाम इस योजना में नहीं जुड़ पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल अतिशीघ्र शुरू किया जावे ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके।

श्री सभापति: धन्यवाद, समाप्त कीजिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): महोदय जी, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला पंजाब-हरियाणा बोर्डर पर स्थित है। पेट्रोल-डीजल के दामों का अन्तर गंगानगर में पंजाब-हरियाणा से करीब 10-11 रुपये महंगा है। पेट्रोल-डीजल के दाम पंजाब-हरियाणा के बराबर किये जाएं।

श्री सभापति: प्लीज, बैठिए। आप प्लीज बैठिए। आप बोलिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): पूर्व में हनुमानगढ़ में पैट्रोलियम डिपो चल रहा था जिसे पुन: चालू किया जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मुझे सरकार को बताते हुए खुशी हो रही है..

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूरे पांच सालों में बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी। अपने वादे से मुकरते हुए पिछले तीन सालों में बिजली के बिलों में पांच बार वृद्धि कर दी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद आपका।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): मैं आग्रह करता हूं बिजली के बिलों को माफ किया जाए क्योंकि गरीब व किसान जो बिजली बिल नहीं भर सकते, उनका सम्पूर्ण कर्जा और बिजली बिलों की माफी की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

सूचना

दांतारामगढ़ में बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेसक्यू

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि दांतारामगढ़, सीकर में कल एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिरा गुड्डू, आज हमारे एन.डी.आर.एफ. व एस.डी.आर.एफ. टीम व हमारे विधायक वीरेन्दर जी के सहयोग से सकुशल वह बच्चा बाहर निकलकर आया है और बिलकुल स्वस्थ है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में विधायकों की गैर-मौजूदगी व अधिकारी दीर्घा में अनुपस्थित अधिकारीगण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, राजस्थान की जनता का लाखों रुपया इस सदन की बैठक आयोजित करने पर खर्च होता है।

(श्री संयम लोढ़ा)

आप सदन की हालत देखिए। 200 में से 175 विधायक सदन में मौजूद नहीं हैं और ऑफिसर्स गैलेरी में एक अधिकारी नहीं बैठा है जो किसी बात को नोट करे। इससे सदन की गरिमा लगातार इस प्रवृत्ति से गिर रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बारे में कोई सख्त व्यवस्था दें जिससे सदन में पूरी उपस्थिति लोगों की रहे। ये जो हाजिरी में दस्तखत करवाते हैं, इसका समय 5 बजे करिए ताकि 5 बजे तक ये मौजूद रहें यहां पर। ये तो अपना दस्तखत करके बस्ता उठा लेते हैं। सदन में बैठते नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर बात उठाई है। हम लगातार देख रहे हैं सदन के जो हमारे दिन हैं, वह कम होते जा रहे हैं। सदन के अन्दर जब माननीय सदस्य बोलता है तो एक भी अधिकारी सामने नहीं। बजट पर बहस चल रही है। माननीय सदस्य अपनी मांगें रख रहे हैं, कोई तो हो। मैं समझता हूं यह सोचने की बात है। हो क्या रहा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नोट कर रहे हैं हम लोग।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप ज्ञानी हैं हर बात के। यह ठीक है क्या? एक भी ऑफिसर, ऑफिसर्स गैलेरी में नहीं बैठा हो। यह सदन की गरिमा को गिराने वाला कृत्य है। आप कार्यवाही कीजिए। जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई हुई है, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अधिकारी को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं डिफेंड करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हम लोग लिख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जैसा व्यक्ति डिफेंड करने के लिए खड़ा हो गया। एक आदमी नहीं है गैलेरी में। मैं प्रतिपक्ष के नेता, आपसे निवेदन करूंगा (व्यवधान) आप चेयर को ..(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सेक्रेटेरियट में भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: It will be taken care of.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): वहां तो कह रहे हैं विधान सभा चल रही है, यहां विधान सभा में भी कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विधान सभा में बिजी है ... (व्यवधान) विधान सभा में एक अधिकारी यहां दिखता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसके लिये बोलें, हम किसको सुनायें? हम अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नेता, प्रतिपक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरे को इतने वर्षों का यहां रहने का अनुभव है, लेकिन लगातार आफिसर गैलरी में, जिन लोगों को भी यहां लगाते हैं, वह इतने लापरवाह हो रहे हैं। उनको डिफेंड करने के लिये कल्ला जी जैसा मंत्री खड़ा होता है। व्यवस्था सुधारने के लिये, उनको ताड़ना देकर, व्यवस्था सुधारो। बनिस्बत यह कि अगर उनको आप बचाने की कोशिश करोगे, तो यह सदन का भट्टा बैठ रहा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मेरा बचाने का उद्देश्य नहीं था। बैठे हुए थे। वह कहीं पानी, पेशाब के लिये गये हैं। बराबर, दिन भर बैठे हुए थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या तरीका हुआ? वाह कल्ला जी ... (व्यवधान) यह कोई तरीका हुआ। सभापति महोदय, एक आदमी, वह भी जूनियर स्केल का आदमी आकर बैठता है, सिर्फ एक आदमी। यह तरीका हुआ, पहले यहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी आकर बैठा करते थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) ड्यूटी लगेगी यहां पर बैठने के लिये। उनके वर्किंग आवर्स होंगे, यहां बैठने के लिये।

श्री सभापति: आपकी बात को नोट कर लिया गया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): यह भी सीनियर स्केल के हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): महेन्द्र जी, महेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह गये तो सही। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप जानते हैं कि आजकल अध्यक्ष जी की व्यवस्था के आधार पर पास वगैरह ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब, आपकी जानकारी में है, कि यह अधिकारी जूनियर स्केल के नहीं है। जोधपुर के जिला कलक्टर रहे हुए हैं। सीनियर लोग हैं ऐसे जूनियर नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इनके पूरे दिन का अटेंडेंस। पूरे दिन में, आफिसर गैलरी में जो एक अधिकारी रहता है, आप अटेंडेंस मंगाकर देख लीजिये ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी बात को नोट कर लिया गया है। It will be taken care of.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अब तक, बजट के ऊपर जब डिस्कशन होता था, तो प्रत्येक सम्भाग का, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति रहता था, ताकि उस क्षेत्र का विधायक, जो भी अपनी बात कहता था, वह उसको नोट करता था। जो विधायक भाग लेता था, उसको भी लगता था कि मेरी बात सही जगह जा रही है।

श्री सभापति: सत्ता पक्ष ने नोट कर लिया है, व्यवस्था की जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं, आप स्पीकर साहब को भी कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं महेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। महेश जी भी गये हैं पर यह तरीका थोड़े ही है। कल्ला जी, आप जैसा व्यक्ति इनको डिफेंड करे। (व्यवधान) सरकारी घोड़ों को डिफेंड करने के लिये खड़े हो आप। यह सरकारी अरबी घोड़ों को डिफेंड करने के लिये खड़े हो आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपको पता है, यह बैठे हुए थे। आदमी पानी, पेशाब के लिये तो जा ही सकता है न। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी बात नोट कर ली। (व्यवधान) श्री किसनाराम।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अधिकारियों के अलावा हाउस में माननीय सदस्यों की उदासीनता भी हमारा एक कन्सर्न है। (व्यवधान) माननीय सदस्यों की उदासीनता को भी आप देखिये।

श्री सभापति: आपकी बात को नोट कर लिया गया है। आप इसको ध्यान रखें प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। या तो आप सदन को बन्द कर दें, या अधिकारियों को यहां कहें।

श्री सभापति: आपकी भावना को नोट ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम चार-चार लाख लोगों के प्रतिनिधित्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने वाले लोग हैं। (व्यवधान) अपनी पीड़ा को यहां कहते हैं। अपनी बात को यहां कहते हैं। यहां अदना अधिकारी नहीं है हमारी सुनने के लिये।

श्री सभापति: आपकी भावना को नोट कर लिया गया है। सचेतक महोदय प्लीज, please take care of it. श्री किसनाराम जी। (व्यवधान) बोलिये प्लीज बोलिये। बैठिये प्लीज। बैठिये। बोलिये किसनाराम जी। (व्यवधान) मंत्री महोदया, बात हो गई।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 के लिये बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बजट, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 23 तारीख को पेश किया। यह कई मायनो में ऐतिहासिक बजट रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में, 2 घण्टे 56 मिनट, आधारभूत ढांचे की संरचना करने के लिये, इस प्रदेश के आम-अवाम के भले के लिये पेश किया, वह एक बहुत बड़ा रिकार्ड रहा है।

(समय: 18.14 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में, दूसरा रिकार्ड अलग से कृषि बजट पेश करके कायम किया गया है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यह पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। चाहे नि:शुल्क दवा योजना हो, नि:शुल्क जांच हो, पूरे देश के अन्दर, इनकी वाह -वाही हुई है। पूरे देश के अन्दर इनका मॉडल साबित हुआ है। तीसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी की विशेषता रही, कि कोरोना काल के अन्दर, जो व्यवस्था राजस्थान में की गयी मानव को बचाने के लिये, उसकी भी वाह-वाही पूरे देश में की गयी थी।

माननीय मुख्य मंत्री जी को हमने नजदीक से देखा है। हमारे जिले से आते हैं। मरुस्थलीय इलाके से आते हैं। जब आप सांसद हुआ करते थे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी मरुस्थल से रेगिस्तान इलाके में घूमा करते थे। इन्होंने गरीब की तकलीफ नजदीक से देखी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पेश किया है। चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह कर्मचारियों के क्षेत्र में हो। आज तीन दिन से, पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, लगातार तीन दिन से। ऐसा बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार आया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज राजस्थान प्रदेश के अन्दर, कोई भी व्यक्ति बीमार है, प्रदेश के किसी अस्पताल में जाये, जिसका चिरंजीवी कार्ड बना हो, उनका 5 लाख का बीमा कवर था, वह 10 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा भी किया है, उसके लिये मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तीसरी बात अगर कार्ड नहीं है, आदमी उस दायरे में आता है, जिला कलक्टर को अधिकृत कर दिया गया है, जिला कलक्टर हाथों-हाथ उनका निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, अधिकृत कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है, कि आज पूरे देश के अन्दर, बीमार की सुध ली है। पूरे उत्तरी भारत के अन्दर, बीमार की किसी ने सुध ली है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने ली है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश के अन्दर तीन दिन से पटाखे छूट रहे हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं। मिठाइयां बंट रही हैं। आज मुख्य मंत्री आवास पर कर्मचारियों ने, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ऐसा मैंने, मेरा राजनीतिक छोटा जीवन है, मैंने तो कभी नहीं देखा। मुख्य मंत्री जी के सांसद के समय से साथ हैं। वह दिन हमने देखे थे। कर्मचारियों की इतनी खुशी, उनके चेहरे पर, हमने आज तक नहीं देखी। हमने 2003 की नाराजगी भी देखी थी, उससे सौ गुना खुशी आज देखकर मुख्य मंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने दिल जीता है।

आज किसानों, आम उपभोक्ता के लिये, अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वह करते हैं। पांच साल तक किसानों का बिजली बिल का एक पैसा नहीं बढ़ाया, उलटा एक हजार रुपये की राहत दी गयी थी। आज आम उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट बिजली जलने के बाद 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी गयी है। आम उपभोक्ता का दिल जीता है।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। किसानों आम उपभोक्ताओं के बारे में उन्होंने सोचा है। 21 मार्च, 2012 से किसानों के कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे। उसके बाद, सामने बैठे साथियों की सरकार भी पांच साल तक रही। कृषि कनेक्शन नहीं दे पाये। 21 मार्च, 2012 से, परसों 22 तारीख तक, 3 लाख 38 हजार कनेक्शन एक साथ, आगामी वर्ष तक देने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

सामने बैठे साथियों ने, कई तरह की बातें करी। जो कहते हैं, वह करते हैं। सामने बैठे हुए साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो 10 मार्च के बाद पेट्रोल व डीजल के भाव मत बढ़ा देना, हम तो आपको सब मान लेंगे। गैस के भी भाव मत बढ़ा देना, सब कुछ हम मान लेंगे।

वह तो तय ही है, मालूम है हमारे को। आपकी नीयत क्या है, वह मालूम है हमारे को। पशुपालकों को दो रुपये पहले प्रति लीटर दूध की सब्सिडी दी जा रही थी, उसको बढ़ाकर तीन रुपये प्रति लीटर सब्सिडी कर दी गयी है। पशुओं के लिए निःशुल्क दवा पहले से ही दी जा रही है। पशुओं के लिए, अनबोल के लिए, अनबोल जानवर के लिए कोई सोच सकता है तो राजस्थान का मुख्य मंत्री सोच सकता है। हमने पहले भी इस सदन में यह बात रखी थी कि ऊंट को वसुन्धरा सरकार ने राज्य पशु घोषित किया था। उसके बाद में ऊंट के पालन पोषण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज ऊंट और ऊंटनी की हालत पूरे प्रदेश में खराब है। जगह-जगह पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड्स में एक्सीडेंट से ऊंट मर रहे हैं। खेतों की तार और जालियों से ऊंट मर रहे हैं। ऊंटों की हालत यह खराब है इसलिए पिछले दिनों, पिछले सदन में भी हमने यह मांग की थी, मुख्य मंत्रीजी ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा बजट में की है और दस करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। ऊंट के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, ऊंट के विकास के लिए, पालन-पोषण के लिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए और एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन करने का फैसला मुख्य मंत्रीजी ने किया है और जो 500 सदस्य बनाने थे,

(श्री किसनाराम विश्नोई)

500 सदस्यों के स्थान पर 300 सदस्यों का कर दिया गया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना जो कि एक महत्वपूर्ण सेवा योजना है। महिलाओं के लिए जो अभी पहले दुल्हन की और दूसरी बात हो रही थी, महिलाओं के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने कितना सोचा है? 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को जो चिरंजीवी कार्ड की धारक महिला है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): उनके लिए स्मार्ट फोन देने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है जो एक रिकार्ड है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज गांव और ढाणी में बैठा गरीब आदमी का बालक भी अंग्रेजी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सके, यह अशोक गहलोतजी ने सोचा है। 1200 स्कूल चालू हो गयी हैं और दो हजार और स्कूलें शहरी और गामीण क्षेत्र में देने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव और ढाणी में बैठा गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सकेगा। गांव और ढाणियों में बैठा गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सकेगा, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सभी विधायक बार-बार यह मांग कर रहे थे कि मेरी यह स्कूल क्रमोन्नत होनी चाहिए, मेरी पंचायत मुख्यालय पर स्कूल क्रमोन्नत होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल करके 3820 स्कूलें एक साथ सीनियर सैकण्डरी करने की घोषणा की है और सभी सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

विशेषकर, धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि हमारे मरुस्थल क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जो मरुस्थल क्षेत्र है, चूरू, मरुस्थल क्षेत्र के अन्दर 200 स्कूल अतिरिक्त देने की, पांचवीं तक की स्कूल देने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही कानून व्यवस्था के बारे में हमेशा मुख्य मंत्रीजी बहुत संवेदनशील रहते हैं और इस बार भी बजट के अन्दर

(श्री किसनाराम विश्नोई)

कानून व्यवस्था में भी 500 पुलिस मोबाइल यूनिट की घोषणा की है और साथ-साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): आजकल क्योंकि आई.टी. का जमाना है, साइबर अपराध ज्यादा होते हैं तो प्रत्येक जिले में यह थाने खोलने की घोषणा की है और साथ ही एस.ओ.जी. के अन्दर चीटिंग सेल भी देने की घोषणा की है। सामने बैठे सब माननीय सदस्यों को मैं यह कहना चाहूंगा कि एस.ओ.जी. को और मजबूत करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): प्रत्येक जिले में तीन-तीन सड़कें देने की बात हो, मनरेगा के अन्दर 100 से बढ़ाकर 125 मानव दिवस पर रोजगार देने की बात की है, शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू करने की बात की है। इसलिए मैं इस बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री को बारम्बार धन्यवाद देना चाहूंगा ताकि यह बजट सभी वर्गों के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए, आम अवाम के लिए यह बजट रामबाण साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट भाषण के जवाब पर सबसे पहले नरेंद्र मोदीजी को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करूंगा क्योंकि जब तीसरी लहर से पूरा विश्व कांप रहा था, डर रहा था लेकिन भारत में भी यह तीसरी वेव जैसे फैल रही है, ऐसा डर लग रहा था लेकिन 156 करोड़ नि:शुल्क वैक्सीन लगाने से आज हम लगभग इस तीसरी वेव से बचे हुए हैं और आज कोरोना की इस तीसरी वेव से हम बचे हुए हैं, यह सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है इसलिए मैं नरेंद्र मोदीजी को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करूंगा।

बात चिकित्सा क्षेत्र की है। मैं मेरे सीधा विधान सभा क्षेत्र आहोर की बात करूंगा। मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में लगभग पांच लाख की जनसंख्या

(श्री छगनसिंह)

है लेकिन वहां पर मात्र दो सी.एच.सी. हैं, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उसमें आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक अनुशंसा की थी लेकिन वहां पर भी डाक्टर्स की कमी है। आदर्श सी.एच.सी. का मतलब यह होता है कि वहां पर पूरे-पूरे डाक्टर्स होने चाहिए लेकिन वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं तो मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करूंगा कि कम से कम आदर्श सी.एच.सी. में तो स्टाफ पूरा हो, डाक्टर्स पूरे हो, इससे हमारे क्षेत्र के मरीजों को लाभ मिलेगा।

अभी दो सी.एच.सी. हैं तथा पांच लाख की जनसंख्या है तो चार सी.एच.सी. और होनी चाहिए तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बागरा, भाद्राजून, चान्दराई और गुडाबालोतान में से, भाद्राजून या बागरा में से किसी एक में सी.एच.सी. अगर मुख्य मंत्रीजी पूरक बजट घोषणा में एक खोल दें तो आहोर क्षेत्र के लिए बड़ी कृपा होगी। पी.एच.सी. में मैं जो आदर्श ग्राम पंचायत है ऊण, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर दूर-दूर से कई लोग, कई पेशेंट्स को दूर-दूर जाना पड़ता है, कई तरह की बीमारियों से कई बार मौतें हुई हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊण में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शंखवाली में अगर खोला जाये तो वहां के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। उसके बाद में सब सेंटर हजार सब सेंटर की अगर घोषणा की है तो मेरे एक रसियावास खुर्द में जहां ए.एन.एम. सेंटर तो बना हुआ है लेकिन वहां पर सब सेंटर घोषित नहीं है और एक सुमेरगढ़ खेड़ा में सब सेंटर बन जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूंगा कि जब अभी यह चर्चा हो रही थी कि करीब 3800 ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जो दसवीं तक की स्कूलें हैं या आठवीं तक की स्कूलें हैं उनको सीधा-सीधा क्रमोन्नत करेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि सिर्फ ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर की नहीं करके एक ग्राम पंचायत में चार-चार गांव होते हैं, तीन-तीन गांव भी होते हैं और दो-दो भी हैं। दो गांव भी, बड़े-बड़े गांव ऐसे भी हैं कि वहां पर वास्तव में जनसंख्या भी है और वह आठवीं तक की स्कूल है, दसवीं तक की स्कूल है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उस आठवीं को बारहवीं तक या उस गांव को भी, छोटे गांव को भी उसमें भी दसवीं तक माध्यमिक या बारहवीं तक स्कूल की जाये, यह मैं निवेदन करूंगा।

जब शिक्षा की बात होती है तो मैं एक संत की बात यहां पर बताना चाहूंगा, यह 1960 की बात है जब शिक्षा का प्रचार-प्रसार सही तरीके से नहीं

(श्री छगनसिंह)

था। उस समय पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा चलती थी। गांवों में सिर्फ पांचवीं तक ही स्कूल हुआ करती थी। पांचवीं भी एक ग्राम पंचायत में बड़ी मुश्किल से होती थी, उस समय पढ़ने के लिए गांवों से शहरों की तरफ जाना पड़ता था, वहां छात्रावास की सुविधा नहीं थी लेकिन संत श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वतीजी ने ऐसे कई हॉस्टल बनाकर, जैसे- जालौर में, सिरोही में, कालेंद्री में, जोधपुर में, पाली में उन्होंने छात्रावास बनाये उस समय 1960 के दशक में। धीरे-धीरे उस समय राजपुरोहित समाज के बच्चे जो पढ़ने की इच्छा रखते थे लेकिन पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी वहां पर छात्रावासों की सुविधा नहीं होने की वजह से वे कहीं भी बाहर चले जाते थे, पढ़ने की दुविधा होती थी लेकिन संत श्री आत्मानन्द सरस्वतीजी ने उस समय कम से कम दस छात्रावास खोले और उन छात्रावासों में चन्दा लेकर, छात्रावास खोलकर उनमें हजारों की संख्या में छात्र पढ़े और आज वे छात्र एक व्यापार जगत में और सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं और उनका गुणगान करते हैं। मैं आज सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, स्वामी संत श्री आत्मानन्द सरस्वतीजी का नाम का कोई पुरस्कार रखें जिससे वास्तव में यह लगेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उनको इस प्रकार से पुरस्कृत भी किया जाता है तो मैं यह निवेदन सरकार से करूंगा कि संत श्री आत्मानन्दजी सरस्वती के नाम का एक पुरस्कार रखा जाये।

सभापति महोदय, मैं महाविद्यालय की बात करता हूं, कन्या महाविद्यालय की खूब घोषणा की। मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है। वह भी ग्रेजुएशन लेवल का है। उसको क्रमोन्नत करने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर छात्र संख्या भी पूरी है। चांदराई या बागरा, सियाणा, भाद्राजून में एक कन्या महाविद्यालय या को-एजुकेशन वाला महाविद्यालय खोला जाए जिससे वहां के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने की सुविधा होगी।

सभापति महोदय, बेरोजगारी भत्ते की बात की गई थी, जब सरकार का घोषणा पत्र आया था, कहा गया था कि सरकार आयेगी तो 3500 रुपये देंगे लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवा मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमारे 3500 रुपये अभी तक नहीं आये। आज 3,500 रुपये की बात होती है तो कभी ड्रेस कोड की बात आ जाती है, कभी नौकरी पर दो-दो घंटे जाने की बात

(श्री छगनसिंह)

होती है। मैं निवेदन करूंगा कि राइडर नहीं लगाकर योग्य बेरोजगार छात्रों को 3500 रुपये दिये जाएं जिससे वे आगे पढ़ाई कर सकें। यदि आप उनको दो-चार घंटे स्कूल में बुला लोगे या कहीं पंचायत में बुला लोगे तो फिर वह पढ़ेंगे कैसे। आप तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय 50 रुपये में मजदूर रख रहे हो। मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी भत्ते में किसी भी प्रकार का राइडर नहीं लगायें और सीधा-सीधा 3500 रुपये उनके खाते में डलवायें ताकि वे उससे पढ़ सकें।

सभापति महोदय, आज संविदाकर्मियों और पंचायत सहायकों की बात हो रही है। जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जब वह विपक्ष में बैठते थे तब चिल्ला-चिल्लाकर कहते थे कि हमारी सरकार आयेगी तो हम पंचायत सहायकों को परमानेंट करेंगे। आज चौथा बजट हो गया। हम लोगों ने कल्पना की थी कि इस बार इस बजट में पंचायत सहायकों को आप परमानेंट कर देंगे, संविदाकर्मियों को परमानेंट कर देंगे लेकिन अभी तक इनके बारे में आपने नहीं सोचा। 20 परसेंट भत्ता बढ़ाकर उनको सिर्फ लॉलीपोप देने की हमेशा बात करते हो। 28 तारीख से वापस वह धरने पर बैठने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यथाशीघ्र इसको संज्ञान में लेकर पंचायत सहायकों को परमानेंट करे ताकि जो 27 हजार परिवार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय मिले।

सभापति महोदय, जब कृषि बजट के बारे में चर्चा हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि किसानों के लिए कुछ नया होगा। किसानों की चिन्ता होगी। किसानों के लिए अलग से कुछ काम होगा। किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ की बात होती थी, वह माफ होने के साथ किसानों के बिजली के बिल हमेशा के लिए माफ हो जाएंगे। किसानों को बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बजट आयेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जैसे घोषणाएं होती थीं, वही किया है, इसमें मिनी किट दिए जायेंगे, हॉर्टीकल्चर में यह किया जायेगा, 50 परसेंट अनुदान दिया जायेगा। वह तो पहले से ही हो रहा था। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए अलग से कृषि बिल इस बात के लिए लायें कि उनको बिजली 6 घंटे के बजाय 8 घंटे दी जाये। वास्तव में यदि किसानों का भला चाहने वाली सरकार है, तथाकथित अपने आपको किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार है तो मैं निवेदन करूंगा कि 6 घंटे के बजाय बिजली 8 घंटे करें तो लगेगा कि वास्तव में कृषि बिल को अलग से पेश किया

(श्री छगनसिंह)

है। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए। किसानों के बिजली के बिल नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से अगर काम हो तो लगेगा कि आपने कृषि का अलग से बजट पास किया है।

सभापति महोदय, सड़क के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पिछले तीन साल से एक छोटे से बजट के लिए, सिर्फ 3 करोड़ का बजट है, एक पुलिया निर्माण की बात करता आ रहा हूं। भूती और रोडला के बीच में पुलिया निर्माण के लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी को बार-बार इसका लैटर भी दिया है और जो भी मंत्रीजी होते हैं उनको भी लैटर दिया है। मैंने कहा कि अगर आप 3 करोड़ रुपये का बजट दे दो तो दस गांवों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जायेगी। भूती और रोडला के बीच में नदी चलती है। यदि थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो उसी में रास्ता पूरा रुक जाता है। 8 से 10 गांवों का सम्पर्क पूरी तरह से टूट जाता है। कभी-कभी तो 7-7 दिन तक उन लोगों को परेशानी हो जाती है। दवाइयों की व्यवस्था भी नहीं है। वहां किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है। कई तरह की बीमारियां वहां फैल जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह छोटा सा काम, सिर्फ ढाई से 3 करोड़ रुपये का, दो-तीन बार मैंने प्रपोजल भी भिजवाया है एक्सईएन से, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी बजट के लिए लैटर भी लिखा था। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा की जाये। मेरे क्षेत्र में चांदराई, पोचोंटा, बल्दराई, मूलेवा, नीमलावाला सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसकी घोषणा करें। सामूजा, वेड़िया, आईपुरा, बावड़ीवाला रोड, भेटाला, चांदना सियाला वाला रोड, बाल्लावास से मेड़ा निचला, राईपुरिया, देवला, भीवलसर वाला रोड, इस प्रकार से करीब 25 से 30 रोड जो अलग-अलग साइड पर हैं, उनको बनवायें। वास्तव में बहुत कमी है। रोड टूटे हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं पेयजल के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। विराजिए। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पेयजल का। आपने पूर्व में नर्मदा योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस काम को होने में दो से तीन साल लगेंगे। अबकी बार ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प की घोषणा नहीं की है। पूरक में ट्यूबवैल की घोषणा की जाए जिससे....

श्री सभापति: पार्लियामेंट की बजाय सीधे विधान सभा में आ जाते तो सब बात बन जाती। पार्लियामेंट में दौड़ते फिर रहे थे आप। समाप्त करिये जल्दी।

श्री छगनसिंह (आहोर): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने 2022-23 का बजट पेश किया। 2022-23 के बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं कि प्रदेश की समस्त जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बहुआयामी बजट को उन्होंने पेश किया जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों का आपने समुचित ध्यान भी रखा और उनको सम्बल देने के लिए इसमें प्रावधान भी काफी अच्छे किये हैं। इस बजट के साथ में आपने एक ऐतिहासिक काम और किया कि राज्य के लिए कृषि का बजट अलग से पेश किया। उसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

कोविड काल से लेकर आज तक जो प्रदेश की सरकार की जो स्थिति रही, वह सब जानते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोविड काल में किसी को भूखा नहीं सोने देने की जो व्यवस्था की और कोरोनाकाल में प्रदेशवासियों को जिस तरह से हरसम्भव सहायता पहुंचाई, यह पूरे देश और विदेश ने भी देखा। हमारे प्रदेश में विकास के बारे में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की बता सकता हूं। हम गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। आज से पहले तो इतना काम नहीं हुआ। यहां पर कृषि मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं। कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे मेडिकल का विभाग ले लीजिए, चाहे पशुपालन का ले लीजिए, चाहे आप कृषि का ले लीजिए, चाहे आप पेयजल का ले लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, किसी भी विभाग की स्कीम्स हों, वह धरातल पर उतरकर आम जनता को लाभ देने का काम कर रही हैं।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा प्रोग्राम जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चलाया, प्रशासन गांवों के संग, उसमें इन विभागों के अन्दर जो भी स्कीम चलती हैं, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा की स्कीम हो, चाहे आम आदमी से जुड़ी हुई योजना हो, उसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंची है और उसको लाभ भी मिला है। पट्टों की बात तो करते आये हैं। मेरे क्षेत्र में भी प्रशासन गांव के संग अभियान में काफी संख्या में पट्टे वितरित हुए हैं। वर्षों पुरानी कई लोगों की समस्याओं का निपटारा हुआ है। आम जनता के बीच में सरकार पहुंची है और उसका फायदा आम जनता तक पहुंचा है। यह सब जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य

(श्री आलोक बेनीवाल)

योजना में जो 5 लाख का बीमा था उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया। साथ ही उन्होंने 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा योजना का भी शुभारम्भ किया। यह निश्चित रूप से आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने की व्यवस्था की है। चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र हो, पी.एच.सी. हो, सी.एच.सी. हो, इनकी भी खोलने की व्यवस्था की है प्रदेश में। उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद भी देता हूं।

एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया, वह था पुरानी पेंशन योजना का काम। एक ऐसा ऐतिहासिक काम हमारे प्रदेश के यशस्वी और गांधीवादी मुख्य मंत्री, जिन्होंने इस प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग, जो 2004 में बन्द हो गयी थी, उसको पुन: चालू किया है और आज मैं समझता हूं कि जिस दिन यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाउस में की थी, उस दिन बाहर जो खुशी थी लोगों के चेहरों पर, वह देखते हुए बनती थी। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा दिल रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह के काम को कर सकता है। कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग थी, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा किया है, उसके लिये उनका आभार और धन्यवाद।

इसके साथ ही, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है। प्राथमिक से आठवीं और आठवीं से दसवीं, और इन सारी स्कूलों को जो आपने सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया है। इससे भी हमारे क्षेत्र के अन्दर काफी सारी जो स्कूलें थीं, वह क्रमोन्नत होकर सीनियर सैकण्डरी स्कूल बन गयीं। उनके लिये भी उनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद।

इसके साथ ही, महिला शिक्षा पर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी सदा से ही अग्रणी रहे हैं और पिछले बजट में भी और इस बार के बजट में भी उन्होंने चाहे कन्या महाविद्यालय का काम हो, चाहे और सुरक्षा की योजनाएं हैं, उसके अन्दर हो, यह सारा काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। महाविद्यालय भी खोले हैं और अन्य सुविधाएं भी उन बच्चियों को दी हैं, चाहे वह स्कूटी की हो, चाहे वह और कोई सुविधा हो। इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस ओर बहुत ही ज्यादा अपना फोकस

(श्री आलोक बेनीवाल)

रखा है कि हमारे प्रदेश की जो बच्चियां हैं, वह पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और अपने प्रदेश का, क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें। इस ओर मुख्य मंत्रीजी का बहुत ही लम्बा अनुभव भी है। उन्होंने इस क्षेत्र को देखा भी है और वह जानते हैं कि इसके बगैर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है।

इसके साथ ही, आपने युवाओं के लिये उदयपुर हाउस दिल्ली में 300 करोड़ की लागत से 250 कमरे, नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा। इसके लिये भी उनको बधाई मैं देता हूं, क्योंकि यह एक बहुत ही नया कांसेप्ट है, जो मुख्य मंत्रीजी ने रखा है।

हर बार मुख्य मंत्रीजी बजट में कोई न कोई नई चीज जरूर लेकर आते हैं, यह देखने में आया है। चाहे वह पुरानी पेंशन योजना का मामला हो, शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरह का डिसीजन माननीय मुख्य मंत्रीजी लेने वाले हैं। इस चीज का कहीं आभास नहीं था, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया। यह निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ही ले सकते हैं। इसके लिये उनका धन्यवाद है।

आपने बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को भी बहुत बड़ा लाभ दिया है। 100 यूनिट वालों को आपने 50 यूनिट फ्री कर दी। ऐसे आगे से आगे उन्होंने इसके अन्दर सब्सिडी देने का काम किया है। किसानों के जो कनेक्शन पेंडिंग थे, वह पूरे के पूरे 22 फरवरी तक जितने भी थे, वह सारे रिलीज करने के लिये सदन को आश्वस्त कर दिया। यह भी बधाई का काम है कि इतनी पेंडेंसी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लगातार देखते हुए और उसको कम्पलीट पेंडेंसी को खतम करना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रदेश की जनता के लिये और किसानों के। पिछली सरकार ने जितने कनेक्शन दिये थे, उससे ज्यादा कनेक्शन तो यह सरकार दे चुकी है लेकिन उसके बावजूद यह जो 3 लाख से ऊपर के जो कनेक्शन थे, उसको भी देने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, यह कोई कम बात नहीं है।

आज हम किसानों के लिये बात कर रहे हैं। किसानों के लिये और चीजों की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है, तो यह सरकार चाहे राज्य की हो, चाहे केन्द्र की हो, किसान के प्रति उनका जो रवैया है, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी से सीखेंगे तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को भी फायदा होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(श्री आलोक बेनीवाल)

आपने मनरेगा के 100 दिनों को बढ़ाकर 125 दिन किया। एक समस्या मुख्य मंत्रीजी ने बिलकुल सही पकड़ी है। जब पिछली बार कोरोना आया था, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मनरेगा से लोगों को रोजगार मिल गया था, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लोग थे, वह बड़े परेशान हुए थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): पांच मिनट में करता हूं। स्ट्रीट वेंडरों और कई लोगों को मुख्य मंत्रीजी ने दिये थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस मनरेगा जैसी योजना का लाभ लेने वाले भी काफी लोग थे और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जो शहरी क्षेत्र के अन्दर भी मनरेगा चालू की है यह भी एक बहुत बड़ा माइल स्टोन है इस सरकार के लिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी भी चीज के अन्दर कमी नहीं छोड़ी। पिछली बार पांच करोड़ रुपये सड़कों के लिये दिये, उसको बढ़ाकर दस करोड़ कर दिये। इस प्रदेश की जनता की मांग के हिसाब से चल रहे हैं।

आज नौकरी की बात कर रहे हैं। एक लाख लोगों को नौकरी दे चुके। सवा लाख नौकरियां पाइप लाइन में हैं और एक लाख लोगों को और नौकरी देने की घोषणा कर दी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की जल्दी से जल्दी परीक्षा हो और उनको नौकरी मिले और यह मुख्य मंत्रीजी का विजन है, सरकार का पूरा विजन है। सरकार के सभी मंत्रीगण भी इसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए इतना बड़ा काम मुख्य मंत्रीजी ने बेरोजगार युवाओं के लिए जो हाथ में लिया है, निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही, आपने 62 हजार पद कर दिये। स्कूटी की भी आपने दो हजार से पांच हजार कर दी। आपने यहां पर एक नये फोर्स का गठन कर दिया। जैसे सी आई एस एफ होती है, उस हिसाब से राजस्थान में स्टेट सेफ्टी फोर्स बनाने का फैसला कर लिया। आपने मुख्य मंत्री डिजिटल सेवा योजना की बड़ी घोषणा की है। आंगनबाड़ी कार्मिकों का वेतन 20 प्रतिशत बढ़ाया है। संविदाकर्मियों का आपने मानदेय बढ़ाया है। आपने जो काम प्रदेश की जनता के लिये आवश्यक है, जल जीवन मिशन का काम भी बड़ी तेजी से इस प्रदेश में हो रहा है। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सी एच सी दी धानोता में, 40 किलोमीटर की मुझे रोड

(श्री आलोक बेनीवाल)

दी और साथ ही एक छात्रावास दिया, उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो मांग रखी हुई है मनोहरपुर में एक नगरपालिका की और धोली में एक पी एच सी की, राडावास में एक बाई पास की, उसका जरा ध्यान रखेंगे। मेरी एक बड़ी मांग है जिले की, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: समाराम गरासिया। एक मिनट विराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर साढ़े सात बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। आज मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चौथा बजट पढ़ा, इससे पूर्व तीन बार बजट पढ़ चुके हैं। जब मुख्य मंत्री अशोक जी 2011 में थे उस समय में एक लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक का एक पत्थर लगाया था। आज की तो क्या? इस सरकार की तो क्या? लेकिन 2011 में जब अशोक जी मुख्य मंत्री थे, तब का लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक लगाया था और उस समय लाखों आदिवासी वहां इकट्ठे हुए थे कि शहीद स्मारक बनाएंगे। वह यूं का यूं ही पत्थर साबित होकर रह गया। इसके अलावा क्या घोषणा पूरी कर सकोगे? जब विधान सभा में तीसरे सत्र में तारांकित-अतारांकित प्रश्न लगाया, तब जाकर कोई स्वीकृति दी है तो अब काम शुरू होगा। ऐसी की ऐसी घोषणा नन्दीशाला की हुई। वह नन्दीशाला कहां पर बनायी है? ऐसी घोषणा जैसे 'न भूतो न भविष्यति' ऐसा बजट दिया है कि

(श्री समाराम गरासिया)

जनता बहुत खुश है। जनता बड़ी दुखी है और यह घोषणाएं धरातल पर आ जाए तो आपको जनता धन्यवाद तो देगी ही, पर आप लोगों ने जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं वह घोषणा-घोषणा बनकर ही रह जाएगी। हमारी पूर्व सरकार के जो कार्य प्रगति पर हैं वह जैसे अभी बत्तीसा नाला चालू है और हमारे कालेज का काम पूर्व सरकार ने पास किया था, अभी वह काम शुरू किया है तीन साल के बाद में। बजट के लिये भी विधान सभा में जब प्रश्न लगाते हैं तब जाकर के काम में प्रगति आती है।

आपने घोषणा की थी कि हम गौरव पथ की जगह विकास पथ देंगे। मेरी विधान सभा में एक विकास पथ दिया। वह विकास पथ 4-5 सौ मीटर ही बना है एक किलोमीटर में से। प्रभारी मंत्री जी सिरोही में आते थे तो मैं इस बात को उठाता था कि हमारा वह विकास पथ अभी नहीं बना तो कहते थे कि बजट का अभाव होने की वजह से नहीं बना। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि बजट ही नहीं है। इतनी सारी घोषणाएं की हैं तो बजट कहां से आयेगा।

आप अस्पतालों की हालत को देखो। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। आपने कहा कि हमने इतनी पीएचसी, सीएचसी खोलीं। कहां खोली हैं? मेरे वहां कीवरली में पीएचसी जमीन के अभाव में नहीं खोली। अगर एक भी पीएचसी खोली होती तो मैं कहता कि इस सरकार ने एक तो पीएचसी खोली।

पूर्व भाजपा सरकार ने सालगांव डैम की डीपीआर बनायी। डीपीआर बनाना कितना कठिन होता है। उसमें भूमि अवाप्ति करना, किसी को मुआवजा देना कितना कठिन काम है। किस प्रकार से डीपीआर बनी होगी। उसकी अब जाकर के घोषणा हुई है। अगर अब भी काम शुरू होगा तो वह आने वाली सरकार ही पूरा कर पायेगी। आपने केवल घोषणा की है। पुरानी घोषणाएं तो पूरी हो नहीं पायीं।

पिण्डवाड़ा नगरपालिका को 2 साल हो चुके हैं। जहां भी भाजपा के अध्यक्ष नगरपालिकाओं में होते हैं, वहां आप काम करने देते नहीं हैं। उनको परेशान करते हैं। उनको बजट देते ही नहीं हैं तो फिर क्या काम होगा। अभी भी पिण्डवाड़ा नगरपालिका में करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं। लेकिन टेण्डर नहीं खोलते हैं। लगा देते हैं लेकिन टेण्डर स्वीकृत नहीं करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

(श्री समाराम गरासिया)

आपने पशु पालकों के लिये क्या दिया? पहले जब ऊंटनी ब्याती थी तो 10 हजार रुपये देते थे। अब उसको कुछ नहीं देते, इस कारण ऊंटों का रख-रखाव कम हुआ।

आपने सिलिकोसिस बीमारी का लागू किया। उसमें भी विधवाएं खूब हैं। आपने पेंशन बढ़ायी तो उसमें विधवा की पेंशन डबल करते। पालनहार योजना पूर्व सरकार ने की थी। पालनहार योजना में आपने बढ़ाया है, इसके लिये तो धन्यवाद। लेकिन आगे आने वाली सरकार भी इससे डबल ही बढ़ाती।

जिस प्रकार से आपने संविदा, पैराटीचर्स, पंचायत सहायकों के बारे में घोषणा की थी कि हमारी सरकार आयेगी तो इन सबको परमानेण्ट करेंगे। आपने 10 तक गिनती करके घोषणा की थी कि आपका 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। आप सरकार में तो आये लेकिन किसानों को भूल गये।

टीएसपी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कोई भर्तियां नहीं हैं। पूर्व सरकार ने मां-बाड़ी खोली थी, 80 मां-बाड़ी, लेकिन अब एक भी मां-बाड़ी जनजाति क्षेत्र में नहीं दी। आप देखिये कि जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। मां-बाड़ी में जो चावल आने चाहिए 95 रुपये किलो के लेकिन आते हैं वह कणकी, वह तो 30-35 रुपये किलो ही आते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं और हो ही नहीं सकता है। मैं इस बजट की निन्दा करता हूं। आपने जो घोषणा की, उसके अनुसार इन शिक्षाकर्मियों आदि को परमानेण्ट करें।

सभापति महोदय, शुभ लक्ष्मी योजना भी आपने बन्द कर दी। बच्चियों के कन्यादान के रूप में पूर्व सरकार ने शुरुआत की थी। इसमें 50 हजार रुपये दिये जाते थे। वह भी आपने बन्द कर दिये। आपने ऐसा कौनसा बजट दिया कि आपकी वाहवाही हो जाये।

आपकी सरकार में एसटी वालों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। गोतम मीणा जी भी सदस्य थे। उनके नाम से भी कालेज खोलते। उनके नाम से भी कालेज हो जाता तो सारे बराबर होते। एसटी के नाम से वोट लेते हो। वह भी आप करें। इसकी भी मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर हमारी पूर्व सरकार ने किया था, अभी भी कुछ एसटी के गांव बचे हैं। आप पूरी पंचायत समिति पिण्डवाड़ा को टीएसपी करें। उसमें सिरोही के भी

(श्री समाराम गरासिया)

गांव आते हैं। एसटी जहां भी हैं, उनको पूरा टीएसपी करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें। इससे जनता को राहत मिलेगी।

आपने चिरंजीवी योजना में 5 लाख के 10 लाख रुपये किये। उससे क्या होगा? वह कई हास्पिटल्स में तो चलता भी नहीं है। भामाशाह योजना तो चलती थी।

अन्नपूर्णा रसोई योजना तो आपके यहां आफिस कार्यालय जैसा हो गया है। वहां अन्नपूर्णा रसोई नहीं चलती है। एक रोटी अगर कम पड़ जाये और वह ले ले तो उसके पांच रुपये लेते हैं। पहले इस प्रकार से नहीं था। हमारी पूर्व सरकार के समय, 2003 से 2008 तक अक्षय कलेवा योजना चलती थी जिससे किसी भूखे को भोजन मिले। पूर्व सरकार ने किसी को भी भूख से न मरने का वादा किया था।

आपने राशन डीलरों को क्या दिया? आपने राशन डीलरों का कमीशन कम किया। पोस मशीन के 10 रुपये काटते हो। पहले जो छीजत मिलती थी, वह भी आपने काटी। राशन डीलरों के साथ भी आप न्याय करें। सिरोही जिले में आपने 2 रुपये की जगह 1 रुपये करने के लिए कहा था। उन डीलरों के, पूरे सिरोही जिले के बाकी हैं, उनके पैसे वापस दिलवाये जायें।

केन्द्र सरकार ने आपको पानी के संग्रहण के लिये पैसे दिये लेकिन सिरोही जिले के किसानों का हौद संग्रहण के लिये, 7 कुओं में से 1 भी पास नहीं हुआ जिससे कि जल स्तर बढ़े। अब गर्मियां आ रही हैं। मैं तो मांग करता हूं कि आप गर्मियों के हिसाब से पूरी व्यवस्था करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उस जनता को, सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सदन में आकर अपनी बात को रख सकूं।

माननीय गहलोत साहब ने जो बजट रखा है, अगर सही मायने में बात करें तो यह शानदार और जानदार बजट है। इसमें 3 विषय तो ऐसे हैं, जैसे क्रिकेट में छक्का लगता है, उस तरह का छक्का गहलोत जी ने लगाया है।

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

सरकारी सेवक 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60 साल की उम्र में वह रिटायर हो जाता है। तब उसका कोई धणी-धोरी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 2004 के बाद जो हमारे सरकारी सेवक भर्ती हुए हैं, उनको पेंशन मिलना अति आवश्यक था। माननीय गहलोत जी ने यह योजना सरकारी सेवकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए की है। मैं उनको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे भारत में 2 ही राज्य पश्चिमी बंगाल और राजस्थान ऐसे होंगे जिनमें पुरानी पेंशन लागू होने की बात है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2024 में जब भारत सरकार के चुनाव होंगे तो केन्द्र सरकार को भी यह योजना लागू करनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत राजस्थान ने की है। इसके लिये राजस्थान के प्रदेशवासियों को, सरकारी कर्मचारियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हू।

दूसरा, संविदाकर्मियों का एक साथ 20 प्रतिशत वेतनमान बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जितने लोग सरकारी सेवा में हैं उनमें लगभग 50 परसेंट लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। उनकी 20 परसेंट एक साथ तनख्वाह बढ़ाना अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के लिये बहुत बड़ी बात है।

इसके साथ ही मध्यम और गरीब परिवारों में जो बिजली का बिल आता है, उसमें 100, 150, 250 यूनिट तक अच्छी सब्सिडी देना एक अच्छे मुख्य मंत्री का परिचायक है। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्णों का भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। इस कारण इस बजट को सर्व समाज का कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये ईडब्ल्यूएस कोष की स्थापना करके 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। इसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

(समय: 19.00 बजे)

शहरी रोजगार गारंटी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, एक आदमी जो गांव में रहता है, अगर उसके पास कोई कमी पड़ती है तो पड़ोसी उसकी कमी को दूर करने का काम करता है, लेकिन जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है लोगों का, शहर में कोई व्यक्ति आता है और वह रहता है और उसको कोई परेशानी होती है तो उसकी पड़ोसी मदद नहीं कर सकता है और वह मदद नहीं मांग सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्माननीय

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

मुख्य मंत्रीजी ने जो शहरी रोजगार गारंटी योजना दी है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में महवा के अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाने का काम करने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय आदरणीय परसादीलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, महवा में कृषि महाविद्यालय, मण्डावर को नगरपालिका, महवा में कन्या महाविद्यालय, महवा में आईटीआई कॉलेज और महवा विधान सभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की सड़कों की आपने इस बजट में घोषणा की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री आदरणीय टीकारामजी पालीवाल मेरे विधान सभा क्षेत्र में जन्मे थे, उस कस्बे का नाम मण्डावर है। आपने सरकारी महाविद्यालय की घोषणा अभी पिछले बजट में की, वह संचालित भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उस ब्राह्मण समाज से हमारे टीकारामजी पालीवाल आते हैं। उनके नाम से अगर हमारे राजकीय महाविद्यालय का नाम हो जाता है तो पूरे ब्राह्मण समाज में ही नहीं सर्व समाज में एक अच्छा संदेश जायेगा ओर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि महाविद्यालय इस बजट में आपने हमें दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही चार बार इस सदन के सदस्य रहे और स्वच्छ छवि के धनी आदरणीय हरिसिंह महवाजी, 2013 में हम आमने-सामने चुनाव लड़े लेकिन हम एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़े, उनके व्यवहार से मैं आज भी कायल हूं और मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि जो कृषि महाविद्यालय हरिसिंह महवाजी के गांव में दिया है, उस महाविद्यालय का नाम हरिसिंह महवा कृषि महाविद्यालय करेंगे तो लोगों को एक अच्छी पहचान मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने कन्या महाविद्यालय महवा में खोला है। इस बजट में, आज मैंने देखा कि बहुत सारे सैनी समाज के लोग 25 फरवरी को आपके विधान सभा का घेराव करने के लिए राजस्थान के कोने-कोने से पधारे थे।

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

उनकी मांग थी कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया जाये। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, आदरणीय कटारिया साहब और राठौड़ साहब से भी निवेदन करूंगा, मैंने प्रधान मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है और इस सैनी समाज की मांग है कि ज्योतिबा फुले दम्पत्ति को भारत रत्न दिया जाये, इसकी पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से, देश के प्रधान मंत्रीजी से मांग करता हूं। मेरे यहां जो कन्या महाविद्यालय खोला है उस कन्या महाविद्यालय का नाम सावित्री बाई फुले कन्या राजकीय महाविद्यालय महवा करने की कृपा करें ताकि सैनी समाज को एक अच्छी व्यवस्था मिलने का काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बजट में समाहित की गयी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए हमने लगभग 62 करोड़ रुपये की पेयजल योजना महवा कस्बे के लिए मांगी है। मैं समझता हूं कि उसे आप पूरी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आठवीं सदी से नाथ सम्प्रदाय का उदय हुआ था, नाथ सम्प्रदाय के सबसे बड़े गुरु गोरखनाथ हुए थे। छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, जब भी कोई अवैध काम होता है तो उस काम को गोरख धन्धे की उपाधि दे दी जाती है। यह शब्द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में बहुत काम में लिया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखनाथजी बहुत बड़े संत थे, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए नाथ समाज, राजस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि एक कोई ऐसा आदेश पारित करें कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सरकारी दस्तावेजों में 'गोरख धन्धा' शब्द बिलकुल नहीं आना चाहिए। मैं इसका आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सैनी समाज के लोग थे, आपने बहुत सारे समाजों का बोर्ड बनाया है, मैं मांग करता हूं कि सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फुले फाउंडेशन और नाथ समाज के लिए राजस्थान नाथ बोर्ड की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी यह कह रहे हैं कि इस बजट की बातें होंगी या नहीं होंगी

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

इस बात की चिन्ता तो उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसने इस पवित्र सदन में बजट रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह चुनावी बजट है। मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं क्योंकि जब एक सरकार का गठन होता है वो पहले दिन से अगली सरकार बनाने का प्रयास करती है। हर बजट इस बात के लिए लाया जाता है कि उनकी सरकार दुबारा रिपीट हो, इसमें कोई भी गलती किसी भी सरकार की नहीं है। यह हर व्यक्ति, आज हम लोग भी विधान सभा में आये हैं और काम करते हैं तो इस बात के लिए करते हैं कि हमें फिर वोट मिलेगा जनता का और इस पवित्र सदन में आने का हमें पुन: अवसर मिलेगा तो मैं उन लोगों की भी आलोचना करना चाहता हूं जो इसको चुनावी बजट बताने की बात कर रहे हैं। हर पांच साल में एक मुख्य मंत्री पांच बजट पेश करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर बजट चुनावी बजट होता है और वोट के लिए ही बजट दिया जाता है, यह बात बिलकुल सही है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के लिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प होना चाहिए क्योंकि जब तक हमारा संकल्प या डेडिकेशन नहीं होगा किसी काम के प्रति, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए कहना चाहूंगा,

"कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए,
साधन तो सब जुट जायेंगे बस संकल्प का धन चाहिए।"

सम्माननीय गहलोत साहब के पास संकल्प का जो धन है वो बहुत बड़ा धन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्दगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है, जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत ले। आज माननीय गहलोत साहब ने राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता को यह बजट पेश करके उनका दिल जीतने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी पंचायती राज का गठन किया। आपने दो साल पहले हमारी तीन पंचायतें, गगवाना, बालेड़ी और टुडियाना पंचायत महवा से पांच किलोमीटर सटी हुई हैं, तीनों ग्राम पंचायतों में चुनाव का बहिष्कार हुआ है, आने वाले चुनावों में भी बहिष्कार करेंगे, ऐसी बात उनकी सामने आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में

(श्री ओमप्रकाश हु ड़ला)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से कि तीनों ग्राम पंचायत गगवाना, बालेडी और टुडियाना को महवा में जोड़ने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के हिंगोटा, पाखर, नाहिड़ा, हु डला, सारेमपुर को पीएचसी बनाने की कृपा करें। माननीय परसादी लालजी मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पावटा और लोटवाड़ा दो पीएचसी हैं। वहां पर भी ओपीडी की संख्या रोज करीब 400-500 रहती है। वहां पर भी सीएचसी करने की कृपा करें।

मण्डावर में, जहां विधायक मुझे जनता ने बनाया था, 42 हजार ओपीडी थी, आज सवा दो लाख ओपीडी है और बैड्स की संख्या 30 ही है। हमने कोरोना काल में कोविड वार्ड भी वहां चलाया था। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि वहां मण्डावर में 30 से 50 बैड करने की कृपा करें।

अन्त में एक मांग और रखूंगा। अभी सिलसिला चल रहा है, हमारे साथियों ने संकल्प लिया है, कइयों ने जूती नहीं पहनने का। मैं भी जब मेरे विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने गया था तब एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं राजस्थान की विधान सभा में पुन: लौटकर नहीं आऊंगा तब तक, चाहे बीस साल लग जायें मुझे इस लायक बनने के लिए, मैं अपने जूते या चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूं गा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, मैं आपको टोकना नहीं चाहूं गा, अबकी बार संकल्प मत कर लेना कि जूती या चप्पल नहीं पहनूंगा। अबकी बार रास्ता बड़ा कठिन है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये आप। (व्यवधान) समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हु ड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, ये तो राठौड़ साहब हैं, ये अपने साथी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो उनको भी हाथ जोड़ता हूं और इनको भी हाथ जोड़ता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती संतोष।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, बस तीस सैकंड में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: और कुछ मत छोड़ देना।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज जब राठौड़ साहब ने कह ही दिया तो इनकी तरफ से एक मैसेज आया था मेरे पास कि आपका मित्र भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, परिवार को बड़ा करना चाहते हो, करिये। मेरे कहने से न तो आप रुक सकते हैं और न किसी को ला सकते हैं, लेकिन मेरी चीज का आप जरूर ध्यान रखना। जब इन्होंने छेड़ ही दी बात तो मैंने यह कहा था कि मेरे यहां अधिकारी मेरे कहने से लगे और मेरे टिकट में हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों से ये लोग मुकर गये तो मैं इधर की तरफ आ गया। मेरा दोष क्या है?

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महवा को जिला बनाने की मांग करता हूं और आपका और पूरे सदन का बहुत-बहुत तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। पुन मांग है कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दम्पति को 'भारत रत्न' देने की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय सर्व समाज।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजट पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट में घोषणाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की व्यवस्था भी सरकार करे। वास्तविकता यह है कि पिछले तीन साल से की जा रही घोषणाओं में से शायद ही कोई काम राजस्थान में पूर्ण हुआ होगा। पूर्व में हम तीन बजट देख चुके हैं। जितना काम प्रदेश में हुआ है वह सबके सामने है। जब तक वित्तीय प्रबन्धन नहीं होगा, घोषणाओं से कोई फायदा नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी विकास का काम इन तीन सालों में नहीं हुआ है। इस वर्ष के बजट में भी मेरे क्षेत्र की जनता को निराशा ही हाथ लगी है।

सरकार ने सड़कों की बात कही है, लेकिन पूर्व में जो दो विकास पथ दिये गये थे, उनमें से एक भी मेरे क्षेत्र में अभी तक नहीं बना है। नई सड़कों

(श्रीमती संतोष)

की घोषणा जब तक धरातल पर नहीं उतरती है, तब तक कोई फायदा नहीं। आज पेयजल की बात करते हैं। पूर्व में 10 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प्स की सरकार द्वारा बात कही गयी थी, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी घोषणाओं का क्या फायदा, जो धरातल पर नजर ही नहीं आती हैं। मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय गजेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे जल जीवन मिशन योजना लेकर आये, जिससे राजस्थान की जनता को सुचारु पेयजल मिल पायेगा।

आज सरकार मुफ्त बिजली की बात कर रही है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिमांड भर देने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा यह कहा जाता है कि सामान नहीं है और कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। सरकार द्वारा कोरोना काल के दो वर्षों के बिजली बिल माफ किये जाएं, यह मैं सरकार से मांग करती हूं। सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, लेकिन आज भर्ती प्रक्रिया को उलझाकर सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकार बेरोजगारों के प्रति कितनी गम्भीर है। बेरोजगार आज सड़कों पर आन्दोलनरत हैं, लेकिन सरकार अपनी वाह-वाही में लगी हुई है। बेरोजगारों की कोई भी सुनने वाला नहीं है।

चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हास्पिटल में डाक्टर्स नहीं हैं। लम्बे समय से मैं इसकी मांग कर रही हूं। डॉक्टर्स के पद खाली हैं, आमजन को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? जो एक-दो डाक्टर लगा भी दिये जाते हैं तो वे पदभार ग्रहण नहीं करते हैं या स्थानान्तरण करवा लेते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। अनूपगढ़ में लम्बे समय से ट्रोमा सेंटर की मांग की जा रही है। वहां की स्थिति को देखते हुए और सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की दूरी को देखते हुए भी अनूपगढ़ में ट्रोमा सेंटर बनाया जाना चाहिये।

बजट में सरकार द्वारा पारदर्शिता की बात कही गयी है। यह कैसी पारदर्शिता है कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर डीटीओ कार्यालय खोला जाता है, लेकिन अनूपगढ़ 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां डीटीओ कार्यालय खोला जाना चाहिये था, पर उसे वंचित रखा गया है। यह सोचने वाली बात है। प्रशासनिक दृष्टि से भी अनूपगढ़ में डीटीओ कार्यालय खोला जाना चाहिये था, लेकिन राजनीतिक भेदभाव के कारण

(श्रीमती संतोष)

अनदेखी की गयी है। मेरी मांग है कि जिला परिवहन कार्यालय अनूपगढ़ में खोला जाये ताकि जनता को राहत मिले।

मेरी सरकार से मांग है कि अनूपगढ़ में सदर पुलिस थाना स्थापित किया जाये ताकि लगातार बढ़ रहे अपराध और नशे के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई हो और जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, बजट के पैरा क्रमांक 130 में जिक्र किया गया है कि पत्रकारों को अधिकाधिक संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि मेरी नगरपालिका अनूपगढ़ में पत्रकारों द्वारा भूखण्ड के पैसे जमा करवाये 4 वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया-प्रेस के पत्रकार भाई काफी समय से डीएलबी के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें अतिशीघ्र पट्टे दिये जाएं।

सरकार कृषि बजट लेकर आयी है, लेकिन यह धरातल पर कितना उतरेगा, इसमें संशय है। लोक-लुभावना बजट देकर किसानों की सहानुभूति बटोरने का और किसान हितैषी बनने का दिखावा किया जा रहा है। मेरा अनूपगढ़ पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। आज हालात ये हैं कि किसानों को समय पर खाद, बिजली, बीज, पानी नहीं मिलता है। हमने देखा है, यूरिया, खाद की इतनी किल्लत होती है, किसानों को रात को दो बजे आकर लाइनों में लगना पड़ता है, सुबह से शाम तक इन्तजार करना पड़ता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती, निराश ही घर लौटना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गम्भीर है।

मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण नरमे की फसल पूरी तरह खराब हो गयी थी, लेकिन गिरदावरी सही नहीं होने के कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मैं एग्जाम्पल दूं तो एक किसान के 8 बीघा नरमा खराब हुआ। लगभग 4 लाख का उसका नुकसान हुआ और मात्र 7 हजार उसे मुआवजा दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था है तो किसानों को कहां लाभ मिलेगा और कौन-से किसान हितों की बात यह सरकार कर रही है? किसान को उसके फसल खराबे का पूरा मुआवजा दिलाये जाने की व्यवस्था सरकार करे।

अभी बजट में घोषणा की गयी है, जैसलमेर में खाळों का पुन: निर्माण करवाया जायेगा, लेकिन वास्तव में पक्के खाळों का निर्माण आईजीएनपी के

(श्रीमती संतोष)

प्रथम चरण में होना चाहिये, क्योंकि यह क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी खाळों का पक्का निर्माण हो और क्षतिग्रस्त खाळों को सही करवाया जाये। साथ ही, जो क्षतिग्रस्त पुलियाएं हैं, उन्हें भी सही करवाया जाये। पिछले बजट में कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गयी थी। अनूपगढ़ में यह सेंटर नहीं खोला गया है, इसका मतलब जो घोषणाएं पहले की गयी थीं या अभी भी की गयी हैं, सब संशय में हैं कि सरकार उन्हें धरातल पर उतार पायेगी या नहीं।

किसान हित की बात अगर करते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के किसानों को समय पर पूरा सिंचाई पानी दिया जाये। आईजीएनपी के प्रथम चरण का पानी रिजर्व किया जाये, जिससे रोजाना सिंचाई पानी के लिए आन्दोलन न करना पड़े। किसानों को बार-बार रेगुलेशन का इन्तजार करना पड़ता है। फसल चक्र के अनुसार रेगुलेशन जारी किया जाये ताकि रबी-खरीफ फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और किसानों की खड़ी फसल नष्ट होने से बच सके।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आईजीएनपी प्रथम चरण की मण्डियों में मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 3 एसटीआर, 24 एससी 2 एमएलडी, 8 पीएसडी रावला और बीकानेर की खाजूवाला, दन्तौर, लूणकरणसर, 465 आरडी छतरगढ़ में, वर्तमान में इनका इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण से सम्बन्धित भूमि का अधिकार क्षेत्र मण्डी विकास समिति क्षेत्र में है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत संचालित अनेक राष्ट्रीय एवं राज्यीय महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि उक्त ग्राम पंचायतों को मण्डी विकास समिति के कानूनों, नियमों, मापदण्डों से बाहर निकालकर ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में दे दिया जाता है तो ग्राम पंचायतों में काफी अरसे से बसे बीपीएल, अन्त्योदय, गरीब लोगों को स्थायी रहने का अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में मैंने अपनी विधायक निधि से राजकीय महाविद्यालय, उच्च महाविद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में सहमति प्रदान की थी और इसका पैसा

(श्रीमती संतोष)

मेरे निधि फंड से जिला परिषद् के माध्यम से समसा में जमा भी हो गया है, लेकिन अभी तक स्कूलों में आईसीटी लैब नहीं बनी है। सरकार आज शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है। शिक्षा कैसे मुहैया हो पायेगी यदि विधायक निधि से दिया गया पैसा भी नहीं लगाया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोला जाये ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। साथ ही, सेठ बिहारी लाल छाबड़ा कालेज में पीजी की क्लासेज शुरू की जाएं ताकि बच्चों को पूर्ण शिक्षा मिल सके और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। माननीय सभापति महोदय, बीपीएल, गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का पोर्टल पिछले दो वर्षों से बन्द है। इसे चालू करवाया जाये ताकि गरीब लोगों को अपने हक के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ें और सरकार की बन्द पड़ी योजनाओं को...

श्री सभापति: समाप्त करें। आप जो बचे हुए कागज हैं, उन्हें टेबल कर दीजिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, बस एक मिनट। मनरेगा में 125 दिन का रोजगार दिया गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन नरेगा मेटों का भुगतान बाकी है, वह भी समय पर करवाया जाये। लम्बे समय से मांग की जा रही है, संविदाकर्मी और पंचायत सहायकों को स्थायी किया जाये। गंगानगर जिले से दूरी को देखते हुए व भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अनूपगढ़ को जिला बनाया जाये। जिला बनाने की सभी शर्तें अनूपगढ़ पूरी करता है। लम्बे समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं। अनूपगढ़ की प्राथमिकता भी बनती है। मेरे क्षेत्र के घड़साना को नगरपालिका का दर्जा दिया जाये ताकि वहां का अधूरा विकास सही से हो सके। घड़साना के नगरपालिका बनने का इन्तजार वहां की जनता द्वारा प्राथमिकता से किया जा रहा है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, समय बहुत कम रह गया है। धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट वर्ष 2022-23 के सन्दर्भ में मैं मेरी बात रखना चाह रहा हूं और आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, बजट तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, लेकिन रात भर नींद हमारी खराब हो गई। यह मैं हकीकत बयान कर

(श्री खुशवीरसिंह)

रहा हूं। सभापति महोदय, हम ज्यों ही यहां से निकले तो हमारे टेलीफोन पर टेलीफोन शुरू हो गये और पूरी रात कम से कम 300 टेलीफोन कार्यकर्ताओं के आये होंगे। मैंने कहा कि क्या बात हो गई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप तो हमारे पटाखों की आवाज सुन लो, यही बहुत है और आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वास्तव में मुख्य मंत्री जी ने करिश्मा करके दिखा दिया। किसी वर्ग, घटक, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, सबके लिए इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने सब सुविधाएं की हैं। यह सत्य है जिसे आप नकार नहीं सकते हो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं। राठौड़ साहब,

"दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय।
जो 'रहीम' दीनहिं लखै, दीनबन्धु सम होय।।"

तो मुख्य मंत्री जी ने वह काम किया है, उस गरीब तबके का भी ध्यान रखा, उस विधवा महिला का भी ध्यान रखा है तो दीनबन्धु यों ही बातों से नहीं हुआ जाता है, उसके लिए विजन चाहिए। जैसे आपके उन नेता का विजन, वे बात विजन की करते हैं। विजन चाहिए। आपने तो उस पेंशन को रोका पर यह मुख्य मंत्री जी का विजन था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सिरियारी गांव है, वहां से हमें राज्य सभा के दो-दो सांसद भी मिले हैं स्वर्गीय विजय सिंह जी और दलपत सिंह जी। वहां पर आर्मी के अन्दर भोपाल सिंह जी नाम के व्यक्ति थे, मेरी बात को गौर से सुनना, मैं प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं। उनको गोरों की सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनकी तीन पीढ़ी को पेंशन जारी की। और आपने, यह विजन है आपका? आपने खुद की नौकरी की हुई उसकी भी पेंशन बन्द कर दी पर यह हमारे मुख्य मंत्री जी का विजन है। आपको स्वीकार करना होगा। मैं उस दिन सबके चेहरे पढ़ रहा था। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने कई चीजों पर मेज भी थपथपाई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बिलकुल थपथपाई हैं आप कैमरे में देख सकते हैं।

सभापति महोदय, मनरेगा योजना, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी गांधी की सोच है। वह दिन मुझे याद है जब मैं प्रधान था और तब अकाल की स्थिति होती तो उस अकाल की स्थिति में लोग गिड़गिड़ाते थे कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवायें। वह स्थिति मैंने आंखों से महसूस की है कि अकाल राहत कार्य होते, जिस दिन नया सप्ताह चालू होता तो मजदूरी के लिए पूरा काम उलट जाता वहां पर और मजदूर कितने लगते? सभापति महोदय, मात्र

(श्री खुशवीरसिंह)

20 या 25 और बाकी 80 प्रतिशत लोग वापस मुंह उतारकर घर जाते क्योंकि रोजगार की आवश्यकता थी। यह भी हमारे नेता का विजन है कि इन सब बातों को महसूस करके मनरेगा योजना लागू की है और मुख्य मंत्री जी के विजन को देखो कि शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा योजना लागू कर दी और साथ ही साथ 125 दिन भी कर दिये जिनकी हमने किसी ने शायद मांग भी नहीं की होगी। लेकिन जो दीनहिं लखै वो दीनबन्धु सम होय, यह अपने आपमें बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना की किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मुझे याद है वह दिन जब एक दस रुपये की गोली लेने के लिए लोग सक्षम नहीं थे और अपने सिर पर पट्टी बांधकर दिन भर काम चला लेते थे। मुख्य मंत्री जी ने जो इसमें कदम बढ़ाये हैं, उसमें हम और आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है और देश का पहला राज्य राजस्थान हुआ जब ये दूसरी बार मुख्य मंत्री बने तब यह योजना लागू की थी और अब उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिये। कल ही रात को मेरे पास में कार्यकर्ता का फोन आया कि कोई बीमार हैं उनके लिए क्या करें तो मैंने कहा कि आप चिन्ता मत करो, दस लाख रुपये तक तो नि:शुल्क है और उसके आगे भी होगा तो देखा जायेगा। इस राज के अन्दर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बिना इलाज के अपने परिवार को खो दे। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी राजस्व शिविर लगे थे वहां पर हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी आये थे। हम सभी उन शिविरों में गये थे और उन शिविरों में सबसे महत्वपूर्ण गांव, ग्राम पंचायत के अन्दर जो रही वह यह रही कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जायें। जो नाम आपने खाद्य सुरक्षा में काट दिये थे वे नाम जोड़े जायें। उसके लिए मैंने पिछली बार महामहिम के अभिभाषण के वक्त अपनी बात रखी थी, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उसका ध्यान रखते हुए 10 लाख परिवारों को इससे जोड़ने की बात कही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने उस वर्ग का भी ध्यान रखा जिस वर्ग के बारे में आज दिन तक लोगों की एक मानसिकता बनी हुई थी कि यह वर्ग तो अपने आप में बहुत सम्पन्न है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो मुख्य मंत्री जी ने आरक्षण की व्यवस्था की और आरक्षण में सभी बन्धन से मुक्त कर दिया इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। अभी 100 करोड़ रुपये का जो

(श्री खुशवीरसिंह)

कोष उन्होंने स्थापित किया है उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। आज सभी कार्यकर्ताओं के इस बात के लिए फोन आये कि आप हमारी तरफ से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन विकास के लिए भी किया है। पर्यटन हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सरकार का जीरो इन्वेस्टमेंट है और उसमें सरकार का किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है और हजारों-हजार लोगों को उससे रोजगार मिलता है। कोरोना काल में इन सभी व्यवसाय वालों की हालत बहुत ही खराब हो गई। उसमें जो लम्बे समय से मांग चली आ रही थी, उसमें मुख्य मंत्री जी ने उसको उद्योग का दर्जा दिया और उस उद्योग के दर्जे से उनको कई तरह के लाभ मिलेंगे। मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वास्तव में सभी वर्गों का, घटकों को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं। पिछली सरकार में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था और वह कुछ सोच के साथ में घोषित किया होगा, निश्चित रूप से वह सकारात्मक सोच रही है। मैं यह नहीं कहता कि कोई ऐसे ही रहा, लेकिन उसकी वजह से आज हमारी ऊंट प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। अगर आप गणना देख लें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य खुशवीरसिंह जी का वक्तव्य पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय माननीय सदस्य का वक्तव्य पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया। आप भी समय का ध्यान रखेंगे।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, सबको धन्यवाद। ऊंट को निश्चित रूप से इस सोच के साथ में राज्य पशु घोषित किया कि कुछ अच्छा कर पायेंगे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि कोई भी चीज जब तक वायबल नहीं होगी, उसको आप किसी सहारे से खड़ा नहीं कर सकते हो। खुद को अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए वह सोच चाहिए। मैं कह रहा था कि सर्वाधिक ऊंट मेरे गांव में हैं। मेरे गांव में ढाणी है, अंजी की ढाणी, जहां मैं रहता हूं। मंत्री महोदय, उस गांव में पांच हजार ऊंट थे। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और आज यहां आने से पहले मैं ढाणी में गया और सभी पशुपालकों को इकट्ठा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब 27 ऊंट रहे हैं, कितने, मात्र 27.

यह विचारणीय बिन्दु हैं, कई प्रजातियां हमारी विलुप्त होती जा रही हैं। आज जो हमारा विकास हुआ। पहले राजसमन्द का बांध, जयसमन्द बांध, जो निर्मित हुआ है। उसमें गधे काम आते थे, वे समाप्त हो गये, विलुप्ति की कगार पर, कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा इसके बारे में जो विलुप्ति की कगार पर हमारे पशुधन हैं, हमारे मवेशी हैं, हमारे वन्य जीव हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना भी हमारा कर्तव्य है।

सभापति महोदय, मैं इस पर एक सुझाव देना चाहूंगा कि आज जो डीएमएफटी फंड, इस धरती मां का छेदन करके विकास के नाम पर धरती का विनाश करके हम अर्जित करते हैं। वह 50 प्रतिशत हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे ऐसे विलुप्त होते पशुओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सर्वसम्मति से निर्णय लेकर किया जाना चाहिए। आज हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम कमरों का निर्माण कर रहे हैं तो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि उस चीज की होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, फसल बीमा योजना बहुत पहले से लागू है। अब नाम परिवर्तन करके प्रधान मंत्री, हम चाहे कुछ भी कह सकते हैं। यह फसल बीमा कम्पनियों का जो खेल है, बहुत निराला खेल है। इस पर हमें विचार करना होगा। वह जो क्राप कटिंग सैम्पल लिये जाते हैं। उस पर किसी को नहीं बुलाया जाता है, न उस किसान को वहां बुलाया जाता है, मनमर्जी से सैम्पल

(श्री खुशवीरसिंह)

लेकर वे फसल खराबा नहीं बताते हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

मैं सुमेरपुर की बात करता हूं। सुमेरपुर में पिछले दो वर्षों में जो फसल बीमा है। वह राशि आज दिन तक सुमेरपुरवासियों को नहीं मिल पायी है तो इसके लिए पारदर्शिता लायी जाये ताकि हम सही लाभ किसानों को दिला सकें।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार कृषि बजट अलग से रखा है। बहुत अच्छी बात है और उसमें आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। आज हम जहर खा रहे हैं। उस जहर से बचाव के लिए शुरुआती जो कदम उठाया है, वास्तव में सराहनीय कदम है। हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए और कृषि बजट की जब बात करते हैं, जब कृषि की बात आती है तो मैं हमारे राजस्थान के लोक देवता श्री तेजाजी महाराज, कुंवर तेजाजी को याद किये बिना नहीं रहूंगा। तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता हैं। आज भी किसान जब खेत में हल लेकर जाता है तो जुताई से पहले तेजाजी महाराज को नमन करता है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उस किसान की फसल कभी खराब नहीं हो सकती है। चाहे पाला गिरे, चाहे कुछ भी हो जाये, किसी तरह का नुकसान उसकी फसल को नहीं होता है। यह मान्यता आज भी है और यह सत्यता भी है। तेजाजी महाराज ने कृषि के अन्दर क्रांतिकारी कदम उठाया। मंत्री महोदय, पहले हमारी कृषि जो होती थी, उसमें ब्राड कास्टिंग से बीज बुवाई किया जाता था, हाथ से छीलकर बीजों को फसल बुवाई की जाती थी लेकिन, सीड ड्रिल के द्वारा अगर किसी ने शुरुआत की है तो वह तेजाजी महाराज ने, हम उनको कृषि वैज्ञानिक भी कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत की। तब से हमारे देश के अन्दर सीड ड्रिल से जुताई शुरू हुई है और सीड ड्रिल के बाद क्रांति घट गई। किसानों की फसल का जो पहले प्रोडक्शन होता था वह चार गुना ज्यादा प्रोडेक्शन होने लग गया। मैं मुख्य मंत्री महोदय को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों का भी ध्यान रखा है।

हमारे कई साथी पेट्रोल और डीजल की बात कह रहे थे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और वह आप नेट पर जाकर सर्च कर लेना कि 2008 में जब ओपेक कन्ट्रीज के अन्दर, जो आयल प्रोडक्ट कन्ट्री जितनी हैं, उनके अन्दर

(श्री खुशवीरसिंह)

पेट्रोलियम की कीमत प्रति बैरल 135 डालर थी और 2008 में डीजल और पेट्रोल की कीमत आप देख लेना कृपा करके। उस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत बीच में तो 30 डालर तक आ गयी थी और हमारे यहां सैंचुरी लगा रहे हैं। ये निर्धारण केन्द्र सरकार करती है। जो गैस के अन्दर हमें सब्सिडी मिलती थी, वह भी बन्द हो गयी है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि डीजल और पेट्रोल के भाव केन्द्र सरकार को कम करने चाहिए, लोगों की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): एक दो बिन्दु और हैं। सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद में 1954 और 1959 में एक सीलिंग एक्ट लागू हुआ था और उसके तहत सीमा निर्धारित कर दी गयी थी। उस सीमा तक भूमि रख पायेंगे, उससे अधिक नहीं रख पायेंगे। प्रदेश में 1954 तक जागीर व्यवस्था थी और देश आजाद 1947 में हुआ, 1954 तक रही। उस वक्त तक जो भी जमीन थी, जागीरदार अपने आप में एक कस्टोडियन था, मालिक नहीं था। जागीरदार के नाम जमीन नहीं थी, उसकी निजी सम्पत्ति अलग थी, वह कस्टोडियन के रूप में जागीरदार था, लेकिन जागीर के बाद में सीलिंग एक्ट लागू हुआ और मैं उसमें निवेदन करना चाहूंगा जिस सोच के साथ में आज उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। आज छोटे-छोटे जोत नुकसान की बात है, आज बड़े जोत की आवश्यकता है। मैं आपको कह रहा हूं, पांच वर्ष के बाद में छोटे जोत हमारे समाप्त हो जायेंगे। हमें बड़े जोत की तरफ विचार करना होगा। लेकिन उस सीलिंग एक्ट में तीन-तीन पीढ़ी के लोगों ने बेच दिया मंत्री महोदय, तीन-तीन पीढ़ी बेचने वाला, खरीदने वाला, तीन-तीन पीढ़ी मर चुकी हैं और आज भी धारा 15(2) के तहत किसी भी वक्त सरकार चाहे सक्षम न्यायालय से फैसला हो रखा है और उस फैसले के बाद में धारा 15(2) के तहत सरकार 100 वर्ष बाद भी उस केस को री-ओपन कर सकती है और उस समय आप सोचो कि उस किसान की क्या दुर्दशा होगी? जिसने खरीदा है, बेचने वाला दुनिया छोड़ चुका है, खरीदने वाला भी छोड़ चुका है। उसकी तीसरी पीढ़ी उस दंश को आज भी भुगत रही है। मैं चाहूंगा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाये और जो सक्षम न्यायालय से जो ये फैसले हो चुके हैं, वे री-ओपन

(श्री खुशवीरसिंह)

नहीं हो और उसको मान्य किया जाये अन्यथा यह तो अन्तहीन है। सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में भी सोचा जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने बोलने तक के लिए समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हम सभी बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा वह भाषा है, जो हमारे दिल के जज़्बातों को प्रस्तुत कर सकती है और आज मैं राजस्थानी भाषा के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2003 के अन्दर मुख्य मंत्री जी गहलोत साहब ने संकल्प पारित किया विधान सभा के अन्दर, यह सोच मुख्य मंत्री जी की है। उसके बाद में आगे एक कदम भी हम नहीं बढ़ पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैं राजस्थानी भाषा की पैरवी करते हुए हिन्दी में बात कर रहा हूं। मेरी मायड़ भाषा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि यहां पर विधान सभा में मायड़ भाषा के लिए हमें मान्यता नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। आज गुजरात चले जाओ, पंजाब चले जाओ, साउथ में कहीं भी चले जाओ, सब जगह वहां की स्थानीय भाषा को मान्यता है और तो और मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही में नेपाल के अन्दर संवैधानिक दर्जा राजस्थानी को मिला हुआ है। सभापति महोदय, हमारे यहां से एक सांसद चुने...

श्री सभापति: छुट्टी का टाइम है, लोगों को अपने घरों पर जाना है, बाद में कर लेंगे बात।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, यह मायड़ भाषा की बात है कृपया मुझे पांच मिनट का समय दें।

श्री सभापति: इनको मायरा याद आ रहा है सबको, अपना-अपना घर।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, पांच मिनट। ये सब राजस्थानी के पक्ष में हैं। यह देखिये, सब पक्ष में हैं। मुझे समय दें, मैं मेरी बात को प्रस्तुत कर सकूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, मेरी बात समाप्त हो, तब तक। अंतिम बात कह रहा हूं। मायड़ भाषा की बात करें तो नेपाल के अन्दर हमारे झुंझुनू जिले से गये हुए सांसद चुन कर गये और उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ ली है। सभापति महोदय, 1901 में लैंग्वेस्टिक सर्वे आफ इंडिया जॉर्ज गियरसन ने करवाया था और उसमें राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र समूह परिभाषित किया है 1901 में और 1909 में, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि द इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया में यह निश्चित किया गया था कि जो भी अधिकारी राजस्थान में रहेगा, उस अधिकारी को राजस्थानी भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। यह बात उस वक्त 1909 में, अंग्रेज सरकार के वक्त ये दस्तावेज जारी हुए। सभापति महोदय, आप इधर देख रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं बीच में ही मेरी बात को कह रहा हूं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। केन्द्रीय भाषा अकादमी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है और उन्होंने, सभापति महोदय, पांच लोगों को...

श्री सभापति: आग लगवा दोगे कहकर।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, पांच लोगों को...

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, 02 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.42 बजे बुधवार, दिनांक 02 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में दर्ज शिकायतों का निस्तारण

114. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? उक्त दर्ज शिकायतों का निस्तारण समिति की कौन-कौनसी बैठकों में किया गया? बैठकवार निस्तारित प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त जिले में जिला, तहसील एवं खण्ड स्तर पर भी चौपालों का आयोजन कर जन सुनवाई की जा रही है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कौन-कौनसे अधिकारियों द्वारा किन-किन स्थानों पर कब-कब चौपालों में जन सुनवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में कुल 140 शिकायतें दर्ज हुईं। उक्त दर्ज शिकायतों में से 139 शिकायतों का निस्तारण सतर्कता समिति की मासिक बैठकों में किया गया है। बैठकवार निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला, तहसील एवं खण्ड स्तर पर चौपालों का आयोजन कर जन सुनवाई की जा रही है, जिला भीलवाड़ा में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक चौपालों पर की गई जनसुनवाई का विवरण निम्नानुसार :-

1. वर्ष 2019 में जिला कलक्टर द्वारा 23, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) द्वारा 29, उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 104, तहसीलदारों द्वारा 15 चौपालों में जन सुनवाई की गई। दिनांकवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।
2. वर्ष 2020 में जिला कलक्टर द्वारा 11, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) द्वारा 14, उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 44, तहसीलदारों द्वारा 23 चौपालों में जन सुनवाई की गई। दिनांकवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री)

3. वर्ष 2021 में जिला कलक्टर द्वारा 11, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) द्वारा 10, उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 127, तहसीलदारों द्वारा 39 चौपालों में जनसुनवाई की गई। दिनांकवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

श्रीगंगानगर में राजश्री योजना की लाभार्थी

121. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कितनी कन्याओं को लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में उक्त जिले में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कितनी नवजात बच्चियों के जन्म पर देय राशि का वितरण कर दिया गया है? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना अंतर्गत उक्त जिले में उक्त अवधि में कक्षा 1-12 तक की किन-किन बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है? कक्षावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 39 हजार 9 सौ 24 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें से 25 हजार 3 सौ 15 नवजात कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित कन्याओं की ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक 25 हजार 3 सौ 15 नवजात बच्चियों के जन्म पर 2500 रुपये प्रथम किश्त के रूप में वितरण किया गया है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजश्री योजना 01 जून, 2016 से प्रारम्भ हुई है, जिसमें 6 किश्तों में कुल राशि 50 हजार रुपये देय है।

योजनान्तर्गत कन्या के जन्म पर 2500 रुपये प्रथम किश्त के रूप में, एक वर्ष उपरान्त टीकाकरण करवाए जाने पर 2500 रुपये द्वितीय किश्त के रूप में लाभ दिया जाता है। अभी तक योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ देय था।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

तृतीय किश्त राशि 4000 रुपये कक्षा एक में राजकीय विद्यालय में कन्या के प्रवेश लेने पर देय है, जो वर्तमान वर्ष से देय हुई है। जिसकी भुगतान प्रक्रिया शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्धारित कर ली गई है। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार भुगतान कार्यवाही वर्तमान वर्ष में आरम्भ की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हथौड (डूंगरपुर) में बिलियारा नदी पर पुलिया का निर्माण

122. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में आदिवासी धार्मिक आस्था के प्रसिद्ध स्थल नीलापानी मेला स्थान पर बिलियारा नदी पर गांव हथौड़ में पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में इस पुलिया निर्माण की किसी भी योजना में स्वीकृति नहीं है। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में आदिवासी धार्मिक आस्था के प्रसिद्ध स्थल नीलापानी मेला स्थान पर बिलियारा नदी पर गांव हथौड में पुल निर्माण कराना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विप्र कल्याण बोर्ड का गठन

123. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बोर्ड के लिये कार्यालय, स्टाफ व बजट का आबंटन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में तथ्य यह है कि सरकार के जन घोषणा पत्र 2018 के बिन्दु संख्या 23(7) के अनुसार विप्र कल्याण बोर्ड का गठन अधिसूचना क्रमांक 7011 दिनांक 10.02.2022 (परिशिष्ट-अ) द्वारा कर दिया

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

गया है। तत्पश्चात् आदेश क्रमांक 7054 दिनांक 10.02.2022 द्वारा माननीय अध्यक्ष पद पर श्री महेश शर्मा एवं माननीय उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती मंजू शर्मा को मनोनीत किया गया है। (परिशिष्ट-ब)

(2) इस संबंध में तथ्य यह है कि उक्त बोर्ड के लिये कार्यालय की व्यवस्था कर दी गयी है तथा बजट एवं स्टाफ की व्यवस्था अभी नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आमेर में नवीन राजस्व ग्राम

99. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पं.स. जालसू के ग्राम कान्यावास तथा ग्राम पंचायत अचरोल, पं.स. आमेर के हनुमान नगर को नये राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों का राजस्व ग्राम बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति जालसू के ग्राम कान्यावास तथा ग्राम पंचायत अचरोल, पंचायत समिति आमेर के हनुमान नगर को नये राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के दौरान आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर स्तर से नियमानुसार तैयार किये जा रहे हैं। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होने के उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा परीक्षण कर प्रशासनिक अनुमोदन पश्चात् नवीन राजस्व ग्राम सृजन की अधिसूचना जारी की जावेगी। यह एक सतत प्रक्रिया है।

खींवसर उपखण्ड कार्यालय में रिक्त पद

100. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खींवसर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय में राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों के कौन-कौन से पद, कब से तथा किन कारणों से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खींवसर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय में राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों तथा रिक्ति की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं उक्त पद कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने, उच्च पदों पर पदोन्नत होने व भर्ती प्रक्रियाधीन होने आदि कारणों से रिक्त हैं।

(2) जी हां। प्रक्रियाधीन भर्तियों से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में नियुक्तियां

101. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के उपरांत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कितने पद पर नियुक्तियां पूर्ण कर ली हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण संविदा पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितने अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्तियां संविदा पर कब-कब से की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3)(II)(B) में ट्रस्ट के कार्य संचालन एवं व्यवस्था हेतु, जहां तक सम्भव हो, कोई भी स्थायी/अस्थायी पद सृजित नहीं करने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट में स्थायी/अस्थायी पद के सृजन से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने तथा आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम कर्मचारियों को संविदा के आधार पर लगाया जाने के भी प्रावधान हैं। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। नियमों के उक्त प्रावधान के तहत राज्य के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्टों में कोई भी स्थायी/अस्थायी पद सृजित नहीं किया गया है। अत: कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(2) जी नहीं। भाग संख्या 1 के उत्तर में अंकित अनुसार नियमों

(खान मंत्री)

में जहां तक सम्भव हो, कोई भी स्थायी/अस्थायी पद सृजित नहीं करने के प्रावधान हैं। आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम कर्मचारियों को संविदा के आधार पर लगाया जा सकता है। उक्त प्रावधान के तहत संविदा पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में डी.एम.एफ.टी. से कराये गये कार्य

102. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में डी.एम.एफ.टी. के तहत जिला जोधपुर जिले को कितनी राशि आबंटित की गई? आबंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया व कितनी राशि शेष है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में उक्त फण्ड के माध्यम से उक्त जिले में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा उक्त कार्यो पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विगत दो वर्षों में उक्त फण्ड से किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के डी.एम.एफ.टी. फण्ड में स्टेट मिनरल फण्ड से वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता हेतु राशि रुपये 6625.00 लाख एवं 20 विकास कार्यों के लिए राशि रुपये 8900.00 लाख, कुल राशि रुपये 15525.00 लाख आबंटित कर हस्तान्तरित की गई। हस्तान्तरित राशि में से उपयोग की गई राशि एवं शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला जोधपुर में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) में उक्त फण्ड (स्टेट मिनरल फण्ड से जोधपुर जिले के डी.एम.एफ.टी. फण्ड में हस्तान्तरित राशि) में से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 1022 व्यक्तियों एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत 410

(खान मंत्री)

व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 3519.00 लाख व्यय की गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 उपलब्ध है। उक्त अवधि में 20 विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि रुपये 8900.00 लाख में से 15 कार्यों पर राशि रुपये 2950.00 लाख व्यय की गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में जिला डी.एम.एफ.टी. कोष में खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस/परमिट आदि से प्राप्त अंशदान से दो विकास कार्यों पर राशि रुपये 70.00 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्त अवधि में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 875 व्यक्तियों एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत 246 व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 2,385.50 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट-5 उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) में उक्त फण्ड (स्टेट मिनरल फण्ड से जोधपुर जिले के डी.एम.एफ.टी. फण्ड में हस्तान्तरित राशि) से ढंढेर-मंगेरिया सड़क के निर्माण हेतु 30.00 लाख का व्यय हुआ है। विवरण परिशिष्ट-3 के क्रम संख्या 10 पर अंकित है। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उक्त फण्ड से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 200 व्यक्तियों एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत 55 व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 612.50 लाख व्यय की गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-6 उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में जिला डी.एम.एफ.टी. कोष में खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस/परमिट आदि से प्राप्त अंशदान से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 160 व्यक्तियों एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत 28 व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 367.00 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट-7 उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्द्रगढ़ के बीजासन माता मन्दिर में रोप-वे का निर्माण

103. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों के अनुमोदित कार्यों में जिला बून्दी के ग्राम इन्द्रगढ में स्थित बीजासन माता मन्दिर के पर्यटन विकास कार्य हेतु एक करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर पर आने-जाने हेतु सीढ़ियां काफी संकरी होने के कारण अनहोनी होने का खतरा बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर पर राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण से रोप-वे व वैकल्पिक मार्ग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों के अनुमोदित कार्यों में कोटा सम्भाग के बून्दी जिले के ग्राम इन्द्रगढ़ में स्थित बीजासन माता मन्दिर पर पर्यटन विकास कार्य करवाये जाने हेतु राशि रुपये 99.74 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 20.00 लाख कार्यकारी एजेन्सी- सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवायी गई है।

उक्त कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर से टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त मन्दिर पर पहाड़ के नीचे से बीजासन माता मंदिर तक पैसेन्जर रोप-वे स्थापित किये जाने हेतु निजी फर्म मैसर्स इन्द्रगढ़ बीजासन माता रोप-वे प्रा.लि. द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी, जिला कलक्टर, बून्दी को दिनांक 19-12-2016 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में प्रकरण वाइल्ड लाइफ क्लीयरेन्स हेतु वन विभाग में विचाराधीन है।

नोखा व पांचू पंचायत समितियों में प्रधानमंत्री आवास योजना

104. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नोखा व पांचू पंचायत समिति में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री आवासीय योजनांतर्गत जनवरी, 2022 तक कुल कितने पात्रताधारी व्यक्ति थे? पात्रताधारी व्यक्तियों में से कितनों को आवास स्वीकृत हुए तथा कितने वंचित रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(2) उक्त पंचायत समितियों में जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2022 तक उक्त योजनांतर्गत कितने आवास स्वीकृत हुए तथा कितने बनकर पूर्ण हुए? ग्राम पंचायत व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों के अंतर्गत बड़ी संख्या में पात्रताधारी परिवारों के स्वीकृत आवास अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कितने व क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नोखा व पांचू में सेक-2011 की जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जनवरी, 2022 तक निम्नानुसार पात्रताधारी व्यक्ति, स्वीकृत आवास व वंचित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पं.स.	पात्रताधारी	स्वीकृत	वंचित/बकाया
1	नोखा	5993	5993	0
2	पांचू	6807	6792	15
कुल		**12800**	**12785**	**15**

(2) नोखा एवं पांचू पंचायत समिति में जनवरी 2019 से 20 जनवरी, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जारी 10079 स्वीकृतियों में से 6386 आवास पूर्ण तथा 3693 आवास प्रगतिरत/अपूर्ण हैं।

जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नोखा एवं पांचू पंचायत समिति में वर्ष 2020-21 तक स्वीकृत 12785 आवास में से 606 आवास (4.73 प्रतिशत) अपूर्ण/प्रगतिरत है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान में स्वीकृत 3167 आवासों सहित कुल 3752 आवास प्रगतिरत/अपूर्ण हैं।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है एवं योजनान्तर्गत आवास स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त, दासा स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर द्वितीय किश्त एवं छत डालने का कार्य पूर्ण कराने के उपरांत तृतीय/अंतिम किश्त की राशि ऑनलाइन लाभार्थी के खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नरेगा श्रमिकों को सौ दिन का रोजगार

105. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्य नरेगा श्रमिकों द्वारा करवाया जाना नियत है?

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराडा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा में कुल कितने पंजीकृत नरेगा श्रमिक हैं? विगत दो वर्षों में कितने श्रमिकों को नरेगा अन्तर्गत सौ दिन का रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नरेगा अन्तर्गत श्रम भाग व सामग्री भाग का अनुपात बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्य महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा प्रपत्र-6 में आवेदन किये जाने पर करवाये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर, सराडा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा में पंजीकृत नरेगा श्रमिकों का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

पंचायत समिति	**जारी जॉब कार्ड की संख्या**
सलूम्बर	29170
सराडा	24826
झल्लारा	958
सेमारी	7079
जयसमंद	20709

(2) विगत दो वर्षों में मनरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले श्रमिकों को संख्या का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

पंचायत समिति	100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या		
	2020-21	2021-22	योग
सलूम्बर	1865	856	2721
सराडा	1767	579	2346
झल्लारा	96	40	136
सेमारी	1523	838	2361
जयसमंद	1776	688	2464

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम व सामग्री भाग का अनुपात क्रमश: 60:40 निर्धारित है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम के तहत किया जाता है। अत: योजना क्रियान्वयन में नीतिगत निर्णय भारत सरकार के स्तर से ही लिया जा सकता है।

मनरेगा मजदूरों को देय मजदूरी

106. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा में श्रमिकों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी देना निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर व नागौर जिले में जनवरी 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक मजदूरों को निर्धारित दर से कम मजदूरी प्रदत्त की गई है? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यूनतम मजदूरी रुपये अठारह हजार प्रति माह देने के फैसले को मनरेगा क्षेत्र में भी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या मनरेगा मजदूर को उसको निर्धारित कार्य पूर्ण करने पर समय से पूर्व कार्यस्थल छोड़ने का अधिकार है? यदि हां, तो क्या प्रदेश में मनरेगा में उक्त शिथिलता की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.03.2021 के द्वारा राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रुपये 221/- प्रति दिवस निर्धारित है। (विभागीय आदेश दिनांक 01.04.21 परिशिष्ट-1)

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान निर्धारित टास्क के विरुद्ध वास्तविक रूप से किये गये कार्य के आधार पर किया जाता है। जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक श्रमिकों को भुगतान की गयी मासिक औसत मजदूरी एवं रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम के तहत किया जाता है। योजना क्रियान्वयन में नीतिगत निर्णय भारत सरकार के स्तर से ही लिया जा सकता है।

(4) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्य स्थल छोड सकता है। (विभागीय आदेश दिनांक 29.07.2020, परिशिष्ट-3) राज्य में उक्त शिथिलता की पालना की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ सम्पत्ति को बोर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया

107. **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति दर्ज करने की क्या प्रक्रिया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ सम्पत्ति को बोर्ड में दर्ज करने के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों का पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु कोई संशोधन कर सभी धर्मों के अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड में किसी सम्पत्ति को दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित फार्म रजिस्ट्रेशन औकाफ् के साथ स्वामित्व संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर सम्पत्ति वक्फ रिकार्ड में दर्ज की जाती है। फार्म की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वक्फ सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर अधिकृत है।

(3) जी नहीं। केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 में किसी प्रकार का संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवन

108. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को भूमि आबंटित कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 2 परियोजनाएं बाल विकास परियोजना बामनवास एवं बौंली संचालित हैं, जिनमें परियोजना बामनवास में 9 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना बौंली के 21 आंगनबाड़ी भवन, कुल 30 आंगनबाड़ी भवन जर्जर अवस्था/मरम्मत योग्य में हैं।

जर्जर अवस्था/मरम्मत योग्य भवन एवं भवन रहित 37 आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

निकाय/स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

109. श्री प्रताप सिंह (छबडा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? उक्त संचालित केन्द्रों में कौन-कौन से संवर्ग में, कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वर्तमान में पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन में, कौन-कौन से संवर्ग में, कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौन से आंगनबाड़ी केन्द्र स्थायी सरकारी भवन में एवं कौन-कौन से केन्द्र किराये या अस्थायी भवन में संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: बाल विकास परियोजना छबड़ा एवं छीपाबड़ौद संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत परियोजना छबड़ा में 178 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 50 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 228 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। परियोजना छीपाबड़ौद में 196 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 25 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 221 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण एवं उन पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों का संवर्गवार एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा सहयोगिनी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र. सं	परियोजना	रिक्त पद				
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी सहायिका	आशा सहयोगिनी	पूर्व प्राथमिक शिक्षक
1.	छबड़ा	10	1	9	13	3
2.	छीपाबड़ौद	2	0	6	5	1
	योग-	**12**	**1**	**15**	**18**	**4**

रिक्त पदों की पदवार सूची परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	केन्द्र संचालन का विवरण			
		विभागीय भवन	किराये के भवन में	स्कूल में	अन्य भवनों में
1	छबड़ा	93	56	71	8
2	छीपाबड़ौद	60	54	98	9
	योग-	**153**	**110**	**169**	**17**

भवनों के संचालन की परियोजनावार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

110. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने आंगनबाड़ीकेन्द्र संचालित हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाडी केन्द्रों में से कितने आंगनबाडी केन्द्रों के सरकारी भवन हैं तथा कितने किराये के भवन में संचालित हैं?

(3) क्या उक्त आंगनबाडी केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली, पानी, टॉयलेट आदि की सुविधा उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कहां-कहां? सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश:

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

बस्सी एवं चाकसू संचालित हैं। परियोजना बस्सी के अन्तर्गत 297 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना चाकसू के 26 आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 323 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के 323 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 255 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में तथा 68 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली, पानी, टॉयलेट आदि की सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली, पानी, टॉयलेट आदि की सुविधाएं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

111. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों द्वारा पिछले काफी समय से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, दो विभागों के स्थान पर एक विभाग में कार्य करने एवं मानदेय राशि बढ़ाने के संबंध में मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मांगों के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आशा सहयोगिनियों की मांगों के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विचार कर लिया गया है एवं शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

(2) वर्तमान में प्रदेश सहित ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/ जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 लिखे गए, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

जैतारण में सहायक अभियंता के रिक्त पद

112. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उपखण्ड में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 2 सहायक अभियन्ता के पद क्रमश: उपखण्ड जैतारण एवं उपखण्ड बर तथा कनिष्ठ अभियन्ता के 2 पद क्रमश: उपखण्ड जैतारण एवं उपखण्ड बर में स्वीकृत हैं। वर्तमान में उपरोक्त सभी पद रिक्त हैं। विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति होने पर रिक्त पदों को पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

रानीवाड़ा में रिक्त पद

113. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के सभी पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण से बजट घोषणाओं एवं अन्य कार्यों के क्रियान्विति में बाधा आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि उक्त विधान सभा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को नजदीकी स्थान पर पदस्थापित अभियन्ताओं को अतिरिक्त चार्ज दिया जाकर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सम्पादित कराया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में उपखण्ड रानीवाड़ा एवं उपखण्ड जसवन्तपुरा में सहायक अभियन्ता (सिविल) के एक-एक एवं अनुभाग रानीवाड़ा में एक पद कनिष्ठ अभियन्ता का स्वीकृत है। वर्तमान में विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति होने पर रिक्त पदों को पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बारां में डामर सड़क से वंचित ग्राम

114. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां में 250 से अधिक आबादी के ऐसे कितने गांव हैं, जो डामर सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में 500 की आबादी का कोई गांव सड़क से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सरकार उक्त गांवों को सड़क से कब तक जोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत तीन वर्षो में उक्त जिले में कहां कहां पर डामर सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के 52 गांव हैं, जो डामर सड़क सुविधा से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, लेकिन उक्त गांवों को सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यो की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(3) बारां जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 500 एवं अधिक आबादी के 10 ग्राम सड़क से वंचित हैं। इन ग्रामों का मार्ग वनक्षेत्र से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

होकर जाने के कारण सड़क निर्माण नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) विगत 3 वर्षों में बारां जिले में किये गये डामर सड़कों के निर्माण का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर में पालनहार योजना के आवेदन

115. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विगत एक वर्ष में पालनहार योजना के तहत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितनों को लाभान्वित किया गया एवं कितने आवेदन शेष हैं?

(3) क्या सरकार शेष आवेदन पत्रों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पालनहार योजनान्तर्गत गत 1 वर्ष में 295 आवेदन प्राप्त हुए।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उपरोक्त आवेदनों में से 257 को लाभान्वित किया गया एवं 36 आवेदन पत्र आवेदक के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लम्बित हैं।

(3) आवेदकों द्वारा आक्षेप पूर्ति करवाने के पश्चात् पात्रतानुसार नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा।

कोटा की भामाशाह कृषि उपज मण्डी की आय

116. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा की भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति की विगत तीन वर्ष में कुल कितनी आय हुई है? वर्षवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(2) विगत तीन वर्ष में प्राप्त आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया?

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र सांगोद में प्राप्त आय से क्या कार्य करवाये गए? कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा को गत 3 वर्षों में प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**राशि (लाखों में)**
2018-19	7361.44
2019-20	8764.07
2020-21	6041.27
2021-22	3918.32 (जनवरी 2022 तक)

(2) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा द्वारा गत 3 वर्षों में प्राप्त हुई आय से कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा द्वारा विधान सभा क्षेत्र सांगोद में गत 3 वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन

117. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बोर्ड के गठन के लिए अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) इलेक्ट्रोपैथी एक्ट बनने से पूर्व प्रदेश में कितने इलेक्ट्रोपैथी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त बोर्ड के गठन में हो रहे विलम्ब के कारण प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम बंद है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018 के अन्तर्गत राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड के प्रथम गठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में (वर्तमान में प्रासंगिकता, उपादेयता, विधि मान्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की विद्यमानता, लाभार्थी समूह, औषधियों की उपलब्धता विधिक राय आदि का गुणावगुण के आधार पर) समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अत इस एक्ट के पारित होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा उक्त सूचना संधारित नहीं की गई।

(4) वर्तमान में Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018 अन्तर्गत इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम संचालन हेतु कोई संस्था अधिसूचित/सम्बद्धता प्राप्त नहीं है।